## [इन्टरमीडियेट-बोर्ड द्वारी समाजन्मास्य के लिए स्वीकृत पुस्तक ]

# भारतीय-सामाजिक-संगठन [INDIAN SOCIAL ORGANISATION]

#### : 有理基

विद्यामार्तण्ड प्रो० सत्यवत सिद्धान्तालंकार

सिंशोधित तथा परिवर्धित संस्करण ]

बूल्य तीन चपमा

वितीय संस्करण ]

1840

#### प्रकाशक : विवासकृष्यः सम्मन्धाः शुक्तः सन्पत्ते, विवास्विहार, ४ वलवीरः ऐहेन्स्,

बेहरावून ।

ं हमारे ग्रन्थ			
- •	. , 1		
?. एक <b>ळकोननिव</b> द्	\$4.311		
[सचित्र, हिन्दी में, मूल-सहि	ਗ]		
२. बार्य-संस्कृति के मूल-तत्व	٧)		
३. ब्रह्मचर्य-सन्देश	¥۱۱)		
४. शिक्षा-मनोविज्ञान	<b>५॥=</b> }		
५. शिक्षा-शास्त्र	Y)		
६. समाज-शास्त्र के मूल-तत्व	१२॥)		
७. समाज-कल्याण तथा सुरक्षा	१२॥)		
दः मानव-शास्त्र	१२॥)		
<ol> <li>समझ्ब-बास्य तथा वाल-कल्य</li> </ol>	ाण ४)		
१०. स्त्रियो की स्थिति	٧)		
११. प्रारम्भिक सम।जशास्त्र	₹11)		
१२. भारतीय-सामाजिक-संगठन	3)		
मिलने का पता:			
विजयकृष्ण लखनपाल एण्ड	कम्पनी		
विका-विद्वार			
४ बसवीर ऐथेन्यू, देहरादूत ।			

मुद्रकः सुरेन्द्रनाथ गुप्ता, सरस्वती प्रेस, बेहराडून

# हिन्दी के इंगारे अगर प्रकाशन

#### ं क्रांकी विकेश संबंध के लिये

#### इस पुस्तक पर १२००) का पारितायिक जिला है

#### शिक्षा-मनोविज्ञान (सचित्र)

लेकिका--वन्द्रावती लखनपाल एम० ए०, बी० टी० (एम॰ पी०)

श्विसा-मतोविज्ञान पर यह हिन्दी में सर्वोत्तम पुस्तक है। इस पर हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, इलाहाबाद ने १२००) का मगलाप्रसाद-पारिलोधिक देकर लेखिका को सम्मानित किया था। काशी विश्वविद्यालय के उस समय के प्रिन्सिपल, जिस समय यह पुस्तक लिखी गई थी, रायबहादुर लज्जाशंकर मा ने इस पुस्तक के सम्बन्ध में लिखा था कि चन्द्राबती जी ने ऐसी उत्तम पुस्तक लिखकर हिन्दी-साहित्य की भारी सेवा तो की ही है, साथ ही ट्रेनिंग कालेज को तो वरतन्तु के शिष्य के समान १४ करोड़ की दक्षिणा चुका दी है।

इस पुस्तक में ४० के लगभग चित्र दिए गए हैं। पहले संस्करणों से अब पुस्तक में दुगना मेंटर है। यह पुस्तक का सालगा संस्करण है। इन्टरमीजियेट तथा नार्मल स्कूलों के खिये इससे बढ़िया दूसरा कोई अन्य नहीं है। सजिल्द पुस्तक का मृल्य पांच रुपया दस माना।

### इन्टरमीजियेट स्था देखिंग के लिये

#### २. शिक्षा-शास्त्र (सचित्र)

तेकक--विकासार्तण्ड श्री प्रो० सत्यवत सिद्धान्तालकार श्रीमती चन्द्रावती सक्षनपाल एम० ए०, बी० टी०

इस पुस्तक की भूमिका माननीय सम्पूर्णानन्द भी ने जिली है। 'शिक्षा' के सम्बन्ध में जितने भाष्ट्रानिक विचार है, वे भव इस प्रत्य में जिले भाष्ट्रानिक विचार है, वे भव इस प्रत्य में जोड़े-से में, प्रत्यन्त सरव तथा रीजक माचा में दिये गए हैं। 'शिक्षा के सिकान्त (Principles of Education), 'शिक्षा की विधि' (Method of Education), 'शिक्षा का विद्यान' (Organisation of Education) तथा 'भारतीय-विक्षा का मादि-काल से भाज तक का इतिहास' (History of Indian Education)—ये सब विषय इस ग्रन्थ में एक साथ क्षिये गए हैं, इस बबीन संस्करण में शिक्षा-शास्त्रियों के पच्चीस चित्र दिए पूर्व है भीर सी पृष्ठ का मैटर बढ़ा दिया गया है। शिक्षा-शास्त्र पर यह महितीय पुस्तक है। सजिल्ब पुस्तक का मृत्य चार रुपया।

#### ्रम्टरमेजियेट होन-साइम्स के सिवे ३. समाज-शास्त्र तथा, बाल-कल्याण [Sociology and Child-Welfare]

(लेखक : विधामातिष्ट्रं प्री॰ सत्यवत सिक्कान्तालंकार)

#### मूमिका-लेखक

बाचार्य मुगलकियोर जी, समान-कल्यास मन्त्री, उत्तर-प्रदेश

संगाज-सारत्र वर्तमान-युग का दिनोंदिन बढ़ता हुआ विषय है। प्राय: समी विश्वविद्यालयों में इस विषय का ग्रव अध्यापन होने लगा है। सर्व-साधारण के लिये भी इसकी जानकारी उन्हें जीवन में सफल बनाने में सक्त्र की मों हुए विद्यान् है। प्रेन्होंने इस विषय पर अनेक पुस्तक लिखी है जो बी०ए० तथा एम०ए० के विद्यायियों को पढ़ाई जाती है। यह पुस्तक समाज-शास्त्र का साधारण परिच्छ देने के लिये लिखी गई है और इसलिये इसमें उन सभी विषयों की चर्चा की गई है जो इन्टरमीजियेट की योग्यता रखने वाले ध्यक्ति के लिये आवश्यक है। अब कन्यायों को होम-साइन्स (Home Science) पढ़ाने के लिए इस पुस्तक का इन्टरमीजियेट की छात्रायों के लिये उपयोग होने लगा है। वैसे सर्व-साधारण के लिये भी समाज-शास्त्र के विषय की जानकारी के लिये बह बहुत उत्तम अन्य है। पुस्तक की विषय नी जानकारी के लिये मह बहुत उत्तम अन्य है। पुस्तक की विषय-सूची निम्न है:—

#### विषय-सूची

		-					
₹.	मानवीय-एषणाएँ 🕖		<del>वि</del> वाहप्राणिशास्त्रीय				
₹.	विफलता		तथा कानूनी दृष्टि से				
₹.	एवणांभीं की पूर्ति का	22.	तथा कानूनी दृष्टि से वैवाहिक-सामंजस्य				
	साधन'परिवार' 💂		परिवार का ग्राय-व्यय का				
¥.	भारतीय-परिवार		लेखा				
	संयुक्त तथा वैय्यक्तिक	₹₹.	गर्भवती की वेख-माल				
3,	'परिवार'	-68.	प्रसव के समय की तैयारी				
€.	बचपन का 'व्यक्तित्व' पर प्रभाव	r 2%.	नव-जात की देख-माल				
	बाल्यावस्था तथा यौन-शिक्षा		शिशु की देख-माल				
₩.	योनि-मेद (बालक-बालिका		बाल-मृत्यु का प्रश्न				
	सम्बन्ध )		बाल-कल्याण की योजनाएँ				
€.	किशोरावस्था के विवाह-		बालकों के विकास का				
	लाभ तथा हानियाँ	•	मञ्चयन				
सजिल्ब पुस्तक को मूल्य चार रुपयो							

#### इन्टरमीजिवेट सोशियोक्रोजी के जिये-पेपर (A)

#### ४. पारम्भिक-समाजशास्त्रः । [Elements of Sociology]

ले -- विद्यामार्तण्ड प्रो० सत्यवत विद्धान्तार्वकार

१६५८ से इन्टरमी जियेट में भी 'समाजवास्य' की विषय पढ़ीया जा रहा है। इस सम्बन्ध में समीजवास्य के माने हुए विद्वान ' भी के संस्यवत जी ने हात ही में वो पुस्तक लिखी है जिनमें से अवन-यन की पुस्तक का नाम ''प्रारम्भिक-समाजवास्त्र'' है। इस पुस्तक की विषय-सूची यहाँ दी जा रही है जिससे स्पष्ट हो जायमा कि यह पुस्तक समाज-बास्त्र के प्रारम्भिक-जान के लिये प्रदितीय है। बोर्ड द्वारा इसे स्वीकृत किया गया है। यह पुस्तक का संभोषित तथा परिवर्णित कितीय संस्करण है।

[प्रथम प्रश्न-पत्र]

 समाजवास्त्र का स्वरूप तथा विषय-क्षेत्र (Nature and Scope of Sociology).

२. समाजकास्य का जन्य सामाजिक-विज्ञानों के साथ सम्बन्ध (Relation of Sociology with other Social Sciences—Economics, Psychology and Political Science).

३. समाज, समुदाय तथा समिति की परिभाषाएँ (Definitions of Society, Community, Association).

४. बाति तथा श्रेणी (Caste and Class).

५. परिवार का सगठन—रचना तका कार्य (Family Organisation —Structure and Functions).

 विवाह—रचना तथा कार्य (Marriage—Structure and Functions).

७. पर्यावरण तथा उसका सामाजिक-जीवन पर प्रभाव (Environment and its effects on social life).

5. भौगोलिक-पर्यावरण (Geographical Environment).

E. सांस्कृतिक-पर्यावरण (Cultural environment).

१०. व्यक्ति तथा समाज (Individual and Society).

११. सामाजिक-वियठन (Social Disorganisation).

१२. अपराध (Crime).

१३. किशोरापराच (Juvenile Delinquency).

१४. निर्वनता—कारण तथा निवारण (Poverty—Causes and Cures).

१५. बेकारी—कारण तथा निवारण (Unemployment—Causes, and Cures).

इस पुस्तक का दाम तीन रुपया घाठ घाना है

[इस पुस्तक पर उत्तर-प्रवेश सरकार द्वारा १००० रुपया तथा श्रक्तिस भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा १२००) संगतात्रसाद पारितोषिक मिला है।}

नवीन परिवर्धित तृतीय संस्करण

६. समाज्ञशास्त्र के मूल-तत्व

(बी॰ ए॰ के प्रथम तथा द्वितीय प्रश्न-पत्रों के लिए) [Elements of Sociology]

(लेखक--विद्यामार्तण्ड प्रो० सत्यवत सिद्धान्तालंकार)

समाज-शास्त्र के मूल-तत्व पर भनेक पुस्तकं प्रकाशित हो रही हैं, परन्तु उन सबमें से प्रामाणिक तथा सर्वे-मान्य पुस्तक प्रो० सत्यव्रत जी का 'समाज-शास्त्र के मूल तत्व' ही है। इस पुस्तक की श्रेष्ठता इसी से प्रमाणित है कि उत्तर-प्रदेश की सरकार ने बी० ए० के लिये अपने विषय की सर्वोत्कृष्ट पुस्तक होने के कारण इस पर १०००) रुपये का और हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ने १२००) का पारितोषिक दिया है।

पुस्तक का पहला तथा दूसरा सस्करण समाप्त हो चुका है। अब पुस्तक का तृतीय सशोधित नवीन-संस्करण प्रकाशित हुन्ना है जिसमे पहले दोनो सस्करणो की अपेक्षा नया मैटर बढ़ाया गया है।

इस पुस्तक के विषय में एक विद्यार्थी ने लिखा या—'यदन्यत्र तदिहास्ति यदिहास्ति न तत्कवित्तत्ं—जो दूसरी किसी पुस्तक में है वह तो इसमें है ही, जो इसमें है वह किसी पुस्तक में नही है।

मूल्य बारह रुपया ग्राठ ग्राना ।

#### बी० ए० सीशियोत्होजी पार्ट II के लिये

समाज-कल्याच तथा सुरक्षा
[Social-Welfare and Security]

मूमिका-लेखिका-श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख,

यध्यक्षा केन्द्रीय-समाज-कल्याण-बोर्ड

(लेखक - विद्यामार्तण्ड प्रो० सत्यवत सिद्धान्तालंकार)

माज का युग समाज-कल्याण का युग है। समाज-कल्याण का भाषार क्या है? समाज-कल्याण किसे कहते हैं? — ये सब विषय आज विषय- विषया के छात्रों को पढ़ाये जा रहे हैं। समाज-शास्त्र की बी० ए० तथा एम० ए० की पाठ-विष्य में समाज-कल्याण एक विषय है, परन्तु इस पर अभी तक कोई प्रामाणिक पुस्तक नहीं थी। प्रो० सत्यव्रत जी ने इस कमी को पूरा कर दिया है। जहां-जहां भी समाज-सेवक तैयार किये जा रहे हैं, वहां-वहां इस पुस्तक के आधार पर इस विषय की सुन्दर विवेचना की जा सकती है। इस पुस्तक द्वारा बी० ए० तथा एम० ए० के विद्यार्थियों की 'समाज-कल्याण'-सम्बंधी समस्या पूर्णक्ष्य से हल हो गई है। पुस्तक में ४० के लगभग अध्याय है और ६५० के लगभग पृष्ठ हैं। बड़े साइज की कपड़े की सजिल्द पुस्तक का दाम केवल बारह रुपया आठ आना रखा गया है। यह पुस्तक का दितीय संस्करण है:

#### मानव-शास्त्र

लेखक-विद्यामार्तण्ड प्रो॰ सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार

यह पुस्तक एम० ए० (श्रागरा विश्वविद्यालय) के द्वितीय-पत्र (Social Anthropology) के लिये लिखी गई है। इस ग्रन्थ के कुछ श्रध्याय बी० ए० पार्ट II के प्रथम-पत्र के लिये भी बहुत उपयोगी हैं। इस पुस्तक में विभिन्न विश्वविद्यालयों की पाठ-विधि के श्रनुसार ३१ श्रध्याय ऋगवद्ध है। विषय को सुबोध बनाने के लिये स्थान-स्थान पर ५० चित्र भी दिए गये हैं।

बिह्या कागज पर ६४० पृथ्ठों की —पूरी कपड़े की बिह्या जिल्द सिह्त इस पुस्तक का मूल्य १२॥) है।

#### ह. ब्रह्मचर्य-सन्देश समिका-सेवक

श्री १०८ स्वामी अद्धानन्द जी महाराज (पुस्तक-लेखक---विद्यामार्तण्ड श्री प्रो० मस्यवत जी सिद्धान्तालंकार)

नवयुवको को बहाचर्य-जैसे सम्भीर विषय पर सरल, सुन्दर भाषा में जो-कुछ कहा जा सकता है, इस पुस्तक मे कह दिया गया है। स्व० स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज ने इस पुस्तक की भूमिका लिखी थी। सण्डवा का कर्मवीर पत्र लिसता है-"सबसे श्रधिक खोजपूर्ण, सबसे अधिक प्रामाणिक, सबसे अधिक ज्ञातच्य विषयों से भरी हुई यही पुस्तक देखने में ब्रायी है।" इस पुस्तक मे ५-१० चित्र ब्रार्ट-पेपर पर दिए भए हैं जिनका बहाचर्य जैसे कठिन विषय को समभने के साथ विशेष सम्बन्ध है। पुस्तक के तीन सस्करण समाप्त हो चुके है, यह चौथा सस्करण है। इस पुस्तक की श्रेष्ठता इसी से सिद्ध है कि गुजराती मे इसके दो स्वतन्त्र अनुवाद हो चुके हैं। अभेजी मे अन्यकर्ता ने स्वय इसका अनुवाद किया है, जिसके कई सस्करण निकल चुके हैं। अनेक नवयुवको ने इस ब्रन्थ को पढ़कर लिखा है कि क्या ही घच्छा होता. कुछ दिन पहले यह पुस्तक मेरे हाथ पड़ जाती और मै जीवन-मार्ग में पथ-भ्रष्ट होने से बच जाता । बड़े भाई को छोटे के, पिता को पुत्र के धीर नवयुवकों के शुभविन्तकों को भपने भिभावको के हाथ में देने के लिए इससे उत्तम दूसरी पुस्तक नहीं हो सकती । कोई भी पुस्तकालय इस पूस्तक के बिना अधूरा है।

कपडे की सजिल्द पुस्तक का मूल्य साढ़े बार रुपया। सेकसरिया-पारितोषिक-प्राप्त-प्रत्य १०. स्त्रियों को स्थिति

लेखिका — प्राचार्या चन्द्रावती लखनपाल एम० ए०, बी०टी० (एम. पी) इस पुस्तक की लेखिका की इस पुस्तक के लेखिन पर हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन इलाहाबाद ने सर्वोत्तम लेखिका घोषित कर ५०० रुपये का 'सेकसरिया-पुरस्कार' दिया था। इस पुस्तक मे स्त्रियों सम्बन्धी प्रश्लो पर बिल्कुल मौलिक ढग से विचार किया गया है। पुस्तक की विचार-धारा में एक प्रवाह है जो साहित्यिक-पुस्तकों में कम देखने में धाता है। यह पुस्तक का नवीन सस्करण है, प्रौर पहले संस्करणों की मपेक्षा कई नवीन विषय इस संस्करण में बढ़ा दिये गये हैं। यह पुस्तक पिता प्रपत्ती पुत्री को, पित ग्रपनी पत्नी को भौर भाई भ्रपनी बहिन को मेंट दे, तो इससे बढकर दूसरी मेंट नहीं हो सकती। पुस्तक पर कपड़े की सुन्दर जिस्द है। दाम चार रुपया मात्र ।

# ११. ग्रार्य-संस्कृति के मूल-तत्व

(लेखक-विद्यामातंण्ड प्री० सत्यप्रत सिद्धान्तालंकार)

दैनिक हिन्दुस्तान अपने १० जनवरी १९१४ के यांक में लिखता है—"हम तो यहां तक कहने का साइस रखते हैं कि भारत से बाहर जाने वाले सास्कृतिक-मिश्चन के प्रत्येक सदस्य को इस पुस्तक का श्रवलोकन करना चाहिये। लेखक की विचार-शैली, प्रतिपादन-शैली, विषय-प्रवेश की सूक्ष्मता डॉ० राघाकृष्णन से टक्कर लेती है। ग्राज के देश के अग्रेशीमय वातावरण में यदि इस पुस्तक का ग्रग्नेशी में अनुवाद करा दिया जाय, तो पुस्तक विशेष लोकप्रिय होगी।"

नव-भारत टाइम्स अपने १० बिसम्बर १६५३ के आंक में लिखता है—"लेखक ने आयं-संस्कृति के अवाह समुद्र में पैठकर, उसका मन्थन करके, उसमें छिपे रत्नों को बाहर लाकर रख दिया है। भाषा इतनी परिमाजित है कि पढ़ते ही बनती है। इस ग्रन्थ को अगर आयं-संस्कृति का दर्शन-शास्त्र कहा जाय, तो अत्युक्त न होगी। हिन्दी के संस्कृति-सम्बन्धी साहित्य में इस ग्रन्थ का स्थान अगर रहने वाला है।"

साप्ताहिक हिन्दुस्तान अपने ३ जनवरी १९४४ के धंक में लिखता है— "हमारी सम्मति में आयं-सस्कृति के सम्बन्ध में आज तक जो पुस्तकें लिखी गई हैं, उनमें प्रो० सत्यव्रत जी की लिखी इस पुस्तक का बहुत ऊँचा स्थान है। समग्र पुस्तक गहन विषयों को सरल भाषा में व्यक्त किये गए विचारों से भरी पड़ी है। आयं-संस्कृति के सम्बन्ध में इस प्रकार की मार्मिक-विवेचना करने वाली यह पहली पुस्तक हमारे देखने में आई है। जो लोग आयं-संस्कृति के सम्बन्ध में जानकारी हासिस करना चाहें, उनका जान इस पुस्तक को पढ़े बिना अधूरा रहेगा।"

#### पुस्तक की विषय-सूची

१. धार्य-संस्कृति का केन्द्रीय विचार, २. विचारो से संघर्ष में ध्रार्य-संस्कृति का वृष्टि-कोण, ३. निष्काम-कर्म, ४. कर्म का सिद्धान्त, ५. धातम-तत्व, ६. स्वार्थ-परार्थ-विवेचन में 'धहंकार' तथा 'धातम-तत्व', ७. विश्व-बन्धृत्व का भाषार भात्म-तत्व, ६. जीवन-यात्रा के चार पड़ाव, ६. नव-मानव का निर्माण, १०. वर्ण-व्यवस्था का धाष्ट्यात्मक धाषार, ११. भौतिकवाद बनाम धाष्ट्यात्मवाद, १२. उपसंहार ।

सजिल्द पुस्तक का मूल्य चार रूपया

#### इस पुस्तक पर ८०० स्थवा पारितोषिक मिला है

### धारावाही हिन्दी में सचित्र

१२. एकादशोपनिषद्
( मूल-सहित )

भूमिका-लेखक

#### भारत के उपराब्द्रपति श्री काँ० राधाकुष्णन

( लेखक-विद्यामार्तण्ड प्रो० सत्यवत सिद्धान्तालकार )

भार्य-संस्कृति के प्राण उपनिषद् है। उपनिषदों के भ्रनेक भनुवाद हुए है, परन्तू प्रस्तृत अनुवाद सब अनुवादों से विशेषता रखता है। इस मनुवाद में हिन्दी को प्रधानता दी गई है। जो व्यक्ति संस्कृत के बखेडे में न पड़ कर उपनिषद् का तत्व ग्रहण करना चाहे, वह सिर्फ हिन्दी भाग पढ जाय। कोई स्थल ऐसा नहीं मिलेगा जो सरल न हो, स्पष्ट न हो, जिसमें किसी तरह की कोई उलभन हो। ऊपर मोटे-मोटे ग्रक्षरो में हिन्दी भाग दिया गया है, जो हिन्दी तथा मूल-संस्कृत की तुलना करना चाहे उसके लिए धँक देकर नीचे सस्कृत-माग भी दे दिया गया है। फुट-नोट मे दिये सस्कृत-भागको इनोड़ कर जो सिर्फ हिन्दी में पढ़ना चाहे वह धारावाही हिन्दी-भाग को पढता चला जाय---विषय एकदम स्पष्ट होता चला जायगा, कही, किसी तरह का **भटकाव नही ग्राएगा। पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषतायह है कि मनुबाद मे मन्स्ती-पर-मन्स्ती भारने की कोशिश नहीं की गई,** विषय को स्रोलकर रख दिया गया है। साधारण पढ़े- लिखे लोगों तथा सस्कृत के भगाध पडितो-दोनों के लिए यह नवीन ढंग का ग्रन्थ है। यही इस भनुवाद की मौलिकता है।

मुख्य-मुख्य उपनिषद् ग्यारह मानी गई है। इन सभी उपनिषदो का भारावाही हिन्दी भनुवाद इस प्रन्य में मूल-सहित दे दिया गया है। पुस्तक को रोचक बनाने के लिए जगह-जगह चित्र भी दिये गये है। बढिया कपडे की सजिस्द पुस्तक का मूल्य बारह रूपया।

इन पुस्तकी के मंगाने का पता

विजयकृष्ण लखनपाल एण्ड कम्पनी विद्या-विहार, ४ बलबीर ऐवेन्यू, देहरादून ।

# भारतीय-सामाजिक-संगठन [Indian Social Organisation]

### ्विषय- सूची

₹.	जाति-व्यवस्थाभाषार-भूत-तत्व, कार्यं, परिवर्तन (Caste Sy	stem
	-Characteristics, Function and Change)	. १६
₹.	जाति-व्यवस्था में परिवर्तन के तत्व (Factors of Chang	e in
	Caste System)	५०
₹.	संयुक्त-परिवारमाघारभूत-तत्व, गुण-दोष, परिवर्तन (र	
	Family-Characteristics, Defects and Factors infl	uenc-
	ing Change)	90
٧.,	विवाह के प्रकार (Forms of Marriage)	59
ų,	सामाजिक-विधान तथा उसका विवाह पर प्रभाव (Social	
	Legislation and its effect on Marriage)	१११
₹.	ग्राम-सगठन (Village-Community)	3 5 9
<b>9</b> .	ग्राम-पचायत (Village-Panchayat)	१६४
<b>5</b> .	मारत की निर्धनता—कारण तथा निवारण	
	(Indian Poverty—Causes and Remedies)	१७८
8.	भारत में भायोजन (Planning in India)	838
	भारत में सामाजिक कल्याण (Social Welfare in India)	२१०
₹.	भशुद्धि-शुद्धि पत्र	3 \$ 5
₹.	१९५६ के इन्टर के समाजशास्त्र के द्वितीय-पत्र का प्रश्न-पत्र	

# भूमिका

प्रत्येक श्रास्त्र का एक 'विचारात्मक' (Theoretical) तथा दूसरा 'क्रियात्मक' (Practical) पहलू होता है। विचारात्मक-पहलू में उस शास्त्र के सिद्धान्तों का, मूल-तत्वों का वर्णन होता है, क्रियात्मक-पहलू में उन सिद्धान्तों ने क्या रूप घारण किया—इसका वर्णन होता है। समाज-शास्त्र के भी इसी प्रकार दो पहलू हैं। समाज-शास्त्र के 'विचारात्मक' पहलू का वर्णन हमने अपने 'प्रारम्भिक-समाजशास्त्र' प्रत्य में किया है, उसके 'क्रियात्मक' पहलू का वर्णन हम 'भारतीय-सामाजिक-संगठन'—इस प्रस्तुत प्रन्थ में कर रहे हैं।

समाज-शास्त्र के जो धाधार-भूत सिद्धान्त है, वे तो हर देश और हर काल में एक-से रहते हैं, परन्तु इन सिद्धान्तों का कियात्मक रूप हर देश में और हर काल में भिन्न-भिन्न होता है। क्योंकि हम भारत में रहते हैं, भारत में भी वर्तमान-काल में रहते हैं, इसलिए हमारे लिए यह जानना भावस्थक हो जाता है कि अपने देश में, और अपने देश में भी वर्तमान-युग में समाजशास्त्र के सिद्धान्तों के आधार पर क्या सामाजिक-सगठन बना और आज बन रहा है। हमारा जो 'भारतीय-सामाजिक-सगठन बना और आज बन रहा है। हमारा जो 'भारतीय-सामाजिक-सगठन' वन चुका है, उसका कुछ थोड़ा-बहुत इतिहास भी है। इसी दृष्टि से इस ग्रन्थ में भारतीय-सामाजिक-संगठन की मुख्य-मुख्य बातों तथा उनके इतिहास को संक्षेप में दिया गया है। उदाहरणार्थ, भारत की जाति-व्यवस्था क्या है, यह व्यवस्था क्यों उत्पन्न हुई, आज इस जाति-व्यवस्था में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, संयुक्त-परिवार-प्रथा क्या है, इसका वर्तमाक रूप क्या है, इसके रूप में वर्तमान-युग में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, विवाह पद्धित किन-किन परिवर्तनो, में से गुजर चुकी है भीर आज गुजर रही है,

विधान-समाधों में क्या नये-नये सामाजिक-विधान बन रहे हैं, हमारा ग्रामीण-सगठन क्या था, उसमें ग्राज क्या परिवर्तन ग्रा रहा है, भारत की ग्रामिक-स्थिति में क्या-क्या परिवर्तन ग्रा रहे हैं, ग्राज हम ग्रपने समाज का किस प्रकार नियोजन कर रहे हैं—इन सभी प्रश्नों पर इस ग्रन्थ में प्रकाश डाला गया है ताकि हम समभ सकें कि समाज-शास्त्र के ग्राधार-भूत सिद्धान्त ग्रपने देश में क्यान्त्र्या कियात्मक रूप धारण कर रहे हैं।

समाज-बास्त्र का गहराई से घट्ययन करने से पहले इस बास्त्र का सामान्य परिश्वय होना धावश्यक है। इसी दृष्टि से उत्तर-प्रदेश के 'शिक्षा-बोर्ड' ने अब इस विषय को इण्टरमीजियेट-कक्षाग्री में पढाने का पाठ्य-कम बनाया है। उसी पाठ्य-कम के धनुसार हमने जहाँ समाज-शास्त्र के सिद्धान्तो को स्पष्ट करने के लिए 'प्रारम्भिक-समाज-शास्त्र'-प्रत्य का प्रकाशन किया है, वहाँ इस शास्त्र के क्रियात्मक रूप को स्पष्ट करने के लिए 'भारतीय-सामाजिक-सगठन'— इस प्रन्य को भी प्रकाशित किया है। हमे पूर्ण आशा है कि यह ग्रन्थ समाज-शास्त्र के छात्रो के लिए ही नहीं, इस बास्त्र से सामान्य परिचय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले ग्रन्थ पाठकों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा।

हमारे 'प्रारम्भिक-समाजकास्त्र' तथा 'भारतीय-सामाजिक-सगठन'— इत दोनों ग्रन्थों को उत्तर-प्रदेश के इन्टरमीजियेट-बोर्ड ने इन्टर के छात्रों के लिये पाठ्य-ग्रन्थ के रूप में स्वीकार किया है, भौर इन दोनो ग्रन्थों को छात्रों के लिये ग्रधिक उपयोगी बनाने के लिये कुछ सुभाव दिये हैं। हमने इस द्वितीय संस्करण में उन सभी सुभाग्नों के अनुसार पुस्तक में संघोधन तथा परिवर्धन कर दिया है।

विद्या-विहार, बलबीर ऐंबेन्यू बेहरादून

# भारतीय-सामाजिक-संगठन [INDIAN SOCIAL ORGANISATION]

## भारतीय-मामाजिक-संगठन

#### (Indian Social Organisation)

### (द्वितीय-भाग)

- जाति-व्यवस्था—माधारभूत-तत्व, कार्य, परिवर्तन (Caste sys'em
  —(haracteristics, Function and Change).
- २ जाति-व्यवस्था मे परिवर्तन के तत्व (Factors of Change in Caste System).
- ३ संयुक्त-परिवार—ग्राधारभूत-तत्व, गुरण-दोष, परिवर्तन (Joint-Family—Characteristics, Defects and Factors influencing Change).
- ४ विवाह के प्रकार (Forms of Marriage)
- भ सामाजिक-विधान तथा उसका विवाह पर प्रभाव (Social Legislation and its effect on Marriage).
- ६ प्राम-संगठन (Village-Communities).
- ७ ग्राम-पंचायत (Village-Panchayat).
- भारत की निषंतता—कारण तथा निवारण (Indian Poverty— Causes and Remedies).
- ६ भारत में ग्रायोजन (Planning in India).
- १० भारत में सामाजिक कल्याएा (Social Welfare in India).
- ११ परिशिष्ट

# 8

## जाति-व्यवस्था

(CASTE SYSTEM)

जाति-व्यवस्था केवल भारत की उपज है। यह अन्य किसी देश में इस ढङ्ग से नहीं पायी जाती जिस ढङ्ग से अपने देश में पायी जाती है। इसका अपने यहा क्रमिक विकास हुआ है। जाति-व्यवस्था के समभने के लिए यह जानना आवश्यक है कि किस कम में से गुजरती-गुजरती यह वर्तमान रूप में पहुँची है।

जाति-व्यवस्था की आधार-भूत भावना है— मनुष्य का मनुष्य से भेद । ग्राज तो सब प्रकार के भेद-भाव को मिटाने का यत्न हो रहा है । जन्म के भेद-भाव को मिटाने के लिए जन्म के श्राधार पर किसी को ऊचा या किसी को नीचा मानने की भावना का सुधारकों की तरफ़ से ही नहीं, शासकों की तरफ़ से भी कानून द्वारा नाश किया जा रहा है । कर्म के द्वारा जो भेद-भाव उत्पन्न हो जाता है, कोई मेहनत करके अमीर हो जाता है कोई मेहनत न कर सकने के कारण ग्रीब रह जाता है—इस स्थिति को भी बदलने का प्रयत्न हो रहा है, सब की स्थिति बराबर की हो—ऐसे उद्योग हो रहे हैं । परन्तु शुरू में ऐसा नहीं था। शुरू में भारतीय-समाज में क्या था—यही हमें देखना है।

# प्रारम्भिक व्यवस्था 'वर्ण-व्यवस्था' थी जिसका ग्राधार 'कर्म' था

(क) आर्थ और दास—भारत की प्रारम्भिक सामाजिक-व्यवस्था में समाज को दो भागो में बाटा गया था—'भार्य' तथा 'दास'। ये दोनो विभाग जन्म पर भ्राश्वित नही थे। सदाचारी व्यक्ति को 'श्रार्य' तथा दुराचारी व्यक्ति को 'दास' कहा जाता था। 'दास' तथा 'दस्यु' का एक ही भर्य था। 'दास' या 'दस्यु'-शब्द 'दसु उपक्षये'—इस धातु से बना है। उपक्षय—धर्यात् नाश करना। जो हर प्रकार की सामाजिक-व्यवस्था को तहस-नहस करते थे, वे दास था दस्यु कहलाते थे। भ्राजकल भी सस्कृत-भाषा में 'दस्यु' का अर्थ है—चोर.। इस दृष्टि से 'श्रार्य' तथा 'दास' का विभाग जन्म पर भ्राश्वित न होकर कर्म पर भ्राश्वित था।

शुरू-शुरू में 'आयं' तथा 'दास' को ही 'वर्ण' कहा जाता था ! उस समय के समाज मे ये दो वर्ण थे, एक तरह से समाज के ये दो विभाग ये— भच्छे लोग भीर बुरे लोग । बुरे लोगो को—दासो को—दण्ड दिया जाता था ! ऋग्वेद २-१२-४ मे लिखा है—'यो दास वर्ण अघर गुहा अक:'—अर्थात, जो दास-वर्ण को गुफ़ा के नीचे कैंद कर देता है । चोरो भीर दुराचारियो को कैंदलाने मे डाला ही जाता है—यही बात इस वेदमंत्र में लिखी है । कई पाश्चात्य-नेसको का मत है कि 'आयं' तथा 'दास' का विभाग जन्म पर आश्रित था । 'आयं' लोग बाहर से भारत में आये थे । यहा के मूल-निवासियो को 'दास' कहते थे । दोनो की नस्ल भलग-अलग थी, दोनो का जन्म-गत भेद था, रुधिर का भेद था । परन्तु यह विचार अम-मूलक है । 'आयं' तथा 'दास' का विभाग जन्म पर आश्रित नही था, कर्म पर था—यह स्थापना इस बात से भी पुष्ट होती है क्योंकि ऋग्वेद ६-६३-५ में लिखा है—'ऋण्वन्तो विश्व आर्यम्'—अर्थात्, सारे बिश्व को आर्य बनग्भो । सारे विश्व को आर्य तभी बनाया जा सकता है, अगर 'आर्य' तथा दास' का भेद जन्म या नस्ल पर आश्रित न होकर

कर्म मर आश्रित हो, सदाचारी को 'श्रायें' कहा जाता हो, दुराचारी को 'दास' या 'दस्यु' ! बौद्ध-प्रत्य मिक्सिम-निकाय १३ के पढ़ने से भी यही बात पुष्ट होती है। वहा लिखा है— "हे श्राश्वलायन ! क्या तुमने सुना है कि यवन, कस्बोज श्रीर दूसरे सीमान्त देशों में दो हो वणं होते हैं— श्रायं श्रीर दास । श्रायं दास हो सकता है श्रीर दास भी श्रायं हो सकता है।"

'आर्य' तथा 'दास' को 'वर्ण' कहा जाता था। ऋग्वेद में 'यो दासं वर्ण'—यह प्राया है, ग्रर्थात् 'दास' तथा 'आर्य' ये दोनो 'वर्ण' थे। कई पाष्ट्रचात्य-विद्वान् वर्ण' का अर्थ रग करते हैं। उनका कहना है कि गोरे रग के 'आर्य' थे, काले रग के 'दास' थे, परन्तु वेदो में कही आर्गों को गौर और दासो को कृष्ण वर्ण का नहीं कहा गया, अत यह विचार भी भ्रम-मूलक है। 'वर्ण'-शब्द 'वृज् वर्रणे' धातु से बना है। वर्ण करना— प्रथान् चुनना। यह व्यक्ति की इच्छा पर है कि वह सदाचार के जीवन को चुने, 'आर्यं' बने, या दुराचार के जीवन को चुने, 'दुराचारी' बने। 'वर्ण'-शब्द भी इस बान को सिद्ध करता है कि शुरू-शुरू में भारत की सामाजिक-व्यवस्था जन्म पर आश्रित न होकर कर्म पर आश्रित थी, और जो जिस प्रकार के जीवन को चुनता था वह अपने कर्म से आर्य या दास वर्ण का कहलाता था।

(ख) बाह्मरा, अत्रिय, वैश्य, शूट तथा निषाब—वैदिक-काल में 'ग्रार्य' तथा 'दास' के सामाजिक-विभाग के साथ-साथ एक और सामाजिक कल्पना ने जन्म लिया। वह कल्पना थी—बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा निषाद के विचार की कल्पना। जैसे शरीर में सिर का काम ज्ञान-प्रधान है, हाथों का काम रक्षा-प्रधान है, उदर का काम सचय-प्रधान है, टागों का काम श्रम-प्रधान है, उसी प्रकार समाज के शरीर की भी व्यवस्था है। कुछ लोग पढाने-लिखाने का काम करते हैं, उन्हें यहां के समाज-शास्त्रितों ने 'बाह्मण' का नाम दिया, कुछ लोग देश की रक्षा करते हैं, उन्हें 'बैश्य' कहा, कुछ विणज-व्यापार करते हैं, उन्हें 'बैश्य' कहा, कुछ विणज-व्यापार करते हैं, उन्हें 'बैश्य' कहा,

कुछ विशेष योग्यता न होने के कारण सेवा-कार्य करते हैं, मेहनत-मजदूरी करते हैं, उन्हें 'शूद्र' कहा, कुछ ऐसे भी होते हैं जो किसी काम को नहीं कर सकते, सर्वथा निकम्मे ग्रीर ग्रपाहिज होते हैं, उन्हे 'निषाद' कहा । इस प्रकार भिन्न-भिन्न प्रकार के 'कर्म' करने के कारण समाज को उस समय पाच भागों में बाटा गया । इसीलिए मानव-समाज के लिए वेद मे 'पचजना '--'पचकृष्टय '---'पचमानवा.'--ये शब्द श्राये हैं। इन सभी का अर्थ है-पाच प्रकार के मनुष्य। 'आर्थ' तथा 'दास' का विभाग तो म्राचार-परक (Ethical) था, बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, नियाद का विभाग कर्म-परक (Professional) था। ऋग्वेद के १०वे मण्डल में लिखा है--- ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाह राजन्य कृतः उरू तदस्य यद्वैश्य पद्भ्या शूद्रोऽजायत'—समाज रूपी शरीर के ब्राह्मण मुख है, क्षत्रिय बाह हैं, वैश्य उरू है, पाव शूद्र हैं। यह विभाग जन्स के ग्राधार पर तो किया नहीं जा सकता। इसका यही ग्रिभिप्राय तो हो सकता है कि जो मुख काम करता है समाज में यह काम जो करे वह ब्राह्मण है, जो हाथ काम करते हैं समाज मे वह काम जो करे वह क्षत्रिय है, पेट का-सचय का - नो काम करे वह वैश्य है, पाव का, मेहनत का जो काम करे वह शूद्र है। इसका मतलब यही हमा कि वेदों में जिस प्रकार की वर्ण-व्यवस्था का वर्णन है उसका ग्राधार कर्म है, जन्म नही।

### २. वर्ण-व्यवस्था के बाद की व्यवस्था 'जाति-व्यवस्था' थी जिसका ग्राधार 'जन्म' था [बर्स-व्यवस्था तथा जाति-व्यवस्था में भेद]

'वर्ण-व्यवस्था' तथा 'जाति-व्यवस्था' में भेद है। वैदिक-काल में वर्ण-व्यवस्था का विचार उत्पन्न हुन्ना, जिसे पीछे के काल मे क्रियात्मक रूप देने का प्रयत्न किया गया, ग्रीर वह जाति-व्यवस्था का रूप धारण कर गया। वर्ण-व्यवस्था का विचार ग्रार्य तथा दस्यु के रूप मे समाज का 'श्राचार-परक' (Ethical) तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य, शूद्र,

निषाद् के रूप में 'कार्य-परक' (Professional) वर्गीकरण था। श्राचार की दृष्टि से भार्य तथा दास भीर कार्य की दृष्टि से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा निषाद । इस विचार में जन्म से वर्गीकरण की कोई बात नहीं थी । भगर कोई पढाता-लिखाता था. तो जैसे भाजकल उसे भ्रध्यापक कहते हैं, वैसे उस समय उसे बाह्मण कह देते थे: अगर कोई सेना में भर्ती होता था, तो जैसे भाजकल उसे सिपाही कहते हैं, वैसे उस समय उसे क्षत्रिय कह देते थे। जैसे मध्यापक सेना में भर्ती के बाद सिपाही बन जाता है, वैसे बाह्मण शस्त्र चलाने का काम शुरू कर देती क्षत्रिय हो जाता है। ब्राह्मण जन्म से ही ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय जन्म से ही क्षत्रिय होता है-ऐसी कोई बात वैदिक काल में नहीं थी। इसीलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र का विभाग उस समय एक 'विचारात्मक-वर्गीकरण' (Theoretical classification) था, और कुछ नहीं । वैदिक-काल के पीछे के काल मे यह कर्म पर भ्राश्रित न होकर जन्म पर भ्राश्रित माना जाने लगा भौर तब यह समाज का 'विचारात्मक-वर्गीकरण' न रह कर 'कियात्मक-वर्गी-करण' (Practical classification) हो गया । वर्ण-व्यवस्था का विचार एक लचकीला विचार था, यह एक तरह का दार्शनिक वर्गीकरण था. इसके मानने-न-मानने से किसी का कुछ बनता-बिगडता न था, परन्तू वही विचार जब जाति-व्यवस्था का रूप घारण कर गया, तब वह ध्रपने लचकीलेपन को खोकर एक कठोर चीख बन गया, इसे जन्म पर माश्रित माना जाने लगा, यह दार्शनिक-वर्गीकरण ही न रहकर एक ठोस, क्रिया-त्मक रूप धारण कर गया, किसी खास जाति का होना व्यक्ति के बनने-बिगडने का कारण बन गया।

### ३. जाति का ग्रर्थ या उसकी परिभाषा (Concept of Caste or its Definition)

जैसा हमने पहले कहा, भारतीय-सामाजिक-व्यवस्था में 'वर्ण'-व्यवस्था पहले प्रचलित थी, उसके बाद 'जाति'-व्यवस्था प्रचलित हुई । इन दोनो का भेद हम दर्शा आये हैं। सदियों ने हमें 'जाति'-व्यवस्था से ही सामना करना पड़ा है। 'जाति'-व्यवस्था में 'जाति'-शब्द का क्या अर्थ है, 'जाति' की क्या परिभाषा है—यह जानना हमारे लिये स्नावश्यक है। इसी सम्बन्ध में हम यहा कुछ चर्चा करेंगे।

[१] केतकर की परिभाषा—केतकर का कथन है कि 'जाति' एक ऐसा सभ्याजिक समुदाय है जिसकी दो विशेषतायें हैं—(क) इसके सदस्य वही होते हैं जो इस में पैदा होते हैं, (ख) इसके सदस्य इनके प्रपने सामाजिक-नियमों के ग्राधार पर ग्रंपने समुदाय के बाहर विवाह नहीं कर सकते।

[२] मजूमदार तथा मदन की परिभाषा—"श्रावृत-श्रेणी जाति कहलाती है।" (श्रेणी या वर्ग का ग्रावार अमी री-गरी है। श्रमीर गरीब हो सकता है, गरीब ग्रमीर हो सकता है। परन्तु जाति का ग्रावार अमी री-गरीबी न होकर जन्म है। जो जन्म से ब्राह्मण हुआ वह ब्राह्मण ही रहेगा। इसी को 'श्रावृत'—closed—कहते हैं, यह व्यवस्था खुली न होकर बन्द है। यही जाति व्यवस्था है—ऐसा मजूमदार तथा मदन का कथन है)।

उक्न परिभाषाए बहुत-कुछ ठीक है, परतु 'जाति' के किसी एक पहलू पर प्रकाश डालती हैं। इन परिभाषाओं के अतिरिक्त अन्य भी अनेक विद्वानों ने 'जाति' की, सब पहलुओं को लेकर, व्याख्या करने का प्रयत्न किया है जो फिर भी कुछ-न-कुछ त्रुटि-पूर्ण है। इनमें से पाश्चात्य-विद्वानों के दो-एक प्रयासों का हम यहा उल्लेख कर रहे हैं.—

<sup>[1] &</sup>quot;Caste as a social group has two characteristics (a) Membership is confined to those who are born of members and includes all persons so born, (b) the members are forbidden by an inexorable social law to marry outside the group."—Ketkar.

<sup>[2] &</sup>quot;A caste is a closed class".—Mazumdar and Madan.

[३] रिजले की परिभाषा—रिजले (Risley) का कहना है कि जाति परिवारों के उस समूह को कहते हैं जो एक काल्पनिक पूर्वज से वश-परम्परा द्वारा चला आता है, यह पूर्वज कोई काल्पनिक मनुष्य या काल्पनिक देवता होता है। इस परिवार-समूह के व्यक्ति एक ही नाम से व्यक्त होते हैं, एक ही व्यवसाय करते हैं।

रिजाले की परिभाषा दोष-पूर्ण है क्यों कि इसमें 'गोत्र' तथा 'जाति' को एक ही परिभाषा में मिला दिया गया है। गोत्र में तो किसी एक काल्पनिक मनुष्य या काल्पनिक देवता को परिवार-समूह का पूर्वज माना जाता है, जाति में नही।

[४] क्लन्ट की परिभाषा ब्लण्ट (Blunt) का कहना है कि 'जाति' एक ऐपा मन्तर्विवाह करने वाला समूह है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसकी सदस्यता वश से वंश मे चली आती है; जो अपने सदस्यों पर कुछ सामाजिक-प्रतिबन्ध लगाता है, जो परम्परागत व्यवसाय को करते हैं, जो अपनी उत्पत्ति एक ही पूर्वज से मानते हैं, जिनका एक सजातीय-समुदाय होता है।

ब्लण्ट की परिभाषा में भी एक ही पूर्वज से उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। इसमें सन्देह नहीं कि अनेक जातियों में एक पूर्वज से उत्पत्ति का वर्णन पाया जाता है, परन्तु इसे अखड नियम नहीं कहा जा सकता। अनेक जातिया किसी पूर्वज का वर्णन नहीं करतीं।

[४] कूले की परिभाषा—कूले (Cooley) का कहना है कि जब एक श्रेणी श्रथवा वर्ग वश-परपरा पर आश्रित हो जाता है, तब उसे 'श्रेणी' या 'वर्ग' कहने के स्थान में 'जाति' कहते हैं।

कूले की परिभाषा 'वर्ग' तथा 'जाति' के भेद को तो प्रकट करती है, परन्तु 'जाति' की पृथक् तथा स्पष्ट व्यवस्था नहीं करती।

<sup>[5] &</sup>quot;When a class is somewhat strictly hereditary we call it a caste"—Cooley.

[६] भारतीय-शास्त्रों की परिभाषा-भारतीय-शास्त्रों की दृष्टि से इस शब्द पर दो पहलुक्षों से विचार किया जा सकता है। एक है व्याकरण का पहलू, दूसरा है इस शब्द की भिन्त-भिन्त स्थलो में ब्याख्या का पहलु । व्याकरण के ग्रनुसार 'जाति' शब्द 'जनि प्रादुर्भवि'-इस घातु से बना है। प्रादुर्भाव का भ्रथं है - प्रकट होना, उत्पन्न होना। जन्म, जननी, जनक आदि शब्द इसी धातु से बने हैं। इस प्रकार व्याकरण की द्षिट से 'जाति' का सबध 'जन्म' से स्पष्ट प्रतीत होता है। 'जाति' पूछने का अर्थ है--- 'जन्म' के सबब मे पूछना। व्याकरण के श्रतिरिक्त दूसरा पहलू है भारतीय-ग्रन्थों में इस शब्द की भिन्न-भिन्न व्याख्याएँ । न्याय-दर्शन मे जाति का लक्षण करते हुए कहा है---'समान प्रसवात्मिका जाति.'--ग्रथात्, जहा ग्रपने समान प्रसव हो, ग्रपने समान सतान उत्पन्न हो, वहा 'जाति'-शब्द का प्रयोग होगा---श्रपने समान उत्पन्न करने को 'जाति' कहते हैं। मनुष्य मनुष्य को उत्पन्न करता है, कुत्ते कुत्ते को और गाय गाय को । इस दृष्टि से मनुष्य की अपनी जाति है, कुत्ते की अपनी जाति है, गाय की अपनी जाति है। अपने समान उत्पन्त करने का श्रथं है--श्रपने समान शक्त-सूरत । इस व्याख्या के श्रनुसार मनुष्य को तो 'जाति' कहा जा सकता है, परत बाह्मण, क्षत्रिय, वर्य, शूद्र को जाति नहीं कहा जा सकता क्योंकि जब कोई प्राणी भ्रपने समान दूसरे प्राणी को उत्पन्न करता है तब उसे शक्ल-सूरत से ही पहचान लिया जाता है। बाह्मण की सन्तान को शक्त-सुरन से ब्राह्मण के तौर पर नही पहचाना जा सकता, ना ही क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को । व्याकरण तथा न्याय-शास्त्र-इन दोनों की व्याख्याओं के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को 'जाति' नहीं कहा जा सकता, फिर भी इन्हीं के लिये धपने देश में 'जाति'-शब्द का प्रयोग होता रहा है। इसका क्या कारण है ? इसका कारण यही हो सकता है कि शुरू शुरू मे बाह्मण, क्षत्रिय ग्रादि का विभाजन जन्म-परक नही था, परत् पीछे कभी जाकर इन्द्रे जन्म-परक माना जाने लगा गौर ये विभाग जो वैदिक-

काल मे 'ग्राचार-परक' (Ethical) तथा 'कर्म-परक' या 'श्रम-विभाग-परक' (Professional or Division of Labour) थे, 'जन्म-परक' (Closed caste) बन गये।

सक्षेप में यह कहा जा सकता है कि व्याकरण तथा न्याय-दर्शन की परिभाषा के अनुसार भी बाह्मण, क्षत्रिय, बैर्य, शूद्र की 'जाति' नहीं कहा जा सकता क्यों कि इनकी परिभाषाभी के अनुसार 'जाति' का अर्थ है अपने समान शक्ल-सूरत की सतान उत्पन्न करना, श्रीर भ्रपने समान का ऋर्थ है दूसरो से भिन्न शक्ल-सूरत की सतान उत्पन्न करना। जैसे कुत्ता गाय से भिन्न सतान को उत्पन्न करता है, गाय भैस से भिन्न सतान को उत्पन्न करती है, वैसे ब्राह्मण क्षत्रिय से भिन्न शक्त-सुरत की सतान को नही उत्पन्न करता। फिर भी बाह्मण श्रादि के लिये 'जाति'-शब्द का प्रयोग पाया जाता है---इमका कारण यही है कि ग्रपने देश में बहुत पीछे जाकर जब जन्म को प्रधानता मिलने लगी तब 'जाति'-शब्द का इन चार 'वर्णों' के लिये भी प्रयोग होने लगा। जब 'जाति'-शब्द इन वर्णों के लिए प्रयुक्त होने लगा तब से बाह्यण-क्षत्रिय-वैश्य-शूद्र का ग्राधार जन्म हो गया, वश-परतरा हो गया, भ्रौर इसका श्राधार 'प्रजननिक' (Genetic) माना जाने लगा। ब्राह्मण-क्षत्रिय म्रादिका जन्म-परक भ्राधार मानने के बाद विवाह भ्रादि के सबध में ग्रनेक नियमो का निर्माण हुन्ना जिनमें 'म्रतिववाही'-'बहिववाही' मादि नियम हैं जिनका अपने-अपने स्थान पर वर्णन किया जायगा।

'वर्ण-व्यवस्था' तथा 'जाति-व्यवस्था' की समानता तथा विषमता के विषय में जो ग्राधिक जानना चाहे वे हमारे 'श्रायं-संस्कृति के मूल-तत्त्व'-ग्रन्थ के 'वर्ण-व्यवस्था का ग्रध्यात्मिक ग्राधार'—इस ग्रध्याय को पढें।

### ४. जाति-व्यवस्था के ग्राघारभूत तत्व (Characteristics of Caste)

वर्ण-व्यवस्था वैदिक-काल की उपज है, जाति-व्यवस्था ब्राह्मण-प्रन्यो तथा स्मृतियो के काल की उपज है। ऊपर हमने 'जाति' की जो भिन्न-भिन्न व्याख्यार्ये दी उनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि 'जाति' की व्याख्या या परिभाषा करने के स्थान मे 'जाति' के स्राधार-भूत मुख्य-मुख्य तत्नो को जान लेने से इसकी व्याख्या स्रधिक स्पष्ट हो जायेगी। इसीलिए जाति-व्यवस्था के स्राधारभूत तत्व क्या है—इस सम्बन्ध मे कुछ जान लेना स्नावश्यक है। जाति-व्यवस्था के स्नाधार-भूत तत्व निम्न है—

- (क) जाति जन्म पर आधित होती है—जब से जाति-व्यवस्था चली तब से यह माना जाने लगा कि जो व्यक्ति जिस जाति मे पैदा होता है वह ग्राजन्म उसी जाति का रहता है, दूसरी जाति का नही हो सकता। जाति के ग्रपने नियम बने होते हैं. उसके ग्रपने रीति-रिवाज होते हैं। ग्रगर कोई व्यक्ति उन नियमो या उन रीति-रिवाजो का उल्लबन करता है, तो वह जाति-च्युत् कर दिया जाता है, जाति-से बहिष्कृत कर दिया जाता है। जाति-च्युत् या जाति-बहिष्कृत करने का नया ग्रथं है? इसका यह ग्रथं है कि किसी जाति का होने से उसे जो ग्रधिकार मिले हुए हैं वे उससे छीन लिए जाते हैं। उदाहरणार्थ, एक जात-बिरादरी के लोग इकट्ठा बैठकर हुक्ता पी सकते हैं, एक साथ खा-पी सकते हैं। जाति के रीति-रिवाजो, जाति की ग्रथाग्रो का उल्लंघन करने वाले का हुक्का-पानी बन्द कर दिया जाता है।
- (क) जाति के लोग जाति में ही विवाह कर सकते हैं—जो जिस जाति का है वह उसी जाति में विवाह कर सकता है, दूसरी जाति में नहीं। ब्राह्मण ब्राह्मणों में, क्षत्रिय क्षत्रियों में, वैश्य वैश्यों में ब्रीर शूद्र गूद्रों में ही विवाह कर सकते हैं, अपनी जाति से बाहर नहीं। इसे 'अन्तिविवाह' (Endogamy) कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी जाति के बाहर विवाह करता है, तो उसकी सन्तान उत्तराधिकार की अधिकारी नहीं समभी जाती, हाँ, इतना अवश्य है कि ब्राह्मण अपने से नीव-कुल की कन्या ले सकता है, परन्तु नीच-कुल का पुरुष अपने से उच्च कुल की कन्या से विवाह नहीं कर सकता। ब्राह्मण का क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र कन्या से या वैश्य का शूद्र कन्या से विवाह 'अनुलोम'

(Hypergamy)-विवाह कहलाता है; शूद्र पुरुष का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कन्या से, या वैश्य पुरुष का ब्राह्मण, क्षत्रिय कन्या से, या क्षत्रिय पुरुष का ब्राह्मण, क्षत्रिय कन्या से, या क्षत्रिय पुरुष का ब्राह्मण कन्या से विवाह 'प्रतिलोम' (Hypogamy)-विवाह कहलाता है। 'अनुलोम'-विवाह को जाति-व्यवस्था के नियम स्वीकार करते हैं, 'प्रतिलोम'-विवाह को स्वीकार नहीं करते। ध्रव 'हिन्दू विवाह तथा तलाक ग्रधिनियम—१६५५' के ग्रनुसार विवाह के इस कानूनी बन्धन को हटा दिया गया है। ग्रव कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति में विवाह कर सकता है। 'अनुलोम' तथा 'प्रतिलोम' घिवाह की बात को छोड भी दिया जाय, तो भी जाति-व्यवस्था के श्राधार-भूत तत्वों मे अपनी जाति मे ही विवाह करना एक मुख्य तत्व है। जब किसी व्यक्ति को जाति-च्युत् या जाति-बहिष्कृत किया जाता है, तब उसका हुका-पानी बन्द करने के साथ-साथ उसके साथ रोटी-बेटी का व्यवहार भी बन्द कर दिया जाता है।

- (ग) जाति के लोग अपनी जाति के हाथ का ही खा-पी सकते हैं— जो जिस जाति का है वह उसी जाति के हाथ का खा-पी सकता है, खासकर, कच्चा खाना तो दूसरी जाति के हाथ का खा ही नहीं सकता। नीच जाति के हाथ का बनाया हुआ भोजन खाने से जाति चली जाती है। ब्राह्मण बनिये के घर का कच्चा खाना नहीं खा सकता, पूरी-पराठे उडा सकता है। कच्चे में ज्यादा और पक्के में कम छूत मानी जाती है। दूघ, घी, हरी सब्जिया, फन, मेवा सब-कोई हर-किसी के हाथ का खा सकता है।
- (ध) जाति-व्यवस्था का परिराम श्रक्ष्तपन है—जाति-व्यवस्था के साधार में मनुष्य का मनुष्य के साथ भेद-भाव है। मैं इस समूह का हूँ, उस समूह का नहीं हूँ—इस मावना से जाति-व्यवस्था की हर बात की शुरूआत होती है। परिणाम यह होता है कि जिनको मनुष्य अपने दायरे का नहीं समक्षता, उन्हें घृणा की दृष्टि से देखने लगता है। इसी कारण हिन्दुओं में जाति-व्यवस्था के परिणामस्वरूप श्रक्तपन का भाव उत्पन्न

हो गया है। जो भ्रपने हैं, वे अपने, परतु जो अपने नहीं हैं, वे इतने पराये हो जाते हैं कि उनमें से कोई-कोई भ्रष्टूत माने जाने लगते हैं। श्रव 'ग्रस्पृत्यता (अपराष) श्रषिनियम-१९५५' के श्रनुसार श्रष्ट्रतपन को श्रपराध घोषित कर दिया गया है।

(इ.) जाति-व्यवस्था में पेशा भी निश्चित होता है — जाति-व्यवस्था में व्यक्ति का पेशा भी पैत्रिक परम्परा से भ्राता है। पाधे का लडका पिधयाई करता है, ग्वाले का लडका ग्वाले का काम, मुनार का लडका मुनार भ्रीर लोहार का लडका लोहार। जिस प्रकार युरोप में 'व्याव-सायिक-संघ' (Guilds) होते थे, इन सघो में वश-परपरा से पेशा चला भ्राता था, इसी प्रकार जाति-व्यवस्था में पेशा वश-परपरा से चलता है। पेशे के वंश-परपरा से चलने का फायदा भी है। जो काम पीढी-दर-पीढी चलेगा, उसमें कार्य-कुशलता का होना स्वांभाविक है। जिन घरानो में हिकमत पीढी-दर-पीढी चली भ्राती है, उनमें हिकमत में कुशलता भी दिखाई देती है। भ्राज जाति-व्यवस्था के शिथल हो जाने से व्यवमायों का लानदानों के साथ भ्रव तक का चला भ्रार हा संबंध भी शिथल होता जा रहा है।

प्र. जाति-व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत (Theories of the Origin of Ceste)

जन्म से जाति-व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई, इस सम्बध मे भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों के भिन्न-भिन्न मत हैं, जिसमे से मुख्य-मुख्य मतो की हम यहा चर्चा करेगे—

(क) हट्टन का आविम-संस्कृति का परम्परात्मक-सिद्धांत (Hutton's Traditional theory of stratified social structure functioning in primitive Indian culture)—कई विद्वानों का कहना है कि जाति-वयवस्था का सिद्धात भारत में परम्परा से चला आ रहा है। किस समय इस सिद्धात का प्रतिपादन हुआ—यह नहीं कहा जा सकता। हम खोज करते-करते जिस समय में भी पहुँचते हैं, वहीं पर किसी-न-

किसी प्राचीन-परम्परा के अनुसार यह पहले से चला आ रहा दीखता है। हम देख ही आये हैं कि वैदिक-काल में 'ब्राह्मणोऽस्य मुखमा-सीत्' के रूप में इस सिद्धात की सत्ता थी। उसके बाद के काल में भी यह सिद्धात पाया जाता है। स्मृति-काल में प्रत्येक स्मृति में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्ध—इन जातियों का वर्णन है। हट्टन का कथन है कि भारत में आदि-काल से जाति का विचार चला आ रहा था। आज की असम की नागा जातियों में भी एक प्रकार की जाति-व्यवस्था पायी जाती है। जाति-व्यवस्था के आधार-भूत तत्व भारतीय-समाज में सदा से रहे हैं। आर्य लोग जब भारत में आये तब उन्होंने यहा की प्रचलित जाति-व्यवस्था—ब्राह्मण, क्षत्रिय, आदि को पेशो का रूप दे दिया।

जहा तक परम्परा से जाति-व्यवस्था के चले आने का सम्बंध है, हम पहले लिख आये हैं कि जन्म से जाति-व्यवस्था के मानने का सिद्धात वैदिक-काल मे नही था। उस समय कर्म से वर्ण-व्यवस्था का सिद्धांत माना जाता था। मानव-समाज के जन्म से वर्गीकरण को भारत की आदि -कालीन परपरा नहीं कहा जा सकता। वह उत्तर-कालीन परम्परा है।

(स) सबे दुबोय का राजनैतिक-सिद्धांत (Abbe Duboi's Political theory)—कुछ विद्वानों का कहना है कि जाति-व्यवस्था झाह्मणों की एक राजनैतिक-योजना थी। इस सिद्धात द्वारा उन्होने प्रपने को दूसरों से उच्च सिद्ध करने का प्रयत्न किया। यह एक प्रकार का दूसरों का शोषण था। इस युग में भी तो हिटलर ने जर्मन-जाति के विश्व-भर की ग्रन्य जातियों से श्रेष्ठ होने की घोषणा की थी। यही बात झाह्मणों ने अपने समय में की। उन्होंने अपने को ग्रन्य सबसे श्रेष्ठ घोषित किया। इस सिद्धात का १६ वी शताब्दी के फासीसी लेखक भवे दुबोय (Abbe Dubois) ने प्रतिपादन किया था। इबेटसन भी इसी सिद्धात को मानता था।

जहां तक दूसरे वर्गों का ब्राह्मणों द्वारा शोषण करने वाले इस राज-नैतिक-सिद्धात का सम्बंब है, यह कह सकता कठिन है कि ब्राह्मणों की इस बात को अन्य बर्गों ने कैसे मान लिया ? ब्राह्मणों ने कहा कि हम ऊचे हैं, दूसरे नीचे हैं, और सब ने ब्राह्मणों की बात मान ली—यह कैसे हो सकता है ?

(ग) रिजले का प्रजातीय-सिद्धांत (Risley's Racial theory)-कुछ विद्वानो का क हनाहै कि जाति-व्यवस्था का सिद्धात प्रजाति ग्रयीत नस्ल पर माश्रित है। माजकल भी कई लोग नस्ल के कारण भ्रपने को दूसरो से श्रेष्ठ समभते हैं। इन विद्वानों के अनुसार नस्ल के कारण ग्रायं लोग प्रपने को दामो से श्रेष्ठ मानते थे। इनके अनुसार श्रार्य भारत के बाहर से ग्राये थे, उन्होंने यहा के ग्रादि-वासियो को जीता, उन्हें दास का नाम दिया। जब विजेता किसी देश को जीतता है, तब विजित देश की लडिक यों को अपने में खपाता है, परतू अपनी लडिक यो को विजित देश के युवको को देने के लिए तैयार नहीं होता। इसी भावना से 'मनुलोम-विवाह' (Hypergamy) का भनुमोदन तथा 'प्रतिलोम-विवाह' (Hypogamy) का विजेता लोग निषेध करते हैं। ग्रपने रक्त की शुद्धता बनाये रखने के लिए वे श्रपनी नस्त के लोगों में ही विवाह करते हैं, जिसे सजातीय-विवाह भौर भ्रतिववाह (Endogamy) कहते हैं। क्योकि भारत की जाति-व्यवस्था मे ये तीनो बातें पाई जाती है, इसलिए इन विद्वानों का कथन है कि बाहर से आने के कारण आर्थ लोगों ने प्रजातीय-सिद्धात के भाधार पर जाति-स्यवस्था का निर्माण किया था । उन्होने भार्य भीर दास का, तथा ब्राह्मण-अत्रिय-वैश्य-शद्र का प्रजातीय-विभाग भ्रपने रक्त की शुद्धता रखने के लिए किया। इस प्रजातीय-सिद्धात के समर्थक अपने पक्ष की पूष्टि में यह भी कहते है कि 'वर्ण'-राब्द का अर्थ रग है। ब्राह्मणो की नस्ल गोरे रग की थी, दूसरे लोग काले थे, इसलिये भ्रपनी नस्ल के वर्ण भ्रर्थात रग के श्राघार पर उन्होने वर्ण-व्यवस्था को जारी किया। ये सब विचार प्रमुख रूप से रखने वाले श्री एच० एच०

रिजले हैं। श्री डॉ॰ घुर्ये, प्रो॰ एन॰ के॰ दत्त तथा डॉ॰ मजूमदार भी इसी विचारघारा को मानते हैं। इस तरह की कुछ बात महाभारत-काल में अपने देश के विद्वानों में भी कभी चली होगी, क्यों कि महाभारत के शातिपर्व के १८८वें अध्याय के १वे श्लोक में भृगु तथा भारद्वाज का सम्वाद आता है, जिसमें भृगु जी कहते है—'ब्राह्मणानां सितो वर्णः क्षत्रियाणा तु लोहित, वैश्याना पीतको वर्ण शूद्राणामसितस्तथा'— अर्थात्, ब्राह्मणो का सफ्रेंद रग होता है, क्षत्रियो का लाल, वैश्यो का पीला तथा शुद्रो का काला।

जहा तक जाति-व्यवस्था का नस्ल के ग्राधार पर चलने का सबध है, इसका मुख्य ग्राघार इस बात पर निर्भर करता है कि क्या श्रार्य लोग बाहर से प्राकर यहा बसे थे, या यही के वासी थे। भ्रगर प्रार्य बाहर से भाकर बसे थे, तो भार्य तथा दास ये दोनों ही बाहर से ही आये होगे, क्योकि आर्य तथा दास ये दो नस्लें न होकर सदाचारियों की आर्य तथा द्राचारियों को दास कहा जाता था। कई लोग आयों को बाहर का तथा दासो को यहां का वासी कहते हैं, परंत्र यह बात बहुत विवादास्पद है कि श्रायं बाहर से श्राकर यहाँ बसे थे श्रीर यहा के वासियों को वे दास कहते थे। श्री पी०टी० श्रीनिवास ग्रायगार ग्रपने 'माधवाचार्य भाष्य सहित यजुर्वेद' में लिखते हैं---"जिन मन्नो मे श्रार्य, दास श्रीर दस्यु शब्द श्राये हैं उनकी सावधानी से परीक्षा करने पर पता लगता है कि ये शब्द वश के या नस्ल के नही वरन धर्म या मत के द्योतक है। ये शब्द सबसे ग्रधिक ऋग्वेद में मिलते हैं। वहा 'ग्रायं'-शब्द ३४ बार ग्राया है। ऋग्वेद में कूल १,५३,६७२ शब्द हैं। इतने शब्दों में 'भ्रार्य'-शब्द का सिर्फ ३४ बार भ्राना ही इस बात का प्रमाण है कि जो लोग ग्रपने को 'ग्रायं' कहते थे, वे ग्राक-मणकारी नहीं थे. जिन्होंने देश को जीतकर यहां के भ्रादि-वासियों-दास-का नाश किया। कारण यह है कि भाक्रमण करने वाली जाति स्वभावतः श्रपनी सफलताओं की निरंतर डींग हांका करती है, जो इतने बड़े ग्रंथ

में कहीं नही है।" श्रीयुत् भायंगार का यह कथन सत्य प्रतीत होता है, परंतु अगर यह मान भी लिया जाय कि आर्य लोग बाहर से आये थे, तो भी जैसा हम पहले लिख आये हैं, आर्य और दास-ये दो नस्लों के नाम तो हैं ही नही । श्रगर ये दो नस्ले होती, तब 'कृण्वन्तो विश्वमार्यम्'--'सबको भार्य बनाभो'--यह बात तो नही कही जा सकती। सबको भ्रपने विचार का तो बनाया जा सकता है. अपनी नस्ल का तो नही बनाया जा सकता। अगर कोई कहे कि सबको नीयो बना दो, तो क्या यह बात कही सिरे बैठती है ? बाकी रहा 'वर्ण'-शब्द का 'रग' ग्रथं होना। जो लोग भगुजी का वह इलोक उद्धृत करते हैं जिसमे उन्होने कहा है कि ब्राह्मणों का रंग सफ़ेद श्रीर शूद्रों का काला होता है, उन्हें भग्नुजी ने स्वय शाति-पर्व के १८८वें ग्रध्याय के १०वें श्लोक में उत्तर दे दिया है---'न विशे-षोस्ति वर्णाना सर्व ब्राह्ममिद जगत् ब्रह्मणा पूर्वसुष्ट हि कर्मभिर्वर्णता गतम'-वर्ण मे सफरेद, लाल, पीला, काला भेद कही नही दीखता। बाह्मण काले और शृद्ध गोरे भी दिखाई देते है, इसलिए वर्ण-भेद रग के ऊपर ब्राश्रित नही है, कर्म पर ब्राश्रित है। कर्म से ही भिन्न-भिन्न वर्ण बने हैं। भुगुजी का पहला कथन पूर्व-पक्ष है, ग्रीर यह दूसरा कथन उत्तर-पक्ष है। यह हम पहले ही लिख ग्राये हैं कि 'वर्ण'-शब्द का ग्रर्थ रंग है जरूर, परतु वर्ण-व्यवस्था मे 'वर्ण'-शब्द का भ्रर्थ रग न होकर 'चुनना' भ्रथं है। चुनना-- ग्रथीत्, जीवन का पेशा चुनना।

(घ) नेसफ़ील्ड तथा इबटसन का व्यवसायात्मक-सिद्धान्त (Nessield's and Ebbetson's Occupational theory)—कुछ विद्वानो का
कहना है कि प्रत्येक समाज मे व्यवसायो के ग्राधार पर मनुष्यों का
वर्गीकरण हुम्रा करता है। जो व्यक्ति किसी खास पेशे, किसी खास
व्यवसाय, किसी खास घषे को करते हैं, वे ग्रपनी सन्तान को उसी पेशे,
व्यवसाय या घषे की शिक्षा देते हैं। इस प्रकार खास-खास पेशे करने
वाले खानदानों के ग्रलग-ग्रलग समूह बन जाते हैं। पाश्चात्य देशो मे
पेशों के जो समूह बने, उन्हें 'व्यावसायक-सघ' (Guilds) कहा जाता

था। इन सघो के बनने का ग्राघार नस्ल नही होता था, एक-सा पेशा होता था। भारतवर्ष में भी इस प्रकार के एक-से पेशे के संघ बने, श्रीर वे सघ ही जातियाँ कहलाईं। ब्राह्मण का पेशा करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय का पेशा करने वाले क्षत्रिय, वैश्य का पेशा करने वाले वैश्य श्रीर शूद्र का पेशा करने वाले क्षत्रिय, वैश्य का पेशा करने वाले वैश्य श्रीर शूद्र का पेशा करने वाले शूद्र कहलाये। सुनार, लोहार भादि जातियाँ इसी प्रकार भिन्न-भिन्न पेशो से बनी। पिता ग्रपने पुत्र को अपने पेशे के रहस्य बतलाता था, इसलिए पुत्र उस पेशे मे कुशल होता था। इस प्रकार ये पेशे वश-परम्परा से चलने लगे, पेशो के वश-परम्परा से चलने के कारण जाति-व्यवस्था भी वश-परम्परा से चल पड़ी। पेशे के लोग दूसरो को ग्रपना रहस्य नहीं बतलाना चाहते थे, इसलिये ग्रपने पेशे के लोगो ग्रर्थात् श्रपनी जाति मे ही विवाह करते थे, जाति से बाहर नहीं। इस सिद्धान्त के सबसे बडे समर्थक श्री नेसफील्ड (Nessfield) तथा श्री एवटसन (Ebbetson) हैं।

इसी दृष्टिकोण का समर्थन करने वालो का कहना है कि समाज में 'श्रम-विभाग का नियम' (Division of labour) काम करता है। भारत में जाति-व्यवस्था को जारी करने वालों ने 'श्रम-विभाग' के इसी प्राधिक-नियम को समाज में क्रियात्मक रूप दे दिया था और भिन्न-भिन्न व्यवसायों को श्रम मानकर उनका ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-दृद्ध तथा प्रन्य जाति-उपजातियों में वर्गीकरण कर दिया था। इन व्यवसायों से जाति तथा इनके अवान्तर भेदों से उपजातियों का निर्माण हुआ।

जहाँ तक व्यवसायों को ग्राघार बनाकर जाति-व्यवस्था के निर्माण का सम्बन्ध है, यह प्रश्न उठ खडा होता है कि पाश्चात्य देशों में भी तो व्यवसायों को ग्राघार बनाकर 'व्यावसायिक-सघ' (Guilds) बने थे, फिर वहाँ जाति-व्यवस्था का निर्माण क्यों नहीं हुग्रा ? यह प्रथा सिर्फ अपने देश में ही क्यों उत्पन्न हुई ?

(ङ) गिलबर्ट का भौगोलिक सिद्धान्त (Gilbert's Geographical theory)—कुछ विद्वानों का कहना है कि जाति-व्यवस्था का आधार

भौंगोलिक है। उदाहरणार्थ, सरस्वती के किनारे रहने वाले ब्राह्मण सारस्वत कहलाये, कन्नौज मे रहने वाले कनौजिये। इस विचार के समर्थको में श्री गिलबर्ट (Gilbert) का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

भौगोलिक सिद्धान्त के विषय मे यह श्रापत्ति की जाती है कि ग्रमेक उप-जातियाँ तो भूगोल की दृष्टि से बनी प्रतीत होती हैं, परन्तु बाह्मण श्रादि जातियों का तो भूगोल से कोई सम्बन्ध नहीं दीखता।

(च) राइस का टोटम का सिद्धान्त (Rice's Totemstic theory)—कुछ विद्वानों का कहना है कि जाति-व्यवस्था का आधार टोटम है। टोटम क्या है ? जातियाँ अपने वश को खोजती-खोजती किसी कल्पित पूर्वज को ढूढ निकालती हैं। कोई अपना प्रारम्भ साप से, कोई आम के पेड से, कोई इसी तरह के अन्य किसी पूर्वज से बतलाता है। इसी कल्पित-पूर्वज को टोटम कहते हैं।

टोटम-सिद्धान्त के विषय में यह आपित्त है कि जगली जातियों में तो यह ठीक प्रतीत होता है, किन्ही-किन्ही उप-जातियों में भी शायद यह ठीक जँच जाय, परन्तु ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैंश्य, शूद्र ग्रादि जिस जाति-व्यवस्था पर हम विवेचन कर रहे हैं उस पर यह ठीक नहीं बैठता क्योंकि इनका 'टोटम' से कोई सबन्ध नहीं।

(छ) हट्टन का बहु-कारएतावाद (Hutton's Multiple theory)—
जाति-व्यवस्था के हमने ऊपर जो अनेक कारण लिखे उनमे से कौन-सा.
एक जाति की व्यवस्था मे कारण बना होगा—यह तो नहीं कहा जा
सकता। इनमे से सबका थोडा-थोडा हिस्सा जाति-व्यवस्था को उत्पन्न
करने में अवस्थ रहा होगा—यहीं कहा जा सकता है। यद्यपि हट्टन का
कहना यह है कि आर्थों के भारत मे आने से पहले ही यहाँ की सामाजिक
रचना विषमता के आघार पर पहले से ही बनी हुई थी, आर्थों ने सिर्फ
उस सामाजिक विषमता पर बाह्यण, क्षत्रिय आदि पेशों की पैंबन्द चढा
दी, फिर भी उसका कहना है कि यहाँ की जाति-व्यवस्था को वर्तमान

रूप देने मे एक नहीं भ्रानेक कारणों ने सहयोग दिया है। किस कारण का कितना हिस्सा जाति-व्यवस्था के उत्पन्न करने में रहा होगा—यह गवेषणा का एक भ्राच्छा विषय है।

जाति-प्रथा की उत्पत्ति मे हमारा जो मृत है वह हम इस अध्याय के प्रारम्भ मे ही दे आये हैं।

### ६. जाति-व्यवस्था के कार्य (Functions of Caste System)

जाति-व्यवस्था के कार्य अच्छे भी हो सकते है, बुरे भी । इन दोनो का यहाँ सक्षिप्त-सा वर्णन कर देना अप्रासगिक न होगा। जाति-व्यवस्था के अच्छे कार्यों को हम 'जाति-व्यवस्था के ग्रुण' तथा बुरे कार्यों को 'जाति-व्यवस्था के दोष'—इन शीर्षकों से लिखेगे।

#### [ जाति-व्यवस्था के गुरा ]

- (क) मानसिक-निदिचन्तता (Psychological Security)—जाति-व्यवस्था का सबसे बडा ग्रुण यह है कि जाति का जो सदस्य होता है उसे अपने भविष्य के कार्य-क्रम की कोई चिन्ता नहीं रहती। जाति की जो परम्पराएँ हैं उन्हों को लेकर व्यक्ति जीवन मे आगे-आगे कदम् रखता जाता है, उसके लिए मानो सारा-का-सारा प्रोग्राम पहले से बना बनाया है, शादी-ब्याह, खाना-पीना, रहन-सहन, रीति-सस्कार—इन सबके लिये उसे कोई चिन्ता नहीं करनी, यह सारी चिन्ता का भार बिरादरी सदा अपने ऊपर लिये रहती है।
- (ख) आधिक-निविचन्तता (Economic Security)—माज उद्योग-धन्धे की समस्या हर व्यक्ति को परेशान करती है, परन्तु जाति-व्यवस्था मे हर व्यक्ति का धन्धा निव्चित है। भगी के लड़के को भगी का काम करना है, कहार-बढ़ई-सुनार के लड़के को अपना परम्परागत धन्धा करना है। इसमें जो-कुछ प्राप्त हो गया उसी को वह बहुत मानता है। जाति क्योंकि जन्म से साती हैं इमलिये ऊँची जाति मे जन्म लिया तो

भी सन्तोष, नीची जाति में जन्म लिया तो भी सन्तोष करना होता है,
यह सोचकर सन्तोष करना होता है कि पिछले जन्म के कर्मों के कारण
नीच जन्म मिला, ग्रब कर्म का फल भोग लेगे तो अगले जन्म में उच्च
वश मे जन्म मिलेगा। जाति-व्यवस्था मे हर युवक को धन्चे की तलाश
नहीं करनी पडती, बाप-दादा का धन्धा उसका धन्धा होता है।

- (ग) सामाजिक-युरक्ता (Social Security) आज वृद्ध, श्रपण, श्रनाथ, विश्ववा के लिये सामाजिक-सुरक्षा के भिन्न-भिन्न प्रयत्न हो रहे हैं। वृद्धों के लिये वृद्धालय, श्रनाथों के लिये श्रनाथालय, विश्ववाश्रों के लिये विश्ववाश्रम खुल रहे हैं। जाति-व्यवस्था में इस प्रकार के श्रसमर्थ व्यक्तियों का पालन-पोषण जात-बिरादरी करती थी।
- (घ) संगठन (Social Unity)—जाति-व्यवस्था मे जाति के सदस्यों का आन्तरिक-सगठन बड़ा दृढ होता है। जाति के मुखिया लोगों ने जो निश्चय कर दिया वह सबको मान्य होता है। बिरादरी अगर हडताल का निश्चय कर दे, तो किसी की मजाल नहीं जो हडताल के विश्व चूँ भी कर सके। आजकल की मजदूरों की हडतालों और बिरादरी की हडताल में यह भेद है कि मजदूरों में दो पार्टियाँ बन सकती हैं, परन्तु बिरादरी की हडताल में दो पार्टियाँ नहीं बनती। बिरादरी की बात जो नहीं मानता उसे बहिष्कृत कर दिया जाता है, उसका हुक्का-पानी बन्द कर दिया जाता है, उमसे रोटी-बेटी का व्यवहार तोड दिया जाता है। इस दृष्टि से जाति का सगठन एक जबर्दस्त सगठन है। राजनैतिक दल जात-बिरादरी का अपाधार पर वोट माँगते हैं, और भारत जैसे देश में जहाँ जात-बिरादरी का भूत हर-एक पर सवार है जाति के आधार पर वोट ज्यादा लिये और दिये जा सकते हैं।
- (क) भिन्न समुदायों को एकता में, बांचना (Unity in diversity)— भारतीयों की जाति-व्यवस्था में एक खास बात यह है कि यह जातियों के भिन्त-भिन्न समूह होते हुए भी उन्हें एक सूत्र में बाँघ देती है। उदा-हरणार्थ, बाहर से आये हुए शक, हुण आदि और अपने देश के अन्दर

के जो लोग भी हैं—इन सबको हिन्दुश्रों की जाति-व्यवस्था मे इस तरह पिरो दिया गया है कि वे सब अलग-अलग होते हुए भी हिन्दू-धर्म का अग माने गये हैं। हिन्दुश्रों की जाति-व्यवस्था मे हर-एक को स्थान हैं। हिन्दू हर-एक के साथ रोटी-बेटी का व्यवहार तो नहीं कर सकता, परन्तु अपनी जाति-व्यवस्था मे हर-एक को स्थान अवश्य दे सकता है। अगर ईसाई हिन्दू होना चाहता है तो हिन्दू रोटी-बेटी का व्यवहार तो उसके साथ नहीं करेगा, परन्तु उसे 'ईमाई-हिन्दू' की जात अवश्य दे देगा। इस प्रकार जो ईसाई-हिन्दू बनेंगे, वे आपस मे रोटी-बेटी का व्यवहार कर सकेंगे, दूसरों के साथ नहीं। इस तरह की है यह जाति-व्यवस्था।

#### जाति-व्यवस्था के वोष ]

- (क) अराष्ट्रीयता (Anti-nationalism)—जाति-व्यवस्था मे जहाँ यह ग्रुण है कि यह छोटे-छोटे समूहो मे एकता उत्पन्न करती है, वहाँ इसमे यह दोष है कि यह बड़े समूह का निर्माण नहीं होने देती, खासकर एक राष्ट्रीय-भावना के उत्पन्न होने में बाधक बन जाती है। जहाँ राष्ट्रीयता की भावना की बात हुई, वहाँ छोटे-छोटे समूह अपने-अपने स्वायों के कारण इस अकार लड़ने-भगड़ने लगते हैं कि बड़ी बात हो ही नहीं पाती। बनिये बनिये के दृष्टिकोण से, खत्री खत्रियों के दृष्टिकोण से जब बात करेंगे, तब राष्ट्रीयता के दृष्टिकोण की बात कहाँ हो सकती है ?
- (ख) शोषण (Exploitation)—जाति-व्यवस्था मे ऊँच-नीच का भाव सदा बना रहता है। यह ऊँच-नीच का भाव कमं पर ग्राधित न होकर जन्म पर ग्राधित होता है। इसका मतलब यह हुन्ना कि जाति-व्यवस्था मे कुछ व्यक्ति सदा जन्म के कारण ऊँचे ग्रीर कुछ जन्म ही के कारण सदा नीचे माने जाते हैं। परिणामस्त्रक्ष्प उच्च-कुल के लोग सदा नीचे कहे जाने वाले वर्ग का शोषण करते रहते हैं। ग्रछूतपन की बीमारी इसी जाति-व्यवस्था की उपज है। हिन्दू-समाज की जानि-व्यवस्था के कारण ग्रछूत कहे जाने वाले वर्ग का सदा शोषण हुग्ना है। जाति-

व्यवस्था के इन अत्याचारो का परिणाम है कि अनेक तथाकथित निम्त-जाति के लोग ईसाई तथा मुसलमान बन गये।

- (ग) सप्रगितशीलता (Static society) जाति-व्यवस्था पर श्राश्रित समाज प्रगितशील नहीं रहता । सब-कुछ पहले से निश्चित हैं । रीति-रिवाज क्या होंगे, रहन-सहन कैंसा होगा, श्रार्थिक-दृष्टि से व्यक्ति किस प्रकार का उद्योग-धन्धा करेगा, कहा शादी-ब्याह करेगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा—सब-कुछ जब व्यक्ति के लिए पहले से निश्चित है, तब वह अपने दिमाग को किसी बात के लिए तकलीफ क्यो देगा ? ऐसे समाज में व्यक्ति में कियाशीलता नहीं रहती, प्रगितशीलता नहीं रहती, वह अपने उद्योग से आगे नहीं बढ सकता ।
- (घ) भ्रत्रजातान्त्रिक (Anti-democratic)—१५ श्रगस्त १६४७ को भाग्त स्वतन्त्र हुम्रा। उसमे पहले म्रग्रेजो के काल मे तो प्रजातन्त्र का कुछ काम ही नही था, उसके बाद इस दिशा मे कदम उठाया गया। इस बीच जो मविधान बना, वह २६ जनवरी १६५० को सम्पूर्ण भारत पर लाग्न हुम्रा। इस सविधान की कुछ विशेषताएँ थी जिनमे से जिस विषय पर हम विचार कर रहे हैं उससे सम्बन्ध रखने वाली विशेषताएँ हैं—'ग्राधारभूत मधिकार' (Fundamental Rights)।

'आधारभूत-धिकार' का मतलब है—कानून की दृष्टि से व्यक्ति व्यक्ति में कोई भेद नहीं होगा, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, धर्म, वश, जाति, लिंग के कारण मनुष्य-मनुष्य में भेद नहीं माना जायगा, सब बराबर होगे, हर किसी को वोट का अधिकार होगा। यह अधिकार ऐसा है जिससे जाति-व्यवस्था की जड़ में कुठाराधात होता है। जाति-व्यवस्था, और प्रजातन्त्र के सिद्धान्त पर माने गये 'आधारभूत-अधिकार'—दोनो एक-दूसरे से विरोधी चीजें हैं। अगर आधारभूत-अधिकारों के अनुसार भारत के हर व्यक्ति को, चाहे वह बाह्मण हो, चाहे चमार हो, एक-सा माना जाय, तो जाति-व्यवस्था खैतम हो जाती है, अगर जाति-व्यवस्था के अनुसार मनुष्य-मनुष्य में जन्म के कारण मेद माना जाय,

तो 'ग्राधारभूत-प्रधिकार' खत्म हो जाते हैं। इन दोनो का मेल नहीं बैठता। वर्तमान-युग में क्यों कि प्रजातन्त्र का ही बोलबाला होगा इसलिए धीरे-धीरे जाति-व्यवस्था समाप्त हो जायगी—इसमें कोई सन्देह नहीं। इसमें भी सन्देह नहीं कि जैसी हालत ग्रभी तक है उसमें चुनावों के समय लोग प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तों को दृष्टि में रखकर वोट नहीं देते, अपनी जात-बिरादरी को सामने रखकर वोट देते हैं। भारत में ग्रसली प्रजातन्त्र तभी चलेगा जब जात-बिरादरी के सकुचित हित को भुलाकर लोग देश-हित की विशाल दृष्टि से सोचने लगेगे।

#### ७. जाति-प्रणाली तथा भारतीय मुसलमान

(क) मुसलमानों में विवाह-संबंध में ऊँच-नीच का भेव—इस्लाम में विद्य-बन्ध्रत्व का सिद्धान्त ग्राधारभूत माना जाता है। हजरत मुहम्मद के ग्रनुसार इन्सान ग्रीर इन्सान में भेद करना ग्रनुचित है। सब मनुष्य एक-समान हैं, उनमें ऊँच-नीच का भेद नहीं है। यह विचार जाति-व्यवस्था के विचार से उल्टा है। जाति-व्यवस्था में तो जन्म से ही कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैद्य ग्रीर कोई ग्रह्म है।

जाति-व्यवस्था के इस रूप से तो इस्लाम ग्रन्थ्त है, परन्तु ग्रसल मे देवा जाय, तो जाति-व्यवस्था का ग्राधारभूत-तत्व बाह्मण-क्षत्रिय-वैश्य शूद्र न होकर मनुष्य का मनुष्य से भेद हैं। जहा मनुष्य का मनुष्य से सेद हैं। जहा मनुष्य का मनुष्य से सामाजिक-दृष्टि से भेद पाया जाता है वहा जाति-व्यवस्था को किसी-न-किसी रूप मे माना जाता है। जो लोग मनुष्य का मनुष्य से भेद करते हैं, वे एक-दूमरे को छूने से परहेज करते हैं, एक दूसरे के साथ उठने-बैठने से, खाने-पीने से, एक-दूसरे को विवाह में भपनी कन्या देने से परहेज करते हैं। इन दृष्टियों से देखा जाय, तो यद्यपि मुसलमानो मे हिन्दुश्रो की तरह उतनी कट्टरता नही हैं, तो भी ग्रन्तिववाह के क्षेत्र मे उनमे भी ऊँच-नीच का भेद विद्यमान है। उदाहरणार्थ, श्री रामधारी सिंह दिनकर ने श्रपने 'सस्कृति के चार

प्रध्याय'-नामक ग्रन्थ में 'मुस्लिम-काल में सामाजिक-संस्कृति का स्वरूप'—इस ग्रध्याय में लिखा हैं, "हिन्दुश्रो की जाति-प्रथा ने भी मुस्लिम-समाज को प्रभावित किया ग्रौर मुसलमान भी शरीफ़ ग्रौर रजील जातो का भेद करने लगे एव जुलाहो ग्रौर धनियो के साथ शरीफ जात वालो को खाने-पीने में ग्रापत्ति होने लगी।" "हिन्दुग्रो की देखा-देखी, मुसलमानो में भी ऊंच-नीच का भेद चलने लगा एव यह प्रथा प्रचलित हो गई कि सय्यद शेख की बेटी ले सकता हैं, किन्तु शैख सय्यद की बेटी से ब्याह नहीं कर सकता।"

(ल) मुसलमानों में ऊंच-नीच के सामाजिक-भेद का काररा-यद्यपि इस्लाम मे मनुष्य-मनुष्य के ऊच-नीच के भेद को स्वीकार नही किया गया, तथापि इस्लाम मे यह भेद किसी-न-किसी रूप में पाया जाता है। इसका कारण क्या है ? इसका कारण यह है कि इस्लाम जब ग्रन्य देशो मे ग्राकाता बनकर पहुंचा, तब वहा जाकर यद्यपि इसने दूसरे देश वालो को इस्लाम धर्म मे दीक्षित कर लिया. तो भी विजेता श्रीर विजित की भावना हर जगह बनी रही। जो लोग मुहम्मद साहब के रक्त के थे. या उनके सबधी थे. या उनके समय के साथी थे, वे तथा उनके वशज सदा ग्रपने को दूसरो से बडा समभते रहे भीर इस बडप्पन के कारण ही वे भ्रपनो तथा दूसरो मे भेद करते रहे। जो विजित थे, उन्होंने यद्यपि इस्लाम स्वीकार कर लिया, तो भी श्रपनी स्वतन्त्र-सत्ता बनाए रखने के लिए वे भी श्रपनो मे ही ब्याह-शादी करते रहे, इसलिए एक तरह की जात-पाँत इन लोगो मे बनी रही। जब इस्लाम भारत मे आया, तब तो इस्लाम का जात-पाँत से प्रभावित होना ग्रौर भी ग्रासान हो गया। यहा तो जाति-व्यवस्था थी ही। इसका प्रभाव यह हुआ कि मुस्लिम भाकान्ताभी मे भी एक तरह से तीन सामाजिक श्रेणिया बन गईं। इतिहासकार श्रन्सारी के कथनानुसार भारत में मुसलमानों मे जो सामाजिक भेद-माव उत्पन्न हो गया उसे तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है। वे भाग क्या है ?

(ग) भारत में मुसलमानों में ऊंच-नीच के तीन भेद— श्रन्सारी के कथनानुसार भारत में मुसलमानों के तीन वर्ग बन गए। एक वर्ग तो वह है जो उच्च जाित के मुसलमानों का है, ये मुसलमान अपने को विजेता मुसलमानों का वशधर बतलाते हैं, अरब या ईरान से श्राया हुआ बतलाते हैं, अपना किसी-न-किसी प्रकार का सम्बन्ध हजरत मुहम्मद से जोडते हैं। इन्हे 'अशरफ' कहा जाता है, 'अशरफ'— अर्थात् 'शरीफ'— जिनका जिक्क हम ऊपर कर आए हैं। इन 'शरीफ' मुसलमानों के बाद सामाजिक स्थित में दूसरे दर्जे पर वे मुसलमान आते हैं जो उच्च जाित के हिन्दू थे, परन्तु मुसलमान हो गये। इनको क्यों कि 'शरीफ'-दर्जें के मुसलमान अपने में शामिल नहीं करते इसलिए इनका दर्जा दूसरा है। तीसरे दर्जें में हिन्दुओं की वे छोटी-मोटी जाितया आ जाती हैं जो उच्च-दर्जें के हिन्दू नहीं थे, नीचे दर्जें के थे, और मुसलमान हो गये।

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि यद्यपि मुसलमानो में हिन्दुश्रों की छूत-छात नहीं है, खाने-पीने ग्रौर हुक्के का परहेच भी नहीं है, इस दृष्टि से हिन्दुश्रों की-सी जाति-प्रणाली भी नहीं है, तथापि उनमें वशगत ऊंच-नीच का भेद मौजूद है, ब्याह-शादी में भी जन्मगत भेद को ध्यान में रखा जाता हैं—इसलिए इन ग्रशो में उनमें भी जाति-प्रणाली के ये दो ग्राधारभूत तत्व—जन्मगत-भेद तथा सामाजिक-स्थिति पर ग्राश्रित ब्याह-शादी का भाव—मौजूद है।

# प्त. जातिवाद (Casteism)

हमने श्रभी कहा कि मुसलमानो मे यद्यपि हिन्दुग्रों की तरह की जाति-प्रणाली नहीं हैं, तो भी उनके जाति-प्रणाली के कई तत्व मौजूद हैं, उनमे ऊँच-नीच की भावना मौजूद हैं। इस भावना को जाति-प्रणाली तो नहीं कहा जा सकता, परन्तु जातिवाद कहा जा सकता है। तो फिर जातिवाद क्या है ?

- (क) जातिवाद की परिभाषा—जातिवाद किसी एक जाति या मानव-समूह के सदस्यों की उस भावना को कहते हैं जो ग्रपने देश या ग्रपने सम्पूर्ण समाज का हित सामने नहीं रखती, ग्रपितु ग्रपनी जाति या ग्रपने से सम्बन्धित छोटे समूह के सदस्यों के हित को सामने रखती हैं। यह जरूरी नहीं कि यह भावना हिन्दुओं की-मी जाति-प्रणाली का ही रूप घारण करे। जहा-जहां देश भर के या ग्रपने सम्पूर्ण समाज के हित को सामने रखने के स्थान में ग्रपनी जाति, ग्रपनी बिरादरी, ग्रपने धर्म या ग्रपने छोटे-से समाज का हित सामने रखकर व्यवस्था बनेगी, वहाँ जातिवाद कहा जा सकेगा। इस जातिवाद का परिणाम यह होता हैं कि लोग ग्रपनी-ग्रपनी जाति को दृढ बनाने का प्रयत्न करते हैं, उसके सदस्यों का ग्रापस में सम्पर्क होता हैं, जाति के सदस्य ग्रापस में ही शादी-ब्याह करते हैं, ग्रपने दायरे से बाहर नहीं जाना चाहते।
- (क्ष) जातिबाद के कारए। मनुष्य इकला भी नही रह सकता, सारे ससार का होकर भी नही रह सकता। इकले रहने से उसके कारोबार नही चल सकते, और सारे समार का बनकर ममुद्र में पानी के बूंद की तरह वह अपने को खो देता हैं। इसलिये अपने कारोबार चलाने के लिए, अपना परिवार बनाये रखने के लिए, शादी-व्याह का चक्र चलाये रखने के लिए, अपने नजदीकी सहायको का दायरा खड़ा करने के लिए वह एक समूह को अपना लेता हैं, इसी मे अपने व्यवहार चलाता हैं, यही उसका जाति का दायरा कहलाता हैं। इस प्रकार के दायरे आजकल की परिस्थितियों में बन भी रहे हैं, टूट भी रहे हैं। क्यो बन रहे हैं और क्यों टूट रहे हैं इसके भी कारण हैं। वे कारण क्या है ?
- (i) उद्योगीकरण तथा नगरीकरण -पहले कभी लोग श्रपनी जात का ही पेशा करते थे परन्तु आज उद्योग बढ रहे हैं, नगरो का विकास हो रहा है, सब लोग गाव से नगर की ओर जाना चाहते हैं। गांव में वे श्रपने सीमित-क्षेत्र मे थे, हर समय जात-बिरादरी वा भूत सवार रहता था, जब वे शहर मे जाते हैं तब उनका जात-बिरादरी

से सम्बन्ध टूट जाता है, नये-नये लोगो के बीच मनुष्य जा पडता है। परन्तु जातिवाद की जो भावना नगर में जाकर टूट गई थी, वह वहां की परिस्थितियों से फिर जाग भी जाती है। इतने बड़े नगर में मनुष्य भ्रपने को इकला-सा अनुभव करने लगता है, कोई मुसीबत में साथ देने वाला नहीं दीखता। ऐसी हालत में फिर वह भ्रपनी जाति वालों की तलाश करता है, भ्रपने गाव वाले, भ्रपनी जात-बिरादरी वाले, ऐसे लोग जो जरूरत के वस्त उसका साथ दें। यही कारण है कि बड़े-बड़े शहरों में जातीय-सगठन बनते दिखाई देते हैं—गीड ब्राह्मण सभा, सारस्वत महामण्डल, भ्रग्नवाल सभा इत्यादि। उद्योगीकरण तथा नगरीकरण से लोग नगरों में जाते है, भ्रौर वहा नगरों की परिस्थितिया जातिवाद को तोडने तथा बढावा देने—दोनों में हाथ बँटा रही हैं।

(ii) आजीविका की समस्या--- आजीविका की समस्या को हला करने के लिए भी जातिबाद का सहारा लिया जाता है। पहले कभी जातिया भ्राजीविका का प्रश्न भी हल करती थी। प्रत्येक जाति का एक पेशा होता था, उस जाति मे जो पैदा हुम्रा उसको पेशा ढ़ ढने की जरूरत नही थी, उसकी जाति का पेशा उसका पेशा था। बाह्मण के लडके को पिधयाई ही करनी है, और कुछ नही, क्षत्रिय के लडके को फौज में भर्ती होना है, बनिये के लडके को दुकानदारी करनी है। धाज की कश्मकश के युग मे यह प्रवस्था नही रही। ब्राह्मण का लडका पिथयाई से सत्ष्ट नही, वह सरकारी नौकरी करना चाहता है। यही हाल श्रीर जातियो का है। इस युग मे जाति का पेशे के साथ श्रव तक जो सम्बन्ध चला ग्रा रहा था वह टूट गया है, परन्तु जहां वह सम्बन्ध ट्रटा है वहा फिर से वह सम्बन्ध बनता भी जा रहा है। वह कैसे ? वह इस प्रकार कि जब कोई ब्राह्मण या किसी जाति या धर्म का कोई व्यक्ति उच्च पद पा लेता है तब वह ग्रपनी जाति के लोगो का स्तर ऊँचा करने के लिए उन्हें सहारा देने लगता है। अगर कोई दलित-वर्ग का व्यक्ति मिनिस्टर बन गया, तो वह अपनी जात-बिरादरी वालो

की जितनी सहायता कर सकता है, करता है, जहाँ तक उसका बस चलता है अपनी जात वालो को नौकरिया देता है। कायस्थ कायस्थों को हूँ उते हैं, काश्मीरी काश्मीरियों को, भिन्न-भिन्न जात वाले अपनी जात वालों को। नौकरियां ढू उने वाले भी इस बात का पता लगाते रहते हैं कि उनकी जात का कौन बड़ा अफ़सर कहाँ लगा है। इन सब लोगों का ऐसा करना स्वाभाविक भी है। जब तक वे अपनी सारी जाति का आजीविका का आर्थिक-स्तर ऊँचा नहीं कर लेते तब तक अपने लड़के-लड़िक्यों के शादी-ज्याह की समस्या उनके सामने बनी रहती है। इस सब से भी जातिवाद को पनपने का अवसर मिलता है।

- (ग) जातिवाद के परिएगम— उक्त कारणो से जातिवाद बढ रहा है—हिन्दुमो में, मुसलमानो में, सिक्खो, ईसाइयो, पार्गसियो— सभी में बढ रहा है। हमें यह देखना है कि जातिवाद के इस प्रकार बढ़ने के क्या परिणाम हैं?
- (i) जातिवाद राष्ट्रीयता तथा लोकतन्त्र-भावना के विपरीत है—
  जातिवाद का यह परिणाम है कि हम प्रत्येक क्षेत्र मे अपनी जाति की
  बात ले बैठते हैं। स्कूली-कालेजो मे प्रबन्धक लोग अपनी जाति के
  लोगो को भरने लगते हैं। नगरपालिका, विधान-सभा आदि के चुनावो
  मे अपनी जाति के लोगो को मतदान देने लगते हैं। राष्ट्रीयता तथा
  लोकतन्त्र की भावना यह नहीं हैं। राष्ट्रीयता तथा लोकतन्त्र मे व्यक्ति
  सारे देश का है, एक समूह का, एक जाति का नहीं। अगर मान
  लिया जाय कि अपनी जाति के वे लोग जिन्हे हम नौकरी मे भरते हैं,
  या जिन्हें हम वोट देते हैं, सब-के-सब योग्य ही हैं, तब भी इसका
  यह परिणाम तो होता ही हैं कि इससे एक क्षुद्र भावना को हम
  बढावा देते हैं, राष्ट्रीयता तथा लोकतन्त्र की महान् भावना को नष्ट
  करते हैं।

- (11) जातिवाद से ग्रयोग्य व्यक्तियों के हाथ में सत्ता ग्राती है—यह समभना कि हमारी जाति के सब लोग योग्य ही होगे, गृलत घारणा है। योग्यता का पट्टा किसी एक जाति का नहीं। योग्य व्यक्ति सब जातियो, सब समूहों में पाये जाते हैं। जातिवाद का मयंकर दुष्परिणाम यह होता है कि सब जगह ग्रयोग्य व्यक्ति मर जाते हैं ग्रीर कोई काम ठीक-से नहीं हो पाता। ग्राज ग्रपने देश में सब जगह कार्य की शिक्तिता का मुख्य कारण यहीं है कि जातिवाद के शिकार होकर हनने सब जगह ग्रपने भाई-भतीजे भर दिये हैं।
- (घ) जातिबाद को दूर करने के साधन—जैसा हमने पहले कहा, 'जातिवाद' हिन्दुओं की ही बीमारी नहीं, सब जगह भिन्न-भिन्न रूपे में पाया जाता है। इसे किस प्रकार समाप्त किया जाय—यह समाज-सुधारकों के सम्मुख सबसे बड़ी समस्या है। 'जातिवाद' से देश को बहुत हानि होती है इसलिये यह विचार करना ग्रावश्यक है कि यह कैसे समाप्त हो?
  - (i) जातिवाद को समाप्त करने के लिये जाति-क्यवस्था को समाप्त किया जाय—समाज-सुधारको मे एक प्रवल-पक्ष यह है कि जब तक हर-एक अपने को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र—इस रूप में मानता है, तब तक हिन्दुओं का जातिवाद समाप्त नहीं हो सकता । इसी दृष्टि से कई लोग अपने को किसी जाति के नाम से न कहकर 'आर्य'—यह लिखते हैं। परन्तु कठिनाई यह है कि जाति-व्यवस्था हिन्दुओं में इतना घर कर चुकी है कि लेखो-व्याख्यानों से यह निकल नहीं सकती। इसके अतिरिक्त जाति-व्यवस्था को खत्म कर देने से जातिवाद समाप्त को जायगा—यह विचारास्पद बात है। जाति-व्यवस्था तो जातिवाद का ही परिणाम है। हमे जातिवाद की भावना समाप्त करनी होगी, तब जाति-व्यवस्था अपने-आप समाप्त हो जायगी, अगर नहीं भी होगी तब भी जाति-व्यवस्था से जातिवाद के कुपरिणाम नहीं उत्पन्न होगे।

- (ii) कानून द्वारा जातिबाद को समाप्त किया' जाय— दूसरा पक्ष यह है कि ग्रगर जातिबाद लेखो-च्याख्यानो-प्रचार से नहीं समाप्त होता, तो इसे कानून बनाकर समाप्त कर दिया जाय । इसी दृष्टि से भारत के संविधान के श्रनुच्छेद १५ विभाग २ के श्रनुसार सभी जातियों को बिना किसी भेद-भाव के सार्वजनिक स्थानों के इस्तेमाल की श्राज्ञा दी गई है, शौर १६ श्रनुच्छेद के श्रनुसार सरकारी नौकरियों के लिये सबको बिना जाति तथा धर्म के भेद के समान श्रधिकार बिये गये हैं। इसमे सन्देह नहीं कि इस प्रकार के कानूनों से जातिबाद के उन्मूलन में पर्याप्त सहायता मिलेगी तथा मिल रही है।
- (iii) अन्तर्जातीय विवाहों द्वारा जातिवाद को समाप्त किया जाय— जातिवाद को दूर करने का एक बडा साधन यह है कि अन्तर्जातीय-विवाहों को प्रोत्साहित किया जाय। जातिवाद के परिणामस्वरूप सबसे पहली बात यह होती है कि हम इस जाति में अपनी लडकी का विवाह नहीं कर सकते, उसमें नहीं कर सकते। इस प्रकार के नवयुवको के तथ्यार होने की जरूरत है जो जान-बूभ कर अन्तर्जातीय विवाह करे। इससे जातिवाद की जडे धोरे-धीरे हिल जाने की सभावना है।
- (iv) जाति-विमुक्त समूहों का निर्माण किया जाय—एक सुक्ताव यह है कि नव-युवकों को प्रोत्साहित किया जाय जो अपने को किसी जाति का न कहें, हर प्रकार की जाति से अपने को विमुक्त कर लें। ऐसे समूह जितने बढते जायेंगे उतने ही वे दूसरों को प्रभावित कर अपने साथ मिलाते जायेंगे। इस प्रकार के समूहों से सिर्फ यह खतरा है कि कही आगे चलकर ये स्वय एक प्रकार की जाति का रूप न धारण कर लें, परन्तु यह खतरा बहुत दूर का खतरा है, अभी इस प्रकार के समूहों से इस तरह का कोई खतरा नहीं हो सकता।

#### प्रश्न

- २. जाति-वयवस्था के ग्राष्ट्रारभूत तत्व क्या है ?
- ३. जाति-व्यवस्था के उत्पत्ति के सिद्धान्तों का वर्शन कीजिये ।
- ४. जाति-व्यवस्था के गुरु तथा बोध क्या हैं ?
- ५. हिन्दुओं की जाति-स्थवस्था की कौन-सी विशेषताएँ भारतीय मुसलमानों में मिलती हैं?
- ६. जातिवाद (Casteism) क्या है ? इसके कारण, परिएगम तथा इसे दूर करने के साथन क्या है ?

## २

# जाति-व्यवस्था में परिवर्तन के तत्व

( FACTORS OF CHANGE IN CASTE SYSTEM)

जाति-व्यवस्था हमारी सामाजिक-रचना का इस समय एक अभिन्न अग बनी हुई है। समक्षा यह जाता है कि यह व्यवस्था सनातन-काल से चली आ रही है, और सनातन-काल तक चलती चली जायगी। जब कभी इसमे परिवर्तन की आवाज उठती है तभी यह कहा जाता है कि यह तो हिन्दू-धर्म की जड़ो मे कुठाराघात है। असल मे यह बात नही है। जाति-व्यवस्था ही क्या, कोई भी सामाजिक-व्यवस्था ऐसी नही होती, जो सदा एक-सी बनी रहे। समय-समय पर समाज की भिन्न-भिन्न आवश्यकताएँ उत्पन्न होती रहती हैं, और उन आवश्यकताओ को पूरा करने के लिये समाजशास्त्री तथा नियम-निर्माता-श्रेणी के लोग भिन्न-भिन्न व्यवस्थाएँ बनाते रहते हैं। एक ही व्यवस्था मे भी समयानुसार परिवर्तन होता रहता है। यह नियम जाति-व्यवस्था पर भी वैसा ही लागू है जैसा और व्यवस्थाओं पर। हमने यहाँ यह देखना है कि जाति-व्यवस्था का वर्तमान रूप क्या सनातन-काल से ऐसा ही चला आया है, या यह सामाजिक-संगठन हमारे समाज मे भिन्न-भिन्न रूपो में से होता हुआ वर्तमान रूप मे पहुँचा है। ग्रपने देश का इतिहास बहुत पुराना है। इतिहासज लोग भिन्नभिन्न घटनाग्रो के भिन्न-भिन्न काल बतलाते हैं। पुरातन-काल की
किसी घटना के विषय में भी सब विद्वानों का एकमत नहीं हैं। हम
यहाँ काल के भगड़े में नहीं पड़ेगे। हमारे उद्देश्य के लिये इतना पर्याप्त
हैं कि हमारा बहुत पुराना काल वैदिक-काल था, उसके बाद उत्तर-वैदिककाल ग्राया, फिर स्मृतियों का काल भाया, श्रीर अब वर्तमान काल हैं।
हमें यह देखना है कि जाति-व्यवस्था का विचार इन चारों कालों में
क्या एक-सा रहा, या इन सब कालों में से गुजरता हुमा समय की
भावश्यकता के अनुसार यह भिन्न-भिन्न रूपों को भारण करता गया,
इसमें समयानुसार परिवर्तन होता गया। हमारी स्थापना यह है कि
ग्रन्य विचारों के अनुसार यह विचार भी समय की भावश्यकताग्रो के
भनुसार बदलता गया, इसमें परिवर्तन होता गया, यहाँ तक कि इस समय
भी इसमें परिवर्तन हो रहा है, ग्रीर समय की भावश्यकता के भनुसार
इसमें ग्रभी ग्रीर ग्रिधक परिवर्तन होने की भावश्यकता है। जाति-व्यवस्था
में किस प्रकार परिवर्तन होता रहा है—यह आगे स्पष्ट हो जायगा।

# वैदिक-काल में जाति-व्यवस्था (ग्रायं तथा दास )

वैदिक-काल भारतीय इतिहास का प्राचीनतम काल समक्षा जाता है। आयों की प्राचीनतम सम्यता, सस्कृति तथा सामाजिक-व्यवस्था जानने के लिये इस काल के ग्रन्थों का अनुशीलन आवश्यक है। इस काल का सबसे प्राचीन ग्रन्थ ऋग्वेद हैं। हम पहले दशी आये हैं कि भारत की प्रारम्भिक—श्र्यात् वैदिक-काल की—सामाजिक-व्यवस्था में समाज को दो भागों में बाँटा गया था। वे दो भाग भे—ग्रायं तथा दस्यु। पाश्चात्य-विद्वानों का कथन है कि आयं लोग भारत के आदि निवासी नहीं थे। वे विजेता बन कर यहां आये। यहां के आदि-निवासी कोई दूसरे लोग थे जिन्हें वेदों में 'दास' या 'दस्यु' कहा गया है।

बायों ने दासों को जीत लिया भीर 'दास' या 'दस्यु' लोग भायों के ग्राधीन भिन्त-भिन्न वस्तियों में रहने लगे। ग्रायं लोग दासों से घुणा करते थे। प्रायीं का रग गोरा था, दासो का काला; भायों की नाक नोकीली थी, दासो की चपटी ! आर्थ लोग विजेता बन कर आये थे इसलिये वे अधिकतर सैनिक थे; दास लोग यहाँ के झादि-वासी थे, उन्हें जीता गया था इसलिये उनसे सब तरह का हाथ का तथा सेवा का काम लिया जाता था। आयाँ तथा दासों का यह सम्बन्ध ही दास-प्रया का रूप धारण कर गया। पारचात्य-विद्वानों का यह विचार ठीक है या नहीं-इस पर विद्वानों के भिन्त-भिन्त मत है। पाश्चात्य-विद्वानो से भिन्त अन्य भनेक विदानों का मत है कि मार्य लोग बाहर से नहीं माये थे, यहीं के द्यादि-निवासी थे। धगर बाहर से भी धाये थे, तो भी 'धार्य' तथा 'दास'--य दो भिन्न-भिन्न जातियाँ, या ये दोनो भिन्न-भिन्न रुधिरों की न होकर ये शब्द ग्रुण-वाचक थे। भ्रुच्छे लोग भ्रार्य कहलाते थे. बरे लोग दस्य कहलाते थे। 'दास' या 'दस्यु'-शब्द 'दसु-उपक्षये' धातु से बने हैं। 'उपक्षय' का ग्रर्थ है-नाश करना, तोडना-फोड़ना। जो उस समय की सामाजिक-व्यवस्था को मान कर उसके भ्रमसार चलते थे वे 'श्रार्य' कहलाते थे, जो चोर-उचक्को की तरह सामाजिक-व्यवस्था को न मान कर मनमानी करते थे उन्हे 'उपक्षय' करने के कारण 'दास' कहा जाता था। समाज में इस प्रकार दो तरह के व्यक्ति सदा रहते है--नियमों का पालन करने वाले तथा नियमो को तोडने वाले. धाज भी ऐसे व्यक्ति हैं। वैदिक-काल में समाज के इस प्रकार के स्वाभाविक-विभाग को 'ग्रायं' तथा 'दस्य' कहा जाता था. विजेता या विजित होने के कारण, या रग का भेद होने के कारण या जाति का भेद होने के कारण नही । इसीलिये ऋग्वेद मे कहा गया—'सब को प्रार्य बना 

की घोषणा का कोई ग्रम्थं नहीं हो सकता। क्योंकि भिन्न रक्त के व्यक्ति को 'ग्रायं' कैसे बनाया जा सकताथा।

जो-कुछ भी हो, ब्रायं बाहर से श्राये या यहीं के श्रादि-वासी थे, भागं तथा दास भिन्त-भिन्न रक्त के थे या एक ही समाज में अच्छे व्यक्तियों को आयं तथा बुरों को दास कहा जाता था-यह स्पष्ट है कि वैदिक-काल में घाज जैसी जाति-व्यवस्था नहीं थी। घाज एक जाति के लोग दूसरी जाति में शादी-व्याह नहीं करते, दूसरी जाति बालों के साथ खाते-पीते नही, उनके साथ मिलते-जलते नहीं - यह सब-कुछ वैदिक-काल में नहीं था, इसलिये नहीं था क्योंकि उस समय समाज का विभाग 'आयं' तथा 'दास' के सिवाय दूसरा-कुछ था ही नही। उस समय क्या था? उस समय, ग्राज जैसे सैकड़ों जात-पात है वैसी जातें नहीं थी; उस समय समाज का बाह्मण, क्षत्रिय, बैंदय, बूद जैसे वर्ण-विभाग भी नहीं था; उस समय सब लोग एक-से थे। सबको ऋग्वेद में 'विद्याः' कहा गया है, 'विद्याः' का मर्थ है--- 'प्रजा', 'जनता', 'लोग' ! इसका यह अभित्राय नहीं कि उस सामाजिक-व्यवस्था में किसी प्रकार का भी भेद नहीं था। भावों के प्रपत-प्रपते कबीले जरूर थे, इन कबीलो को 'जना:' कहा जाता था। ऋग्वेद में इस प्रकार के 'पंचजनाः' या 'पंच कुष्टयः' का वर्णन झाता है। ये पंचजन थे--- झरणु, बुह्यु, यदु, तुर्वस झीर पुरु। परन्तु ये पांचों 'मार्य' ये भीर ऋग्वेद की परिभाषा में 'बिहा:' थे, उस समय की 'जनता' थे। भाज जो 'वैदय' शब्द चला हुआ है, यह 'विद्याः' से ही बना है। इसका अर्थ भी है- जनता। क्योंकि ग्राम जनता वणिज-व्यापार से भपना गुजारा करती है इसलिये वणिज-व्यापार करने वालो को भी 'वैश्य' कहा जाने लगा। 'वेश्या'-शब्द भी इसी 'विशः' से ही बना है। 'वेश्या' मी किसी एक की न होकर जन-साधारण की, लोगों की, जनता की होती है इस लिये उसे 'वेश्या' कहा जाता है। हमारे कहने का श्रीभाग्य इतना ही है कि वैदिक-

काल में यहाँ सामाजिक-व्यवस्था मे सब लोग 'विश्व' कहलाते थे, 'जनता' कहलाते थे, इस जनता के मुख्य तौर पर दो ही विभाग थे— 'ग्रार्य' तथा 'दस्यु', श्रीर भ्राजकल जैसा जात-पांत या वर्ण-व्यवस्था का-सा कोई भेद नही था, सारा-का-सारा समाज एक था, श्रीर ग्रगर कोई भेद था तो भ्रच्छे व्यक्तियो (ग्रार्यो) ग्रीर बुरे व्यक्तियो (दस्युग्रों) का था। यह भेद जन्म पर ग्राश्वित न होकर कर्म पर ग्राश्वित था। इस भेद को 'ग्राव्वार-परक-भेद' (Ethical) कहा जा सकता है, श्रीर कुछ नही।

### २. उत्तर-वैदिक-काल में जाति-व्यवस्था (कमं के झाधार पर चार वर्ग)

ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, तथा अथर्ववेद--ये चार वेद है। इनमे ऋग्वेद सब से पूराना है। इस समय को वैदिक-काल कहते हैं। वैदिक-काल में वर्ण-व्यवस्था या जाति-व्यवस्था नही थी। उस समय वार वर्णी का कहीं जिक्र नहीं माता। मगर वर्णों का जिक्र माता भी है, तो सिर्फ दो का-- "उभौ वणौ ऋषिरूप्र पुपोष" (ऋक् १-१७६-६)-- ग्रथित्, उग्र ऋषि ने दोनो वर्णों को पूष्ट किया। वैदिक-काल मे वर्णो या जात-पॉत के ग्राधार पर होने वाला ऊच-तीच का भेद भी नही था। ऋग्वेद (५-६०-५) मे लिखा है-"अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते सभातरो वावधु सौभगाय"-तुममे से न कोई ऊँचा है न नीचा. त्म सब भाई-भाई हो, इसलिये सौभाग्य पाने के लिये ही भाई-भाई की तरह बरतो। एक वर्ण का अर्थ होता है-एक ही काम-धन्धा करना परन्तु ऋग्वेद (६-११२-३) मे लिखा है--- "कारुरह ततो भिषक् उपलप्रक्षिणी नना नानाधियो वसूयवोऽनु गा इव तस्थिमेन्द्रायेन्दो परिस्नव"--मै बढई हैं, मेरा पिता वैद्य है, मेरी माता चक्की पीसती है। इस सब से ज्ञात होता है कि वैदिक-काल में जाति-व्यवस्था या वर्ण-ज्यवस्थाका वर्तमान रूप नही था। वैदिक-काल के बाद बाह्मण-ग्रन्थो तथा उपनिषदो का काल ग्राता है। इसे

उत्तर-वैदिक-काल कहा जाता है। हमने देखना है कि इस उत्तर-वैदिक-काल में सामाजिक-व्यवस्था का क्या रूप हो गया। क्या वह वैदिक-काल के 'ग्रार्य' तथा 'दस्यु' के रूप मे ही रही या इसका रूप बदल गया।

हम कह ग्राये हैं कि वैदिक-काल मे चातुर्वर्ण्य की-सी वर्ण-व्यवस्था नहीं थी, परन्तू इसका यह ग्रभिप्राय नहीं कि उस काल में वर्ण-व्यवस्था का विचार भी नही था। समाज का इस प्रकार का विभाग हो सकता है —यह 'विचारात्मक कल्पना' (Theoretical idea) उस समय मौजूद थी। ऋग्वेद के १०वे मडल मे आता है-"ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत बाह राजन्यः कृतः उरू तदस्य यद्वैश्यः पद्म्यां शूद्रोऽजायत ।"---ग्रथात्, जैसे मानव-शरीर में सिर है, वैसे समाज भी एक प्रकार का विशाल मानव-शरीर है जिसके सिर बाह्मण है, जैसे मानव-शरीर में बाह रक्षा का काम करते हैं वैसे समाज रूपी मानव-शरीर में राजन्य (क्षत्रिय) रक्षा का काम करते हैं, पेट तथा जंधाओं का काम वैश्य, पैरो का काम शूद्रों का है। वह कल्पना ऋग्वेद में पायी जाती है, परन्तू वैदिक-काल मे यह विचार कल्पना तक ही सीमित था, इसे क्रियात्मक रूप नही दिया गया था। उत्तर-वैदिक-काल में इस विचार को क्रियात्मक रूप दिया गया श्रीर समाज की रचना-बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शुद्र-इन चार पेशो के श्राधार पर की गई। ग्रब तक समाज का विभाग म्रच्छाई तथा बुराई पर ग्राधित होने के कारण 'म्राचार-परक' (Ethical) था, परन्तु धव यह 'श्रम-विभाग' (Division of labour) पर प्राश्रित होने के कारण 'कर्म-परक' (Professional) हो गया; वैदिक-काल में यह विभाग विचारात्मक-वर्गीकरण (Theoretical classification) था, उत्तर-वैदिक-काल में यह विभाग क्रियात्मक-वर्गीकरण (Practical classification) हो गया । क्रियात्मक रूप मे ग्राने पर भी उत्तर-वैदिक-काल की सामाजिक वर्गीकरण की ब्यवस्था को 'ग्रनावृत जाति-व्यवस्था' (Open caste system) कहा जा सकता है, 'मावृत जाति-व्यवस्या' (Closed easte system) नहीं कहा जा सकता । 'भनावृत' तथा 'भावृत' में क्या भेद है ? 'भनावृत' में हर वर्ण का व्यक्ति अपने वर्ण को हर दूसरे वर्ण में परिवर्तित कर सकता है, बाह्मण क्षत्रिय हो सकता है, क्षत्रिय बाह्मण हो सकता है, शुद्र चाहे ती बाह्मण बन जाये, बाह्मण चाहे शूद बन जाये; 'झावृत' में हर-कोई भपने-अपने वर्ण में रहता है। 'अनावृत' व्यवस्था कर्म पर आश्रित रहती है, 'प्रावृत' व्यवस्था जन्म पर बाश्रित रहती है। जो जैसा कर्म करेगा वह उसी वर्ष का कहलायेगा--यह 'झनावृत वर्ण-व्यवस्या' का आधार है; जो जिस घर में जन्म लेगा वह उसी वर्ण का कहलायेगा—यह 'श्रावृत वर्ण-व्यवस्था' का बाधार है। उत्तर-वैदिक-काल की सामाजिक व्यवस्था माजकल की जाति-व्यवस्था की तरह की नही थी। प्राजकल की जाति-व्यवस्था में जाति बदली नहीं जा सकती, उस समय की जाति-व्यवस्था में जाति बदली जा सकती थी न्योंकि वह सिर्फ काम-धंधे के बाबार पर बनी थी। जो पढाने-लिखाने का काम करे वह बाह्यण, जो देश की रक्षा का काम करे वह क्षत्रिय, जो विणिज-व्यापार करे वह बैश्य, जो मेहनत-मजदूरी करे वह शूद्र। द्यापस्तम्ब धर्मसूत्र में लिखा है-"धर्मचयेया जचन्यो वर्णः पूर्वं पूर्वं वर्णमापद्यते जाति परिवृक्ती। प्रधमें चर्यया पूर्वी वर्णी जघन्यं वर्णमापद्यते जातिपरिवृत्ती ।"-प्रधात, धर्माचरण से निकृष्ट वर्ण अपने से उत्तम वर्ण की प्राप्त होता है. धधर्माचरण से उत्तम वर्ण निकृष्ट वर्ण की प्राप्त होता है।

इस सबसे स्पष्ट है कि उत्तर-बैदिक-काल में यद्यपि वर्ण-व्यवस्था ने कियात्मक रूप धारण कर लिया था तथापि उस समय इसका रूप 'मनावृत (खुली) जाति-व्यवस्था' का था, 'ग्रावृत (बंद) जाति-व्यवस्था' का नहीं। पुराणों तथा मनुस्मृति धादि में भी 'शूदो बाह्यणतामेति बाह्यणहर्चैति शूद्रताम्'—अर्थात् कर्म के धनुसार बाह्यण शृद्र हो सकता है भीर शूद्र बाह्यण हो सकता है—इत्यादि पाया जाता है जिसका भिन्नाय यही है कि उत्तर-बैदिक-काल में 'मनावृत जाति-व्यवस्था' थी, यह व्यवस्था मचकीली थी, रूढ़ नहीं हुई थी, कर्म-परक थी, जन्म-परक नहीं थी, इसमें रोटी-बेटी झादि के व्यवहार की रुकावट भी नहीं थी। इसीलिये उत्तर-वैदिक-काल तक के समय की व्यवस्था को हमने 'वर्ण-व्यवस्था' का नाम दिया है, 'जाति-व्यवस्था' का नाम नहीं दिया क्योंकि हमारी दृष्टि से 'वर्ण-व्यवस्था' का अर्थ है 'अनावृत सामाजिक व्यवस्था', प्रश्ति खुली व्यवस्था तथा 'जाति-व्यवस्था' का अर्थ है 'आवृत सामाजिक व्यवस्था', अर्थात् बन्द व्यवस्था।

#### ३. उत्तर-वैदिक-काल की जाति-व्यवस्था में ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों की स्थिति

यह हम पहले कह आये हैं कि वैदिक-काल में वर्ण-अयदस्या नहीं थी, परन्तु वेद में वर्ण-अयवस्था-सम्बन्धी विचार अवस्य था। "बाह्यणोऽस्य मुखमासीत् बाहू राजन्यः कृतः"—यह ऋग्वेद का मंत्र इस विचार को ही सूचित करता है। यह विचार बाह्यण-प्रन्थों तथा उपनिषदों के काल में, जिसे हम उत्तर-वैदिक-काल कह आये हैं, क्रिया का रूप धारण कर गया। इस उत्तर-वैदिक-काल में बाह्यण-अत्रिय-वैदय-शूब वर्णों का उसी प्रकार सामाजिक परीक्षण होने लगा जैसे आजकल के समाज में समाजवाद (Socialism) तथा कम्यूनिज्म (Communism) का परीक्षण हो रहा है। उत्तर-वैदिक-काल के दो प्रसिद्ध प्रन्थ है जो उस समय की सामाजिक-अयवस्था पर प्रकाश डालते हैं। एक हैं, बाह्यण-प्रन्थ तथा दूसरे हैं, उपनिषद्। बाह्यण-प्रन्थ उस समय की बाह्यणों की कृतियों हैं, उपनिषद् उस समय के क्षत्रियों की कृतियों हैं। बाह्यण-प्रन्थों से बाह्यणों का महत्व प्रदर्शित होता है, उपनिषदों से क्षत्रियों का महत्व प्रदर्शित होता है।

इन दोनों ग्रन्थों के झध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि ऋग्वेद-काल के बाद जब वर्ण-व्यवस्था क्रियात्मक रूप में झायी तब वर्णों में जन्मगत भेद नहीं था, कमंगत मेद ही था, अच्छे कमं वाला बाह्मण

हो सकता था, बुरे कर्म वाला अपने वर्ण से गिर जाता था। इस समय धर्म-कर्मका काम बाह्मण के मुपूर्वथा, ग्रीर बाह्मण ने धर्मके क्षेत्र में यज्ञ-यागादि तथा भनेक प्रकार के विधि:विधान-भनुष्ठान बनाकर धार्मिक विधानो को मत्यन्त जटिल बना दिया था। उस जटिलता के नमूने ही ब्राह्मण-ग्रन्थ है। घार्मिक विधि-विधानो की इस जटिलता को देख-कर उस समय के कुछ क्षत्रिय राजाको ने घार्मिक-क्षेत्र में भी चिन्तन श्रूक किया। इन राजाश्रो मे जनक, श्रश्वपति, कैकेय श्रादि का नाम सुख्य है। इनकी खोजो का परिणाम ब्रह्म, पुनर्जन्म, ब्रात्मा श्रादि तत्व हैं भौर इन तत्वों को इन क्षत्रिय राजाओं ने उपनिषदों के रूप मे सर्व-साधारण के सम्मुख रखा। उपनिषदो को पढने से जगह-जगह पता चलता है कि बाह्मण लोग ब्रह्म-विद्या सीखने के लिये क्षत्रिय राजाओं की शरण में गये। राजा जनक के पास श्वेतकेत तथा याज्ञवल्क्य स्रादि बाह्मण ग्रध्यात्म-विद्या का उपदेश लेने गये, राजा कैंकेय ग्रश्वपति के पास प्राचीनशाल, मत्ययज्ञ, इन्द्रबुम्न भादि बाह्मण गये। इस काल में बाह्मणों के यज्ञ-यागादि तथा क्षत्रियों की अध्यात्म-विद्या की चर्चा करते हुए एक उपनिषद् मे कहा है कि ये यज्ञ-यागादि जिन पर ब्राह्मण लोग बहुत बल देते है--'प्लवा ह्यते अदृढा यज्ञरूपा.'--ऐसे बेडे है जिनमे भव-सागर को पार नही किया जा सकता।

कहने का श्रीभप्राय यह है कि ब्राह्मण-ग्रन्थो तथा उपनिषदों के समय वर्ण-व्यवस्था का श्रीगरीश हो गया था, श्रीर ब्राह्मणों श्रीर क्षत्रियों में श्राध्यात्मक-क्षेत्र में भी एक-दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति चल पड़ी थी। ब्राह्मण लोग यज्ञ-यागादि पर बल देते थे, क्षत्रिय लोग ब्रह्म-ज्ञान श्रादि पर बल देते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मण लोग मसाज में श्रपनी सबसे ऊची स्थिति बनाने में श्रीर क्षत्रिय श्रपनी ऊची स्थिति बनाने में श्रीर क्षत्रिय श्रपनी ऊची स्थिति बनाने में श्रीर क्षत्रिय

यह वाद-विवाद बौद्ध-काल तक चलता रहा। बौद्ध-काल के साहित्य मे जगह-जगह बाह्मणो की निन्दा की गई है। उपनिषद्-काल से लेकर बौद्ध-काल तक क्षत्रियों का प्रावत्य रहा, वे शारीरिक वल में ही नही, ग्राध्यात्मिक-क्षेत्र में भी भपना सिक्का जमाने का प्रयत्म करते रहे। जातक-कथाओं में क्षत्रियों को सबसे उच्च वर्ण कहा गया, बाह्मणों के लिये 'नीच बाह्मण'-'तुच्छ-बाह्मण' भादि शब्द प्रयुक्त किये गये।

#### ४. स्मृतियों तथा धर्मशास्त्रों के काल की जाति-व्यवस्था (जन्म के बाधार पर चार जातियाँ)

उपनिषदों के काल से लेकर बौद्ध-काल तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों में अपनी-अपनी स्थित को एक-दूसरे से ऊचा कहने-कहलाने के प्रयत्न होते रहे, और इसमे क्षत्रियों का पक्ष प्रवल रहा । परन्तु इसके बाद स्मृतियों का काल आया । इस काल में ब्राह्मणों का पक्ष प्रवल हो गया और उनकी स्थिति समाज में सर्वोपरि मानी जाने लगी। यह किस प्रकार हुआ—यह बात कल्पना का विषय है परन्तु फिर भी उस कल्पना का थोडा-बहुत आधार है। वह आधार क्या है?

भारत मूलतः षर्म-प्रधान देश है भौर जो व्यक्ति या जो समुदोय सिर्फ धर्म-कार्य में लगा हुआ हो उसके सामने सिर भुकाना इस देश की परम्परा का स्वभाव है। यह बात अन्य देशों में भी पायी जाती है, प्राचीन-काल में तो विशेष रूप से पायी जाती थीं। आह्मणों का काम क्योंकि सिर्फ धर्म-कार्य था, क्षत्रियों का धर्म के क्षेत्र में केवल पदार्षण था, उनका असली क्षेत्र देश-रक्षा था, इसलिए अन्त में ब्राह्मणों को सर्वोपरि माना जाने लगा।

ब्राह्मणों की स्थिति उभर माने का दूसरा कारण यह था कि क्षत्रियों का प्रतिनिधि धर्म माब बौद्ध-धर्म हो चुका था, श्रीर बौद्ध-धर्म नास्तिकता का रूप घारण कर चुका था। भारत की भूमि में नास्तिकता को श्राधार बनाकर चलने वाले को सफलता नहीं मिल सकती थी क्योंकि यह भूमि माब तक मुख्य तौर पर म्रास्तिकता के लिए उपजाऊ रही है।

स्मृति-काल में जब बाह्मणों तथा क्षत्रियों की एक-दूसरे से बढने की प्रतिस्पर्घा समाप्त हो चुकी थी ग्रौर बाह्मणों को समाज का मूर्धन्य

माना जाने लगा था, तब ब्राह्मणी ने अपने अधिकार को अक्ष्ण बनाये रखने के लिए वर्ण-व्यवस्था को जाति-व्यवस्था का रूप दे दिया। इस कथन का क्या अर्थ है ? इस कथन का यह अर्थ है कि अब तक तो वर्ण-व्यवस्था लचकीली व्यवस्था थी, इसका ग्राधार जन्म न होकर कर्म या, यह 'ग्रनावृत' (Open)-व्यवस्था थी, शब यह लचकीली न रही, इसका ग्राधार कर्म न होकर जन्म हो गया, 'श्रावृत' (Closed)-व्यवस्था है। गई, जो जन्म का बाह्मण वह बाह्मण ही रहेगा, चाहे वह बाह्मण के कर्मकरला हो यान हो, जो जन्म का¦ शूद्र वह शूद्र ही रहेगा, बाहे वह कमें से कितना ही पंडित क्यो न हो । इस समय जाति-न्यवस्था में जो ऊंच-नीच का भेद, बड़े-छोटे का भेद, श्रहंकार की भावना, श्रेणी-बद्धता (Hierarchy) पायी जाती है, अपने को जन्म से बड़े या छोटेपन की भावना पायी जाती है, यह वैदिक-पुग की देन न होकर स्मृति-युग की देन है। इस समय स्मृतिकारों ने बाह्मणों तथा शूद्रों के प्रति क्या-क्या विधान बनाये, किस प्रकार जन्म के विचार को पुष्ट किया, ग्रपने को बडा घोषित किया—यह निम्न उदाहरणों से स्पष्ट हो जाएगा ।

"मुख से उत्पन्न होने के कारण बाह्यण सबसे बड़े हैं भीर सृष्टि के प्रभु या स्वामी है।"--(मनु १-६३)

"देवता लोग बाह्मणो के मुख द्वारा ही मोजन करते हैं, इसलिए संसार में बाह्मण से बढकर कोई प्राणी नहीं।"—(मनु १-६४)

"संसार में जो-कुछ है, सब बाह्मण का है क्योंकि जन्म से ही वह सबसे श्रेष्ठ है।"—(मनु १--१००)

"बाह्मण जो-कुछ भी खाता, पहनता और देता है, वह सब उसका अपना ही है। संसार के सब लोग बाह्मण की कृपा से ही खाते-पीते भीर केते-देते हैं।"--(मनु १-१०१)

स्मृति-काल में शूद्रों के सम्बन्ध में जो नियम बनाए गए वे अत्यन्त भैद-भाव को उत्पन्न करने वाले थे, तथा-कथित निम्न-जातियों पर प्रत्याचार करने वाले थे। उदाहरणार्थ, इन नियमों में कहा गया था कि ब्राह्मण निःसंकोच शूद्र का घन ले ले, क्योंकि शूद्र का प्रपना कुछ नही, उसका सब घन उसके स्वामी (ब्राह्मण) का है। — (मनु ८-४१७)

मनुस्मृति, ग्रध्याय ८, श्लोक २७० में लिखा है कि यदि शूद्र द्विजातियों को कडी ग्रर्थात् चुभने वाली बात कहे तो उसकी जीभ काट बालनी चाहिए क्योंकि वह निकृष्ट ग्रंग से उत्पन्न हुन्ना है।

इस समय के विधानों में घूदों को सब प्राधकारों से विचत किया गया, धन्यों के विषय में नहीं लिखा गया, इसका कारण यहीं हो सकता है कि श्रेणी-श्रृंखला में जो सबसे नीचे के स्तर पर था उसे जब सब ग्राधकारों से वंचित कर दिया गया, तो ऊपर के स्तरों के, वैदयों तथा क्षत्रियों के घषिकार इसी तुलना में धपने-ग्राप कम हो गये। सब से नीचे वाले को जब घकेला, तब उससे ऊपर वालों को भी घपेक्षाकृत उतना ही नीचा हो जाना स्वाभाविक था।

यद्यपि स्मृति-काल मे अन्म की जाति का विचार प्रवल हो गया,
तो भी इसका यह मतलब नहीं कि कमं से वर्ण-क्यबस्था का विचार
सर्वथा लुप्त हो गया। इस काल मे दोनो विचार-धाराएँ धापस
में टक्कर लेती रहीं, दोनो विचार विचारात्मक दृष्टि से तथा
कियात्मक दृष्टि से इस समय पाये जाते हैं। स्मृतियों में जन्म से
जाति की बात पाई जाती है, कमं से जाति की बात भी पायी
जाती है। दोनो प्रकार की बातों का पाया जाना सिद्ध करता है
कि यद्यपि इस काल में जन्म की प्रधानता हो चली थी, तब भी
कमें सिद्धान्त को लेकर दोहाई देने वालों की कमी न थी। इतना
ही नहीं कि विचार-क्षेत्र में दोनों प्रकार के लोग उस समय मौजूद
थे, किया के क्षेत्र में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जो बाह्मण
होते हुए ग्रन्थ जातियों में क्याह-शादी को अनुचित नहीं समस्रते

थे। उस समय भी भ्रनेक भ्रन्तर्जातीय विवाह होते थे। ये भ्रन्तर्जातीय विवाह दो तरह के थे--- ग्रनुलोम तथा प्रतिलोग । ग्रन्तोम-विवाह वे थे जिनमें उच्च कूल का पूरुष नीच कूल की कन्या से विवाह करता था, प्रतिलोम-विवाह वे थे जिनमे नीच कुल का पुरुष उच्च कुल की कन्या से विवाह करता था । इस समय अनुलोग विवाह स्मृति द्वारा अनुमोदित समभे जाते थे, प्रतिलोम नहीं, परन्तु होते दोनो थे। उदाहरणार्थ, शिव पूराण ( उत्तरार्ध, शब्याय ३० ) में लिखा है कि पिप्पताद बाह्मण ने क्षत्रिया पद्मा मे विवाह किया। देवी भागवत पुराण (स्कथ ४) मे लिखा है कि विज्वामित्र ने देवलोक की ग्रप्सग मेनका से शकून्तला को उत्पन्न किया जिसका राजा दृष्यन्त से विवाह हमा। दृष्यन्त कापूत्र भरत हुन्नाजिससे इस देश कानाम भारत पडा। ये **मन्**लोम विवाहो के उदाहरण है। इसी प्रकार प्रतिलोम विवाह भी होते थे। उदाहरणार्थ, भागवत पूराण (स्कथ ११२१) में लिखा हैं कि राजा नीप क्षत्रिय थे, उन्होंने बाह्मण गुकाचार्य की पुत्री कृत्वी से विवाह किया जिससे ब्रह्मदत्त उत्पन्न हुन्ना। इसी कुल मे मुद्गल उत्पन्न हुम्रा जिसके नाम पर बाह्मणो का मौद्गल्य गोत्र चला।

वर्तमान-काल की जाति-व्यवस्था

( जात-पात ) स्मृतियो तथा धर्मजास्त्रो के काल को भारतीय इतिहाम का मध्य-युग कहा जा सकता है। मध्य-युग के बाद से वर्तमान-काल तक जाति-व्यवस्था की जटिलता दिनो-दिन बढ़ती गई। इस काल में जाति-व्यवस्था निह्नित रूप से कर्म-परक न रहकर जन्म-परक हो गई। जातियो के जन्म-परक होने के बाद ध्रमुलोम तथा प्रतिलोम विवाहो का सर्वथा निषेघ हो गया**ा** प्रत्येक जाति ग्रपनी जाति मे ही विवाह सम्बन्घ कर सकती थी, अपनी जाति के बाहर नही। ब्राह्मण बाह्मणो में ही बिवाह-सम्बन्ध करता था, क्षत्रिय क्षत्रियो में, वैश्य वैश्यो तथा शुद्र शुद्रो मे । जातियो के भोजन के सम्बन्ध में भी प्रतिबन्ध

बने । रोटी-बेटी का व्यवहार अपनी जाति में सीमित हो गया । इस काल में प्रतिबन्ध के नियम इतने बढ़े कि अछतपन की एक नवीन समस्या ने जन्म ले लिया। एक दृष्टि से यह कहना ग्रसंगत न होगा कि अछ्तपन की समस्या जाति-व्यवस्था की ही उपज है। अभी तक चार जातियां थी । श्रब प्रत्येक जाति में उप-जातियां बनने लगी । प्रत्येक जाति तथा उपजाति की अपनी-अपनी बिरादरी थी. जो विरादरी के नियमो का उल्लंघन करता था उसे बिरादरी से बहिष्कृत कर दिया जाता था। इस बहिष्कार के भय के कारण जाति-उपजाति के समर्थको का बल बढता गया । इस समय ब्राह्मणों में गौड, सारस्वत, सनाढ्य, सरजुपारी, कान्यकृब्ज ब्रादि भ्रनेक भ्रवान्तर भेद हो गये, क्षत्रियो में चोपडा, बेरी, बुजाही, सरीन, कपूर, खन्ना, कक्कड श्रादि श्रनेक श्रवान्तर भेद हो गये, वैश्यो मे अग्रवाल, श्रोसवाल, मवाल, बारहसेनी, लोहिया ग्रादि अनेक प्रवान्तर भेद हो गए। इन भेदो का ग्राधार कही भौगोलिक है, कही भौर कुछ । उदाहरणार्थ, मत्स्य पुराण मे पजाब के हरियाना प्रान्त (रोहतक, पानीपत, करनाल, सोनीपत) तथा मारवाड़ एवं मरयु नदी के उत्तर के प्रदेश को गौड प्रदेश कहा गया है। इस प्रदेश के ब्राह्मण अपने को गौड ब्राह्मण कहने लगे और गौडों में ही रोटी-बेटी का व्यवहार करने लगे। सरस्वती नदी के किनारे एहने के कारण सारस्वत तथा कन्नौज में रहने के कारण कान्यकृब्ज ब्राह्मण हुए। ये लोग जब अपने-अपने प्रदेशों से चले भी गये तब भी अपने को उसी नाम से पुकारते रहे। क्षत्रियों में बेरी जाति के लोग वे थे जिनका पूर्वज बेरी के नीचे पैदा हुआ। बुंजाही खत्री तथा सरीन सन्त्रयों की उत्पत्ति की भी एक कहानी है। बादशाह धलाउद्दीन खिलजी खत्रियों मे विभवा-विवाह चलाना चाहते थे। कुछ खत्रियों ने इसका विरोध किया, भीर ५२ खत्रियों का एक प्रतिनिधि मंडल इस विरोध का आवेदन-पत्र लेकर बादशाह के पास गया। इन बावन खत्रियों की. सतान बावनजी या 'बुंजाही' कहलाई, और जिन खत्रियों ने बादशाह

के कानून को मान लिया वे 'शरम माईन' कहलाये। यही 'शरम माईन' बिगड कर 'सरीन' बन गया। लोहे के ब्यापारी 'लोहिया' कहलाये, कपड़े के ब्यापारी 'कापडिया' कहलाने लगे। इस प्रकार कहीं भौगोलिक कारण से, कही ब्यापार-धर्ष के कारण से, कही ग्रन्थ किसी कारण से मध्य-युग से बतंमान-युग तक जातियों-उपजातियों का विभाग दिनो-दिन बढ़ता चला ग्या और इन जातियों-उपजातियों के अपने-अपने विधि-विधान बनते चले गये जिनसे मनुष्य-मनुष्य तथा जाति-जाति में भेद बढ़ता चला गया। भ्राज जाति-व्यवस्था अपने सम्पूर्ण दोपों के साथ हिन्दू-समाज को घेरे हुए है और एक बिल्कुल 'म्रावृत' (Closed)-व्यवस्था बन गई है।

#### ६. वर्तमान-काल में जाति-ध्यवस्था में परिवर्तन के तत्व

जपर हमने जो विवेजन किया उससे स्पष्ट है कि जाति-अयबस्था का रूप सनातन-काल से एक-सा नही रहा। वैदिक-काल मे इसका रूप धार्य और दास का था, उत्तर-वैदिक-काल मे इसका रूप धार्य और दास का था, उत्तर-वैदिक-काल मे इसका रूप धार्य और दास का था, उत्तर-वैदिक-काल मे इसका रूप धार्य-अयवस्था' (Open Caste System) का था, स्मृति-काल मे इसका रूप धार्य जाति-अयवस्था' (Closed Caste System) का हो गया, बतंमान-काल मे यह जाति-उपजातियों का रूप धारण कर गया। धाज खाति-अयबस्था फिर धनेक परिवर्तनों में से गुजर रही है, विगठित हो रही है। धाज इस व्यवस्था में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनके धनेक कारण है, जिनमें से मुख्य-मुख्य कारण निम्न हैं:—

(क) सजाजवादी विचारवारा (Socialism)—हमने देखा कि भारतीय-समाज के वर्गीकरण में तीन तस्य हैं—कर्म, जन्म तथा भेद-भाव। वर्ण-व्यवस्था तथा जाति-व्यवस्था दोनो में भेद-भाव का तत्व भाषारभूत तस्य है। इन दोनो प्रकार की व्यवस्थाओं का अभिजाय यह है कि मनुष्य मनुष्य में भेद तो है और रहेगा, परन्तु वर्ण-व्यवस्था

इस भेद का ग्राघार कर्म (Effort) बतलाती है, जाति-व्यवस्था इस भेद का ग्राघार जन्म (Birth) बतलाती है। मनुष्य-मनुष्य में जो भेद दिखलाई देता है, वर्ण-व्यवस्था उस भेद के कारक-तत्व 'कर्म' पर बल देती है, जाति-व्यवस्था उस भेद के कारक-तत्व 'जन्म' पर बल देती है। जब तक 'व्यक्तिवाद' (Individualism) का बोलबाला था, तब तक 'कर्म' या 'जन्म' पर बल दिया जाता था, ग्रीर मनुष्य-मनुष्य के भेद को स्वाभाविक माना जाता था। ग्राज समय बदल चुका है। ग्राज 'व्यक्तिवाद' की जगह 'समाजवाद' (Socialism) का बोलबाला है। ग्राज 'कर्म' या 'जन्म' का भेद तो क्या, हर प्रकार का भेद-भाव मिटाया जा रहा है, इमलिए वर्तमान-युग की विचार-धारा वर्ण-व्यवस्था तथा जाति-व्यवस्था दोनो को एक जबर्दस्त टक्कर दे रही है। ग्राज की विचार-धारा का कहना यह है कि मनुष्य-मनुष्य में भेद जन्म या कर्म के कारण नहीं, यह भेद हमारा, समाज का बनाया हुआ है, ग्रीर जैसे समाज ने इसे बनाया है वैसे समाज इसे दूर भी कर सकता है।

(ल) नगरीकरण तथा उद्योगीकरण (Urbanization and Commercialization)—जब देश में बड़े-बड़े नगर नहीं बने थे, छोटे गाँव या छोटे शहर थे, तब जाति-व्यवस्था का चल सकना आसान था। हर-कोई हर-दूसरे को जानता था। अगर किसी का हुक्का-पानी बन्द कर दिया गया, तो वह मुसीबत मे फंस जाता था, इसलिए हर-कोई जाति के बन्धन में बधा रहता था। धब बड़े-बड़े नगरों के बन जाने से कोई किसी को जानता-पहचानता नहीं, और जाति के बन्धनों को तोड देने से किसी का कुछ बनता-बिगडता नहीं। इसीलिए गाँवों में जहाँ छोटे समुदाय हैं, जहाँ वैयक्तिक-संपर्क हो सकता है, वहाँ जाति के बन्धन कठोर हैं, शहरों में वे बन्धन शिथल हो जाते हैं। इसी प्रकार व्यापार के एक जगह केन्द्रित हो जाने से शहरों में भीड़-मडक्का हो जाता है, अपने चूल्हे पर ही रोटी पका सकना कठिन हो जाता है,

होटलो में लोग खाते हैं, रेलो में भंगी-चमार-ब्राह्मण एक-साथ कन्धे-से-कथा मिलाकर सफ़र करते हैं, ब्यापार-घन्धे के लिए हर-किसी के संपर्क में ग्राना पडता है—इन कारणो से भी जाति के बन्धन ढीले पड़ते जा रहे हैं।

- (ग) प्राधिक-दुष्टिकोए। की प्रधानता (Ecohomic view of life)—श्रत्र जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण श्रार्थिक होता चला जा रहा है। धन-सम्पत्ति मे जो बडा है वह बडा, बिना पैसे वाला किसी काम का नहीं। इस हालत में नीच वश का भी सम्पत्तिशाली होने से उच्च-स्थिति प्राप्त कर सकता है। ग्राज धन सभी कमा सकते है-उच्च-कूल के भी, नीच-कूल के भी। जो धन कमा ले वह किसी खानदान का क्यो न हो, सब उसके साथ खाते-पीते हैं, उसके साथ उठते-बैठते हैं। ग्रार्थिक-दृष्टिकोण की प्रधानता से जन्म की जाति-व्यवस्था ग्रपने-ग्राप ढीली पडती जा रही है, ग्रगर कहा जाय कि 'जाति-प्रया' (Caste system) के स्थान मे 'वर्ग-प्रथा' (class system) श्राती जा रही है, तो कोई अत्युक्ति नही । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शृद्ध श्रादि जातियो के स्थान मे धनी-निर्धन—ये वर्ग बनते जा रहे है, श्रीर जैसे कर्म की वर्ण-व्यवस्था के बाद जन्म की जाति-व्यवस्था ग्राई, वैसे ही ग्रब जाति-व्यवस्था के बाद वर्ग-व्यवस्था ग्रा रही है, ग्रीर इस सारे विकास की दिशा वर्ण से जाति, जाति से वर्ग श्रीर वर्ग से वर्ग-हीन समाज की तरफ जा रही है। म्रन्य देशों में तो यह प्रक्रिया हो ही रहीहै, भ्रपने देश में भी सामाजिक-विकास का प्रवाह इसी दिशा की तरफ है।
- (घ) साधुनिक-शिक्षा का प्रभाव—प्राचीन-शिक्षा और साधुनिक-शिक्षा में यह भेद है कि प्राचीन-शिक्षा ब्राह्मणों के हाथ में थी, नवीन-शिक्षा का सगठन भारत के अग्रेज शासकों ने किया था। शिक्षा के ब्राह्मणों के हाथ में होने के कारण प्राचीन-शिक्षा में जाति-व्यवस्था के प्रति शिष्यों में अटूट श्रद्धा-भिन्त भर दी जाती थी और उस शिक्षा में पले हुए जाति-व्यवस्था को एक अटल-व्यवस्था सममते थे। अछूतों को

दूसरे लोग ही प्रछूत नहीं समक्षते थे, अछूत स्वयं अपने को पिछले जन्म के किन्ही पापो के कारण अछूत समक्षते थे। अग्रेजो के युग मे आधुनिक-शिक्षा का प्रचार हुआ, शिक्षा बाह्यणो की ही बपौती नही रही। प्राचीन-शिक्षा धर्म-मूलक थी, आधुनिक-शिक्षा धर्म-निरपेक्ष है। इसका जहाँ धर्ममात्र को घक्का लगा, वहाँ जाति-व्यवस्था को भी इसका धक्का पहुँचा और इस शिक्षा मे पले हुओ की इस व्यवस्था में श्रद्धा नहीं रही। इसके अतिरिक्त अग्रेजी-शिक्षा ने कुछ नवीन विचारों को जन्म दिया जो जाति-व्यवस्था के विरोधी विचार थे। उदाहरणार्थ, जाति-व्यवस्था मनुष्य-मनुष्य के बीच भेद-भाव पर टिकी हुई थी, वर्तमान-शिक्षा ने एकता, समानता, विषव-बन्धुत्व, स्वतन्त्रता, लोकतन्त्रता आदि पश्चिम की हवा को यहाँ ला बहाया। इन नवीन-विचारों के प्रभाव से भी जाति-व्यवस्था के बन्धन ढीले पडने लगे।

- (इ) समाज-मुषार ग्रान्दोलन —ग्राष्ट्रिनिक-शिक्षा का प्रभाव यह हुग्रा कि समाज सुघार श्रान्दोलन उठ खडा हुग्रा। बगाल में ब्राह्मो-समाज तथा उत्तर-भारत मे श्रार्य-समाज ने समाज-रूपी वृक्ष में घुन की तरह लगे हुए ग्रन्ध-विश्वासो को निकाल कर बाहर करना शुरू किया। इन ग्रन्ध-विश्वासों मे जन्ममूलक जात-पाँत भी थी। इसी ग्रादोलन के उग्र-रूप मे पंजाब में जात-पाँत-तोड़क-मडल का जन्म हुग्रा, जिसके सदस्य यह वृत लेते थे कि वे जन्म की जाति को तोड कर विवाह करेंगे।
- (थ) राजनैतिक आन्वोलन—ग्राधुनिक-युग में देश को स्वतन्त्र करने के लिए महात्मा गाधी ने जो राजनैतिक आन्दोलन उठाया, अस्पृश्यता-निवारण उसका एक अभिन्न अग था। यह हम पहले ही कह श्राये हैं कि जन्म की जात-पाँत का एक आवश्यक परिणाम अस्पृश्यता का विचार था। जब अस्पृश्यता के विचार को धक्का लगा तब जाति-व्यवस्था का ढीला पड जाना स्वाभाविक था। इस दृष्टि से राजनैतिक आन्दोलन ने जाति-व्यवस्था के विघटन में बहुत बडा हिस्सा लिया।

(छ) राज्य की तरफ़ से कानूनी हस्तक्षेप-जाति-व्यवस्था के धनुसार अन्तर्जातीय विवाह नहीं हो सकते थे, और अस्पृश्य कहे जाने वाले व्यक्तियों को मन्दिरों में अन्य दिजातियों के समान प्रवेश करने का, उनके कुँग्रो से पानी भरने का प्रधिकार नही था। ग्राधुनिक-युग में इस प्रकार की रूढियों को राज्य भी बर्दाइत नहीं कर सकता था श्रौर इन सब बातो को रोकने के लिए कानून बनने लगे जिनसे जाति-व्यवस्था की जड़ें हिल गईं। उदाहरणार्थ, धन्तर्जातीय-विवाहो को वैष करार देने के लिये १८७२ में 'विशेष-विवाह-प्रधिनियम' (Special Marriage Act) बना । १६२३ तथा १६५४ मे इस कानून मे फिर संशोधन हुआ। इस कानून की चर्चा आगे के एक अध्याय में की गई है। जाति के एकाधिकार पर प्रहार करने के लिए १८५० में 'जाति नियोंग्यता निवारक भिषानियम' (Caste Disabilities Removal Act) बना, भीर १९५५ में 'मस्पश्यता (अपराध) ग्रधिनियम' (The Untouchability-Offence-Act) बना जिसके ग्रमसार किसी प्रकार की भी अस्पृश्यता को कियात्मक रूप देने वालो को अपराधी घोषित कर दिया गया । उक्त अधिनियम मे कहा गया है कि मगर कोई किसी को सार्वजनिक स्थान पर जाने से या स्नान करने से जात-पाँत की वजह से रोकेगा तो उसे छ महीने की सजा भीर ४०० रु० तक का दण्ड दिया जा सकेगा।

इस प्रकार हमने देखा कि भारतीय समाज का वर्गीकरण पहले आर्य तथा शूद्र के रूप में, फिर वर्ण-व्यवस्था के रूप मे, फिर जाति-व्यवस्था के रूप में से होता हुआ ग्रन्य देशों की तरह अब वर्ग-व्यवस्था का रूप धारण करता जा रहा है। हमने यह भी देखा कि जाति-व्यवस्था अपने पहले रूप में अब नहीं टिक सकती, इसका विगठन होता जा रहा है, और वर्तमान-युग में ऐसे तत्व बढते जा रहे हैं, जो इसके वर्तमान रूप को परिवर्तित करते जा रहे हैं। इन सब परिवर्तनों के हो जाने से ऐसा समय दूर नहीं रहेगा जब जाति-व्यवस्था नाम-मात्र की रह जायगी।

#### प्रश्न

- १. क्या जाति-ज्यवस्था भारत के वैदिक-काल से खली आ रही है ?
- २. भिन्न-भिन्न समयों में भारतीय समाज के वर्गीकरण के सम्बन्ध में भाग क्या जानते हैं ?
- जाति-व्यवस्था बदलती रही है—इस पर ग्रपने विचार प्रकट कीजिए।
- ४. वर्तमान-पुग में जाति-स्यवस्था में परिवर्तन करने वाले तत्व क्या है ?

## संयुक्त-परिवार

( JOINT FAMILY )

## १. संयुक्त-परिवार की उत्पत्ति का कारण तथा रूपै

परिवार का ब्राधार 'प्राणि-झास्त्रीय एषणाएँ (Biological drives) तथा 'ब्राधिक-एषणाएँ (Economic drives) है। कैंमे ? स्त्री-पुरुष में 'यौन-भावना' (Sex drive) है, जब तक उसे कानूनी रूप न दे दिया जाय, तब तक समाज उसको खुली छूट नही देता। स्त्री-पुरुप में 'सन्तान की कामना' (Procreative drive) भी है। ये दोनों एपणाएँ परिवार का 'प्राणि-आस्त्रीय' (Biological) ग्रावार हैं। इसके ग्रानिरिक्त भूख-प्यास हर-एक को लगती है, सुरक्षा हर-एक चाहता है। भूख-प्यास कर प्राणे 'बुभुक्षा' (Hunger drive) तथा जीवन की रक्षा के कारण 'सुरक्षा' (Security drive) की चाह भी हर-एक मे है। ये दोनों एपणाएं 'ग्राधिक' (Economic) हैं। इन 'प्राणि-झास्त्रीय' तथा 'ग्राधिक' एषणाग्रो को पूर्ण करने के लिए ही परिवार बना है। इन एषणाग्रो के परिणाम-स्वरूप परिवार में पति-पत्नी तथा सन्तान होते हैं, परन्तु शुरू-शुरू में जब परिवार का सगठन हुग्रा था, उस समय केवल इन तीन से तो परिवार नहीं बना होगा। उस समय एक-दो के नहीं, ग्रानेक व्यक्तियों के सहयोग से भोजन-प्राप्ति जैसा कठिन कार्य सम्पन्न होता

होगा। एक पूर्वज से परिवार के जितने लोग उत्पन्न हुए ये सब साथ रहते थे। एक माता-पिता की पाँच सन्तानें हैं। खेती-बाड़ी के लिए माता-पिता के अतिरिक्त इन पाँची की जरूरत थी। कोई हल चलाता, कोई बीज बोता, कोई खेती की रक्षा करता सब कामों के लिए ग्रधिक-से-ग्रधिक व्यक्तियों की ग्रावश्यकता थी। सब की साभी जमीन में तो सब का ग्रजर चल सकता था, जमीन के दकड़े-दुकडे करके कौन कितना पैदा कर सकता वा ? परिवार में पति-पत्नी भ्रौर बच्चे ही नही थे, चाचा-ताऊ भ्रौर उनके बच्चे-सब शामिल थे। किसी के सन्तान न होती तो गोद ले लेता था, श्रकेला भादमी कहाँ तक काम कर सकता है, इस प्रकार का जो परिवार बनता था, उसे 'सयुक्त-परिवार' (Joint Family) कहते थे। इस परिवार मे म्रविवाहिता कन्याएँ भौर भविवाहिता बहनें भी शामिल थीं। यह ध्यान देने की बात है कि बहनें तथा कन्याएँ तभी तक इस 'सयुक्त-परिवार' का श्रंग मानी जाती थी जब तक उनका विवाह नही हो जाता था। विवाह होने के बाद वे दूसरे परिवार का ग्रंग बन जाती थी, ग्रौर पहले परिवार से उनका सपत्ति-सबधी कोई लगाव नहीं रह जाता था. जिस परिवार मे वे जाती थीं उसमें भ्रपने पति के साथ उनका भाषिक-सम्बन्ध जुड़ जाता था। विवाह से पहले ही कन्या भ्रपने पिता या भाई से अपने भरण-पोषण की अधिकारिणी हो सकती थी, उसके बाद इस परिवार का उसके भरण-पोषण के साथ कोई सम्बन्ध नही रह जाता था। जब तक वह इस परिवार मे थी तब तक वह ग्रपने पिता तथा भाई पर ग्राश्रित थी, जब वह उस परिवार मे बली गई तब अपने पति पर आश्रित हो गई; यहाँ रहते हुए वह यहाँ के देवी-देवताओं की पूजा करती थी, वहां जाकर वह वहाँ के देवी-देवतायों की पूजा करने लगी; यहाँ की जिम्मेदारी यहाँ छोड़कर उसने वहाँ कीजिम्मेदारी ले ली । इस दृष्टि से 'सयुक्त-परिवार' में लडकी उम्र भर लडकी नही मानी जाती, भरण- पोषण की दृष्टि से लडकी के साथ तभी तक लड़की का-सा व्यवहार होता है अब तक वह किसी की पत्नी नहीं बन जाती। पत्नी बनते ही उसके भरण-पोषण का किसी प्रकार का उत्तरदायित्व संयुक्त-परिवार पर नहीं रहता।

### २ संयुक्त-परिवार की परिभाषा

संयुक्त-परिवार के स्वरूप के सम्बन्ध में हमने ऊपर जो-कूछ लिखा उससे उसकी परिभाषा स्पष्ट हो जाती है। संयुक्त-परिवार वह कहलाता है जिसमें परिवार के सब सदस्यों की सम्पत्ति तथा ग्राय सम्मिलित हो, वे एक-साथ रहे, उन सबकी एक जगह रसोई बनती हो, उनका मार्थिक तथा सामाजिक जीवन एक-सूत्र में बँधा हो। झार्थिक तथा सामाजिक-जीवन एक-सूत्र में बँघा हो---इसका क्या धर्य है ? इसका यह श्रयं है कि जो-कोई कमाये वह उसकी अपनी निजी कमाई न समस्री जाकर सबकी साभी कमाई समभी जाय, धगर किसी एक भाई की लड़की या उसके लड़के की शादी हो तो किसी भाई के निजी लड़के-लडकी की शादी न समभी जाकर वह उस परिवार के लडके-लड़की की शादी समभी जाय। इसका भर्य यह हुआ। कि संयुक्त-परिवार के सदस्यों के कुछ कर्राव्य तथा कुछ प्रधिकार भी होते हैं। संयुक्त-मरिवार के बड़े सदस्यों का कर्तव्य है कि छोटो की व्याह-शादी अपने लडको की तरह करे, त्रौर छोटो का अधिकार है कि वे अपनी शिक्षा-दीक्षा, ब्याह-शादी पर ग्रपने माता-पिता से ही नही, परन्तु परिवार के बड़े से हर प्रकार की सहायता की ग्राशा करें। इस दृष्टि से संयुक्त-परिवार की परिभाषा कुछ विस्तृत हो जाती है। हमने कहा था कि सयुक्त-परिवार वह है जिसमे परिवार के सब सदस्य एक-साथ रहें, उन सबकी एक जगह रसोई बनती हो। अगर वे एक-साथ न भी रहे, एक-साथ न भी खार्ये-पीयें, कोई गाँव मे भौर कोई अम्बई-कलकत्ता मे रहता हो, परन्तु भगर बाधित तौर पर उन्हें उन कर्तब्यों तथा ष्रिकारों को निषाहना पड़ता हो को एक-साथ रहते हुए उन्हें निषाहने होते हैं, तब भी वे संयुक्त-परिवार के ही भग समके बायेंगे। 'सबुक्त-परिवार' की परिमाषा करते हुए हमें समक लेना चाहिये कि यह एक कानूनी-शब्द है, और सिर्फ़ इतना कह देने से कि मैं संयुक्त-परिवार का सदस्य नहीं रहना चाहता कोई व्यक्ति सयुक्त-परिवार की भगनी कानूनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकता। 'संयुक्त-परिवार' का भाषार धन-सम्पत्ति-अमीन-भागदनी है, भौर क्योंक दीवानी के सब मुकदमे धन-सपत्ति सम्बन्ध होते हैं इसलिये दीवानी की भदालतों में 'संयुक्त-परिवार' से सम्बन्ध रखने वाले भनेक मुकदमें लड़े जाते हैं।

## ३. संयुक्त-परिवार की मुख्य-मुख्य बातें

परिवार दो तरह का होता है—'संयुक्त' तथा 'वैयक्तिक' । 'संयुक्त' में पिता-माता-पुत्र-वाचा-ताऊ सब एक-साथ रहते, एक-साथ खाते-पीते हैं। 'वैयक्तिक' में शादी होने पर पुरुष तथा स्त्री— इनका 'वैयक्तिक' या 'एकाकी' परिवार बन जाता है। 'वैयक्तिक' परिवार में दो ही व्यक्ति होते हैं, और उन्हीं दो का सिलसिला आये चलता है, इसलिए उसमें प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति की कोई समस्या नहीं उठती, 'संयुक्त-परिवार' में क्योंकि अनेक व्यक्ति होते हैं, इसलिए उनकी सामाजिक तथा आर्थिक समस्याएँ प्रायः उठा करती हैं। अदालतों में दीवानी के मुकदमें उपादातर 'संयुक्त-परिवार-प्रवा' से सम्बन्ध रखते हैं। क्योंकि परिवार की मुख्य समस्याओं का सम्बन्ध 'संयुक्त-परिवार' से है इसलिये इसकी मुख्य-मुख्य वातों को हम यहाँ लिख रहे हैं।

(क) संयुक्त-निवास तथा संयुक्त-शोजन संयुक्त-परिवार की सबसे मुख्य बात है परिवार के सब सदस्यों का एक ही मकान में रहना भीर उन सबका एक ही जगह भोजन बनना। भगर किसी परिवार के सदस्य एक ही सकान मे रहते हैं, परन्तु उनका चौका-चूल्हा अलग-अलग है, तो वे कह सकते हैं कि वे संयुक्त-परिवार के श्रंग नहीं हैं।

- (स) सम्मिलित-ग्राय तथा सम्पत्ति—ग्राजकल जैसे ज्वॉइन्ट-स्टाक कम्पनी होती है जिसमे कई हिस्सेदार होते हैं, सब उसकी श्राय में सामित्रीदार होते हैं, कम्पनी भी सबकी सम्पत्ति समभी जाती है, इसी-प्रकार 'सयुक्त-परिवार' में ग्राय श्रलग-ग्रालग व्यक्ति की नहीं समभी जाती, सबकी साँभी समभी जाती है, परिवार की सम्पत्ति भी किसी एक की न होकर सबकी साँभी मानी जाती है।
- (ग) संयुक्त-परिवार के सदस्य—सयुक्त-परिवार मे तीन पीढ़ियाँ ध्रा जाती हैं। पिता,पुत्र तथा पौत्र, पिता के छोटे तथा बड़े भाई, उनके पुत्र तथा पौत्र—ये सब सयुक्त-परिवार के ध्रग हैं। इन पीढियों से पहले के व्यक्ति कम जीवित पाये जाते हैं, परन्तु ध्रगर कोई जीवित हो, तो वे भी संयुक्त-परिवार के ही अग समभने चाहियें।
- (घ) संयुक्त-परिवार का मुखिया या कर्ता—परिवार में जो व्यक्ति आयु में सबसे बडा होता है वह सयुक्त-परिवार का मुखिया कहलाता है। कानूनी परिभाषा में उसे 'कर्ता' कहते हैं। 'कर्ता' का अर्थ है— मैंनेजर। वह परिवार की सम्पत्ति का स्वामी न होकर उसका प्रबन्धक माना जाता है। परिवार के सब व्यक्तियों की आमदनी 'कर्ता' के पास ही जमा होती है और वही आवश्यकतानुसार परिवार के खर्वे चलाता है। किसी बच्चे की शिक्षा है, किसी बच्चे की शादी है—परिवार के सब बच्चों की शिक्षा, विवाह आदि का प्रबन्ध परिवार के कोष में से 'कर्ता' ही करता रहता है। परिवार की समस्याओं के सम्बन्ध में 'कर्ता' का निश्चय ही अन्तिम समक्ता जाता है।
- (क) संयुक्त-परिवार में बहू की स्थिति—'वैयक्तिक-परिवार' में तो बहू को सिर्फ़ अपने पित से वास्ता पडता है, परंतु 'संयुक्त-परिवार' में कहीं सास-ससुर है, कही तैय्या ससुर-सास, कही चिचया ससुर-सास, कही जेठ, कही देवर। एक ही घर में इन सबकी

मौजूदगी में बहू को सब संबंधों को निवाहना पड़ता है और वह एक विकट-स्थिति में बनी रहती है। उसका ज्यादातर समय इन्हीं लोगों की सेवा में बीतता है, अपने पति के सभ्य भी वह सब लोगों के सामने बात नही कर सकती, केवल रात को ही उसे अपने पति के दर्शन होते हैं। बहू के लिये संयुक्त-परिवार में जाना एक विकट-स्थिति में जाना है।

- (च) संयुक्त-परिवार में स्त्री-मन संयुक्त-परिवार में सब आय तथा सब सम्पत्ति सिम्मिलत परिवार की होती है, परन्तु विवाह के समय तथा विवाह के बाद समय-समय पर स्त्री को जो मेंट के तौर पर उसके मां-बाप या रिस्तेदार देते या देते रहते हैं बह स्त्री-भन कहलाता है भौर वह सम्पूर्ण परिवार का न होकर उसका निजी भन समभा जाता है। इस स्त्री-भन पर इन्कम-टैक्स भी नहीं लगता इसलिये कई भनी परिवार आय-कर से बचने के लिये अपनी निजी सम्पत्ति को भी स्त्री-भन के तौर पर दर्शा देते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि स्त्री से तो वे अब चाहेंगे भन ले सकेगे।
- (छ) संयुक्त परिवार के संबंध में उसराधिकार का १६४६ का अधिनियम— 'वैयिक्तक-परिवार' में तो पित की सम्पत्ति अपनी उपाँजत की हुई सम्पत्ति होती है, इसलिये वह अपनी वसीयत के अनुसार जिसे देना चाहे दे सकता है, परन्तु 'संयुक्त-परिवार' की सम्पत्ति को वसीयत के अनुसार किसी को नहीं दिया जा सकता, वह तो उन्हीं वारिसों को मिलती है जो उसके उत्तराधिकारी हैं। इस दृष्टि से 'संयुक्त-परिवार' के लिये उत्तराधिकार के नियम विशेष अहत्व रखते हैं। १६४६ से पहले उत्तराधिकार के नियम विशेष अहत्व रखते हैं। १६४६ से पहले उत्तराधिकार के रूप में पत्नी का लानदान की जायदाद में कोई हिस्सा नहीं था, लड़की का मी नहीं था, विधवा को सन्तान न होने पर अपना गुजारा चला सकने का अधिकार या, वेचने का अधिकार नहीं था, उसके भरने के बाद अगर दूर-से-

हूर का भी उसका कोई रिश्तेदार निकल पड़ता था तो सम्पत्ति उसको खली जाती थी। मद १६५६ के 'हिंदू-उत्तराधिकार-प्रधिनियम' (Hindu Succession Act, 1956) के मनुसार स्त्री को सम्पत्ति सम्बन्धी कई मिषकार मिल गये हैं। उदाहरणार्थ, लड़की को पिता की वसीयत न की गई प्रपत्ती कमाई सम्पत्ति में भी लड़के के बराबर का हिस्सा दे दिया गया है, भौर खानदानी सम्पत्ति में भी कुछ हिस्सा दिया गया है। विभवा को पति की खानदानी सम्पत्ति में हिस्सा दिया गया है जिस पर उसका पूर्ण-प्रधिकार होगा, वह नाहे तो उसे बेच भी सकेगी। 'हिन्दू-उत्तराधिकार-अधिनियम' के इन सब पहलुओ पर हमने मगले एक प्रध्याय मे जिसका शीर्षक है—'सामाजिक-विधान तथा उसका विवाह पर प्रभाव'—विस्तार से प्रकाश जाता है।

### ४. संयुक्त-परिवार तथा सम्पत्ति— दायमाग तथा मिताक्तरा

#### [ संयुक्त-परिवार का ग्राधारभूत-तत्व ]

हमने देखा कि संयुक्त-परिवार के जितने सदस्य होते हैं सब एक ही मकान में रहते हैं, एक जगह उनका भोजन बनता है, सबकी कमाई एक ही जगह जमा हो जाती है, एक ही देवी-देवताओं की वे बाराधना करते हैं। यद्यपि वर्तमान-पुग की बाधिक-परिस्थितियों के कारण संयुक्त-परिवार के सदस्य भी भिन्न-भिन्न स्थानों पर बाजीविकोपार्जन के लिए जाते हैं, तो भी जहाँ कहीं वे होते हैं वहाँ से अपनी आय का अधिकांश वे परिवार के उस सदस्य के पास भेजते रहते हैं जो उनके बाल-बच्चों की देख-माल करता रहता है। समय-समय पर वे बम्बई, कलकत्ता, जहाँ-कहीं भी हों वहाँ से अपने घर बाते रहते हैं, लासकर बादी-क्याह के अवसर पर, होली-दीवाली-दशहरे के ध्रवसर पर, बौर उस समय वे अपनी पूँजी परिवार के प्रचान के सामने रख देते हैं। ध्रगर किसी कारणवश संयुक्त-परिवार के सदस्य एक-दूसरे से जुदा होना चाहें, तो अपनी सम्पत्ति बराबर-बराबर बाँटकर अलग हो सकते हैं। संयुक्त-परिवार की सम्पत्ति के बँटवारे के सम्बन्ध में अपने देश में मुख्य तौर पर दो प्रकार के कानून प्रचलित हैं। एक कानून तो बंगाल तथा असम के कुछ हिस्सों में प्रचलित हैं। इसे 'दायभाग' कहते हैं। दायभाग-विधान के अनुसार पिता अपने जीवन-काल में सम्पत्ति का अखण्ड स्वामी माना गया है, वही इसका प्रबन्धक भी है, और चाहे तो अपनी इच्छानुसार उसे बेच भी सकता है। दूसरा कानून बंगाल, असम तथा दक्षिण-मारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर भारत में सर्वत्र माना जाता है। इसे 'मिताअतरा' कहते हैं। इसके अनुसार पिता के साथ उसके पुत्र भी जन्म लेते ही सम्पत्ति के मालिक माने गये हैं, पिता वश-परारा-प्राप्त सम्पत्ति को बेच नहीं सकता, अगर हर-एक अलग-अलग सम्पत्ति का मालिक बनना चाहता है, तो 'संयुक्त-परिवार' को भग करना आवश्यक है, कानूनी तौर पर 'संयुक्त-परिवार' में सपत्ति का बँटवारा 'संयुक्त-परिवार' को भग किये बिना नहीं हो सकता।

हमने ग्रभी कहा कि 'संयुक्त-परिवार' में सब सदस्य अपनी ग्राय की एक जगह एकिति कर देते हैं और इसी 'सगृहीत-द्रव्य' (Common pool) से परिवार के सब सदस्यों का खर्चा चलता है, इसी से परिवार का मुखिया सब के जादी-व्याह करता है। कई सदस्य ऐसे भी होते हैं जो कुछ कमा नहीं रहे होते। वे भी क्योंकि परिवार के सदस्य होते हैं ग्रतः उनका भी खर्चा इसी 'संगृहीत-द्रव्य' से चलता है। परिणाम यह होता है कि कई सदस्य नकारे बने रहते हैं, उन्हें इस बात की फिक नहीं होती कि उन्हें भी कुछ करना है, क्योंकि उनके गृहस्थी के कारोबार तो सब चलते ही रहते हैं। जहाँ 'सयुक्त-परिवार' के सदस्य एक ही जगह रहते हैं, सब की साँभी जमीन होती है, सब को खेती-बाडी का कुछ-त-कुछ काम करना पड़ता है, वहाँ अगर कोई सदय अपने ग्रतिरिक्त समय में, प्रतिरिक्त मेहनत से कुछ कमा-बमा लेता है, तो वह उसका निजी धन समभा जाता है। इसके ग्रतिरिक्त पत्नी विवाह के समय जोवर,

जबाहरात, कपड़े भ्रादि भ्रपने पिता के घर से लाती है वह भी उसकी निजी सम्यक्ति—'स्त्री-धन'—समभी जाती है।

देवी-देवताचो की पूजा के सम्बन्ध मे 'सयुक्त-परिवार' की यह व्यव-स्था है कि सब एक स्थान पर इकट्ठे होकर पूजा करते हैं और यदि सब लोग एक जगह पर नहीं रह रहे, माजीविका के लिए भिन्न-भिन्न स्थानों पर चले गये हैं, तो मूर्ति को बारी-बारी सब के पास भेजा जाता है, ताकि हर-एक देवता की व्यक्तिकप से पूजा कर सके।

'संयुक्त-परिवार' का, श्रायु मे जो सबसे बडा पुरुष-सदस्य होता है, यही 'सयुक्त-परिवार' की सब सम्पत्ति का 'प्रबन्धक' माना जाता है। घर के श्रान्तरिक-प्रबन्ध की देख-रेख की जिम्मेदारी उसकी स्त्री की होती है। वैसे तो श्रविकसित-समाज में सम्य-समाज की श्रपेक्षा ईमानदारी श्रधिक पायी जाती है, 'सयुक्त-परिवार' का प्रधान सबके साथ समान बर्ताव करता है, परन्तु जिसके हाथ मे सारी सम्पत्ति हो उसका बेईमान हो जाना भी सम्भव है, उसका घर की साँभी सम्पत्ति को सिर्फ श्रपना समभ लेना कोई श्राह्चयं की बात नही। कभी-कभी इस प्रमुख व्यक्ति का श्रन्य सदस्यों के साथ बर्ताव भी कठोर हो जाता है। इन दोनों कारणों से 'सयुक्त-परिवार' में भगडे उठ खडे हुश्चा करते हैं, परन्तु प्रचलित प्रथा के श्रनुसार इस मुखिया की श्राज्ञा का कोई उल्लंघन नही करता, जो वह कहता है वही दूसरे करते हैं, उसका कथन सबके लिये श्रनिवार्य तौर से शिरोधार्य होता है।

### ५. 'संयुक्त' से 'वैयक्तिक' (एकाकी)परिवार की तरफ़

इस समय भानव-समाज की जिस दिशा की तरफ प्रगति हो रही है उसमे 'सयुक्त-परिवार'-प्रथा टूटती नजर ग्रा रही है। लोग सामूहिक-जीवन बिताने के स्थान में वैयक्तिक-जीवन बिताने की तरफ़ बढ़ रहे हैं, जिसका परिणाम यह हो रहा है कि ग्रव तक जो परिवार 'संयुक्त' थे, वे 'वियुक्त' हो रहे हैं, जो 'ग्रविश्वन्त' थे, वे 'विश्वक्त' हो

रहे हैं, इसीलिये यह कहना ग्रसंगत न होगा कि वर्तमान-युग की दिशा 'सयक्त-परिवार' (Joint family) से 'वैयक्तिक-परिवार' या 'एकाकी-परिवार' (Individualistic Immediate family ) or ' की तरफ जा रही है। 'संयुक्त-परिवार' में चचा-ताऊ, भाई-भतीजे सब साथ रहते हैं, 'वैयक्तिक-परिवार' में पति-पत्नी तथा सन्तान-इन तीन का ही साथ रह जाता है। 'वैयक्तिक-परिवार' को 'सन्तान-केन्द्रिक' (Filiocentric) भी कहते हैं क्योंकि 'वैयक्तिक-परिवार' के सब लोगों की जबान पर रहता है कि बाल-बच्चों की परवरिश करें, या सबको कमाकर खिलावें। आजकल जीवन में प्राधिक विषमता बढती जा रही है, पहले की तरह की हर बात की बहुतायत नही रही, भ्रपने बाल-बच्चो का ही भरण-पोषण कठिन होता जा रहा है, सबका भरण-गोषण तो कौन कर सकता है—इन्ही सब कारणों से 'संयुक्त-परिवार' प्रथा ट्टती जा रही है। 'संयुक्त-परिवार' के ट्ट-टटकर 'वैयक्तिक-परिवार' या 'एकाक़ी-परिवार' बनने में अनेक कारण हैं. ग्रीर ग्रनेक हानि-लाभ है, परन्तु उनमें मुख्य कारण तथा मुख्य हानि-लाभ निम्न है--

### ६. संयुक्त-परिवार के टूटने के कारण, हानियाँ तथा लाभ [संयुक्त-परिवार के टूटने के कारण]

(क) भार्यिक-कारए- 'सयुक्त-परिवार' के टूटने का सबसे मुख्य कारण भाष्यिक है। पहले जब 'संयुक्त-परिवार' का निर्माण हुआ था तब परिवार वस्तु का 'उत्पादन' (Production) भी करता था, 'उपभोग'

<sup>†</sup> श्रंभेजी में Joint family का उल्टा Immediate family कहलाता है।

(Consumption) भी करता था। भ्रपने उपभोग के लिये जिस वस्तु की भावश्यकता थी वह परिवार में ही उत्पन्न कर ली जाती थी। कपडे की ज़रूरत है, तो घर में करघे लगे हये थे, जितना कपडा चाहिए बना लिया। साने की जरूरत है, तो भपनी खेती में से जितना भनाज चाहिए मिल गया। प्रपनी जरूरत से जितना ज्यादा होता था वह दूसरों को देकर उनके पास जो चीज होती थी वह बदले में ले ली जाती थी। प्राधिक-व्यवस्था इतनी जटिल नहीं हुई थी जितनी प्राज हो गई है। घर ही 'गृहोद्योग' का केन्द्र था, भीर उसके लिये 'सयुक्त-परिवार-प्रया' प्रत्यन्त उपयुक्त थी । यह मानो एक बनी-बनाई कम्पनी थी, एक कार्पोरेशन था। परन्तु युरोप में १८वी सदी में अनेक आविष्कार हए। १६वीं तथा २०वीं सदी में ये भाविष्कार भीर बढे जिनका परिणाम कल-कारखाने लगना हुग्रा। पहले करघे पर जितना काता-बुना जाता था, श्रव मशीनों के जरिये श्राठ-दस धुना काता-बुना जाने लगा। इसे 'ग्रीद्यौगिक-क्रांति' (Industrial revolution) कहते हैं। वैज्ञानिक ग्राविष्कारो के साथ-साथ श्रीद्योगिक-क्राति का रूप उग्र होता चला गया। क्यों कि घर की अपेक्षा घर के बाहर कल-कारलाने में उद्योगो से अधिक काम हो सकता था, अत: जितने उद्योग घर में केन्द्रित थे. वे १६वीं तथा २०वीं सदी से ग्रीद्योगिक-कान्ति के कारण घर से बाहर जाने लगे। परिणाम यह हुन्ना कि घर केवल 'उपभोग का केन्द्र' (Consuming centre) रह गया, 'उत्पादन का केन्द्र' (Producing centre) न रहा। 'उत्पादन के केन्द्र' के रूप में 'संयुक्त-परिवार' का विशेष महत्त्व था क्योंकि सब लोग मिलकर काम करते थे। जब परिवार 'उत्पादन का केन्द्र' ही न रहा, तब उसका टूट जाना स्वामाविक था। 'मौद्योगिक-क्राति' का यह परिणाम हुम्रा कि भनेक व्यक्तियों का काम मशीन के जरिये एक व्यक्ति करने लगा। इससे बेकारी और बेरोजगारी का बढना स्वाभाविक था। तब लोग क्या करते ? कारसाने हर जगह तो थे नहीं। बडे-बड़े शहरों में

कारलाने लगे थे। लोग पेट्र की सादित शहरों में जाने लगे। शहरों में रोटी-पानी का क्या प्रबन्ध हो? वे अपने बाल-बच्चों की भी बुला लेते थे। जब घर में परिवार के सदस्य न रहे, तो 'संयुक्त-परिवार-प्रथा' का टूटना स्वाभाविक हो गया।

- (२) घरेल-फंगडे-- 'संयुक्त-परिवार'-प्रया ट्रटने के जिन आर्थिक-कारणों का ऊपर निर्देश किया गया है उनके अतिरिक्त इस प्रथा के टूटने का दूसरा कारण घरेलू-फगड़े हैं। 'सयुक्त-परिवार' में ३०-४० सदस्य तो होते ही है। बगाल के एक 'संयुक्त-परिवार' में ५०० के लग-भग सदस्य गिने गये थे। इस विषय का विस्तृत अध्ययन करने के लिए हमे कुछ परिवारो को चुनकर उनकी सब मवस्यामों की क्रियात्मक जानकारी हासिल करनी चाहिए। यह गवेषणा का एक दिलचस्प विषय है। इतने व्यक्तियों के एक-साथ रहने से उनके भापस के सामाजिक-व्यवहार में समय-समय पर मनोमालिन्य हो जाना कोई भचम्मे की बात नहीं है। ऐसे परिवारों में प्रायः स्त्रियों से फगड़े उठा करते हैं। बो लोग कमाऊ होते हैं जनकी स्त्रियां दूसरो को ताना दिया करती है, उन्हें भ्रपने पति के कमाऊ होने पर गर्व होता है, वे नही चाहती कि उनका पति कमाता रहे और दूसरे बैठकर खाते रहें। कभी-कभी 'सयुक्त-परिवार' का मुखिया रुपये-पैसे की गड़बड़ कर जाता है, पैसे भ्रपने काम मे उड़ा देता है। ये सब कारण जब इकट्ठे हो जाते हैं, तब घरेलु-मगडे उम्र रूप धारण कर लेते हैं, भीर 'संयुक्त-परिवार' टूटकर 'वैयक्तिक-परिवार' बन जाते हैं।
- (३) नवीन विचार—इस बीसवीं सदी में मानव-समाज जो प्रगति, कर रहा है उसके प्रभाव में भाकर भी लोग 'संयुक्त-परिवार' में बंधे रहना नहीं पसन्द करते । जैसे सयुक्त-परिवार प्राचीन-काल से चला भा रहा है, वैसे इसका विरोध भी प्राचीन-काल से ही होता भाषा है। शुक्र-मीति में लिखा है—

कुछ रस्मो-रिवाक होते हैं। परिवारों के धनग-धनग हो काने से लोग सब-कुछ भूल जाते हैं, नई सन्तित तो पुरानी किसी बात को याद ही नहीं रखती, धपने निकट के सम्बन्धियों तक को नई धौलाद नहीं पह्नानती। साथ-साथ रहने से एक-दूसरे को कार्म रहती हैं, लिहाक रहता है, कार्म-लिहाज किसी को न रहे तो मनुष्य सच्चरित्रता से भी ध्रप्ट हो जाता है। बम्बई, कलकत्ता धादि में कई ऐसे परिवार हैं जो ध्रपने रिक्तेदारों से दूर रहते हैं, उन्हें उनका कोई रिक्तेदार नहीं जानता, वे धपने किसी रिक्तेदार को नहीं जानते। शराब पीते, मस्त-मौला बन धपना दिन काटते हैं। उन्हें सन्मार्ग दिखाने वाला कोई नहीं। इसका यह धिमप्राय नहीं कि 'सयुक्त-परिवार' से जो धलग होगा उसका यही हाल होगा, इसका इतना ही ध्रिभप्राय है कि परिवार के धन्य सदस्यों की देख-रेख का बन्धन मनुष्य को पथ-ध्रप्ट होने से रोकता है।

- (क) नियन्त्रण—'सयुक्त-परिवार'-प्रथा मनुष्य को नियम में रखती है, बन्धन में रखती है। मनुष्य बन्धन नहीं चाहता—यह ठीक है, परन्तु कभी-कभी बन्धन मनुष्य के लिए धावव्यक हो खाता है। 'वैयक्तिक-परिवार' में मनुष्य को अपने को बन्धन में रखने के लिये, धपने को धपनी ही जिम्मेदारी पर छोड़ना पडता है, उस पर से सामाजिक-बन्धन उठ जाता है। अपनी जिम्मेदारी धपने पर कितने लोग ले सकते हैं? सर्व-साधारण को तो अपने नियन्त्रण के लिए दूसरे पर ही छोड़ना पडता है।
- (ग) बेकारी में सहायक वर्तमान-युग की आर्थिक प्रवस्थाओं में कौन कब बेकार हो आयगा, इसे कौन कह सकता है? 'संयुक्त-परिवार'- प्रथा बेकारी में अपने सदस्यों की सहायक सिद्ध होती है, परिवार के दूसरे सदस्य अपने संगे-सम्बन्धों के काम आते हैं। धमीर लोगों की बात तो आज दूसरी है, वे एक दिन से ज्यादा किसी को अपने घर नहीं रख

सकते, परन्तु गरीब लोग जिनमें 'संयुक्त-परिवार'-प्रथा के प्रति सभी तक धादर है, अपने रिश्तेदारों को महीनों तक धपने पास रखते हैं, जब तक उन्हें नौकरी नहीं मिल जाती तब तक यथाश्रावित उनकी सहायता करते हैं।

- (घ) स्त्रियों की सहायक—स्त्रियों की तो इस प्रथा से विशेष सहायता होती है। खास कर अपने समाज में जो विषवायें शादी-ज्याह नहीं करतीं उनका त्राण 'वैयक्तिक-परिवार' में नही हो सकता, 'संयुक्त-परिवार' में उनका भरण-पोषण भी औरो के साथ-साथ चलता रहता है।
- (ङ) वृद्धों की सहायक—मनुष्य बूढा होकर खुद तो कमा नहीं सकता, आजकल के 'वैयक्तिक-परिवार' के नौजवान अपने बूढे माँ-वाप की पर्वाह नहीं करते, वे कहते हैं—अपने बाल-बच्चो को खिलायें या बूढे माँ-वाप को खिलायें । जिन माता-पिता ने उनको पाल-पोसकर बड़ा किया, उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं जाता । ऐसी अवस्था में या तो राष्ट्र अपने ऊपर बूढ़ों की परवरिश की जिम्मेदारी ले, या 'संयुक्त-परिवार'-प्रया द्वारा उनका भरण-पोषण हो, तीसरा रास्ता उनका रोरोकर अपना बुढ़ापा काटने के सिवाय क्या रह जाता है ?
- (च) निःस्वार्यपरता—'वैयक्तिक-परिवार'-प्रथा व्यक्ति को स्वार्धी बना देती है, 'सयुक्त-परिवार'-प्रया उसे निःस्वार्थी, अपने को छोड कर दूसरों को भी अपना समभना सिखलाती है।

ऊपर 'संयुक्त-परिकार'-प्रथा तथा 'वैयक्तिक-परिवार'-प्रथा के संबंध में जो विवेचन किया गया है उससे स्पष्ट है कि दोनो के अपने-अपने लाभ श्रीर अपनी-अपनी हानियाँ हैं। इस समय समाज की दिशा 'संयुक्त' से 'वैयक्तिक' परिवार की तरफ़ जा रही है, परन्तु समाज के कर्णधारों को दोनों का इस प्रकार का समन्वय करना चाहिए जिससे दोनों के गुण रह जाँय, श्रवगुण नष्ट हो जाँय।

#### प्रश्न

- १--संयुक्त-परिवार किसे कहते हैं, इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?
- २-संयुक्त-परिवार की उत्पत्ति के कारए। क्या है ?
- ३ संयुक्त-परिवार के बाधारभूत तत्व क्या है ?
- ४--संयुक्त-परिवार-प्रया के हानि-लाभ क्या है ?

# 8

# विवाहों के प्रकार

( FORMS OF MARRIAGE )

### १. विवाह के प्रकार

विवाह के मुख्य तौर पर दो प्रकार है—'एक-विवाह' (Monogamy) तथा 'बहु-विवाह' (Polygamy) । 'एक-विवाह' का अर्थ हैं—एक पुरुष एक स्त्री से शादी करे, और एक स्त्री एक पुरुष से शादी करे । 'बहु-विवाह' के तीन भेद हैं—अनेक पुरुषों की एक स्त्री से शादी को 'बहु-भर्तृता' (Polyandry) कहते हैं; एक पुरुष की अनेक स्त्रियों से बादी को 'बहु-भार्यता' (Polygyny) कहते हैं; अनेक पुरुषों के अनेक स्त्रियों से विवाह को 'यूथ-विवाह' (Group-marriage) कहते हैं । किसी प्रकार के विवाह के बिना स्त्री-पुरुष के यौन-सम्बन्ध को 'संकरता' (Promiscuity) कहते हैं । विवाह के प्रकारों को समझने के लिए इन सबका जानना आवश्यक है, इसलिए हम इन सबकी यहाँ थोड़ी-थोड़ी चर्चा करेंगे और क्योंकि विवाह के इन प्रकारों में अनेक जंगली जातियों में पाये जाते हैं इसलिये स्थान-स्थान पर हम उनकी भी चर्चा करेंगे।

(क) एक-विवाह (Monogamy)—एक-विवाह की प्रथा ग्राजकल के सम्य-समाज में पायी जाती है, श्रीर श्रादि-काल के श्रशिक्षित समाज में पायी जाती थी। मादिकालीन-समाज की ग्राधिक-व्यवस्था फल-मल एकत्रित करने वाली सरल भाषिक-व्यवस्था थी । इस माथिक-व्यवस्था की जो प्रशिक्षित जन-जातियाँ इस समय जीवित पाई जाती है उनमें एक-विवाह की प्रया पायी जाती है, उनके परिवार के सदस्यों में एक पुरुष तया एक स्त्री-पही नियम है। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रादि-समाज को यही पद्धति बच्चे की परवरिश के लिए सर्वोत्तम प्रतीत हुई होगी और इसीलिए उस समाज ने इसी पद्धति को अपनाया होगा। श्रादि-काल की प्रवस्थाओं में एक स्त्री तथा एक पुरुष के विवाह से ही मनुष्य जीवित रह सका, दूसरे किसी प्रकार का विवाह होता—'बहु-भार्यक' या 'बहु-भर्त क' तो मनुष्य की सन्तान माता तथा पिता के ध्यान बँट जाने से जीवित न रह सकती । इसके श्रतिरिक्त श्रग्र हम जीवित जगली जातियो का श्रध्ययन करें, तो उनमे से भी श्रधिकाश 'एक-विवाही' ही पाई जाती हैं। ठीक भी है, इन निम्न-स्तर की मशिक्षित जन-जातियों में पुरुष का युवावस्था प्राप्त करते ही विवाह कर लेना लाजमी प्रतीत होता है क्योंकि युवा बन जाने के बाद इनको खिलाने-पिलाने की जिम्मेदारी दूसरा कोई नहीं ले सकता। युवा होने कें बाद ग्रगर ये शादी करके ग्रपना अलग खाने-कमाने का सिलसिला न बना लें, तो हर समय घर में वैमनस्य बना रहे। स्नादि-कालीन समाज में क्योंकि स्त्री-पुरुषो की संख्या मे विषमता होने का कोई कारण नहीं प्रतीत होता, भीर उन्हें घर में वैमनस्य न पैदा हो जाय इस कारण घर से ग्रलग होना जरूरी था, ग्रीर साथ ही क्योंकि उस समय स्त्री-पुरुषों की संख्या भी बराबर-बराबर थी, इसलिये कई लोगो का कहना है कि मादि-कालीन समाज बहु-विवाही न होकर एक-विवाही ही था। भाजकल का सम्य-समाज तो एक-विवाही है ही।

- (स) बहु-भत् ता (Polyandry) बहु-विवाह की प्रधा संसार के बहुत भागों में प्रचलित है। बहु-विवाह का रूप एक स्त्री के अनेक पति होना है, इसी को 'बहु-भर्त् ता' (Polyandry) कहते हैं। 'बहु-भर्तता' के दो रूप है--(१) 'भ्रातक बहु-भर्तता' (Adelphic या Fraternal polyandry) वह है जिसमें कई भाई मिलकर एक स्त्री से बादी कर लेते हैं, (२) 'घन्नातुक-बहु-मर्नुता' (Non-fraternal polyandry) वह है जिसमें एक स्त्री से जो लोग बादी करते हैं, वे भाई-भाई नहीं होते। पहले प्रकार की 'बहु-भर्तृता' मे स्त्री तथा सब, पति इकट्रे, एक ही स्थान पर रहते हैं, यह सयुक्त-परिवार में पायी जाती है, दूसरे प्रकार की 'बह-भतुंता' में स्त्री भिन्त-भिन्न समयो में भिन्न-भिन्न पतियो के घरो मे जाकर रहती है, या पति भिन्न-भिन्न स्थानों में रहते हुए भिन्त-भिन्न समयों में पत्नी के यहाँ आकर रहते है। जब तक स्त्री किसी एक पति के साथ रह रही होती है तब तक भ्रन्य पतियो का उस पर भ्रधिकार नहीं होता। यह प्रथा कम देखने में श्राती है। मद्रास के नायर लोगो में यह प्रथा है। पहले प्रकार की 'बहु-भर्तृता' नीलगिरि के टोडा, देहरादून जिले के जौनसार-बाबर के इलाके मे पायी जाती है। काश्मीर से लेकर असम तक जो मगोल लोग रहते हैं उन सबसे यही प्रया है।
- (ग) बहु-भायंता (Polygyny)—एक पुरुष की अनेक स्त्रियाँ होना अनेक समाजो मे पाया जाता है। आदि-कालीन फल-भूल एकत्रित करने वाली सरल आधिक व्यवस्था में स्त्री तथा पुरुष की स्थिति एक-समान थी, उनमें कोई मौलिक भेद नही था, इसलिये कोई स्त्री अपनी साँभीदार दूसरी स्त्री को अपने घर में कैसे बर्दास्त कर सकती थी? इसके अलावा शुरू-शुरू में स्त्री-पुरुष की संस्था में भी कोई आधारभूत विषमता नहीं थी, इसलिए आदि-कालीन विवाह-संबंधी-व्यवस्था तो एक-विवाह की ही थी। यह संभव है कि किसी-किसी परिवार मे जहाँ

काम अधिक था पत्नी की इच्छा से दूसरी स्त्री भी ले ली जाती थी। जब आधिक-व्यवस्था विकसित अवस्था का रूप धारण कर गई, तब इस समाज का जो मुख्या होता या वह अपनी शान के लिये चार-पाँच स्त्रियाँ रख लेता था, उसके साथ के लोग भी एक की जगह दो स्त्रियाँ रख लेते थे। अपने देश में हिन्दुओं में अनेक स्त्रियाँ रखने की प्रया रही है जो अब १६५५ से बन्द की गई है। मुसलमान तो अब भी अनेक स्त्रियों से विवाह कर सकते हैं।

- (घ) यूच-विवाह (Group marriage)—कुछ पाश्चात्य विद्वानों का कथन है कि पहले कभी यूच-विवाह की प्रथा प्रचलित थी। एक परिवार के सब भाइयों का दूसरे परिवार की सब बहनों के साथ विवाह हो जाता था। दूसरे पक्ष के विद्वान् इस बात को नहीं मानते। ध्रादि-काल की जन-जातियों में कई जातियाँ ऐसी पायी जाती हैं जिनमें चाचा-ताया, चाची-ताई ग्रादि के लिये पिता-माता—ये शब्द ही पाते जाते हैं। इनके ग्राधार पर यह कल्पना की जाती हैं कि इन जन-जातियों में कभी यूच-विवाह की प्रथा प्रचलित थी, परन्तु भगर ऐसा होता, तो मादि-कालीन किसी ग्रीवित जंगली-जाति में भी यह प्रथा पायी जाती। इसका न पाया जाना सिद्ध करता है कि यूच-विवाह की कल्पना, कल्पना ही है, इस कल्पना का ग्राधार यथार्थ नहीं है।
- (क) संकर-विवाह (Promiscuity)— कुछ पाश्चात्य विद्वानों का कथन है कि भादि-कालीन समाज में परिवार का विचार नही था, विवाह का विचार भी नही था, संकरता थी। यह बात भी कल्पना के भाषार पर ही कही जाती है। असल में जीवित जगली-जातियों में ऐसी कोई जन-जाति दिखाई नहीं पडती जिसमें विवाह की संस्था न हो और संकरता हो।

#### २. विवाह में विधि तथा निषेध अथवा अन्तर्विवाह तथा बहिविवाह

#### (Preference and Prohibition or Eudogamy and Exogamy)

विवाह के सम्बन्ध में सब जगह दो प्रकार के नियम बने हुए हैं। एक नियम तो दे हैं, को यह बतलाते हैं कि कहाँ शादी की जाय, दूसरे नियम वे हैं, जो यह बतलाते हैं कि कहाँ शादी न की जाय। कहाँ शादी की जाय, यह बतलाने वाले 'विधि-नियम' (Preference) कहलाते हैं, कहाँ न की जाय, यह बतलाने वाले नियम 'निषेध' (Prohibition) कहलाते हैं। पहले हम 'निषध' की चर्चा करेंगे, फिर 'विधि' की।

- (क) निषेष, बहिर्विवाह (Prohibition, Exogamy)—कहाँ-कहाँ विवाह न किया जाय, इस प्रकार के निषेषक नियमों को बहिर्विवाह (Exogamy) के नियम कहा जाता है। संसार के सब समाजों में— प्रादि-समाज प्रौर उन्नत-समाज मे—पिता-पुत्री का, माता-पुत्र का, प्रौर निकट के रुधिर के सम्बन्धियों का विवाह-संबंध विजित है। कुछ-एक समाज ऐसे हैं जी निकट के सम्बन्धियों को विवाह की म्राज्ञा देते हैं, परन्तु प्रधिकांस समाजों में यह सम्बन्ध विजत ही नहीं, दंडनीय भी है। माई-बहिन का विवाह उचित नहीं, इसे 'मनाचार' (Incest) कहा जाता है। 'समान-घिरवालो का विवाह' (Consanguineous marriage) भी संसार के प्रधिक मागो में प्रनुचित सममा जाता है। समान-घिर के जो बहुत नजवीकी रिस्तेवार होते हैं, उनका विवाह सम्बन्ध ही विजत नहीं है ग्रिपतु एक गोत्र के लोग भी विवाह नहीं कर सकते क्योंकि यह सममा जाता है कि एक गोत्र वालों का घिर संबंध होता है।
- (स) विधि, अन्तर्विवाह (Preference, Endogamy) हमने देखा कि कहाँ विवाह नहीं कर सकते। माई-बहन में, अपने रुधिर वालो में

शादी-ज्याह नहीं कर सकते, परन्तु अपनी जात-विरादरी के बाहर भी नहीं जा सकते । आधारभूत सिद्धान्त यह माना जाता है कि जहाँ 'रुधिर' की समानता हो, वहाँ विवाह उचित नहीं, जहाँ 'जाति' की समानता हो वहाँ विवाह उचित हैं। हिन्दुओं में यह समभा जाता है कि गोत्र तथा सिंपड में रुधिर की समानता होती है, अतः वहाँ विवाह का निषेध हैं; अपनी जाति में रुधिर की समानता नहीं होती, अतः वहाँ विवाह का विधान है। हिन्दू अपने गोत्र में शादी नहीं कर सकते, परन्तु अपनी जाति से बाहर भी शादी नहीं कर सकते। ऐसा क्यो हैं? ऐसा इसलिये हैं क्योंकि अपनी जाति से बाहर जाने में मनुष्य एक ऐसे समुदाय में जा पडता है जिससे अपने समुदाय के दूदने का तथा समुदाय में बाहर के रुधिर आजाने का भय है, इसलिये अपनी जाति के बाहर जाने का भी हिन्दुओं में ही नहीं, सब प्राचीन जातियों में निषेध है। अपनी जाति के भीतर विवाह करने को ही 'अन्तिविवाह' (Endogamy) कहते हैं। यह 'विधि' है, 'नियमें' है कि अपनी जाति में ही विवाह किया जाय।

### ३. विवाह में ग्रनुलोम तथा प्रतिलोम (Hypergamy and Hypogamy)

विवाह में विधि तथा निषेध पर विचार करते हुए हिन्दुओं के अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह पर विचार करना जरूरी जान पडता है, क्यों कि अनुलोम-विवाह करने की हिन्दुओं में छूट है, प्रतिलोम-विवाह करने की छूट नहीं है। 'अनुलोम' तथा 'प्रतिलोम' क्या है ? हिन्दुओं की जाति-व्यवस्था के अनुसार लडकी की विवाह से पहले जाति पिता की जाति होती है, विवाह के बाद जाति पति की जाति हो जाती है। एक तरह से स्त्री की तो कोई जाति ही नहीं होती, पुरुष की जाति होती है, स्त्री जिस जाति के पुरुष के साथ विवाह करे स्त्री की , बही जाति मानी जाती है। विवाह सबस में बाह्मण का बाह्मण-सन्निय-वैश्य-सुद्र की

कन्या से विवाह हो सकता है, इनमें ब्राह्मण तथा ब्राह्मण-क्रन्या का विवाह सवर्ण-विवाह एवं बाह्मण का क्षत्रिय, वैश्य या शुद्र की कन्या से विवाह भनुलोम-विवाह कहलाता है, क्षत्रिय तथा ब्राह्मण-कन्या का विवाह प्रतिलोम-विवाह कहलाता है। अगर पूरुष अपने से नीचे वर्ण की कन्या से विवाह करता है, तो यह अनुलोम-विवाह है, इसकी शास्त्र आजा देता है, ग्रगर पुरुष भपने से ऊँचे वर्ण की कत्या से विवाह करता है, तो यह प्रतिलोम-विवाह है, इसकी शास्त्र ग्राज्ञा नहीं देता । बाह्मण शूद्रा से शादी कर सकता है परन्तु शृद्ध-पूरुष ब्राह्मणी से शादी नहीं कर सकता । इस प्रया का सामाजिक परिणाम क्या हुद्या ? इसका सामाजिक-परिणाम यह हमा कि बाह्मण-लडके का विवाह का क्षेत्र बाह्मण-लडकी के विवाह के क्षेत्र से बहुत विस्तृत हो गया, और बाह्मण-लडकी का विवाह का क्षेत्र बहुत सीमित हो गया, ब्राह्मण-लड्का जहाँ चाहता शादी कर सकता था, ब्राह्मण-लड़की सिर्फ अपने वर्ण मे ही शादी कर सकती थी। ब्राह्मण-लड़िकयो के लिए विवाह एक समस्या हो गयी । या तो बाह्मण-लडका पाने के लिए लड़की के माता-पिता दहेज दें, या जन्म-भर लड़की कुँवारी बैठी रहे। 'प्रतिलोम-विवाह' को नाजायज करने का परिणाम ब्राह्मणो में 'दहेज' (Bridegroom price) प्रथा का चलन हो गया, एक-एक लडका कई लडिकियों से विवाह करने लगा, उनमें 'बहु-भार्यता' (Polygyny) चल पडी, लड़की का होना बाह्मणो में एक मुसीबत का सामना करना हो गया । इसके प्रतिकूल जहाँ बाह्मण-लड़का 'भनुलोम-प्रया' के भनुसार हर जात में सादी कर सकता था, भौर ब्राह्मण-लडकी 'प्रतिलोम-प्रया' के भनुसार सिर्फ़ भपनी जाति में शादी कर सकती थी, वहाँ शुद्र-लड़का तो सिर्फ अपनी जाति में शादी कर सकता था, परन्तु शुद्ध-लड्की हर जाति में शादी कर सकती थी। इसका परिणाम वह हुआ कि शुद्र-लड़के का विवाह का क्षेत्र बहुत संकृचित हो गया, शूद्र-सडकी का क्षेत्र बहुत बढ़ गया। नतीजा यह हुमा कि शूद-लड़के को लड़की मिलना ही कठिन हो गया। बाह्मणों

में 'पित-मूल्य' (Bridegroom price) तथा शृद्धों में 'पत्नी-मूल्य' (Bride price) की प्रथा चल पड़ी। नीची जातियों में लडिक याँ ही नहीं मिलती, लडिक यों के लिये पैसा देना पडता है, वे बिकती हैं। अनुलोम तथा प्रतिलोम प्रथा का आज हिन्दू-जाति पर यह प्रभाव पढ़ रहा है कि बड़ी जातों में लडिक बिकते हैं, छोटी जातों में लडिक याँ विकती हैं, बड़ी जातों में एक पुरुष अनेक स्त्रियाँ रखता रहा है, छोटी जातियों में अनेक पुरुष एक स्त्री रखते हैं। बड़ी जातियों में पुरुष अविवाहित नहीं रहता, छोटी जातियों में कई बार पुरुष को प्रविवाहित रह जाना पडता है, बड़ी जातों में लडिकी आसानी से मिल जाती है, छोटी जातों में लडिकी को लूटकर, भगा कर लाना पडता हैं। हिन्दू-समाज में मिल्न-भिन्न जातियों में लडिकी की स्थित की विषमता का कारण अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह की प्रथा है।

भव 'हिन्दू-विवाह तथा तलाक-प्रधिनियम-१६५५' (Hindu Marriage and Divorce Act-1955) के अनुसार 'प्रतिलोम' विवाहो को वैधानिक मान लिया गया है।

- ४. जंगली जातियों (म्रादि-वासियों) में विवाह के प्रकार भादि-वासियों में माठ प्रकार के विवाह के प्रकार पाये जाते हैं जो निम्न हैं:--
  - (क) परीक्षण-बिवाह (Probationary marriage)
  - (ख) परीक्षा-विवाह (Marriage by trial)
  - (ন) মণ্ছবল-বিবাह (Marriage by capture)
  - (ঘ) ক্ৰ-বিৰাह (Marriage by purchase)
  - (ङ) सेवा-विवाह (Marriage by service)
  - (च) विनिमय-विवाह (Marriage by exchange)
  - (छ) पलायन-विवाह (Marriage by elopement)
  - (অ) মলিন্দ-বিৰাह (Marriage by intrusion)

- (क) परीक्षरा-विवाह (Probationary marriage) कहीं जातियों में लड़का कुछ दिन लड़की के पिता के घर धाकर रहता है। लड़की-लड़के को मिलने-जुलने की छूट रहती है। धगर कई दिन रहने के बाद लड़का अनुभव करे कि दोनों की प्रकृति मिलती है, तब वे शादी कर लेते हैं, नहीं तो लड़का लड़की के पिता को कुछ मुधाविजा देकर चला जाता है। कुकी जाति में यह प्रधा पायी जाती है। इस प्रकार के विवाह को 'परीक्षण' कहा जाता है।
- (क) परीक्षा-विवाह (Marriage by trial)— कई जातियों में लड़के के बाहु-बल, चातुरी झादि की परीक्षा लेकर उसके साथ लड़की का विवाह किया जाता है। अपने यहाँ इस प्रकार की परीक्षा के लिये स्वयवर रचे जाते थे। रामचन्द्र जी ने घनुष तोड़ा था, अर्जु न ने चलती मछली की झाँख को बीधा था। भीलो में होली के दिनों में एक वृक्ष पर नारियल तथा गुड़ टाँग दिया जाता है। वृक्ष के चारों तरफ़ गाँव की लड़कियाँ घेरा बनाकर नाचने लगती हैं, उनके गिर्द पुरुषो का एक दूसरा घेरा लग जाता है। जो लड़का चाहे लड़कियों के घेरे को चीर कर वृक्ष पर चढ़ सकता है। लड़कियों के घेरे को जो भी चीरने का साहस करता है उसे लड़कियाँ मारती हैं, पीटती हैं, नोचती हैं, काटती हैं, परन्तु जो इस सबको पार कर ऊपर चढ़ जाता है उसे इन लड़कियों में से किसी को भी चुनने का धिषकार होता है।
- (ग) अपहरण विवाह (Marriage by capture) कुछ विद्वानों के कथनानुसार 'अपहरण-विवाह' विवाह के क्षेत्र में मनुष्य की सबसे पहली ईजाद थी। भादि-काल का मानव युद्ध-प्रिय था। जब किसी जाति के लोग दूसरी जाति पर हमला बोलते थे, तो उसकी स्त्रियों को हर लाते थे। इन्हें या तो वे मार डालते थे, या उनसे विवाह कर लेते थे। जिन लोगों में स्त्रियों की कमी होती है, वे जैसे अन्य वस्तुमों के लिये लूट-मार करते हैं, वैसे स्त्रियों का अपहरण करने के लिये भी लूट-मार करते हैं। भारत में दंड-विधान की धाराश्रों के कारण स्त्रियों

का ग्रपहरण भवैधानिक हो गया है, परन्तु कोई समय था जब कई जातियों में स्त्री प्राप्त करने का यही एक साधन था। नागा जाति के लोग तो मुन्दर स्त्रियों के कारण उन पर हमले न हों इसलिये लडिकयों को ही मार दिया करते थे। भील, गोड तथा इन लोगो में भ्रब भी स्त्रियों का भपहरण किया जाता है, गोंड लोगों में तो माता-पिता की भ्रमुमित से कन्या का भपहरण होता है। देर तक भविवाहित रहना इनमें ठीक नहीं समभा जाता, इसलिये जब इनकी भनुमित से ही कन्या का भपहरण होता है, तब दिखाबे के तौर पर ये इस भपहरण का विरोध करते हैं, लडकी भी दिखाबे के लिये रोने लगती है, परन्तु क्योंकि यह सब-कुछ एक-दूसरे की स्वीकृति से होता है इसलिये लडका भासानी से कन्या का भपहरण कर ले जाता है।

(घ) कय-विवाह (Marriage by purchase)— भिन्न-भिन्न सामाजिक-प्रथाश्रों के फलस्वरूप कही वर और कही वधू के लिये भून्य देना पड़ता है। श्रादि-जातियों में बहुधा 'पत्नी-मृत्य' (Bride price) की ही प्रथा प्रचलित है, कन्या पाने के लिये कन्या का मृत्य चुकाना पड़ता है। कन्या का मृत्य चुकाने के दो कारण हो सकते हैं। एक कारण तो यह कि जिस जाति में कन्या कम होगी उसे कन्या का मृत्य चुकाना पड़ेगा, दूसरा कारण यह कि कन्या अपने माता-पिता के घर उनका काम-काज करती थी, विवाह के बाद उनका काम-काज कौन देखेगा। इसका मुश्राविजा कन्या के पिता को चुका कर कन्या मिलती है। इन सब बातों को देखकर 'कय-विवाह' का आधार आधिक प्रतीत होता है। परन्तु श्राधिक-दृष्टि से कन्या का मृत्य चुकाया जाय—यह बात कुछ अनैतिक-सी प्रतीत होती है, इसलिये नागा लोग विवाह के समय कन्या का मृत्य तो चुका देते हैं, परन्तु मृत्य देते हुए जितना दाम पहले लगा रखा होता है उससे १० रुपये कम देते हैं ताकि यह न समभा जाय कि उन्होंने पैसा देकर लड़की को खरीदा है।

- (क) सेवा-विवाह (Marxiage by servie)—जो लोग 'पत्नी-धन' नहीं दे सकते उन्होंने विवाह की एक ग्रौर पद्धति निकाली, ग्रौर वह थी लड़की वाले के यहां नौकरी करके एक तरह से 'पत्नी-धन' को चुका देना। गोंड तथा बैगा जन-जाति में वर कन्या के घर नौकर बन कर रहने लगता है ग्रौर कुछ वर्ष नौकरी करने के बाद लड़की से शादी कर अपना स्वतंत्र घर बना लेता है। बिरहौर जन-जाति में कन्या का पिता ही लड़के को रूपया उचार देता है, जिसे वह धीरे-धीरे किश्तो में चुकाता है, जब तक पूरी रकम चुका नहीं देता तब तक ग्रपने ससुर के घर में रह कर उसकी नौकरी करता है। नैपाल के ग्रुरखा मजदूर किसी जौनसार खासी के यहा ग्राकर इस शर्त पर खेती-बाड़ी का काम करता है कि निश्चित श्रवधि तक काम करने के बाद खासी माता-पिता ग्रपनी लड़की का उस नैपाली के साथ विवाह कर देगे। बाइबल में भी जेकब की कथा ग्राती है जिसके ग्रनुसार वह ग्रपने मामा के यहाँ इसलिये सात साल तक नौकरी करता रहा ताकि उसके बाद जेकब का ग्रपने मामा की लड़की से ब्याह हो सके।
- (च) विनिमय-विवाह (Marriage by exchange) 'पत्नी-धन' देने से बचने का सेवा-विवाह के ग्रातिरिक्त दूसरा तरीका विनिमय के विवाह का है। 'पत्नी-धन' देकर विवाह करने के स्थान में ग्रपनी लड़की देना भीर उसी परिवार की लड़की विवाह में ले लेने को 'विनिमय-विवाह' कहा जाता है। एक तरह से 'सेवा-विवाह' ग्रीर 'विनिमय-विवाह' ये दोनो 'क्रय-विवाह' के ही ग्रस्तग-ग्रस्तग रूप है।
- (छ) पलायन-विवाह (Marriage by elopement)—ग्रादि-वासियों में बाल-विवाह की प्रया नहीं पायी जाती, वे युवावस्था में ही विवाह करते हैं, जब से वे हिन्दुओं के सम्पर्क में ग्राये हैं तब से कहीं-कही बाल-विवाह शुरू हो गया है। युवावस्था में विवाह माता-पिता की सहमति से ही हीता है, परन्तु कभी-कभी

ऐसी स्थित भी पैदा हो जाती है जब माता-पिता की सहमित के बिना भी प्रेम-वश युवा-युवती विवाह करना चाहते हैं। ऐसी स्थित उत्पन्न होने पर एक-दूसरे के साथ वे घर से भाग जाते हैं। पुराने जमाने में जब इस प्रकार कोई जोड़ा भागता था, तो ब्राम की हद तक उसका पोछा किया जाता था। ग्रगर वे पकड़े नही जाते थे, तो लोग भी पीछा करना छोड़ देते थे, ग्रीर जब-कभी, पीछे, ग्रसें के बाद वे गांव ग्राते थे तो उन्हें पित-पत्नी मान लिया जाता था। ग्रपहरण ग्रीर पलायन विवाह में यह भेंद है कि ग्रपहरण में तो कन्या की ग्रनुमित के बिना लडका लडकी को उड़ा ले जाता है, पलायन में दोनों की सहमित से पलायन होता है।

(ज) प्रक्षिप्त-विवाह (Marriage by intrusion)—जबर्दस्ती के विवाह दो तरह के होते हैं। एक विवाह में ता लड़का जबर्दस्ती करता है, कन्या न भी चाहे, तो मेले उत्सव भादि में छिप कर खड़ा हो जाता है और लड़की के सामने पड़ते ही उसके माथे पर कुकुम का टीका लगा देता है। टीका लग जाने पर लड़की के माता-पिता को यह विवाह मानना पड़ता है। जबदंस्ती के दूसरे प्रकार में लड़की पहल करती है। लड़का नहीं चाहता, लड़के के घर वाले नहीं चाहते, परन्तु लड़की लड़के वालो के सिर रहती है, उसे दुत्कारा जाता है तब भी नहीं मानती भीर हार कर लड़के को लड़की से विवाह करना पड़ता है। इस प्रकार के विवाह को हमने प्रक्षिप्त इसलिये कहा क्योंकि यह एक प्रकार का 'क्षिप्त' ग्रंथांत् जबदंस्ती लड़की या लड़के के सिर मढ़ा गया विवाह है।

### ५. प्राचीन भारत में विवाह के प्रकार

जंगली-जातियों में विवाह की पद्धतियो का हमने अध्ययन किया। प्राचीन भारत मे भी विवाह के इनसे मिलते-जुलते कुछ प्रकार थे। मनु, मारद तथा याजवल्क्य-स्मृति मे विवाह के ग्राठ प्रकार कहे गये हैं—

#### ब्राह्मो दैवस्तवैवार्षः प्रजापत्यस्तथासुरः

गान्धर्वो राक्षसक्त्रैव पैशाचक्चाष्ट्योऽघम: । मनु, ३, ६ अर्थात्, विवाह के भाठ प्रकार हैं—ब्राह्म, दैव, भार्ष, प्राज।पत्य, भ्रासुर, गान्धर्व, राक्षस तथा पैशाच । इन भाठों का क्या भर्य है ?

- (क) बाह्य—योग्य, सुशील, विद्वान युवक को घर पर निमन्त्रित कर कन्या को केवल एक वस्त्र से अलंकृत करके कन्या को उस युवक के सुपुर्व कर देना 'बाह्य' विवाह है। यह विवाह सादगी का नमूना है।
- (क) दैव—योग्य, सुशील, विद्वान् आह्यण युवक को भीर बड़े-बड़े विद्वानों की विस्तृत यज्ञ में निमन्त्रित कर के भीर कन्या को वस्त्रों तथा श्राभूषणों से ग्रलकृत कर के युवक के सुपुर्द कर देना 'दैव' विवाह है। यह विवाह तड़क-भड़क का नमूना है। कई लोगों का कहना है कि पुरोहित को कन्या-दान करना 'दैव' कहलाता है, परन्तु ग्रधिक संगत बात यही प्रतीत होती है कि भूम-धाम से विवाह करने को 'दैव' कहा जाता है।
- (ग) मार्ष-इस विवाह में कुछ लेने-देने का मामला होता है। वर से एक-एक गाय और बैल या इनका जोडा लेकर कन्या को वर के सुपुदं कर देने को 'मार्ष' विवाह कहते हैं। यह जन-जातियों के कय-विवाह से मिलता-जुलता है।
- (थ) प्रजापत्य—इस विवाह में कोई उत्सव नहीं रचाया जाता था, किसी को निमन्त्रित नहीं किया जाता था। वर तथा कन्या को यज्ञशाला में बैठा कर और सत्कार पूर्वक यह उपदेश देकर कि तुम दोनों साथ-साथ वर्म का जीवन व्यतीत करो एक-साथ कर दिया जाता था। इस विवाह में प्रधानता प्रजा अर्थात् सन्तान उत्पन करने को दी जाती थी, और वर-अधू को यह शिक्षा दी जाती थी कि सन्तानो-त्पत्ति के लिये विवाह किया जाना है।

- (इ) झासुर—ऊपर के चार विवाह तो उत्तम माने गये हैं, झसुर गान्धवं-राक्षस-पैशाच झधम माने गये हैं। जब वर अपने पितृ-पक्ष के बन्धु-बान्धवो तथा कन्या पक्ष के बन्धु-बान्धुग्रो—दोनो को धन देकर विवाह करता है, तब इसे 'श्रासुर' कहा जाता है।
- (ख) गान्थवं जब वर तथा कन्या बिना विवाह-सस्कार के एक-दूसरे की इच्छा-पूर्वक काम भाव से सयोग करने लगते तथा एक-दूसरे के साथ रहने लगते हैं, तब इसे 'गान्घवं' कहा जाता है।
- (छ) राक्सस—मार-काट कर, छीन-भपट कर, रोती-बिलपती कन्या का हरण कर लाना 'राक्षस'-विवाह कहलाता है। यह जन-जातियों के प्रपहरण-विवाह से मिलता-जुलता है। ग्रादि-जातियों में इस प्रकार के विवाह ग्रधिक होते थे।
- (क) पंशाच सोती, पागल, नशे में उन्मत्त कन्या को एकान्त में पाकर उसे दूषित कर देना सब विवाहों से नीच 'पंशाच' विवाह कहलाता था, परन्तु इस प्रकार के विवाह को विवाह मानने का यह अर्थ है कि जिस स्त्री के साथ बलात्कार किया गया हो उसे भी समाज में से निर्वासित नहीं कर दिया जाता था, सिर्फ उस विवाह का दर्जा नीचा माना जाता था, परन्तु इस प्रकार की स्त्री को भी समाज में स्थान था।

इन ग्राठ प्रकार के विवाहों का विवरण सिद्ध करता है कि हिन्दू-समाज में विवाह के सम्बन्ध में जितने भी भिन्न-भिन्न विचार हो सकते हैं उन सबको स्मृतिकार ने खपाने का प्रयत्न किया है। इनमें से कौन कब प्रचलित था, कब नहीं था, कौन सबसे पुराना तरीका है—प्रह गवेषणा का विषय है।

### ६ हिन्दू-समाज में विवाह

हमने देखा कि विवाह के क्या-क्या प्रकार ससार में चले हुए हैं। हमारे लिये यह जानना ज्यादा जरूरी है कि ग्राजकल हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी तथा सिक्खों में विवाह के क्या-क्या प्रकार हैं क्योंकि इन्हीं का हमसे प्रधिक सम्पर्क है। हम इन सबके विवाह के प्रकारों का प्रागे संक्षेप से वर्णन करेंगे।

- (क) ग्रांग्न को साक्षी रखना तथा सप्तपदी—हिन्दू विवाह के दो ग्रावझ्यक तस्व—इस समय हिन्दू-समाज में जो विवाह-प्रथा प्रचलित है जसमे दो बातों का होना लाजमी है—एक तो श्रांग्न को साक्षी रखकर प्रतिज्ञा करना, दूसरा सप्तपदी की विधि । सप्तपदी-विधि के सातवें पैर के रखते ही विवाह विधि-वत् पूर्ण कहा जाता है, फिर यह नहीं टूट सकता । विवाह के लिये द्विरागमन ग्रावझ्यक नहीं है । द्विरागमन हो, न हो, ग्रगर सप्तपदी हो चुकी है, तो हिन्दू-विवाह जायज माना जाता है । हौं, ग्रगर हिन्दुयों में कोई ऐसी जाति-उपजाति है जिसमे विवाह की कपर कही गई प्रथा से भिन्न कोई प्रथा हो, उसका ग्रपनी प्रथा के ग्रनुसार विवाह जायज माना जायगा । ग्रसली बात प्रथा है । कपर की विधियों के होने पर विवाह का जायज माना जाना भी इसी कारण है क्योंकि ग्राधिकाश हिन्दुयों में ग्रांग्न को साक्षी रखकर प्रतिज्ञा करना तथा सप्तपदी-विधि की प्रथा प्रचलित है ।
- (क) हिन्दू-विवाह में बहु-विवाह का स्थान—प्रचलित प्रया के अनुसार हिन्दू-स्त्री के लिए एक पतित्रत जरूरी है; पुरुष इच्छानुसार एक या ग्रनेक जितनी स्त्रियों से चाहता, श्रव तक विवाह कर सकता था। श्रव १६५४-५५ में 'हिन्दू-विवाह तथा तलाक'-श्रधिनियम के अनुसार पुरुष का बहु-विवाह वर्जित करने का कानून बन गया है। कई स्थानों पर स्त्री ग्रनेक पतियों से विवाह कर सकती है। उदाहरणार्थ देहरादून के पहाडी इलाके जीनसार में यह प्रथा प्रचलित है। श्रन्य भी अनेक पहाडी स्थानों में यह प्रथा पायी जाती है। मद्रास के नायर लोगो तथा नीलियरी के टोडा लोगों में भी एक स्त्री का श्रनेक पुरुषों से सम्बन्ध पाया जाता है। इन सब प्रथाशों को भी प्रथा होने के कारण श्रपना-श्रपना स्थान प्राप्त है।

- (ग) हिन्दुझों में बाल-विवाह-- मध्य-युग में हिन्दुझों मे बाल-विवाह की प्रया प्रचलित हो गई थी। इसके अनेक कारणी में सती-प्रथा भी एक कारण था। परन्तु सती-प्रथा बाल-विवाह का परिणाम होने के साथ-साथ कुछ ग्रश में स्वय भी बाल-विवाह का परिणाम थी। बाल-विवाह से बाल-विधवाधी का होना तो आवश्यक था। विधवा क्या करती ? विधवा के पूनविवाह की प्रया तो मध्य-पुग में थी नही, ग्रत विधवा, या तो सती हो सकती थी, या श्राजन्म वैधव्य बिता सकती थी । मध्य-युग मे सती-प्रया पर स्मृतिकारो ने जोर देना शुरू किया। यह कहा गया कि जो विधवा पति के साथ जल जायगी वह स्वर्ग पहुँचेगी। कभी-कभी स्त्रियो की बेदना कम करने के लिये उन्हें ग्रफीम खिलाकर, बेहोश करके सती किया जाता था। जलती चिता से जो स्त्रियाँ मुलस कर भागती थी, उन्हें कभी-कभी बाँसों से भाग मे धकेला जाता था, कभी-कभी चिता मे रस्सी के साथ बाँघ दिया जाता था। इस सम्बन्ध में राजा राममोहनराय ने बड़ा श्रान्दोलन किया। १८११ में राजा राममोहनराय ने अपनी भामी को सती होते देखकर तीव भान्दोलन उठाया । उस समय लार्ड बैटिक गवर्नर-जनरल थे। उन्होंने भी इस प्रान्दोलन का समर्थन किया और १८२६ मे सती-प्रथा को कानूनन बन्द कर दिया गया।
- (घ) हिन्दुओं में विधवा-विवाह—बाल-विवाह से विधवाधों की समस्या उत्पन्त हुई थी, विधवाधों की समस्या को हल करने के लिये सती-प्रथा में तेजी था गई थी, सती-प्रथा को कानून द्वारा रोक देने से विधवाधों की समस्या फिर उग्र हो उठी। १८५५ में बंगाल के ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने एक पुस्तिका प्रकाशित की जिसमें विधवा-विवाह को शास्त्र-सम्मत सिद्ध किया। १८५६ में 'विधवा-विवाह कानून' स्वीकृत हुआ, परन्तु इस कानून के बावजूद विधवा-विवाह करना बुरा ही समक्षा जाता रहा। इस कानून के स्वीकृत होने के २८-३० वर्ष बाद बहरामजी मलाबारी ने फिर सरकार का विधवाधों की दुर्दशा पर व्यान

खींचा। घीरे-घीरे जनता का घ्यान इघर जाने लगा। १८८७ में शिशपद बैनर्जी ने कलकत्ता के पास बरहानगर में, रमाबाई ने बम्बई में विधवाश्रम खोले, और १८६६ में श्री कर्ने ने विधवाश्रम स्थापित किया। १६०६ से आर्य-समाज ने इस दिशा में वेग से काम शुरू किया। १६१४ में सर गंगाराम ने लाखों की सम्पत्ति इस कार्य के लिए दान दी और भारत के हर प्रान्त में 'विधवाश्रम' स्थापित किये। श्रब देश वासियों का घ्यान विधवाश्रों की समस्या की तरफ काफी जा चुका है और जा रहा है।

(क) हिन्दुओं में सींपड विवाह का निषेष—हिन्दुओ में विवाह जाति के मीतर हो सकता है, बाहर नही । इसे 'भन्तिविवाही-प्रया' (Endogamy) कहा जाता है। ब्राह्मण ब्राह्मणों में ही विवाह कर सकता है, क्षत्रियों या वैश्यो में नहीं। भव 'हिन्दू-विवाह तथा नलाक कानून' के अनुसार 'असवणें'-विवाह को वैध मान लिया गया है। जो अपने वर्ण में शादी करना चाहें उन पर कोई रोक नही, परन्तु जो अपने वर्ण के बाहर शादी करना चाहें उन पर की रोक हटा दी गई है।

जैसे समाज में यह विधान था कि धपनी जाति में ही शादी हो सकती है, वैसे ही धपनी जाति में भी कुछ ऐसी पीढ़िया गिनाई गई थीं जिनमें शादी नहीं हो सकती। इस प्रकार कहाँ-कहाँ शादी नहीं हो सकती इसको गिना देना, 'बहिंविवाही-प्रथा' (Exogamy) कहलाता है। हिन्दू-प्रथा के अनुसार 'सिंपड' विवाह नहीं हो सकता, यह 'बहिंविवाही'- क्षेत्र है। 'सिंपड' का क्या धर्थ है ? बालक का दो व्यक्थि से सम्बन्ध होता है—पिता से, धौर माता से। प्राचीन शास्त्रकारों ने पिता की सात पीढियों धौर माता की पाच पीढियों में विवाह का निषेध किया था। इसी को 'सिंपडता' कहते हैं। इस प्रकार का सिंपड-विवाह नहीं हो सकता। जिसका विवाह होने को है उससे पीढी की गणना की जाती है। धब जो 'हिन्दू विवाह तथा तलाक'-धिवनियम स्वीकृत हुआ है उसके अनुसार पिता की विजत पीढियाँ सात से पाँच तथा माता की

र्वाजत पीढियाँ पाँच से तीन कर दी गई हैं। ग्रर्थात्, श्रव सपिड-विवाह के निषेध का ग्रमं होगा कि पिता की पाँच तथा माता की तीन पीढियों में शादी न कर सकना। इस दृष्टि से 'सपिड-विवाह-निषेध' तथा 'बहिविवाही-प्रथा' (Exogamy) का एक ही ग्रथं है। सपिड-विवाह 'समान-कियर-विवाह, (Consanguineous marriage) का ही दूसरा नाम है। सपिड-विवाह के निषेध का ग्रथं है समान-कियर वालों के ग्रापसी विवाह की मनाही।

- (च) हिन्दुसों के लगोत्र-विवाह का निषेच सिंपड के श्रितिरिक्त सगोत्र-विवाह का भी हिन्दू-समाज में निषेच है। गोत्र की समानता समान रुधिर वालो में भी हो सकती है, असमान-रुधिर वालो में भी। माई-वहिन का, जब तक बहिन की शादी नहीं हो जाती, एक ही गोत्र होता है, शादी के बाद लड़की का गोत्र बदल जाता है, जहाँ शादी होती है, वहाँ का उसका गोत्र हो जाता है। जिन लोगो से हमारा रुधिर का कोई सम्बन्ध नहीं उनका और हमारा भी एक ही गोत्र हो सकता है। १६४६ के 'सगोत्र-विवाह' कानून के अनुसार ग्रब 'सगोत्र-विवाह' पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहा। 'सगोत्र-विवाह' को समान-रुधिर-विवाह नहीं कहा जा सकता, 'सिंपड' को समान-रुधिर-विवाह कहा जा सकता है।
- (छ) हिन्दू-विवाह तथा तलाक—हिन्दू-समाज मे ग्रव तक स्त्री-पुरुष को 'तलाक' का कानूनी श्रिषकार नहीं था। पुरुष श्रपनी स्त्री को छोडकर या बिना छोड़े दूसरा विवाह कर सकता था, परन्तु स्त्री पुरुष को छोडकर दूसरा विवाह नहीं कर सकती थी। जहाँ प्रथा हो वहाँ की दूसरी बात है, परन्तु श्राम हिन्दू-कानून यही था। श्रगर पुरुष ने स्त्री को छोड दिया है, तो श्रपने भरण-पोषण के लिये वह कानून का सहारा लेकर पित से सहायता लेने की श्रिषकारिणी थी, श्रीर श्रगर स्त्री श्रपनी मर्जी से छोडकर गई है, तो पित उसे कानूनन श्रपने पास ला सकता था, यह कहना कि पित ने

दूसरी शादी कर ली है, या व्यभिचारी है, इस बात में घव तक रकावट नहीं था। ग्रगर यह सिद्ध हो जाता कि पति कृष्ठ-ग्रातशक ग्रादि किसी धसाध्य रोग से पीडित है, अविवाहिता को घर रखे हुए है, मार-पीट करता है, स्त्री का उसके घर आकर रहना असुरक्षित है, और फिर भी धगर पति जबदंस्ती पत्नी को अपने पास रखना चाहता था, और इस के लिये प्रदालत का सहारा चाहता था, तब प्रदालत को प्रधिकार था कि पत्नी के विरुद्ध पति के दावे को खारिज कर दे। अब 'हिन्दू-विवाह तथा तलाक कानुन' के अनुसार पति-परनी दोनों को किन्ही खास-लास भवस्थाओं मे तलाक का अधिकार दे दिया गया है। वे भवस्थाएँ हैं--(१) ग्रगर यह सिद्ध हो जाय कि दोनों में से कोई भी शादी के समय नप्सक था ग्रौर ग्रब तक है, (२) ग्रगर यह सिद्ध हो जाय कि पति किसी दूसरी स्त्री को रखैल के तौर से रखे हुए है या पत्नी का किसी दूसरे पुरुष के साथ सम्बन्ध है या वह वेश्या का जीवन व्यतीत कर रही है (३) अगर दोनों में से कोई एक हिन्दू-धर्म का परित्याग करके दूसरे वर्म मे प्रवेश कर ले, (४) बगर दोनो में से कोई भी एक मानसिक-रोग से इतना पीडित है कि उसका इलाज नहीं हो सकता भीर कम-से-कम पाँच साल से उसकी चिकित्सा होती रही है, तथा (४) भगर यह सिद्ध हो जाय कि दोनो में से कोई भ्रसाध्य कृष्ठ-रोग से पीडित है।

(ज) हिन्दू-विवाह तथा विवाह के एक प्रकार का ठेका होने का विवार—यद्यपि हिन्दुमों में विवाह एक धार्मिक-कृत्य है, 'संस्कार' (Sacrament) है, जन्म-जन्मातर के चक का फल है, पित-पत्नी का इसी जन्म का साथ-साथ रहने का सममौता या ठेका नहीं, तथापि मब जो प्रवृत्तियाँ चल पड़ी हैं, जो नये कानून बन रहे हैं, उनके भ्रनुसार यह भी एक 'ठेकें' (Contract) का रूप घारण करता जा रहा है। विवाह जिस मतलब से किया जाता है भगर यह उस मतलब को पूरा करती है तो ठीक, अगर अपने मतलब को पूरा करती है तो ठीक, अगर अपने मतलब को पूरा करती है तो ठीक, अगर अपने मतलब को पूरा करता, तो टूट

सकता है — यह विचार जो श्रव तक अपने यहाँ नहीं था श्रव हिन्दू-समाज में भी बढ़ रहा है।

### ७. मुस्लिम-समाज में विवाह

मसलमानों में विवाह को एक 'ठेका' (Contract) माना जाता है। ठेका दो व्यक्तियों में होता है, और अपनी मर्जी से होता है, इसलिए मुसलमानो मे विवाह का 'प्रस्ताव' ग्रौर 'स्वीकृति'—मे दोनों ग्रावश्यक मानी गई है। प्रस्ताव करते हुए कहा जाता है कि मैने तुम्हारे साथ विवाह किया, भीर इस प्रस्ताव की स्वीकृति देते हुए कहा जाता है कि मुक्ते यह विवाह मजूर है। मुसलमानों में स्त्री श्रनेक पतियों से शादी नहीं कर सकती, परन्तु पुरुष को चार स्त्रियो तक शादी करने का प्रधिकार है। इस दृष्टि से इनमें बहुपत्नी-प्रथा प्रचलित है। दूसरे की विवाहिता पत्नी से शादी नहीं की जा सकती। इसी कारण जब भारत में मुसलमान भाषे, तो हिन्दुओं ने भपनी छोटी बच्चियों की शादी करना शुरू कर दिया। पति की मृत्यु या तलाक के बाद ही स्त्री दूसरी शादी कर सकती है। तलाक हुआ हो तो तीन, और पित मर गया हो तो चार चान्द्र-मास बीत जाने पर स्त्री दूसरा विवाह कर सकती है, अगर स्त्री गर्भवती हो तो सन्तान उत्पन्न होने के बाद । जिस प्रकार ग्रन्य जातियों में कई सम्बन्ध विवाह मे निषिद्ध है, जिन्हे 'बहिं विवाही-प्रया' (Exogamy) कहते हैं, इसी प्रकार मुसलमानों मे पिता की स्त्रियों, माताम्नी मपनी लडकियो, मपनी सगी बहतों, चाची-मामियो, भाई-बहिन की लडकियों से शादी मना है। मुसलमान स्त्री गैर-मुसलिम पुरुष से शादी नहीं कर सकती, परन्तु मुसलमान पुरुष मुस्लिम, ईसाई तथा यहदी स्त्री से शादी कर सकता है। विवाह के समय लड़के को लड़की के लिए भेंट या दहेज देना पडता है, जिसे 'महर' कहते हैं। कहते हैं. हजरत मुहम्मद ने कम-से-कम १० दिरम देने का आदेश दिया था जिसका भाजकल 📢 परिभाषा में १०७ रूपया मर्थ बनता है। दिरम को दो भागों में बौटा गया है। भाषा भाग तो विवाह के समय ही देना होता है, बाकी भाषा भाग स्त्री को तलाक हो तब, या पति की मृत्यु के समय मिल जाता है। 'महर' वह सम्पत्ति है जिसे पति विवाह के समय पत्नी को देता है। यह चार प्रकार का हो सकता है। 'निश्चित-महर' वह है जिसे पित-पत्नी निश्चित कर लें। 'उचित-महर' वह है जिसे भदालत पति की स्थिति को देखकर तथा पत्नी के परिवार की दूसरी लडकियों को मिले महर को देख कर तय करती है। 'सत्वर-महर' वह है जो पत्नी के मांगने पर फौरन देना पड़ता है, 'स्थिगत-महर' वह है जो तलाक के समय दे दिया जाता है। विवाह के समय ही पति-पत्नी यह तय कर लेते हैं कि कितना 'महर' उक्त परिभाषा के धनुसार 'सत्वर' होगा, कितना 'स्थगित' समका जायगा । मुसलमानों मे एक ग्रीर प्रकार का विवाह भी माना गया है। यह शिया-सम्प्रदाय में प्रचलित है, भीर इसे 'मुताह' कहते हैं। 'मुताह'-विवाह एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है, जो उस अवधि के समाप्त होने पर समाप्त समका जाता है। यह एक प्रकार का 'साथी-विवाह' (Companionate marriage) है। इस दृष्टि से मुसलमानों के शिया लीग अमरीकनों से भी आगे बढ़े-चढ़े हैं। इस विवाह से जो सन्तान हो वह जायज मानी जाती है।

#### प्रंग्रेज तथा भारतीय-ईसाइयों में विवाह

जब ग्रंग्रेज भारत में ग्राये, उनमे से कई यहाँ बस गये, पादिरयों ने यहाँ के लोगों को ईसाई मत की दीक्षा देनी शुरू की, तब से यह अनुभव किया जाने लगा कि अग्रेज तथा भारतीय ईसाइयों के विवाह के लिये पृथक् कानून बनाने की भावश्यकता है। अग्रेज-ईसाइयों पर विवाह का ग्रंग्रेजी कानून लाग्न हुग्रा, परन्तु भारतीय-ईसाइयो पर न सिफ्रें अंग्रेजी कानून लाग्न हो सकता था, न सिफ्रं भारतीय कानून। उनके लिये १८७२ में 'इण्डियन किश्चियन मेरैज एक्ट' बनाया गया।

यह विवाह दो तरह से हो सकता है—या तो गिर्जे में, या रिजस्ट्रार के सामने जाकर विवाह को रिजस्टर्ड कराने से। गिर्जे में हो, तो प्रात:काल ६ से लेकर सायंकाल ७ बजे तक हो सकता है, श्रगर शास-पांस ५ मील तक कोई गिर्जा न हो, तो जिस स्थान पर विवाह होना हो उस स्थान की विशेष तौर पर स्वीकृति लेना जारूरी है। विवाह करने से पहले उसका सार्वजनिक स्थान पर नोटिस न्यिकाया जाता है। श्रगर किसी को कोई ग्रापत्ति न हो, तो दो मास के भीतर विवाह कर लेना श्रावश्यक है, न हो, तो दुवारा नोटिस देना पडता है। विवाह के समय गिर्जे में या रिजस्ट्रार के सामने, जिस प्रकार की भी शादी हो रही हो, कहना पडता है कि जो व्यक्ति यहां साक्षी के तौर से उपस्थित है उनके सम्मुल में यह घोषणा करता हूँ कि श्रमुक को मैं भ्रपनी वैध स्त्री (श्रथवा वैध पित) स्वीकार करता हूँ। श्रंग्रेज तथा भारतीय-ईसाइयों की इस घोषणा के शब्दों में थोडा-सा भेद है, वैसे दोनो में विवाह की प्रथा समान है। इनमे एक-विवाह-प्रथा है श्रीर विवाह का रूप एक ठेके का है।

### ६. पारसी तथा सिक्खों में विवाह

पारसियों में भी विवाह तथा तलाक दोनो प्रचलित हैं। १८६४ में इनका विवाह-कानून बना जिसे 'पारमी विवाह तथा तलाक अधिनियम—१८६४' (Parssee Marriage and Divorce Act of 1865) कहते हैं। इनका विवाह पारसी पुरोहित द्वारा दो साक्षियों के सामने होना चाहिये। सस्कार का नाम 'आसीर्वाद' है, आसीर्वाद के बिना कोई विवाह नहीं हो सकता। बहु-विवाह निषद्ध है। विवाह एक 'ठेका' है, इसलिये किन्ही खास अवस्थाओं में तलाक जायज है। सिक्खों की विवाह की प्रथा को 'आनन्द-विवाह' कहते हैं। इसके सम्बन्ध में १९०६ में कानून बना जिसका अभिप्राय यह था कि 'आनन्द'-विधि से जो विवाह-सस्कार हो, वे जायज समक्षे जायोंगे। इस विधि में यज

आदि कुछ नही होता, ग्ररु-ग्रन्थ-साहब का ग्रानन्द-पाठ होता है । सिक्खों में तलाक की प्रथा नही है ।

#### १०. स्पेशल-मैरेज-एक्ट

जिन विवाहो का हमने वर्णन किया वे भिन्न-भिन्न धर्मों को श्राधार बनाकर किये जाते हैं, परन्तु यह भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी धर्म-विशेष को न मानता हो । ऊपर कहे गये विवाहों में जो जिस धर्म को मानता है वह उसी धर्म वालों मे विवाह कर सकता है। 'हिन्द-विवाह तथा तलाक'-मधिनियम जो १९४४-५५ में स्वीकृत हुआ है उसमें, हिन्दुमी में भी जो जातियों के बन्धन हैं उन्हें शिथिल किया गया है, धर्म के बन्धन को नही । बगाल मे ब्राह्मोसमाज के धनुयायियो ने म्रान्दोलन किया कि भिन्त-भिन्त धर्मों को मानने वालों को मधिकार होना चाहिये कि वे श्रापस मे शादी-विवाह कर सकें। इस श्रान्दोलन का परिणाम यह हुमा कि १८६२ में 'स्पेशल-मैरेज-एक्ट' पास हुमा। इस विवाह मे तर-वधू को यह घोषित करना पडता है कि वे ईसाई यहदी, हिन्दू, मुसलमान, पारसी, बौद्ध, सिक्ख या जैन किसी धर्मको नहीं मानते। इसका यह मतलब नहीं कि व्यक्ति के ऊपर किसी धर्म-विशेष का कोई नियम लागू नही हो सकता। सम्पत्ति, दायभाग म्रादि के सम्बन्ध में उनके वैयक्तिक-धर्म के कानून ही उन पर लाग्न समभे जाते हैं। इस कानून के ब्रघीन विवाह करने वाले की पत्नी या विवाह करने वाली का पति जीवित नहीं होना चाहिए, वर की १ = तथा बच्च की १४ वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए, अगर दोनों में से कोई भी पक्ष २१ वर्ष से कम आयु का है, तो उसे अपने अभिभावकों की स्वीकृति लेनी चाहिए, दोनों का रुधिर का सम्बन्ध नही होना चाहिए। विवाह से पूर्व दोनो में एक को विवाह का नोटिस देना चाहिए, नोटिस रजिस्ट्रार के यहाँ दर्ज होना चाहिए, इसके १४ दिन बाद यह विवाह हो सकता है। प्राय: इस कार्य के लिए

डिरिट्रक्ट मैजिस्ट्रेट रजिस्ट्रार का कार्य कर देता है। उसके सामने तीन साक्षियों को लाना होता है जिसके समक्ष वर-वधू एक-दूसरे के लिए यह प्रतिज्ञा करते हैं कि हम एक-दूसरे को पित-पत्नी स्वीकार करते हैं। इसके बाद उन्हें विवाह का एक सर्टीफिकेट दे दिया जाता है। यह विधि विवाह को ठेका मानकर चली है ब्रतः इसमें तलाक हो सकता है।

१६२३ में इस विधान में कुछ परिवर्तन किया गया। इस प्रकार का विवाह करने वालों को दत्तक पुत्र लेने का अधिकार न रहा, और अगर जो व्यक्ति इस प्रकार से अपनी शादी कृंरता था वह किसी का दत्तक-पुत्र होता था तो उसे उस परिवार से अपने को पृथक समक्षना होता था।

#### प्रश्न

- १ प्राचीन भारत में कौन-कौन-से विवाह के प्रकार माने जाते थे?
- २. हिन्दू-समाज में विवाह के कौन-कौन-से भावश्यक तत्व है?
- ३. मुसलमानों के विवाह के विषय में ब्राप क्या जानते हैं ?
- ४. ईसाइयों की विवाह-प्रया क्या है ?
- प्र. सिक्लों में विवाह कैसे होता है ?
- ६ संसार की जंगली जातियों (जन-जातियों) में विवाह के कौन-कौन से प्रकार प्रचलित हैं ?

## y

# सामाजिक-विधान तथा उसका विवाह पर प्रभाव

(SOCIAL LEGISLATION AND ITS EFFECT ON MARRIAGE)

प्राचीन-काल मे जब राज्य का उदय नहीं हुआ था, समाज का शासन 'प्रयाख्री' द्वारा होता था। समाज को जो त्र्यवस्था मावश्यक लगी वह चल पड़ी, भीर जो देर तक चलती रही, वह 'प्रया' हो गई। भव इस 'प्रथा' को तोडना कठिन हो गया। जो इस 'प्रथा' की तोडता उसका बहिष्कार हो जाता । जब समाज में राज्य का प्रादर्भाव हुआ, तब 'प्रथा' का स्थान 'कानून' ने ले लिया। कभी-कभी तो 'प्रथा' तथा 'कानून' ऐसे थे जिनकी परिस्थितियों के अनुसार आवश्यकता थी. कभी-कभी ऐसी स्थिति भी उत्पन्न होती रही जब परिस्थितियां बदल गई, परन्तु 'प्रथा' तथा 'कानून' वही रहे । जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तब दो बातें होती हैं। या तो लोग स्वयं उस 'प्रया' या 'कानून' को बदलने का झान्दोलन करते हैं, या राज्य के हस्तक्षेप से वह 'प्रया' या 'कानून' बदल कर नवीन परिस्थितियों के भनुसार नया कानून बना दिया जाता है। जब व्यक्तियो द्वारा 'प्रथा' या 'कानून' को का भान्दोलन होता है तब उसे 'सुधार' (Reform) कहते है, जब राज्य के हस्तक्षेप से यह कार्य होता है तब उसे 'कानून' (Law) या 'विधान' (Legislation) कहते हैं।

देश में सदा दो तरह के विचारक रहा करते हैं— रूढ़िवादी तथा
मुधारवादी। रूढिवादी पुरानी प्रथा के दास बने रहना पसन्द करते हैं।
वे पुराना जो-कुछ भी हो उसे बदलना नही चाहते। सुधारवादी
परिस्थितियों के बदल जाने पर 'प्रथा' या 'कानून' को बदल देना चाहते
हैं। सुधारवादियों में भी कुछ लोग जनता में आन्दोलन द्वारा परिवर्तन
चाहते हैं, राज्य द्वारा नहीं, कुछ लोग चाहते हैं कि राज्य अपने
हस्तक्षेप द्वारा परिवर्तन कर दे, फिर जनता अपने-आप इन परिवर्तनों
के लिये अपने को अभ्यस्त कर लेगी। कभी-कभी तो जनता राज्य द्वारा
किये गये परिवर्तन को बिना ज्यादा ननु-नच के स्वीकार कर लेती है, कभीकभी राज्य द्वारा किए गए परिवर्तन को देखकर जनता चौक उठती हं
श्रीर राज्य ही डांवाडोल हो जाता है।

राज्य को चाहिए कि जिस सामाजिक-प्रथा मे कानून द्वारा परिवर्तन लाना चाहे, पहले उसके लिए जन-मत तैयार कर ले। जब जनता के भ्रान्दोलन द्वारा किसी रूढि की, प्रथा की जान निकल जायगी तब, बोदी दीवार को जैसे एक घनके से गिरा दिया जाता है, वैसे थोथी प्रथा को कानून के हल्के-से धक्के से खत्म कर दिया जा सकता है। बिना जन-मत तैयार किये कभी-कभी राज्य के हस्तक्षेप से लेने के देने पड़ जाते हैं। कभी-कभी जब कोई प्रथा समाज को सीधा नुकसान पहुँचा रही हो, तब राज्य को इन्तजार किये बिना हस्तक्षेप करने की जरूरत पड जाती है। उदाहरणार्थ, जब सती-प्रया इस देश में प्रचलित थी तब लाई बेंटिक ने जबर्दस्ती इस प्रथा को रोकने का कानून बनवाया। लोग कहते थे, यदि ऐसा कानून बना तो उपद्रव हो जायगा। परन्तु जीते-जी एक स्त्री को भाग की लपटो की मेंट कर देना-इससे ऋर कार्य क्या हो सकता था। ऐसी हालतो मे पहले-पहल कुछ हलचल होती है, पीछे जनता स्वयं उसी प्रकार सोचने लगती है, जनता का विचार-स्तर ऊँचा उठ जाता है। परन्तु भच्छा यही है कि राज्य उन्ही बातो में हस्तक्षेप करे जिनसे समाज को सीधा नुकसान पहुँच रहा हो, बन्यथा जन-मत जागत हो जाने पर हस्तक्षेप करे। वहाँ भी ऐसे कानून बनाये जो 'इच्छात्मक-विधान' (Permissive legislation) हों। उदाहरणार्थ, जात-पाँत तोड़ कर शादी होनी चाहिए या नहीं—यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर जबर्दस्ती किसी को जात-पाँत तोड़ने के लिए बाधित नहीं किया जा सकता, परन्तु अगर कोई तोड़ना चाहे तो उसे तोड़ने की भी आजादी न हो यह भी ठीक नहीं प्रतीत होता। ऐसी हालत मे, जो तोड़ना चाहे, उन्हें जात-पाँत तोड़- कर शादी करने की इच्छा को पूर्ण करने की आजा देने मे क्या हवं है ?

भारत में १६ वीं-शताब्दी के मध्य-काल से बीसवी शताब्दी के मध्य-काल तक धनेक सामाजिक सुधार हुए। इन सुधारों का भारत की विवाह-प्रथा पर जबवंस्त प्रभाव पड़ा तथा आगे पड़ने बाला है, धतः इन सामाजिक-सुधारो पर तथा उनके परिणामस्वरूप विवाह-प्रथा पर पड़ने बाले प्रभाव पर हम यहाँ विचार करेंगे। मुख्य-मुख्य सामाजिक-सुधार निम्न थे—

#### सती-प्रथा के ग्रन्त का कानून—१८२६ (Regulation No. XVII, 1829)

१६२६ से पहले भारत में विषवा के अपने पित की चिता पर सती हो जाने की प्रथा थी। इस प्रथा का नाम लेकर भारतीय-स्त्री के चरित्र की कितनी ही सराहना क्यों न की जाय, यह कहे बिना नहीं रहा जाता कि जिस समाज में ऐसी प्रथा चल रही थी वह समाज अत्यन्त िरी हुई हालत में था। लाई बैटिक का, जो उस समय भारत का शासक था, कहना था कि सिर्फ़ उसके शासन-काल में केवल बंगाल में ६०० सती हुई। उस समय के समाज-सुभारक राजा रामुमोहन राय (१७७२-१८३३) ने इस विषय में बड़ा आन्दोलन किया। इस प्रथा के अनुसार विधवा को अफ़ीम खिलाकर बेहोस कर दिया जाता था और जबर्दस्ती उसे चिता पर रख दिया जाता था। आग की अपटो से वह बचकर भामने की कोशिश्व करती भी, तो बड़े-बड़े बाँसों से उसे घकेल-चकेल कर

बहीं भस्म कर दिया जाता था। जिस समय यह कानून बन रहा था उस समय कई लोगों को यह डर था कि कहीं इस कानून के बनने से देश में विद्रोह न उत्पन्न हो जाय, परन्तु ऐसा-कुछ नहीं हुमा भौर ४ दिसम्बर १६२६ को रैग्नलेशन नं० १७ स्वीकृत हुमा जिसके मनुसार जीवित-विधवा को सती करना कानून द्वारा दण्डनीय घोषित कर दिया गया।

सती-प्रथा का प्रभिप्राय यह था कि स्त्री का विधवा होकर जीना व्यर्थ है। ग्रगर स्त्री विधवा होकर पुनर्विवाह नहीं कर सकती तभी तो विधवा होकर उसका जीना व्यर्थ कहा जा सकता था भौर तभी उसके सामने सती होने का ही एक विकल्प रह जाता था। सती-प्रया पर प्रतिबन्ध लग जाने पर हिन्दू-समाज में भ्रपने-भ्राप यह प्रश्न उठ खड़ा हुगा—ग्रगर विधवा सती नहीं हो सकती, तो विधवा स्त्री विधाह क्यों नहीं कर सकती ? इसी जागृति के उत्पन्न होने का परिणाम 'विधवा-विवाह-कानून' बना।

#### २. विधवा-विवाह कानून—१८५६ (Hindu Widows Remarriage Act XV, 1856)

सती-प्रथा का घन्त होने के बाद भी विधवा-जीवन एक दासता का जीवन था। वह निवाह नहीं कर सकती थी, घर में अपराकुन की तरह जिन्दा थी। इस घवस्था के विरुद्ध जनता में धान्दोलन करने का श्रेय ईश्वरचन्द्र निद्यासागर (१८०२-१८६१) को है। ईश्वरचन्द्र निद्यासागर ने कई प्रावेदन-पत्रों पर हस्ताक्षर करवा कर उन्हें सरकार के पास भिजवाया। पक्ष में २५ ग्रावेदन-पत्र धाये जिन पर ५,००० हस्ताक्षर थे, जिनमें निधवा-निवाह को कानून का रूप देने की माँग थी; निपक्ष में ४० ग्रावेदन-पत्र धाये जिनमें ५०-६० हजार हस्ताक्षर थे। फिर भी सर जै० पी० ग्रान्ट के उद्योग से निधवा-निवाह का कानून १८५६ में बन गया जिससे विधवा को विवाह करने की ग्राज्ञा दे दी गई। विधवा-निवाह कानून बन जाने का परिणाम यह तो नहीं हुआ कि सब विधवाएँ

किवाह करने ही लगीं, परन्तु इतना धवश्य हुआ कि जो विषका स्त्री विवाह करना चाहती है उसके मार्ग में कोई कानूनी वाका नहीं रही।

#### ३. विशेष-विवाह-कानून—१८७२, १६२३, १६४४ (Special Marriage Act—1872,1923,1954)

१८७२ के कानून के अनुसार उन सब लोगों को आपस में विवाह करने का अधिकार दे दिया गया जो किसी वर्म को नहीं मानते। अगर कोई कहे कि वह ईसाई भी नही है, मुसलमान भी नहीं है, हिन्दू भी नहीं है, वह किस कानून के अन्तर्गत शादी करे? विवाह तो अब तक धर्म का एक अंग समभा जाता रहा है और अत्येक विवाह किसी-न-किसी धर्म के अन्तर्गत होता रहा है, परन्तु जो किसी धर्म को नही मानता उसे भी तो विवाह का अधिकार है। १८७२ के विशेष-विवाह-कानून के अनुसार ऐसे व्यक्तियों को भी विवाह का अधिकार वे दिया गया।

१८७२ के 'विशेष-विवाह-कानून' के अनुसार यह आवश्यक है कि जो स्त्री-पुरुष विवाह करने लगे हैं उनमें से कोई विवाहित न हो, अर्थात् एक-पत्नी तथा एक-पति-व्रत इस विवाह का आवश्यक अंग है। इसमें तलाक की भी छूट है।

१६५४ में १८७२ का कानून रह कर दिया गया। १६५४ के इस कानून के अनुसार बातें तो प्रायः सब वही रहेंगी जो १८७२ के कानून में थी, परन्तु अब हर कोई किसी धर्म या जाति में विवाह कर सकेगा, और जैसे पहले कहना पड़ता था कि मैं किसी धर्म को नही मानता—ऐसा अब नहीं, कहना पड़ेगा। विवाह का रूप एक-पति-व्रत तथा एक- पत्नी-व्रत आवश्यक होगा, तलाक का भी दोनों को अधिकार होगा। २१ वर्ष की आयु हो, तो माता-पिता की आजा लेने की आवश्यकता नहीं, १८ वर्ष से २१ वर्ष के बीच की आयु हो, तो माता-पिता की आजा लेने की आवश्यकता होगी। अवर

र्रावस्ट्री के समय दोनों में कोई पागल हो या मूढ़ हो, तो ऐसे विवाह पर एतराज किया जा सकता है। इस कानून के भन्तर्गत जो शादी होगी उसमें हिन्दू, बौढ़, सिक्ख या जैन जो-कोई भी शादी करेगा, यह माना जायगा कि उसका अपने परिवार से सम्बन्ध-विच्छेद हो गया।

# ४. बाल-विवाह-निषेध कानून (शारदा-एक्ट) \_\_१६३० (Child-Marriage Restraint Act, 1930)

१६२७ में डॉ॰ हरिसिंह गौड के बिल के अनुसार एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम 'एज ऑफ कनसेंट कमेटी' (Age of Consent Committee) था। इसने इस बात का पता लगाया कि किस आयु में विवाह हानिप्रद नहीं है। इस कमेटी के परिणाम-स्वरूप १६३० में 'शारदा-एक्ट' स्वीकृत हुआ जिसमें विवाह-योग्य आयु लड़के के लिए १४ निश्चित की गई। इससे कम आयु का विवाह दण्डनीय घोषित कर दिया गया। उसके बाद १६३८ तथा १६४६ में इस कानून में कुछ सुधार हुए जिनके अनुसार विवाह-योग्य आयु लड़के की १८ रही, परन्तु लड़को की १४ कर दी गई। इस विधान के बनने से पहले दुधमुँही बच्चियों की शादियाँ अपने देश में होती थीं, अतः बाल-विवाह को रोकने में इस विधान का बड़ा हाथ रहा।

#### ४. आर्थ विवाह कानून—१९३७ (Aryan Marriage Validating Act, 1937)

मार्यसमाजी जात-पाँत को सिद्धान्तानुसार नहीं मानते। वैसे तो थोड़े ही मार्यसमाजी ऐसे हैं, जो व्यावहारिक रूप मे जात-पाँत को न मानते हों, जैक्चर बहुत देते हैं, परन्तु फिर भी कई व्यवहार से भी धार्यसमाजी होते हैं, वे जात-पाँत तोडकर शादी करते हैं। हिन्दू-विवाह तो भ्रपनी चाति में ही हो सकता है भीर 'स्पेशल मैरेज एक्ट' में यह कहना पड़ता था कि वह हिन्दू भी नही है। ऐसे धार्यसमाजियों के लिए को हिन्दू भी कहलाना चाहें धौर जात भी तोड़ना चाहें, श्रीयुत बनस्यामसिंह के उद्योग से यह बिल बना जिसका विवाह-प्रथा पर काफ़ी प्रभाव पड़ा।

#### ६. हिन्दू-विवाह वैधीकरण कानून-१६४६ (Hindu Marriages Validating Act, 1949)

धार्यसमाजियों के लिए तो १६३७ में भार्य-विवाह-कानून बन गया, परन्तु जो हिन्दू जात-पाँत तोड़कर विवाह करना चाहते वे भौर भार्य-समाजी भी नहीं थे, उनके लिये क्या हुआ ? उनके लिए पहले-पहल १९४६ में 'हिन्दू-विवाह-नियोंग्यता-निवारण भिष्ठिनयम' (Hindu Marriage Disabilities Removal Act) बना, परन्तु इसका तथ्य सिर्फ हिन्दुभो की उप-आतियों में जहाँ विवाह नहीं हो सकता या उस विवाह को वैधानिक स्प देना था, हिन्दू किसी भी जाति में विवाह कर सके—यह नहीं था । सबसे पहले मैसूर में १९४६ में भारत से समस्त हिन्दुभो के लिए हर जाति-उपजाति में विवाह को वैध करार देने का उक्त कानून बना विया गया।

## ७. हिन्दू विवाह तथा तलाक ग्रधिनियम—१९५५ (Hindu Marriage and Divorce Act, 1955)

हमारे सामाजिक-विधान में पिछने एक-डेढ़ हजार साल से बहुत थोड़ा परिवर्तन हुआ। आज की और हजार साल पहले की दुलियाँ में जमीन-आस्मान का मन्तर होगा, फिर भी वही पुरानी सामाजिक-व्यवस्था जो भव से हजार साल पहले थी भाज भी प्रचलित है। परिस्थितियाँ बदल गई किन्तु कानून नही बदला। यही कारण है कि वर्तमान कानून हमारे समाज की ज्वलन्त-समस्याओं को हल करने में भसमर्थ सिद्ध हो रहा है। उदाहरणार्थ, उस स्त्री के सम्मुख, जिसका पति उसके जीते-जी दूसरा विवाह कर लेता है, परित्यक्ता के रूप में दुःखी तथा अपमानपूर्ण जीवन बिताने के अतिरिक्त दूसरा क्या उपाय है ? वह स्त्री जिसका पल्ला एक बार किसी व्यक्ति से बंघ गया, चाहे वह पागल या हद्द दर्जे का मुखं ही क्यो न हो, उससे भाजन्म छूट नहीं सकता। एक लखपित की कन्या यदि विधि के विधान से किसी गरीब घर में ब्याह कर चली गई, तो अपने पिता की सम्पत्ति से उसे कोई हिस्सा नही मिल सकता, क्योंकि कानन के अनुसार केवल पुत्र ही सम्पत्ति का मालिक हो सकता है, पुत्री नहीं। एक विधवा पत्नी को ग्रपने पति की कमाई पर भी पूरा अधिकार नहीं मिलता । इस प्रकार हमारी वर्तमान कानून-व्यवस्था ने हमारे समाज की समस्यात्रों को हल करने के स्थान में नई समस्याएँ खड़ी कर दी हैं। ये समस्याएँ पिछले सौ डेढ-सौ सालो से तो इतनी उम्र हो चुकी है कि लगभग सभी समाज-शास्त्रियों का ध्यान अपने-अपने समय में इनकी श्रोर जाता रहा है। पिछले तीस साली में तो हमारे विधान-निर्माताओं ने नई परिस्थितियों के अनुकुल एक नया हिन्दु-कोड बनाने के अनेक सगठित प्रयत्न किये। 'हिन्दू-विवाह तथा तलाक श्रधिनियम' इन्ही प्रयत्नो का परिणाम है। यह मधिनियम समाज की मधिकाश ज्वलत समस्यामी का. जिनमें से कुछ की ग्रोर ऊपर संकेत किया गया है, हल करने का प्रयत्न करता है। इसके द्वारा हमारे सामाजिक प्रवनी की किस प्रकार सुलक्काया गया है तथा हमारे सामाजिक जीवन पर इसका व्यावहारिक रूप में क्या प्रभाव पडेगा, इस सम्बन्ध में विचार करना आवश्यक है।

'हिन्दू विवाह तथा तलाक ग्राधिनियम' का भारत मे प्रचलित विवाह-प्रथा पर जबदंस्त प्रभाव पडेगा इसलिए इस ग्रिधिनियम के दोनो भागो—विवाह तथा तलाक—पर हम यहाँ कुछ विस्तार से विचार करेंगे—

#### विवाह

विवाह सामाजिक-जीवन का स्राघार है। विवाह ही पारिवारिक-जीवन के मुख तथा उसकी शान्ति का वास्तविक स्रोत है। प्राचीन-काल में हमारे यहाँ विवाह की एक भावर्श प्रथा का जन्म हुमा था, जिसके भनुसार स्त्री भौर पुरुष को विकास की समान सुविधाएँ प्राप्त शीं। दोनों के लिए समान नियम, समान कत्तं व्या तथा समान भिषकार थे, इसलिए उस समय का समाज भत्यन्त उन्नत भवस्था में था। कालान्तर में हमारी विवाह की प्रथा विकृत तथा दूषित हो गई। स्त्री तथा पुरुष दोनों के लिए भिन्न-भिन्न नियम बनाये गए, दोनों को एक ही माप-दण्ड से मापने के स्थान में भिन्न-भिन्न पैमानों से मापा जाने लगा। स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध में प्रचलित इस दोहरे माप-दण्ड ने समाज में भनेक गम्भीर बुराइयाँ उत्पन्त कर दी जिनका निराकरण इस विवाह-मधिनियम का उद्देश्य है।

(क) एक-विवाह--सबसे बडी बुराई जो पैदा हुई वह थी पुरुष के लिए बहु-विवाह की छूट। अब तक इस अधिनियम के बनने से पूर्व यह भवस्या थी कि पुरुष एक स्त्री के जीते-जी दूसरी शादी कर सकता था। पुरुष चाहता तो भनेकों विवाह करता चला जा सकता था भीर भनेक स्त्रियों को सकारण घोर नारकीय-जीवन बिताने के लिए बाध्य कर सकता था । कौन नही जानता कि किसी भी स्त्री के लिए अपनी आंखों के सामने भपने पति को दूसरा विवाह करते देखना विष पी लेने से भी अधिक दुखदायी है। सह-पत्नी के घर में आते ही पहली पत्नी को घोर धपमान-जनक जीवन बिताना पड़ता है, पुरुष के दूसरे विवाह का प्रभाव पहली पत्नी के बच्चों पर भी इतना बुरा पड़ता है कि उनका सारा जीवन ही विश्वखलित और कठित हो जाता है। समस्त पारिवारिक जीवन को सब्यवस्थित तथा कड़वा बना देने वाली बहु-विवाह की यह प्रया १६५६ में 'हिन्दू विवाह तथा तलाक'-कानून (Hindu Marriage and Divorce Act, 1955) के स्वीकृत हो जाने के साथ समाप्त हो गई। इसके धनुसार पुरुष के ऊपर भी वही प्रतिबन्ध लग गया जो स्त्री पर था। जिस प्रकार स्त्री के लिए पति के जीवित रहते दूसरा विवाह त्याज्य माना जाता था, उसी प्रकार पुरुष के लिए भी पहली पत्नी के जीवित

रहते दूसरा विवाह करना त्याज्य हो गया । ग्रब एक पत्नी के रहते यदि कोई पति दूसरी शादी करेगा, तो वह कानून की दृष्टि में अपराधी और दण्डनीय माना जायेगा । इस प्रकार यह कानून स्त्री ग्रीर पुरुष दोनो के लिए 'एक-विवाह' की ग्रनिवार्यंता को राजकीय नियम का रूप दे देता है। बहु-दिवाह की प्रया समाप्त होने से, समाज में स्त्री ग्रीर पुरुष के बीच जो विषमता थी, ग्रीर उस विषमता के कारण स्त्री को जिन कठिनाइयो का सामना करना पडता था, उन सब का भव भ्रन्त होगा । स्त्री के वैवाहिक-जीवन में एक सुरक्षा की मावना पैदा होगी, ग्रौर उसका जीवन पहले से अधिक सम्मानपूर्ण और सुझी बनेगा। इस नियम का परिणाम यह भी होगा कि हमारे समाज मे अब तक जो अनमेल विवाह होते थे, वे बहुत हद तक रुक जायेंगे। पुरुष को नियोकि अनेको शादियाँ करने का ग्रधिकार था, उसे छोटी ग्रायु की कुमारी कन्याग्रों से भी शादी कर लेने की छूट थी, जो अब भी है, इसलिए अक्सर साठ वर्ष के बुड्हे ग्रद्धारह-बीस वर्ष की कुमारी लडिकयों से विवाह करते पाये जाते थे। इन श्रनमेल विवाहो से भी समाज के ग्रन्दर भीषण बुराइयाँ पैदा होती थी। भव इस 'एक-विवाह' सम्बन्धी कानून का परिणाम यह होगा कि समाज बहुत से दोषों से मुक्त होकर उन्नति के मार्ग पर तीव्र गति से बह सकेगा।

(ल) प्रन्तर्जातीय-विवाह—'हिन्दू-विवाह तथा तलाक अधिनियम' के द्वारा प्रन्य जो सुघार हुए उनमें से एक यह है कि अब हिन्दुओं के अन्तर्गत एक जाति के लोगो को दूसरी जाति मे विवाह करना अधिक सुविधापूर्ण हो जायेगा। अभी तक कानून 'अनुलोम' विवाहों को तो मान्यता देता था, 'प्रतिलोम' विवाहों को नहीं। बाह्मण का लड़का यदि क्षत्रिय की लड़की से शादी कर लेता, तो वह वैधानिक तथा शास्त्र-सम्मत माना जाता था, किन्तु यदि बाह्मण की लड़की क्षत्रिय था वैस्य के लड़के से विवाह कर लेती थी तो कानून उसे अवैध मानता था। इस प्रकार के 'प्रतिलोम' विवाह जब होते थे, तो उन्हें वैधानिक रूप देने के

लिए 'स्पेश्यल मैरिज-एक्ट' की शरण लेनी पड़ती बी भौर अदालत के सामने कहना पड़ता था कि हम किसी बमं को नहीं मानते क्योंकि 'स्पेश्यल मैरिज एक्ट' के अनुसार वही लोग शादी कर सकते वे जो यह घोषणा करें कि वे किसी बमं के अनुयायी नहीं हैं। धव जो परिवर्तन हुआ है उससे 'प्रतिलोम' विवाह भी वैधानिक माने आर्येगे, अर्थात् यदि बाह्यण जाति की लड़की का विवाह सित्रय के साथ, या अत्रिय कन्या का विवाह वैश्य लड़के के साथ हो जाये, तो हिन्दू रहते हुए भी ऐसे विवाह की सन्तान को सम्पत्ति सम्बन्धी सभी अधिकार प्राप्त होंगे। इससे अन्तर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन मिलेगा और जाति-प्रया के, जो राष्ट्र की एकता ये भ्राज सब से अधिक वाषक है, उन्मूलन का मार्ग खुल जायेगा।

(ग) समोत्र तथा श्रसपिंड विवाह-मन तक हिन्दू अपने मोत्र भीर भ्रपने प्रवर में शादी नहीं कर सकते थे। समन्ता यह जाता है कि एक गोत्र तथा एक प्रवर के लोग एक ही वंश से रुधिर के सम्बन्ध से जुड़े हुए हैं। परन्तु यह बात गलत है क्योंकि भिन्न-भिन्न जातियों में एक ही गोत्र पाया जाता है, और एक ही माता-पिता की सन्तान में भिन्न-भिन्न गोत्र पाये जाते हैं। उदाहरणार्थ, बलराम तथा श्रीकृष्ण भाई-भाई थे परन्तु पुराणो के अनुसार बलराम का गोत्र गार्थ तथा श्रीकृष्य का गोत्र गौतम था। गोत्र मे विवाह के निषेष का परिणाम यह है कि श्री करन्दीकर के कथनानुसार एक हिन्दू के लिये २१२१ लडकियाँ वर्जित हैं। इसी प्रकार हिन्दू का सर्पिड में विवाह नहीं हो सकता । सर्पिड का अर्थ है - अपनी पीढी का। हिन्द्भों के विचार के अनुसार पिता की सात तथा माता की पाच पीढियां छोडकर विवाह होना चाहिए । अब जो १६५५ का कानन बना है उसके अनुसार गोत्र का सगढा हटा दिया गया है और सपूर्ण भारत में किसी भी मोत्र में विवाह हो सकता है। ऐसा विवाह पहले अवैध मामा जाता था, अब वैध माना जामगा। स्पिंड मे भी पिता की सात की जगह पाच तथा माता की पांच की जयह

तीन पीढ़ियाँ निषिद्ध कर दी गई हैं। इससे विवाह का क्षेत्र जो अस्यन्त सीमित हो गया वा विस्तृत हो जायेगा।

(छ) बाल-विवाह पर रोक-१८६० में 'भारतीय दंड-विधान' (Indian Penal Code) बना । उस समय १० वर्ष से कम आय की कन्या का विवाह दण्डनीय माना गया । १८६१ में यह ग्रायु १० से बढा कर १२ वर्ष कर दी गई। जब आयु १० से १२ वर्ष की जा रही थी तब इसका हिन्दू पडितों की तरफ़ से बहुत विरोध हुआ। सर एण्डू स्कोबल जो इस सुधार के प्रस्तावक ये उन्होंने कहा कि राज्य को अपनी प्रजा के उस वर्ग के हितो की रक्षा करने का अधिकार है जो वर्ग अपनी रक्षा अपने-प्राप नहीं कर सकता। १६२४ में यह ब्रायु बढ़ा कर १३ कर दी गई। उसके बाद 'बाल-विवाह-निरोधक-मधिनियम' (Child Marriage Restraint Act) के अनुसार जिसे 'शारदा-कानून' (Sharda Act) भी कहा जाता है, १६३० में यह आयु लड़के के लिए १८ और लड़की के लिए १४ कर दी गई। इसके बाद १६३८ तथा १६४६ में इसमें फिर परिवर्तन किया गया जिसके अनुसार लडकी १५ तथा लड़का १८ वर्ष से कम की आयु में विवाह नहीं कर सकते। अभी १६५५ में जो 'हिन्दू विवाह तथा तलाक कानून' (Hindu Marriage and Divorce Act. 1955) स्वीकृत हुआ है उसमे भी विवाह की बायु लडके तथा लड़की के लिए कमशः १८ तथा १५ रखी गई है जिससे बाल-विवाह पर रोक लग जाती है।

हमारी दृष्टि से तो आयु की यह सीमा कम ही रखी गई है। विवाह की म्यूनतम आयु लड़की की १८ वर्ष से और लड़के की २५ वर्ष से कम नहीं होनी वाहिए। विवाह की आयु जितनी ऊँची होगी, भारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से हमारी भावी सन्तित उतनी स्वस्थ तथा विकसित होगी। इसके अतिरिक्त आजकल की दिनोदिन बढ़ती जन-संख्या पर भी वह प्रतिबन्ध का काम करेगी। हमे आशा है, हमारे विधान-निर्माता इस 'अधिनियम' द्वारा निर्धारित विवाह की उपरोक्त

न्यूनतम-आयु से ही सम्बुष्ट म हो जायेंगे, प्रपितु शीध्र ही उसमें उचितः। परिवर्तन करने के लिए उपयुक्त संशोधन लायेंगे।

इसी प्रकार वर्तमान 'हिन्दू बिवाह तथा तलाक श्रिभनियम' विवाह के क्षेत्र में उठती हुई अनमेल तथा बाल-विवाह जैसी अनेक ज्वलन्त समस्याओं का समाधान कर सकेगा। किन्तु फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि इस क्षेत्र में जिन सूधारों की भावश्यकता थी वे सभी इस कानुन से पूरे हो जायेंगे। इसके उपरान्त भी हमारी दृष्टि में भभी सुधार की काफी गुँजाइश है। उदाहरणार्य, विधुर के कुमारी कन्या से विवाह की प्रथा जो इस समय शिक्षित-समाज तक मे प्रचलित है, समाज के धन्दर कई जटिलतायें उत्पन्न कर देती है। इस समय ४०-५० वर्ष का विश्वर यदि चाहे तो १८--२० वर्ष की कुमारी कन्या से विवाह कर सकता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इसका परिणाम न तो कुमारी कन्या पर ही ग्रच्छा पडता है, ग्रीर न ही विश्वर के बच्चों पर। इसके अतिरिक्त समाज मे जो विधवायें हैं, उनके लिये पुनर्विवाह करना एक विषम समस्या बन जाती है, क्योंकि विधुर को जब कूमारी कन्या सरलता से मिल जाती है, तो वह विघवा से विवाह करना नहीं चाहता । इन सब विषम परिणामों का निराकरण करने का गही उपाय था कि कानून द्वारा विधुर के कुमारी कन्या से विवाह पर कोई प्रतिबन्ध लगा दिया जाता । जिस समय विवाह विधेयक पर ससद में विचार हो ँरहाथा, तब श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल ने इस ग्राशय का एक संशोधन प्रस्तुत भी किया या जिसका प्रभिप्राय यह या कि विध्र केवल विधवा से और विषवा केवल विधुर से ही विवाह कर सके-ऐसी एक शर्त और विवाह की शर्तों में ओड दी जाय। किन्त इस प्रकार की शर्त व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर कड़ा प्रतिबन्ध होगां-ऐसा कह कर सदन में यह संशोधन गिरा दिया गया । यदि उपरोक्त संशोधन मान लिया जाता, तो इस प्रधिनियम मे जो अधूरापन रह जाता है वह न रहता । हमें

विश्वास है कि निकट-भविष्य में ही वह समय आयेगा जब कि विवाह-कानून के इस दोष को निकाल दिया जायेगा ।

#### सम्बन्ध-विच्छेद (तलाक)

विवाह एक प्रटूट और धार्मिक-सम्बन्ध है---यह विचार-परम्परा हमारे समाज में बहुत देर से चली था रही है। इसमें सन्देह नहीं कि यह एक सुरूर और ऊँवी कल्पना है, किन्तु अपने समाज में इस सिद्धात का पालन गत कई शताब्दियों से एक पक्ष की ग्रोर से ही हुगा, दूसरा पक्ष तो निरतर इसका उल्लघन ही करता रहा। जहाँ तक स्त्री का सम्बन्ध रहा, वहाँ तक तो विवाह एक पवित्र सम्बन्ध माना जाता रहा, किन्तु पुरुष ने बाहा तो एक के बाद एक विवाह करता रहा, धौर एक नहीं भ्रमेक बार विवाह के 'प्रदूट' कहे जाने वाले सम्बन्ध को तोडता रहा। इसके विपरीत स्त्री को किसी भी भयकर-से-भयकर परिस्थिति में हमारा कानून पुनर्विवाह की भाजा नही देता रहा। इस एक-पक्षीय भादर्श-वादिता का परिणाम समाज के लिए ग्रत्यन्त हानिकर हुआ। एक ग्रोर पुरुष की इस स्वेच्छाचारिता से तथा दूसरी भ्रोर स्त्री पर कठोर प्रति-बन्धों के लगाने से समाज का शान्त वातावरण विक्षुव्ध तथा दूषित हो उठा। इस सारी परिस्थिति मे विवाह-सम्बन्ध की पवित्रता की रक्षा के हेत् ही यह प्रावस्थक हो गया कि विवाह के कानून मे समयानुकृत परिवर्तन भीर सशोधन किये जाये । यह वह पष्ठभूमि है जिसमे उपरोक्त 'विवाह-अिमनियम' सम्बन्ध-विच्छेद या तलाक की व्यवस्था करता है। "

तलाक-सम्बन्धी घारा इस 'अघिनियम' की सबसे अधिक विवादास्पद धारा है, किन्तु जितना भी विवाद है वह अम के कारण है। यह समभा खाता है कि तलाक की छूट मिलते ही हर-कोई अपने जीवन-साथी को तलाक देने चल पड़ेगा। ऐसी स्थिति में बिवाह की सस्या का नाझ हो जायेगा, समाज में अध्यवस्था छा जायेगी, धर्म का लोप हो जायेगा। किन्तु यह सब अम है क्योंकि इस अधिनियम के अनुसार किन्ही विशेष ही परिस्थितियों में और कठोर प्रतिबन्धों के अन्दर तलाक का अधिकार दिया गया है। जिन श्रवस्थाओं तथा परिस्थितियों में इस कानून के शनुसार सम्बन्ध-विच्छेद की ज्यवस्था की गई है, वे निम्न हैं:---

- (क) यदि पति-पत्नी दोनों में से कोई-एक व्यक्तिवारपूर्ण जीवन बिता रहा हो, तो उसे दूसरा तलाक दे सकता है।
- (स) दोनों में से एक यदि हिन्दू-धर्म छोडकर धन्य धर्मायलम्बी हो जाय, तो दूसरे की उससे संबंध-विच्छेद करने का धर्षिकार होगा ।
- (ग) यदि पति या पत्नी दोनों में से कोई-एक तसाक की अर्थी देने के समय पिछले तीन साल से ब्रसाच्य रूप से पागल रहा हो, तब भी दूसरे पक्ष को तलाक की ब्राज्ञा मिल सकती है।
- (घ) यदि पति या पत्नी में से कोई मयंकर भीर मसाध्य कुंब्छ-रोग से अथवा सकामक यौन-रोग से पीड़ित हो, भीर लगातार तीन वर्ष तक इलाज कराने पर भी ठीक न हुआ हो, तो दूसरे पक्ष को तलाक का अधिकार होगा।
- (ङ) यदि दोनों पक्षों में से कोई-एक सांसारिक जीवत छोड़कर वैरागी हो गया हो, तो दूसरे पक्ष को तलाक मागने का अधिकार होगा।
- (च) दोनों पक्षो में से यदि कोई-एक सात साल तक लापता रहे, तो दूसरा पक्ष तलाक का प्रस्ताव कर सकेगा।
- (छ) इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व यदि किसी पुरुष ने दूसरी शादी कर ली है, और उसकी पहली स्त्री जीवित है, तो पहली स्त्री को अधिकार होगा कि वह अपने पति को तलाक देकर अपने दुःशी जीवन से मुक्त हो आये।
- (ज) विवाह हो चुकने के तीन साल बाद ही तलाक के लिए प्रावे-दन-पत्र दिया जायगा, इससे पूर्व नहीं। तलाक मिल जाने के भी एक साल बाद तक कोई पुनविवाह न कर सकेगा।

उक्त अवस्थाओं को देसते हुए यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि तलाक की जो शर्ते रखी गई हैं, वे काफ़ी कठोर हैं, और इनके रहते हुए सम्बन्ध-विच्छेद करना कोई हैंसी-सेल नहीं होगा। स्त्री-पुरुष बहुत विवशता की हालत में ही इस प्रिषकार का प्रयोग करेंगे क्यों कि बो लोग विवाह करते हैं वे एक-साथ रहकर सुखमय जीवन बिताने के विचार से ही इस बन्धन में बंधते हैं। विवाह को संस्था को तलाक से किसी प्रकार का खतरा नहीं है क्योंकि विवाह मनुष्य की स्वामाविक प्रवृत्ति पर धाधा-रित है, और इसलिए वह किन्ही बाह्य-साधनों से नष्ट नहीं हो सकता।

तलाक की प्रथा ग्रपने देश के लिए बिलकुल नई बीज भी नहीं है। इस समय भी ७५ प्रतिशत जनता में यह प्रचलित है। यह बात दूसरी है कि इस समय यह ग्रांधकतर वर्ण-रहित जातियों तक ही सीमित है। जाह्मण, क्षत्रिय तथा वैद्यों में इस प्रथा का समावेश प्रथम बार इस प्राधिनियम द्वारा ही होगा। इस समय नीची जातियों के अन्दर तलाक भिन्न-भिन्न रूपों में प्रचलित है—कहीं 'छूट' की शकल में, ग्रौर कहीं दूसरे किसी रूप में। वर्तमान कानून तलाक के भिन्न रूपों में एकरूपता लायेगा, उन्हें एक दृढ़ सुव्यवस्था में बाँध देगा और जहीं श्रव छीटी जातियों में मामूली-सी बातो पर तलाक हो जाता है, वैसा न होकर, ऊपर विणत की हुई कठोर अवस्थाओं में छोटी तथा बडी जातियों में तलाक हो सकेगा।

सम्बन्ध-विच्छेद को कानूनी स्वीकृति मिल जाने का प्रभाव हमारे सामाजिक जीवन पर स्वास्थ्यकर पडेगा। ग्रव स्त्री को व्यभिचारी, पागल, घृणित रोगो से पीड़ित पित के साथ इच्छा के विरुद्ध रहने को मजबूर न होना पडेगा। ग्रात्म-निर्माण का मानवोजित अधिकार स्त्री को प्राप्त हो जाने पर उसके ग्रन्दर मानवीय ग्रुणो का विकास हो सकेगा। स्त्री शौर पुरुष के बीच विषमता की खाई को पाटने में भी यह धिक सहायक सिद्ध होगा। ग्रभी तक तराजू का एक पलडा जैंचा भीर एक नीचा था, ग्रव ये दोनों पलडे बराबर के स्तर पर भा जायेंगे, समाज मे विषमता का लीप होने से मुख तथा शान्ति का जदय होगा।

#### उत्तराधिकार ग्रिधिनियम-१९५६

'हिन्द्घो का उसराधिकार का कानून' (Hindu Succession Act, 1956) 'दिवाह-कानून' से भी अधिक महत्वपूर्ण है। स्त्री 'विवाह-अधि-नियम' द्वारा प्रदान की गई स्विधाओं का लाम आर्थिक-प्रविकारों को प्राप्त करके ही उठा सकती है। 'उत्तराधिकार-अधिनियम' स्त्री को सम्पत्ति-सम्बन्धी कई महत्वपूर्ण ग्रधिकार देता है। ग्रभी तक स्त्री को सम्पत्ति में किसी प्रकार का श्रिषकार प्राप्त नहीं था। वह प्राधिक दृष्टि से पूर्णतया पराधीन थी। जीवन के हर क्षेत्र में उसे अपने भरण-पोषण के लिए पुरुष का आश्रय लेना पडता था। "पिता रक्षति कौमारे मर्ता रक्षित यौवने । पुत्राः रक्षन्ति वार्धक्ये न स्त्री स्वातन्त्र्यमहंति ।"-- प्रवात्, स्त्री को स्वतन्त्र नही रहना है, उसे सदा पिता, पति तथा पूत्र के प्रधीन ही रहना उचित है। इस शास्त्र-वाक्य पर ही हमारा भव तक का उत्तरा-धिकार कानून ग्राधारित था। इस पराधीनता से स्त्री की परिवार तथा समाज में स्थिति बहुत नीचे गिर गई। उसका सामाजिक ही नहीं, नैतिक मघ:पतन भी हम्रा । मघ:पतन के इस गतं से स्त्री को निकालने का एक ही मुख्य उपाय था। वह उपाय यही था कि स्त्री को माथिक स्वतन्त्रता मिले । यह 'उत्तराधिकार-कानुन' सम्पत्ति सम्बन्धी इस प्रावश्यक श्रध-कार को स्त्री को प्रदान करके उसकी चहुँमुखी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अनुसार स्त्री को पुत्र, पत्नी तथा माता के रूप में सम्पत्ति-विषयक जो ग्रधिकार मिले हैं, वे निम्न हैं:---

(क) परनी के रूप में स्त्री को उसके पित की सम्पत्ति में अधिकार देने का पित्ना कानून १९३७ में बना जिसके अनुसार पित की मृत्यु के पश्चात् उसके पुत्र और पुत्रियों के साथ उसकी विधवा स्त्री को बरा-बर का हिस्सा मिलता था। किन्तु इस कानून के अनुसार विश्ववा का अपने हिस्से पर पूर्ण स्वत्व नहीं था। वह इस प्रकार प्राप्त की हुई अपनी जायदाद को अपनी इच्छानुसार नहीं वर्त सकती थी। दान में या

उपहार में उसे नहीं दे सकती थी, इस सम्पत्ति को बेचने का भी उसे प्रिष्ठकार न था। शब यह 'उत्तराधिकार-कानून' विश्ववा स्त्री को अपनी आयदाद पर सीमित नही, पूर्ण अधिकार प्रदान करता है। शब वह जिस प्रकार चाहेगी अपने हिस्से की जायदाद का उपयोग कर सकेगी। सन्तान न होने की दशा में वह पूर्ण जायवाद की मालिक होगी। अगर वह पुन-विवाह कर केगी, तो वह सम्पत्ति, शगर पति से मिली थी, तो पति के परिवार को, और शगर पिता से मिली थी, तो पिता के परिवार को लौट आयेगी।

- (क) नाता के रूप में—भारत के दक्षिण-पश्चिम भाग मे प्रचलित 'मरुमकटस्यम' नातृन को छोड़कर भारत की ग्रन्य किसी भी दाय-प्रणाली के धनुसार माता का पुत्र की सम्पत्ति मे अब तक कोई भाग नही था। पुत्र की मृत्यु के बाद माता को ग्रंपनी पुत्र-वधू की दया पर ग्राश्चित रहना पड़ता था। सास-बहू के सम्बन्ध थोड़े ही परिवारों मे स्नेहपूर्ण होते हैं। ऐसी परिस्थित में उसका जीवन बहुधा दु:समय बन जाता है। माता को पुत्र-वधू ग्रौर पौत्र-पोत्रियों की दृष्टि मे एक प्रतिष्ठित स्थान प्रदान करने की दृष्टि से माता को भी पुत्र की सम्पत्ति में उसके पुत्र-पौत्रयों तथा पत्नी के समान एक भाग यह ग्रिधिनयम देता है।
- (ग) पुत्री के कप में इस समय भारत में मुख्यतया दो दाय-प्रणाली प्रचलित हैं। 'दाय-भाग' बंगाल में तथा पजाब के कुछ हिस्सों में चलता है, भीर भारत के श्रेष लगभग दो-तिहाई भाग में 'मिताक्षरा' प्रणाली प्रचलित है। किन्तु इन दोनों में से किसी में पिता की सम्पत्ति में पुत्री का अधिकार नहीं माना जाता। हों, भारत के दक्षिण-पश्चिम तट पर ट्रावनकोर-कोजीन भादि में जहां 'मरुमकटय्यम'-प्रणाली का कानून प्रचलित है, वहाँ पुत्री को पिता की सम्पत्ति में पुत्र के बराबर ही हिस्सा मिलता है। देश के शेष भागों में जहां 'दाय-भाग' तथा 'मिताक्षरा' प्रणाली प्रचलित है, शभी तक पिता की सम्पत्ति में पुत्री का अधिकार कानून नहीं भानता। सब यह अधिनियस 'मिताक्षरा' तथा 'दाय-भाग'

प्रमाणी के बीनों में बी पुनी को जिला की 'पुनरीनी' तका 'स्वाबित - दोनों 'प्रमाण की संस्थित में हिस्सा वेता है। पिता को 'स्वाबित-सम्मार्ग में तो लड़की को जड़के के बराबर हिस्सा मिलेगा, तेकिन 'पुनरीनी-बागपाव' में सड़की को अपने 'पिता के हिस्सा में से एक ही हिस्सा मिलेगां, जुल जायंवाद में के नहीं। वह हिस्सा वो उते 'पुनरीनी-जायंवाद' में भयंने पिता के मान में से मिलेगा, लड़के के बराबर ही होगा। किए भी 'मिला- सर्ग'-प्रमाली के अनुसार कुल मिलाकर 'पेतुक-सम्माली में लड़नी की लड़के की अपेता बहुत कम मिलेगा। ही, 'दायमार्ग-प्रमाली में जहीं 'पुनरीनी' तथा 'स्वाजित' जायंवाद का कोई मेद नहीं किया जाता, लड़की को लड़के के बराबर ही हिस्सा मिलेगा। परल्यु ब्यान रक्षने की बात यह है कि 'दाय-भाग' की प्रमाली सुविकल से देश के एक-बौधाई हिस्से में प्रचलित है।

वर्तमान 'उत्तराधिकार-धिषिनियम' के अनुसार 'मिलाकारा' सथा 'दाय-भाग' प्रणाली के अन्तर्गत खड़की, लडके, विषवा-पत्नी सथा माला की किस प्रकार हिस्सा मिलेगा यह नीचे के उदाहरण से स्पष्ट ही जायमा।

(क) मितासारा के अनुसार—मान लीजिए के कुल २०,००० र० की सम्पत्ति छोड़कर गरता है। इसमें १४,००० र० की 'पैतृक'—पुन्ती- सम्पत्ति हैं, और ४,००० र० उसकी अपनी कमाई या 'स्वा-जित'-सम्पत्ति हैं। उसके वो पुत्र 'स' और 'म' हैं, एक पुनी 'म' हैं, जीविस विश्ववा पत्नी 'प' है, और जीविस माता 'म' है। अब मूर्त व्यक्ति 'क' की बो अपनी कमाई हुई 'स्वर्धवत'-सम्पत्ति ४,००० रूठ है, वह तो 'स', 'ग', 'म', 'प' और 'म' पांची में बरसार बेंट जामेगी, और दोनों लड़की, लड़की, विश्ववा-मरंगी सथा जाता—हन सबमें अत्यक्त को १,००० रूठ मिल बाएगा, सेविन मृत क्यांकित 'क' की पीतृक'—पुरत्ति जायदाव में ऐसा नहीं होगा । १४,००० रूठ मी जो पुरत्ति' प्राण्याव में एसा नहीं होगा । १४,००० रूठ मी जो पुरत्ति' प्राण्याव है, वह पहले केवल दोनों सक्कों और पिता में बेंटेगी—सर्वात् उसके तीन हिस्ते होने क्यांकि अवने संस्वावा उसके से पुत्र है। इस

प्रकार 'क', 'ख', 'ग' में से हर-एक को १,००० का मिलेंके से सब मुखः 'क' के हिस्से को १,००० का पड़ा, उसमें से नक्की, उसकी जियन-पर्सी की उसकी माता को हिस्सा मिलेगा, परन्तु स्परण रखने की जात कर हैं। 'को उसकी माता को हिस्सा मिलेगा, परन्तु स्परण रखने की जात कर हैं। 'को पिता के इस १,००० का में से वूसरों के करावर का हिस्सा की का पिता के इस १,००० का में से वूसरों के करावर का हिस्सा की का पिता के इस १,००० का में से वूसरों के करावर का हिस्सा की का पिता के इस १,००० का मिलेगा। इस प्रकार इस 'पुरतनी' १४,००० का में से वोनों पुनों 'ख' को १,००० का जीवित जियमा पत्नी 'प' को १,००० का मिलेगा। मह भी ध्यान रखने की बात है कि यवि 'ख' वा 'ग' में से कोई एक या दोनों पिता से बलग हो चुके हैं तो पृथक हुए 'स' या 'ग' को मृत-पिता 'क' के हिस्से मे से दुवारा कोई भागन मिलेगा।

(स) बायभाग के सनुसार—दायभाग में जहाँ 'पैतुक' भीर 'स्वा-जित' सम्पत्ति—दोनों में एक ही नियम सनता है, मृत-पिता 'क' की १५,००० रु० 'पुरतनी' तमा ६,००० रु० 'स्वाजित' जायदाद को एक साथ मिलाकर 'स', 'ग', 'च', 'प' तथा 'म' में बर्ज्य-बराबर बाँट दिया जायेगा, धर्षात् दायभाग में सड़के, लड़की, विश्वकः कौर माँ सबको बराबर-बराबर ४,००० रु० मिल जायेगा।

उपरोक्त उदाहरण से आत होया कि मिताक्षरा के अन्तर्गत पुक्तिमी जायदाद में लडकी को लड़के से काफ़ी कम हिस्सा मितता है। इसके मितिरक्त मिताक्षरा में लड़की के हिस्से पर कुछ भीर भी प्रतिकल्य लयाये जाते हैं जिनका भाषान मह है कि पुक्तिनी जानदाद का मनावदमक विभाजन न हो पाये। उदाहरणार्क, लड़की अपनी भीर से जायदाद के भपने हिस्से का प्रकृत नहीं छठा सकती, सड़के जायदाद का बँढनारा करेंगे तभी उसको भपना हिस्सा सजय मित सकेगा। वह अकान का भपना हिस्सा किराये पर वहीं उठा सकेगी, उसे नेच नहीं सकेगी, सिर्फ़ उसमें स्वयं रह मर ककेगी। यहाँ वह भी स्वयंक स्वता आवद्यक है कि पुनी को पैतृक-सम्मत्ति में को सक्किशर किसा है, वह केयक स्व

सम्मादिः में जिल्हा है जिल्हाको उत्तका विता जिल्हा बसीमत किये छोड़ा जावपाः। पिता क्सीवद्ध बाहा पूत्री को कुछ भी हिस्सा न है - यह भी। उसे अधिकार है। पिता की सम्मति में पुनीः के अभिकारः पर बोह प्रतिबन्धं समाचे वार है, उनका मुक्क अभित्रांव संयुक्त विज्ञात प्रथा: की रहा करना है। परन्त विसाधारा-परिवार रूपी भवना में बाबा जगह-जगह तरेड़ या चुकी है। इसे अब बचाया नहीं का सकता। धाव से सी साम पहले को ब्राविक ग्रीर सामाजिक धवस्थाएँ मीं, वे प्राज वदन सकी है। १०० साल पहले 'मरिवार' समाज की इकाई या, धाव 'परिवार' नहीं, 'म्यक्ति' समाधः की इकाई है। याचः यदि कोई भी-प्रशा 'व्यक्ति' के विकास को रोकती है, तो उस प्रया को 'व्यक्ति' के हिंत की रक्षा के लिए सतम कर देना होगा। साम की इमारी परिस्थितिकों में 'मिलक्कारा'-प्रणाली, जो स्त्री-पुरुष के भेर पर सडी है, मेल नहीं साती। इसी कारण सन्निकांश विभान-निर्मासकों के विचार से बाय-भाग-प्रणाली ही अपने, देश के लिये अधिकः उपयुक्त है। इसीलिए हिन्दु-कोड-बिल जब प्रयंग बार संविधान-सम्बद में पेश हवा था, तो उसमें मिताक्ष को समस्त ही कर विया गया था, और समस्त देश में दाय-भाग-प्रणाली प्रचलित कर देने की-सिकारिश की नई थी। दुर्भाग्य से यह बाह स्वीकृत न ही सकी । हमें बाक्या है कि:शील ही हमारे विवाल-निक्षता इस बाबिनियम में या इसका कोई भीर विधेयक लाकर 'मिताकरा'-प्रकासी को समाप्त कर देंगे और स्की तथा : पुरुष के उत्तराधिकार सम्बन्धी इस भेक को मिठाने का प्रवस्त करेंचे ।

'हिन्दू-विवाह तथा तमक अधितियम' एवं 'छत्तरविकार, अधिन नियम' का मुख्य उद्देश्य स्त्री: को सामाजिक अध्य आधिक अधिकार, देकर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था को समुन्तत करता है । सम्बद्धि इस सम्बद्धः स्त्री को राजनीतिक क्षेत्र में समान विकार प्राप्त हो पुके हैं, तथापि जब तक उसे सामाजिक तथा वार्षिक क्षेत्र में तो पुरुष के समान

श्रविकार नहीं मिल जाते तब तक वह पूर्ण रूप से विकास तथा उन्नित के मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकती । भीर, जब तक स्त्रियों के रूप में देश की श्राधी जनता पिछडी भीर पराधीन रहती है तब तक हमारे नेताघों का समाजवादी-समाज को स्थापित करते का स्वप्न मूर्त-रूप नहीं ले सकता। इसी भूमिका में 'विवाह' तथा 'उत्तराधिकार' के भ्राचिनियमों का असली महत्व है, क्योंकि ये इस समय तक पिछडी हुई, झत्याचारों से पीडित तथा अधिकार-शून्य स्त्री को शक्ति-सम्पन्न बनाने की दिशा में एक बडा ठोस कदम उठाते हैं। विवाह-कानून से स्त्रियों के पारिवारिक जीवन में एक सुरक्षितता की मावना बायेगी, और साथ ही स्त्रियों को भी विशेष प्रवस्थाओं में सम्बन्ध-विच्छेद की सुविधा मिल जाने से वे भी पुरुषो के समान स्तर पर भा खडी होगी। वैवाहिक-कीवन की सफलता जीवन-क्षेत्र में दोनों के सम-कक्ष होकर प्रवेश करने में है। विवाह-कानून स्त्री को जो स्वतन्त्रता सामाजिक-क्षेत्र में प्रदान करता है, वही स्वतन्त्रता उत्तराधिकार-कानून स्त्री को धार्थिक-क्षेत्र में देता है। माज हजारों सालो के बाद इस कानून के द्वारा प्रथम बार स्त्री के सम्पत्ति-सम्बंधी प्रधिकारो को मान्यता मिली है। इन प्रधिकारो को प्राप्त करने के साथ भारत की नारी, इतिहास के एक सुनहरे युग में प्रवेश कर रही है। इन अधिकारों के सीमित रहते हुए भी इन्हें "भारतीय नारी के मिवकारों का घोषणा-पत्र" (Charter of the Rights of Indian Women) कहा जा सकता है।

'उत्तरिष्ठिकार-प्रधिनियम' के परिणामस्त्ररूप स्त्री के भाषिक दृष्टि से स्वावलम्बी हो जाने का भवरुयंभावी नतीजा यह होगा कि भाजीविका के लिये विवाह ही उसका एक मात्र भवलंबन नहीं रहेगा। भाज तो विवाह स्त्री के लिए भाषिक-समस्या का एकमात्र हल है—इस कानून के बन जाने से यह स्थिति बदल खायेगी।

#### ह. मुसलमानों में विवाह-विच्छेंद

हमने प्रभी तक उन्हीं सामाजिक-विधानों का वर्णन किया है जिनका हिन्दू-समाज में विवाह पर प्रभाव पड़ता है। विवाह के सम्बन्ध में मुसलमानों की क्या स्थित है ? यह हम पहसे ही कह बावे हैं कि मुसलमानों के यहाँ विवाह मुख्यतः एक 'धार्मिक-संस्कार' (Sacrament) न होकर पित-पत्नी का एक समक्रीता, एक 'ठेका' (Contract) है। समक्रीते या ठेके में दोनो पक्ष कुछ लेते हैं, कुछ देते हैं। स्त्री तो प्रपने मा-बाप का घर छोड़ कर पित को अपने-आप को दे देती है, पित उसे 'महर', 'भेंट' या 'दहेज' देता है। 'धार्मिक-संस्कार' का धाधार तो धर्म है, धौर धर्म नित्य है, इसलिये उस पर चलने वाला विवाह टूट नहीं सकता, परन्तु ठेका तो किन्ही धर्तों पर भाषारित होता है, वे धर्ते टूट जायाँ, तो ठेका टूट जाता है, इसलिये मुसलमानों में किन्ही खास-लास ध्रवस्थायों में विवाह-विच्छेद हो जाता है। वे ध्रवस्थाएँ क्या हैं?

मुसलमानों में विवाह-विच्छेद ज्यादातर पति के हाथ में है, परन्तु किन्ही-किन्हीं भवस्थाओं में पत्नी को भी इसका अधिकार आग्त है। विवाह-विच्छेद की अवस्थाएँ निम्न है:—

(क) तलाक पति जब नाहे पत्नी को तलाक दे सकता है। तलाक देने के समय पत्नी या किसी गवाह का उपस्थित होना भावश्यक नहीं है। भगर पति तीन बार एकदम तलाक-तलाक-तलाक कह दे, तो तत्काल विवाह-विच्छेद हो जाता है; भगर सिर्फ़ एक या दो बार कहे, तो तलाक को कियात्मक रूप घारण करने के लिये पत्नी को तीन महीने प्रतीक्षा करनी पडती है। यह प्रतीक्षा-काल 'इह्त' कहलाता है। 'इह्त' के बाद कलाक पूरा हो जाता है।

- (स) इसा—यदि पति चार महीने तक यौन-सम्बन्ध न करने की शपथ सा ले ग्रीर उस पर चार महीने तक ग्रटल रहे तो तलाक हो जाता है।
- (ग) खिहर—अगर पित अपनी स्त्री की तुलना अपनी बहन या ऐसी स्त्री से कर दे जिसके साथ इस्लामी कानून के अनुसार विवाह निषिद्ध है, तो उसे श्रायदिवत करना चाहिए। अगर अपनी यत्नी के कहने पर कि वह श्रायदिवत करे वह ऐसा नहीं करता तो तलाक हो जाता है।
- (घ) खुला—वैसे तो विवाह के साथ 'महर' (मेंट) पति वेता है, कमी-कभी 'महर' का कुछ हिस्सा रोक रखता है जिसे 'स्थिगत-महर' कहते हैं, और अगर कभी वह पत्नी को तलाक दे तो यह 'स्थिगत-महर' उसे पत्नी को देनी पड़ती है। परन्तु कभी-कभी पत्नी को पति से इतनी घृणा हो जाती है कि वह उसके साथ नही रहना चाहती, उसे छोड़ देना चाहती है। ऐसी अवस्था में अगर पित भी विवाह-विच्छेद के लिये नैयार हो जाय, तो उसे 'खुला' कहते हैं। इसमें पित पत्नी को 'महर' नही देता, परन्तु पत्नी पित को कुछ हरजाना देती है। अवसर वह 'स्थिगत-महर' के अपने अधिकार को छोड देती है। अगर पत्नी ऐसी अवस्था में पित को 'हरजाना' न दे, तो पत्नी पर मुकदमा दायर हो सकता है। इस तलाक में पहल पत्नी की तरफ़ से होती है।
- (क) मुबारत—इसमें दोनो की सहमति से विवाह-विच्छेद हो जाता है, 'खुला' की तरह पत्नी की तरफ़ से या तलाक की तरह पति की तरफ़ से पहल नहीं होती। दोनों साच-साच नहीं रहना चाहते, धलग-धलग हो जाते हैं।
- (च) तसाके तफावीच अगर विवाह के समय पति अपनी पत्नी को यह अधिकार दे दे कि वह अमुक अविधि तक अपनी इच्छानुसार विवाह-विच्छेद कर सकती है, तो पत्नी उस अविधि के भीतर विवाह-

विच्छेद कर सकती है। ऐसी अवस्थां में यह विवाह-विच्छेद पत्नी द्वारा किया गया न माना जाकर पति द्वारा किया गया जाना जायगा भीर सलाक के समय 'महर' भादि का कोई भगड़ा ने किया जा सकेगा।

#### १०. मुस्लिम विवाह-विच्छे द-म्रिधिनियम—१६३६ (Dissolution of Muslim Marriages Act, 1939)

कपर तलाक के सम्बन्ध में जिन अधिकारों का वर्णन किया गया है, वे प्रायः सब पुरुष के अधिकार हैं। उनमें से तो कई बै-सिर-पैर के, असाधारण अधिकार हैं। उदाहरणार्थ, तीन बार तलाक-तलाक-तलाक कह देने से एकदम स्त्री की स्थित असुरक्षित हो जाती हैं। इस सब स्थिति को देखकर १६३६ में 'मुस्लिम-विवाह-विच्छेद-अधिनियम' बना जिसमें पत्नी के दृष्टिकोण से कुछ नियम बनाये गये जिनके आधार पर पत्नी भी तलाक करने की अधिकारिणी बना दी गई। वे नियम क्या है? पत्नी अपने पति का त्याग कर सकती है:—

- (क) अगर चार साल तक पति का कुछ पता न चले,
- (स) अगर दो वर्ष तक पति अपनी पत्नी की मरण-पोषण की व्यवस्थान कर सके,
- (ग) मगर उसे माजीवन या मधिक वर्षों तक जैल की सजा मिले,
- (घ) प्रगर तीन वर्ष तक वह अपने वैवाहिक-कर्तव्य पूरा न करे,
- (ङ) भगर विचाह के समय से ही वह नगुंसक सिद्ध हो जाय,
- (च) भगर दो वर्ष से वह पागल हो,
- (छ) अगर वह कोढ़ या यौन-रोग (सिक्शलिस, गनोरिया आदि) से पीड़ित हो,
- (क) भगर उसका विवाह १५ वर्ष की भायु से पहले कर दिया गया हो, और इस बीच उसका पति से यौन-सम्बन्ध न हुआ हो, तो १८ वर्ष की भायु से पहले वह विवाह से इन्कार कर सकती है,

- (फ) ग्रगर पति कूर हो, दुराचारी-व्यभिचारी हो, पस्नी को व्यभिचार के लिये मजबूर करता हो,
- (अ) प्रगर वह पत्नी की सम्पत्ति को उसकी आज्ञा के बिना बेचता हो, उसे अपनी सम्पत्ति का उपभोग न करने देता हो,
- (ट) प्रमर वह पत्नी की वार्मिक-कृत्य न करने देता हो,
- (ठ) अगर अन्य पत्नियो की तुलना मे उसके साथ अन्यायपूर्ण भ्यवहार करता हो,
- (ड) ग्रगर वह पत्नी पर व्यभिनार का दोष लगाये भौर वह दोष सिद्ध न हो सके।

#### ११. पारिसयों में विवाह-विच्छे द

पारितयों में भी विवाह एक 'धार्मिक-सस्कार' न होकर 'ठेका' माना जाता है। इनके विवाह तथा विवाह-विच्छेद सम्बन्धी नियम १०६४ में पहले उसी समाज के चलते ये जहाँ कोई पारसी रहता था, परन्तु १०६४ में 'पारसी विवाह तथा तलाक ग्राधिनयम' बना जिसका भाषार बहुत-कुछ भग्नेजी-कानून (English law) था। इस कानून के बनने के बाद बिना तलाक लिये, अपनी पहली स्त्री के रहते दूसरी स्त्री से विवाह करना बहु-विवाह माना गया भौर जैसे 'भग्नेजी-कानून' में बहु-विवाह अपराध है, वैसे पारसियों में भी बहु-विवाह दडनीय घोषित किया गया।

इस कानून के अनुसार पित-पत्नी दोनों को एक-दूसरे के व्यभिचारी सिद्ध होने पर तलाक मिल जाता है। अगर पित किसी वेक्या से महनास करता है तो उसे तलाक की दृष्टि से व्यभिचारी नहीं कहा जाता। अगर वह एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करता है तभी स्त्री तलाक की अधिकारिणी है। अगर वह कूर है, दो साल से पत्नी को छोडे हुए है, यौन अपराध करता है, तुब भी स्त्री तलाक प्राप्त कर सकती है। कूरता का धर्ष स्वभाव का तेज होना, गाली-गलीज करना धादि नहीं, परन्तु कूरता, कानूनी धर्यों में कूरता होनी चाहिए। कानूनी धर्यों में कूरता का धर्य है ऐसी मार-पीट करना जिससे बीवन को खतरा हो, किसी धर्म को धाति पहुँचे, स्वास्थ्य के इतना गिर जाने की सम्भावना हो जो जीवन के लिए भयप्रद है। इन धर्यों में मानसिक-कूरता को कूरता की अणी में नहीं गिना गया। धर्म पारसियों के उक्त कानून में कुछ और सुपार हुए है जिनके धनुसार (१) धर्मर पति-पत्नी ने से कोई दूसरे को धौन-रोगों से जान-बूभकर दूचित करता है, (२) या दोनों में से कोई सात साल या धिक समय के लिए जेल में चला गया है, (३) या दोनों में से कोई तीन साल तक दूसरे को छोड़े रखता है, तो वह विवाह-विच्छेद का ग्राधकारी है।

#### १२. ईसाइयों में विवाह-विच्छेद

१८६६ में 'भारतीय विवाह-विच्छेद-प्रधिनियम' (Indian Divorce Act, 1869) बना जो ईसाइयो पर लाग्न होता है। इस कानून के अनुसार प्रगर यह सिद्ध हो जाय कि पित ने ऐसी स्त्री से बौन-सम्बंध किया है जिसके साथ कानून के अनुसार विवाह वर्जित है, या उसने एक स्त्री से अधिक से शादी की है, व्यभिचारी है, सम-लिंगी या पशु-व्यभिचार करता है, उसने अपने धमं का परित्याग करके किसी अन्य स्त्री से विवाह कर लिया है, तो पत्नी को विवाह-विच्छेद का अधिकार मिल जाता है।

इस प्रकार हमने देखा कि हिन्दू, मुसलमान, पारसी तथा ईसाई लोगों में जो सामाजिक-विधान बन रहे हैं उनका उनकी विवाह-सम्बन्धी धारणा पर नथा-नथा प्रभान पड़ रहा है। ग्राधिकतरइन सुधारों की दिशा विवाह को 'धार्मिक-संस्कार' (Sacrament) मानने के स्थान में एक 'ठेका' (Contract) मानने की तरफ जा रही है।

#### प्रश्न

- १. निम्न सामाजिक-ग्रांचिवियमों के बारे में ग्रांप क्या जानते हैं— (क) सती-प्रचा-कातून, (ख) विभवा-विवाह-कातून, (ग) विशेष-विवाह-कातून १९६४, (घ) जारवा-कातून, (ङ) ग्रांप-विवाह-कातून ।
- २. 'हिन्दू विचाह तचा तलाक-अधिनियम—१६५५' के विवय में आप क्या जानते हैं ? इस कानून के अनुसार किन-किन अवस्थाओं में तलाक दिया जा सकता है ? इस कानून का विवाह की प्रया पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?
- ३. 'उत्तराविकार ग्रावितियम—१९५६' के अनुसार माता, पत्नी सथा लड़की की स्थिति में क्या परिवर्तन किया गया है? इस परिवर्तन का सामाजिक तथा ग्राविक प्रभाव क्या पड़ेगा? विवाह की प्रथा पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है?
- ४. जुसलमानों, पारिसयों तथा ईसाइयों में तलाक के सम्बन्ध में क्या कानून हैं और उनमें तलाक की दृष्टि से स्त्री की क्या स्थित हैं?

## ६

### ग्राम-संगठन

( VILLAGE COMMUNITY )

ग्राम्य-जीवन की कुछ बातें ऐसी हैं जो पूर्व-पश्चिम-सब जगह के गाँवों में एक-सी है, सामान्य हैं। ऐसी एक-सी बातें कौन-कौन-सी हैं?

### १. ग्राम्य-जीवन के सामान्य-गुण

(क) प्राकृतिक-जीवन—सब जगह के गाँवों की पहली विशेषता जो सब में सामान्य तौर पर पाई जाती है उनका प्रकृति के निकट होना है। प्रकृति के सुन्दर दृश्यों को जब कैनवास पर चित्र में उतारा जाता है, तब उसका सैकड़ों रुपया दाम देने को लोग तैयार हो जाते हैं, फिर जीती-जागती प्रकृति में रहने का तो कुछ भी दाम खुकाया नहीं जा सकता। गाँव के प्रकृति-दृश्यों में फोंपडों को भी 'पुष्प-लसाघों से ऐसे सजाकर रसा जा सकता है कि महलों को भी बैसा न रखा जा सके। करोड़पति को भी शहर में उतनी विस्तृत खुली जगह नहीं मिल सकती जितनी एक ग़रीज किसान को अपने टूटे-फूटे फोंपड़े के लिए गाँव में मिल जाती है। धमर मनुष्य चाहे तो बाँव में प्रकृति के वरदान से चर को स्वर्ग जना सकता है, परन्तु बाँव के लोग जैसे रहते हैं, उससे तो उन्होंने अपने हाथ से स्वर्ग को नरक बनाया होता है।

प्रामीण-व्यक्ति, प्रामीण परिस्थिति में रहता है। वह मुख्य तौर पर खेती करेगा—जो-कुछ भी करेगा उसका स्थान प्रकृति के बीच में है, वह हर समय प्रकृति के निकट है। सर्वी, गर्मी, वर्षा—हर समय का वह उस-उस मौसम में प्रनुभव करता है। उसे मालूम है, यब कौन-सी ऋतु मा रही है क्योंकि उम ऋतु का उस ऋतु के मनाज के पैदा करने के साथ विशेष सम्बन्ध है। वह सूर्य की रिश्मयों को फूटता देखकर उठता है, प्रचेरा होने पर सो जाता है, रात को जाग खुले तो तारों को देखकर बता देता है कि कितनी रात बाकी है। वह चाहे स्वतन्त्र खेती करता हो, या किसी दूसरे का जेत जोतता हो, उसे हर समय तैनात नहीं रहना होता, प्रकृति के वर्षा-गर्मी-सर्दी के भिन्त-भिन्न समय उसके कार्य की प्रणाली को बौधते हैं। जब बोने-काटने का समय नहीं है, तब उसे खेत मे यूँ ही धक्के खाने की जारूरत नहीं। इस दृष्टि से उसके पास समय बहुत है भीर भ्राने समय का वह मालिक है।

(क) बामीस-संस्कृति—ग्रामीण-सस्कृति की ग्रपनी कई विशेषताएँ होती हैं। प्रकृति के निकट होने के कारण प्रामीणों के कथा-कथानक, उनके नृत्य, उनके गीत—सबका उदय प्रकृति के प्रथाह सागर से होता है। ग्रामीण-सस्कृति में कृतिमता नहीं होती, ग्रामीण लोग श्रपने स्वाधाविक जीवन को अपनी सस्कृति में उँडेन देते हैं। ग्राम-वासी का पहनावा, उसका चेहरा-मोहरा—सब प्रकृति के निकटतम होने के कारण स्वाधाविक होता है। मनुष्य के मनुष्य के साथ व्यवहार में भी ग्राम-वासी की सस्कृति की ग्रपनी विशेषता है। गांव का रहने वाला मनुष्य के निकटतम सम्पर्क में रहता है। परिचित व्यक्तियों का ग्राम में समूह होता है, इसलिए गांव के एक-एक व्यक्ति को बह जानता है, ग्रीर इसीलिए मानवीयता की भावना उसमें ग्रोत-शोत रहती है। शहर का ग्रादमी भूखे को देख कर पास से निकल जायया, गांव का ग्रादमी भूखे को रोटी देगा; शहर का ग्रादमी मेहमान को नफ़रत से देखेगा, गांव का ग्रादमी मेहमान को नफ़रत से देखेगा, गांव का ग्रादमी मेहमान को नफ़रत से देखेगा, गांव का ग्रादमी मेहमान को

प्रेम से देखेगा; शहर का भावमी निरा स्वार्थी होगा, गाँव का भावमी स्वार्थी नहीं होगा---ये ग्रामीण-सस्कृति की विशेषताएँ हैं।

- (ग) परिवार की प्रधानता—गाँव की परिस्थित में जीवन-रूपी वृत्त का केन्द्र घर तथा परिवार होता है। ग्रामीण-जीवन में अनुष्य च्रारों तरफ़ से संसार से तो कटा रहता है, परन्तु अपने परिवार से धामन्त तौर पर बँधा रहता है। सबका साथ-साथ खेती करना पारिवारिक-बंधनों को घौर धांक वृढ़ बना देता है। परिवार की प्रथाएँ तथा पुरानी परम्पराएँ व्यक्ति के जीवन को कसे रहता है। ग्रामीण-जीवन में क्योंकि परिवार मुख्य होता है, व्यक्ति नही, इसलिए इस जीवन में बुजुर्गों का शासन होता है—यह एक प्रकार की 'पितृ-प्रधान-व्यवस्था' है। परिवार के सब सदस्यों पर बडों-बूढों की हुकूमत चलती है, परिवार की सत्ता में व्यक्ति की सत्ता विलीन हो जाती है। परिवार का जितना कँचा स्थान है, व्यक्ति का भी उतना ऊँचा स्थान अपने-आप बन जाता है। ऊँचे खानदान का व्यक्ति अपने खानदान की वजह से ऊँचा माना जाता है। शहर में कमें तथा गाँव में जन्म प्रधान होता है। शहर का धादमी परिवार से उज्जड़ सकता है, गाँव के धादमी की नस-नस परिवार में धोत-प्रोत होती है।
- (च) संयुक्त-परिवार-प्रया नामीण-जीवन परिवार-प्रधान होने के कारण 'संयुक्त-परिवार-प्रया' के लिए ज्यादा उपयुक्त है। गांवों में परिवार के सब लोग साथ-साथ रहते हैं। एक चूल्हें पर उनका खाना बनता है, प्रगर परिवार का कोई सदस्य नहीं भी कमाता तो उसे घर से निकाल नहीं दिया जाता। एक तरह से 'संयुक्त-परिवार-प्रथा' प्राचीन समय की सुरक्षा-पद्धति (Security system) का एक रूप है। सम्पत्ति परिवार के किसी विशेष व्यक्ति की नहीं, परिवार की सामी सममी जाती है। परिवार में किसी लड़के-सड़की की कारी होती है, तो उसका खर्च किसी एक पर न पड़कर सारे परिवार

पर पड़ता है। बाज का कहरों का युग व्यक्तिवाद का मुम है, हर-एक अपने-अपने लिए है, परन्तु श्रामीण-जीवन में यह स्वार्थ-वृत्ति दिखाई नहीं देती।

- (क) विरावरी का प्रभाव—गाँव का व्यक्ति क्योंकि परिवार के साथ बँधा हुआ होता है, इसलिए उसका व्यक्तित्व स्वतन्त्व रूप धारण नहीं करता। वह 'मैं' की मावना में न सोचकर 'हम' की मावना में सोचता है। उसका धर्म-धंधा, उसके धाचार-विचार—सब बातों का नियन्त्रण विरावरी के वृष्टिकोण से होता है, वह स्वय नहीं सोचता, विरावरी उसके लिए सोचती है। विरावरी के निर्णय के सामने सिर मुकाना उसके लिए स्वय-सिद्ध है। स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध भी ग्रामीण-जीवन में विरावरी के वृष्टिकोण से होते हैं। गाँव का वासी विरावरी-प्रधान जीवन व्यतीत करता है।
  - (क) परम्परा, प्रचा तथा किंद्र का प्रभाव—शहर के व्यक्ति पर कानून का प्रभाव होता है, प्रामीण व्यक्ति पर परम्परा का प्रभाव होता है, परम्परा के सामने वह कानून को तुच्छ समभता है। जो बात बाप-दादों के समय से चली छा रही है, जो पुरुखाओं की परम्परा है, वह उसके लिए जीने-मरने का सवाल बन जाती है। ठीक भी है। ग्रामीण व्यक्ति, उसके जो-कुछ नजदीक है, उससे अपने को अभिन्न समभने लगता है। परिवार, गाँव और इन दोनों की परम्परा—यही तो उसके निकटतम की वस्तुएँ हैं, इसलिए अपने परिवार, अपने गाँव की परम्परा का दूट जाना वह अपनी नाक कट जाने के समान समभता है। वह अपने विचारों की नींच से हिला नही सकता। गाँव-वासियों के विचार उसके विचार होते हैं, ग्रीर जो उन विचारों का वरोध करता है सारा गाँव उसका दुसम हो जाता है। परम्परा का दास होने के कारण ग्राम-वासियों में असहि-प्राता अभिक होती है। दुनिया मे कितनी रोक्षमी क्यो न फैस जाय, गाँव

में उसः रोशनी का असर नहीं होता, होता भी है तो भीरे-भीरे भीर मदम तौर पर ।

(छ) पड़ौसीपन की जावना—गाँव वाले जानते हैं कि पड़ौसी किसे कहते हैं। शहर में रहने वाला ऐसे व्यक्तियों से चिरा होता है जिन्हें वह जानता भी नहीं होता। गाँव में ऐसी बात नहीं हो सकती। गाँव का हर घादमी हर-एक गाँव-वासी को जानता है। इससे किसी की कमजोरी दूसरें से छिप्री नहीं रहती। इसका लाभ भी है। लोकापवाद के भय से लोग बुरे काम से बने रहते हैं। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का सारे गाँव से निकट-तम सम्बन्ध होता है, इसलिए सुख-दुःख में सब एक-दूसरे का साथ देते हैं। इसके विपरीत शहर का कोई ब्यक्ति इकला पड़ा अपने दुःख में मर भी जाय, तो उसे पूछने वाला कोई नहीं होता। गाँव में दुश्मनी होती है तो वह भी जबरदस्त, पुश्तैनी चलती है, दोस्ती होती हैं तो उसका भी कोई ठिकाना नहीं। गाँव में ममुख्य एक छोटे-से समूह का हिस्सा होता है जिसमें सब सबको जानते हैं, इसलिए उच्च-कोटि के सब गुणों को प्रकट करने को हर-एक की इच्छा बनी रहती हैं, हर-एक यह चाहता है कि वह ऐसा काम करे जिससे सारा गाँव उसकी तारीफ़ करे।

#### २. भारत में गाँवों का महत्व

भारतवर्षं साम-प्रकान देश है। १६५१ में यहाँ ३०१८ शहर में प्र, ५,५८,८०६ शांव, भीर गांवों तथा शहरों की भावादी का पारस्परिक भनुपात इस प्रकार था :---

<sup>1.</sup> India 1956-भारत सरकार द्वारा प्रकाशित

सन्	सारी भावादी के भनुपात में	
	गाँवों की माबादी	शहरो की भावादी
१६२१	55.V	₹ ? ₹
१६३१	3.0≈	१२.१
\$ EX\$	<b>द</b> ६ १	9.₹9
9829	= 20	₹७.₹

हमारे देश में ३५ ७ करोड़ की आवादी में ६.२ करोड़ अर्थात् १७३ प्रतिशत शहरों में रहते हैं, बाक्षे २६.५ करोड प्रयात् ६२.७ प्रतिशत व्यक्ति गाँवों में रहते हैं। जिस देश में पाँच हिस्सों में से चार हिस्सा आवादी गाँवों में रहती हो उसमें गाँवों का महत्व अपने-प्राप बढ जाता है। इ गलैण्ड में माँच हिस्सों मे एक हिस्सा आवादी गाँवों में भीर चार हिस्सा शहरों में रहती है, जो भारत से ठीक उल्टा है। बहां गाँवों का वह महत्व नहीं जो इस देश में है।

संख्या के मितिरिक्त गाँवों का एक भीर भी महत्व है। गाँव तथा शहर के कुटुम्बों का तुलनात्मक भ्रष्ययन करने वालो का कहना है कि भगर एक ही स्तर का जीवन बिताने वाले गाँव तथा शहरों के कुटुम्बों का मध्ययन किया जाय, तो पता चलेगा कि शहर के बसे हुए ऐसे कुटुम्ब जिनका जीवन का स्तर भ्रपने जैसे गाँव वाले कुटुम्ब का-सा हो कुछ पीढ़ियों के बाद नष्ट हो जाते हैं, परन्तु उसी स्तर का जीवन बिताने वाले गाँव में बसे हुए कुटुम्ब पीढ़ी-दर-पीढ़ी बने रहते हैं। इसका मतलब यह है कि भगर गाँवो से लगातार शहरों में भावागमन न होता रहे, तो शहरों का जीवन ही कठिन हो जाय। शहरों के लिए गाँव एक प्रकार की जीवन की वह धारा है जिसके प्रवाह के ऊपर ही शहर का जीवन भवलियत है। इस दृष्टि से गाँवों का महत्व भीर भी भ्रष्टिक बढ़ जाता है। गाँवों में मानव-शिक्त ही नहीं, प्राण-शक्ति भी है।

#### ३. भारत में गाँव की रचना श्रीर संगठन

(क) गाँव वालों का मोटा खाका—भारत की भौगोलिक रचना में गाँव उसकी इकाई है। गाँव को मौजा भी कहते हैं। इंगलैंण्ड में भारत के गाँव की तरह वहाँ 'पैरिश' होता है। गाँव की सीमाएँ बेंधी हुई हैं, ग्रौर एक शताब्दी से दूसरी शताब्दी निकल जाती हैं, इनमें हेर-फेर नहीं होता। साघारणतः एक गाँव में १०० से १५० एकड भूमि होती है, परन्तु कहीं-कहीं ज्यादा भी पायी जाती है, १०००-१५०० एकड तक एक-एक मौजे में जमीन हो सकती है।

भारत के गाँवो में साधारण-से मिट्टी के फ्रोंपडे दिखाई देते हैं, फूस की उनके ऊपर छत होती हैं, कहीं-कहीं मिट्टी की छत भी डाल दी जाती है। किसी घर मे एक, किसी मे दो कमरे बने होते हैं—पीछे की तरफ एक सेहन जिसमे गाय, भैस, बैंल बँघे रहते हैं। कोने में एक चूल्हा जिसके घूएँ से सारा घर भर जाता है, और पास बड़ी सफाई से मँजे पीतल के बर्तन तरतीब से लगे होते हैं। आँगन गोबर से लिपा होता है—साफ-सुथरा, परन्तु गली मे या तो नालियों के पानी से कीचड़ भरा होता है या कूड़ा-कर्कट घर से बाहर बुहार कर फेंक दिया जाता है। गाँव में टट्टियाँ नहीं होतीं, प्राय सभी खेतों में जाते हैं, या बालक कोठों की छतो पर टट्टी फिर आते हैं। गन्दगी और कीचड़ से मच्छरी और मिक्खयो के मारे नाक में दम रहता है। जो भी रोगन घेरे—वहीं थोड़ा है।

खेती के लिए बरसात पर ही निर्भर रहना पडता है, नहरों का इतना प्रबन्ध नहीं, इसलिए, किसान के छ. महीने बैकारी में गुजरते हैं। जिनके पास खेती के लिए जमीन नहीं, जो खेतो में मजदूरी करके गुजर करते हैं, उनके तो ब्राठ महीने बैकारी में गुजर जाते हैं। ऐसे सब लोग गिलयों में ताश लिए खेला करते हैं, या दोपहर को चहर सान कर सोया करते हैं, सर्दियो में चौपाल में बैठकर सब लोग गप्नें उडाते हैं, श्राग

जल रही हैं, चारो तरफ़ घेरा लगाकर सब बैठे हैं, हुक्का सामने घरा है—इस प्रकार की जिन्दगी हमारे ग्रामीण माई सदियो से बिताते चले भा रहे हैं।

ग्राम-वासी ग्रधिकाँश शाकाहारी होते हैं। जिस जगह जो अन्त होता है वहाँ उसी को खाते हैं। देहरादून मे जावल ग्रौर लुषियाना में गेहूँ। जिस मौसम मे जो ग्रन्न उपजता है उस मौसम में उसी अन्त का इस्तेमाल करते हैं—बाजरे की मौसम मे बाजरा ग्रौर मक्का की मौसम मे मक्का। पहले तो गाँव का रहने वाला हर-एक खूब दूध पीता था, घी खाता था, परन्तु ग्रब तो गाँव वालो को भी चाय का चस्का लग गया है, कटोरे मर-भर कर चाय पीते हैं, दूध-धी का गाँवों मे से भी नामो-निशान मिटता जा रहा है। नतीजा यह है कि हमारे गाँव वालो के जो मरे हुए चेहरे ग्रौर उभरी हुई छाती दिखाई दिया करती थी, वह लुप्तप्राय होती जा रही है। सुकड़े हुए चेहरे ग्रौर चमकती हुई नोकीली हड़िडया शहरों में ही नहीं, गाँवों मे भी चारो तरफ़ दिखाई देने लगी हैं।

(क) गाँव का संगठन—हमारे यहाँ गाँवों मे जो सगठन रहा है उसे एक छोटी-सी रिपब्लिक कहा जा सकता है। अग्रेजी-शासन-काल में इस संगठन को कायम नहीं रहने दिया गया, परन्तु उस समय के जो रजवाड़े वे उनमें इस सगठन का शुद्ध-रूप दिखाई देता था। रजवाड़े की तरफ़ से जो सूचनाएँ आती थीं वे गाँव के पच या पटेल के नाम भेजी जाती थीं। पच का अभिप्राय है गाँव के चुने हुए पाँच या न्यूनाधिक व्यक्ति। गुजरात आदि मे गाँव का मुख्या पटेल कहलाता है। पटेल का काम भी गाँव के संबंध मे जब्दी काम-काज करना है। गाँव के सामूहिक कार्य पच या पटेल की आज्ञानुसार चलते हैं। गाँव के नाई, धोबी, बढ़ई, लोहार—ये सब किसी एक का काम नहीं करते, सारे गाँव का काम करते हैं। शादी-स्याह का मौका हो, तो इन सब से काम लिया जाता है। इनको साल की दोनो फ़सलों में दो बार सब लोगो की तरफ़ से

धनाज दिया जाता है। कुछ लोग गाँव में ऐसे भी होते हैं जिनसे हर प्रकार का काम लिया जाता है। चमार लकड़ी भी ला देंगे, मरे जानवरो को भी उठा ले जायेंगे, सब-कुछ करेंगे। गाँव का सगठन कुछ ऐसे ढंग का बना हुआ है कि वह अपने में पूर्ण है, उसे बाहर से किसी प्रकार की सहायता की आवस्यकता नहीं पड़ती।

पंच और पटेल गाँव के अगडों को गाँव मे ही निपटा देने की कोशिश करते हैं। उनकी कोशिश यह रहती हैं कि जहाँ तक हो सके मामला अदालत में न जाय। गाँव का सगठन इतना जबर्दस्त है कि अगर सरकार भी किसी प्रथा या गाँववालों के किसी वास्तविक अथवा काल्पनिक अधिकार में हस्तक्षेप करना चाहे, तो वह पंचों को अपने साथ में लिये बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। जब पंचों की आवाज उठती है तो वह सारे गाँव की आवाज होती है—अन्दर वाले भी पंचों की बात को नहीं मोड़ सकते, बाहर वालों को भी पंचों की आवाज को सुमना पडता है। गाँवों में पुलिस का कोई प्रबन्ध नहीं होता इसलिए पच ही अपराधी के पकड़े जाने पर ऐसी सजा देते हैं कि किसी में दुवारा अपराध करने का साहस नहीं होता। जहाँ-जहाँ गाँवों का पुराना सगठन चल रहा है, वहाँ-वहाँ यही हाल है, जहाँ वह संगठन टूट चुका है वहाँ की बात दूसरी है।

(ग) गांवों का संगठन टूट चुका है—गांवो का अपने देश में जो सगठन या वह अंग्रेजों के समय बहुत-कुछ टूट गया। पंचायतों भौर पंचों का जोर कम हो गया। इस जमाने में गांवों में एक चौकीदार रखा जाने लगा जिसका काम गांव की हर शिकायत को चाने में पहुँचाना हो गया। पहले गांव का गांव से ही शासन होता या, अब गांव का गांव के वाहर के चाने से शासन होने लगा, पंचों की ताकत घट गई भौर गांवों में भी एक नई किस्म का वर्ग उत्पन्न हो गया जो बोड़ा-बहुत पढ़-लिख गया था, खेती-बाडी छोड़कर बाबूगिरी करने लगा था। भौर अपनी हर पूरानी बात को नफरत की नजर से देखने लगा था।

ये लोग न गाँव वाले रहे थे, न शहरी—इन लोगों का एक कदम गाँव में गड़ा था, परन्तु दूसरा शहर की तरफ बढ़ रहा था। इन्होंने गाँवों के समठन को ढीला कर दिया।

(घ) गाँवों की भूमि-व्यवस्था—गाँव का सबसे बड़ा पेशा काइतकारी है। किसान खेत जोतता-बोता है, उसकी पैदावार से अपना पेट भरता है। परन्तु उसी के पेट भरने से तो काम नही चलता। देश की सरकार भी तो चलनी है। किसान अपने लिये कमाता है भौर सरकार के लिए भी कमाता है। भारत मे भूमि-व्यवस्था-सम्बन्धी-नीति का भाषार यह समभा जाता रहा है कि देश का राजा या देश की सरकार ही भूमि की स्वामी है। उसकी दी हुई भूमि पर किसान हल चलाता है इसलिए राजा या सरकार किसान से जो भूमि-कर लेना चाहे, ले सकती है, किसान को भूमि से हटाना चाहे, हटा सकती है। भूमि-कर दिये जिना भी किसान भूमि का स्वामी हो सकता है—यह स्थित अपने यहाँ नहीं मानी जाती। गाँव का सगठन गाँव वालों की दृष्टि में खेती की पैदावार तथा सरकार की दृष्टि में मालग्रुजारी के लिए है, और इन दोनो का सम्बन्ध 'भूमि-व्यवस्था' से है इसलिये इस सम्बन्ध में हम यहाँ एक पृथक शीर्षक देकर उस पर विचार करेगे।

#### ४. गाँवों की भूमि-व्यवस्था 'माजगुजारी' (Revenue) तथा 'भू-स्वामित्व' (Tenancy)

भूमि के सम्बन्ध में गाँव बालो की अनेक समस्याएँ हैं। किसान जमीन का मालिक माना जायगा या नहीं, अगर मालिक नहीं माना जायगा तो उसे बेदखल किया जा सकेगा या नहीं, अगर बेदखल किया जा सकेगा तो कितनी मालगुजारी न देने पर बेदखल किया जा सकेगा, मालगुजारी का माप-दंड क्या होगा, उपजाठ-अनुपजाठ भूमि पर प्रति एकड़ एक-समान मालगुजारी देनी होगी या भूमि की उपजाठ-शक्ति के आधार पर मालगुजारी लगेगी, मालगुजारी एक बार निश्चित कर दी

r meet or at a telephonology transfer being to the transfer of the

जायमी या समय-समय पर बदलती रहेगी—ये सब समस्याएँ हैं जो सिंदयों से किसानों को परेशान करती रही हैं। इन समस्याश्रों की धाल्मा को समभने के लिये हमें इस विषय के पिछले इतिहास पर सरसरी नजर डालनी होगी।

इन समस्याओं को हम दो भागों में बाँट सकते हैं। एक भाग तो 'मूमि-मालगुजारी' (Land Revenue) से सम्बन्ध रखता है भीर बहत-से प्रश्न इस 'भूमि-मालगुजारी' से जुड़े हुए हैं। 'मालगुजारी' (Revenue) तथा 'लगान' (Rent) में भेद है। जहाँ जमींदारी-प्रथा रही है, वहाँ सरकार जमींदार से 'मालग्रजारी' लेती रही है, परन्तु 'जमींदार' किसानीं से सरकार को मालग्रुजारी देने के लिये 'लगान' लेता रहा है। जमीदार 'लगान' बहत बडी राशि में वसूल करता रहा है, उसका कुछ हिस्सा 'मालग्रजारी' में देता रहा है । भूमि-व्यवस्था में सबसे बडी समस्या यही रही है कि सरकार किसान से सीधे मालग्रुजारी ले. या जमीदार को बीच में डालकर उसे वसूल करे। मालग्रजारी के झतिरिक्त भूमि-व्यवस्था की दूसरी समस्या 'भू-स्वामित्व' (Land tenure) की रही है। गाँव की मूमि का कौन मालिक है ? क्या उसकी मालिक सरकार है, क्या जमींदार है, या किसान है ? भूमि-मबंधी प्रश्नों को हम 'मालग्रजारी' (Revenue) तथा 'भ-स्वामित्व' (Tenancy)—इन दो में बाँट सकते हैं। दोनो का अपना-अपना इतिहास है इसलिए हम इन दोनों पर कमशः विचार करेंगे।

# ५. भ्रंग्रेजों से पहले गाँवों की 'मालगुजारी' की व्यवस्था (Land-Revenue System before the British)

मुगल-बादशाही से यहले, मनु के समय से लेकर अनेक हिन्दू-राजाओं तके, यहाँ की प्रथा यह थी कि उपज का छठा हिस्सा राज-कोष में चला जाता था। शेरशाह और अकबर के समय यह सुधार किया गया कि उपज का नंकद दाम या अनाज दोनों में से कुछ भी मालगुजारी या भूमिकर के रूप में दिया जा सकता था। कितना दिया जाय—यह भूमि की उपजाऊ-शक्ति को देख कर भिन्न-भिन्न तय किया जाता था। इसके बाद, डॉ॰ राधाकमल मुकर्जी के कथनानुसार, मुगल-राज्य में सामूहिक मालगुजारी की प्रथा चालू की गई। इसका मतलब यह था कि प्रत्येक प्रान्त
से शाही खजाने के लिए मालगुजारी की रकम पँदाबार का भाधा हिस्सा
निश्चित कर बी गई भीर यह भाधा हिस्सा उन प्रान्तों से बसूल कर
लिया जाता जिन पर यह रकम लाग्न की गई थी। भिन्न-भिन्न प्रान्तों,
भौर प्रान्तों में भी भिन्न-भिन्न रकबो से मालगुजारी वसूल करने की जिम्मेदारी किन्ही खास-खास व्यक्तियो पर रख दी गई। ये व्यक्ति ही जमीदार
कहलाते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि किसानो पर ज़ोर-जन्न होने
लगा, मालगुजारी की बढी हुई माग को पूरा न कर सकने के कारण
स्वियो तथा बच्चो तक को गुलामों के तौर पर किसानो को बेचना पडा।

६.श्रंग्रेजों के समय गाँवों की मालगुजारी की व्यवस्था (Land Revenue System under the British)

(क) खर्नोदारी-प्रथा—प्राचीन-काल में तो ऐसा नहीं था, परन्तु मुगल-काल से भारत में एक व्यवस्था चल पड़ी थी जिसके अनुसार सरकार किसान से सीधी मालगुजारी न लेकर एक बीच के व्यक्ति से मालगुजारी वसूल करलेती थी, हर-एक से अलग-अलग लेने के अगड़े में नहीं पड़ती थी, और वह बीचवाला हर-एक किसान से अलग-अलग मालगुजारी वसूल करता था। ईस्ट-इण्डिया-कम्पनी जब भारत में आई, तो उसको भी मालगुजारी वसूल करने का यह तरीका आसान प्रतीत हुआ। इस प्रकार जमीदारी-प्रथा अग्रेज़ों के शासन-काल में पक्की हो गई। इन जमीदारों के साथ एक रकम निश्चित कर दी आती थी, और उस रकम को अदा करना जमीदार का काम होता था। इस रकम में हेर-फेर नहीं हो सकता था। इस व्यवस्था को 'स्थायी-बन्दोबस्त' (Permanent Settlement) कहा जाता है। कुछ अग्रेजों को इस व्यवस्था में दीव

दिखलाई दिया। वे देखते थे कि किसान नई-नई जमीन जोतने लगा है, उपज बढ रही है, परन्तु मालग्रुशारी की जमीदार के साथ मात्रा निश्चित होने के कारण वे उसे बढ़ा नहीं सकते थे। वारन हेस्टिग्स ने 'स्थायी' की जगह 'ग्रस्थायी-बन्दोबस्त' (Temporary settlement) अलाना चाहा, परन्तू वह चल न सका। धन्त में लार्ड कार्नवालिस ने बंगाल में 'स्थायी-बन्दोबस्त' जारी कर दिया। उसने जमीनें नीलाम करनी शुरू कर दीं, जो ज्यादा-से-ज्यादा मालग्रजारी देने की बोली देता था. उसके नाम जमीन छोड दी जाती थी। कार्नवालिस खुद इङ्गलैंग्ड का एक जमींदार था भ्रौर इस प्रथा को रुपया वसूल करने का सहज तरीका समभता था। कार्नवालिस की इस कार्यवाही का परिणाम यह हुआ कि जमींदार जो श्रभी तक सरकार की देख-रेख में एक तरह के मालग्रजारी वसूल करने के एजेंट थे, उन्हे अपने-अपने क्षेत्र में मालगुजारी वसूल करने के पूरे-पूरे अधिकार दे दिये गए । इस सब का नतीजा यह हुआ कि जमीं-दारों का एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो गया जिसका काम किसानो से भ्रधिक-से-श्रधिक पैसा वसूल करना था, वे खुद कोई काम-काज नही करते थे, ग्राराम से शहरों में कोठियां बनाकर चैन की बसी बजाते थे, भौर भ्रपने मुनीमो के जरिये मालगुजारी वसूल कर एक तरह का राज करते थे। नीलामी मे उन्होने जितनी मालग्रजारी देने की बोली दी होती थी उतनी मालगुजारी सरकार को देने के बाद जितना भी वे किसान से वसूल कर सकते थे उसे अपने पास रख सकते थे, इसलिए 'स्थायी-बन्दोबस्त' मे किसान से वे ज्यादा-से-ज्यादा वसल करने लगे।

अभी हमने कहा कि कार्नवालिस ने बगाल में 'स्थायी-बदोबस्त' जारी किया था। इस व्यवस्था से जिस प्रकार नियमपूर्वक मालग्रजारी आ रही थी उसे देखतें हुए ईस्ट-इण्डिया-कम्पनी के डायरेक्टरो ने बनारस, उत्तरी-मद्रास तथा दिखणी-मद्रास में भी इस प्रथा को जारी करने का प्रयत्न किया। जब दिखणी-मद्रास में 'स्थायी-बन्दोबस्त' को जारी

करने की कोशिश की जा रही थी, तब कम्पनी को किठनाई का सामना करना पड़ा। 'स्थायी-बन्दोबस्त' के लिए यह जरूरी था कि कुछ इलाकों को इकट्ठा करके उनकी बोली ली जाय, और जो सबसे ब्यादा बोली दे उसे उस इलाके का जमीदार बना दिया जाय। अभी तक ये किसान सीघा सरकार को मालगुजारी दे रहे थे। इस प्रकार सरकार तथा किसान के मालगुजारी के सीघे सम्बन्ध को 'रय्यतवारी'-प्रथा कहते हैं। सरकार और किसान के बीच इस प्रकार एक तीसरे, प्रथात् जमीदार का आ जाना किसानों को भला कैसे दच सकता था। इसका मतलब तो यह होता कि किसान जो अब तक सीघा सरकार के प्रति जिम्मेदार था, अब जमीदार के प्रति उत्तरदायी हो जाना, और जमीदार उस पर मन-माना मालगुजारी का बोक लाद देना। दक्षिणी-मद्रास के किसानों ने सरकार के इस प्रयत्न को सफल नहीं होने दिया और वहाँ 'स्थायी-बन्दोबस्त' न चल सका।

'स्थायी-बन्दोबस्त' भीर 'ग्रस्थायी-बन्दोबस्त' का जिस प्रकार ऐति-हासिक विकास हुआ है उससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे 'स्थायी-बन्दोबस्त' का जमीदारी-प्रथा से सम्बन्ध हो, भीर 'ग्रस्थायी-बन्दोबस्त' का 'रय्यत-वारी'-प्रथा के साथ, परन्तु ऐसा-कुछ नही है। 'जमीदारी-प्रथा' का भ्रथं है सरकार तथा किसान के बीच मालगुजारी के लिए जमीदार का माध्यम के रूप मे होना, 'रय्यतवारी-प्रथा' का भ्रथं है सरकार तथा रय्यत भर्थात् किसान का मालगुजारी के सम्बन्ध में सीधा सम्बन्ध होना। 'जमीदारी-प्रथा' में भी मालगुजारी की रकम पक्के तौर से निश्चित की जा सकती है, 'रय्यतवारी-प्रथा' मे भी, 'जमीदारी-प्रथा' में भी मालगुजारी की रकम समय-समय पर बदली जा सकती है, 'रय्यतवारी-प्रथा' मे भी। परन्तु क्योंकि शुरू-शुरू मे कानंत्रालस के समय 'स्थायी-बन्दोबस्त' करते हुए जमीदारो के साथ स्थायी तौर से मालगुजारी निश्चित करने का प्रकन उठा था, इसलिए 'जमीदारी-प्रथा' भौर 'स्थायी-बन्दोबस्त' का सम्बन्ध जुड गया है, वास्तब में इन दोनो का ऐसा कोई सम्बन्ध नहीं है को ग्रामिट हो। 'स्थायी' ग्रीर 'श्रस्थायी'-बन्दोबस्त बृश्नीदारी तथा रय्यत-वारी दोनों प्रकार की भूमि-ब्यवस्थाओं में हो सकता है ३ ज्मीदारी तथा रय्यतबारी दोनों प्रथाकों में ग्रगर सरकार स्थायी तौर पर मालगुज़ारी की रकम निश्चित कर देती है, तो वह स्थायी-बन्दोबस्त कहलाता है, ग्रगर स्थायी तौर पर निश्चित नहीं करती, समय-समय पर बदलती रहती है, तो वह ग्रस्थायी-बन्दोबस्त कहलाता है।

क्योंकि 'स्थायी-बन्दोबस्त' से कम्पनी-सरकार को मुकसान होता का, किसान की पैदाबार ज्यादा होती थी और खमीदार के साथ पहले से निश्चित रकम बँची हुई थी, इसलिए १६२१ में कम्पनी के डायरेक्टरों ने यह घोषित कर दिया कि उत्तरी-भारत मे वे 'स्थायी-बन्दोबस्त' को नही जारी करेंगे। इस सम्बन्ध मे काफी देर तक विवाद चलता रहा, परन्तु अन्त में १६६३ में भारत-सचिव ने ऐसी घोषणा कर दी कि अब से 'स्थायी-बन्दोबस्त' को नीति को आगे से जारी नही रखा जा सकेगा।

(क) महासवारी-प्रथा—ज्मींदारी-प्रथा में बंगाल में तो यह मान लिया गया था कि कुछ गाँव एक जमीदार की मिल्कियत हैं, उनकी मालगुजारी वह जमीदार देता है, परन्तु आगरा-धवध तथा पंजाब में यह बात नहीं मानी गई। इनमे यह सिद्धान्त माना गया कि गाँवों के कुछ समूह, जिन्हें 'महाल' कहा जाता है, किसी व्यक्ति-विशेष की मिल्कियत नहीं हैं, वे सब गाँव वालों की सामी सम्पत्ति हैं, इसिक्ये किसी एक जमींदार से उस 'महाल' की मालगुजारी के लिये कोई फैसबा नहीं किया जा सकता। इन सामीदारों में से किसी एक को सरकार इस बात का जिम्मेदार ठहरा देती थीं कि वह सारे 'महाल' की—अर्थात् उन सब गाँवों की जो उस 'महाल' के अन्दर आ जाते हैं—मालगुजारी इकट्टी करके सरकार के कोष में जमा कर दे। इस प्रथा के कियात्मक रूप जगह-जगह पर जिन्न-जिन्न हैं। आयरा-बन्दोकस्त के अनुसार यद्यपि मालगुजारी अदा करने की जिम्मेदारी सारे-के-सारे गाँव

की साभी है, लो भी गाँव का कोई हिस्सा या गाँव का कोई किसान इस बात की मांग कर सकता है कि उसकी जिम्मेदारी सबसे भ्रमग कर दी जाय, वह ग्रपना जिम्मा ले सकता है, सबका जिम्मा नहीं ले सकता। साभी जिम्मेदारी का यह मतलब था कि अगर कोई किसान मालगुजारी नहीं देगा, तो वह गाँव के दूसरे लोगो से भी वसूल की जा सकती है। पंजाब में यद्यपि कहने को 'महालवारी' की प्रथा है, तो भी किसान से व्यक्ति-रूप में भी मालगुजारी वसूल की जा सकती है। सी० पी० में भागरा-महालवारी-बन्दोबस्त जैसी ही प्रथा है। जैसे जमीदारी-प्रथा मे 'स्थायी' तथा 'मस्यायी'-बन्दोबस्त हो सकता है, वैसे 'महालवारी' मे भी हो सकता है--ग्नर्थात् 'स्यायी-बन्दोबस्त' में मालगुजारी की रकम एक बार मन्तिम तौर पर निश्चित की जा सकती है, ग्रीर 'ग्रस्थायी-बन्दोबस्त' में उस रकम को २०-३० साल के बाद घटाया या बढ़ाया जा सकता है। परन्तु जैसा हम ऊपर कह आये है, १८८३ के बाद से भारत में 'स्थायी-बन्दोबस्त' की नीति को छोड़ दिया गया क्योंकि बार-बार मालग्रजारी की रकम को बदलने से सरकार उसे बढ़ाकर अपना कोठा पूरा कर सकती थी।

(ग) रम्मतबारी-प्रथा—इस प्रथा में किसान का सम्बन्ध सीधा सरकार के साथ होता है। जमीदारी-प्रथा में जमीदार किसान से मालगुज़ारी वसूल करता है, महालवारी-प्रथा में भी सरकार सब किसानों से मलग-मलग मालगुज़ारी नहीं वसूल करती, मालगुज़ार से वसूल करती है, परन्तु रय्यतवारी-प्रथा में तो सरकार का बौर किसान भर्मात् रय्यत का सीधा सम्बन्ध होता है। शुरू-शुरू में कैंप्टन रीड तथा धौमस मनरों ने १७६२ में इस प्रथा को मद्रास के बारामहल ज़िले में चालू किया भौर उसके बाद धीरे-धीर बम्बई में भी यही प्रथा जारी की गई। भ्रसल में जिन गाँधो में रय्यतवारी-प्रथा जारी की गई उनमें भी पहले 'महालवारी'-प्रथा चल रही थी। 'महालवारी'-प्रथा गाँव की सामुदायिक भावना का एक जीता-जागता दृष्टान्त है। गाँव का सब-कुछ सबका

साभा है। इस दृष्टि से भ्रपने यहाँ साम्यवाद का यह एक क्रियात्मक नमृना या । श्रंग्रेजों ने या तो जमीदारी-प्रवा को प्रोत्साहन दिया, या रय्यतवारी-प्रया को। जमीदारी-प्रया को इसलिए क्योंकि इससे मालगुजारी वसूल करने की उनकी दिक्कत बचती थी, और रम्यतवारी-प्रथा को इसलिये क्योंकि इससे बीच का मुनाफ़ा भी उनकी जेब में जाता था। भग्नेज यही कहते रहे कि 'महालवारी-प्रथा' भारत की प्रथा नहीं है, यहाँ 'रय्यतवारी-प्रथा' ही चलती रही है। बेडन-पावल का कहना है कि भारत के गाँव 'रय्यतवारी' सिद्धान्त पर ही बने हुये थे। इस बात का श्री राधाकमल मुकर्जी ने समर्थन किया है। उनका कहना है कि यहाँ की प्रचलित 'महालवारी'-प्रया इस बात की सिद्ध करती है कि भूमि पर ग्रामवासियों के सामृहिक स्वामित्व की प्रथा यहाँ मौजूद थी। हीर, 'रय्यतवारी-प्रया' का यह अभिप्राय है कि किसान को सीधी सरकार से भूमि प्राप्त होती है, भीर बीच में इसरा कोई दखल देने वाला नहीं है। उसका जमीन पर कब्जा होता है, वह जमीन विरासत मे आगे-आगे जाती है, उसे बेचा जा सकता है। हाँ. प्रगर मालगुजारी न दी जाय, तो उस जमीन को सरकार अब्त कर सकती है, बेदख़ली करा सकती है। भाशा तो यह करनी चाहिए थी कि जहाँ इस प्रकार किसान का भूमि पर स्वामित्व होगा वहाँ किसान खुशहाल होगा, परन्तु क्योंकि अग्रेजी सरकार 'स्थायी-बन्दोबस्त' को छोड चुकी थी, ग्रीर बार-बार नए सिरे से लगान लगाती रहती थी, ग्रीर हर बार पिछली बार से कुछ बढा देती थी, इसलिए 'रय्यतवारी'-प्रधा से भी किसान खुशहाल न हमा।

७. श्रंग्रेजों के समय 'भू-स्वामित्व' की व्यवस्था (Land Tenure System under The British)

भूमि-व्यवस्था के मुख्य झंग दो हैं—'मालग्रुजारी की व्यवस्था' (Land revenue system) तथा 'भू-स्वामित्व की क्यवस्था' (Land

tenure system)। हमने देखा कि अंग्रेजो ने इस देश में जमींदारी-प्रया को प्रधानतादी। उनका ऐसा करना स्वामाविक भी था। पश्चिम से वे झाये थे, वहा 'सामन्त-पद्धति' (Foudalism) को उन्होंने देखा था। पहिचम के ये 'सामन्त' राजा तथा किसान के बीच माध्यम का काम करते थे। भारत के प्राचीन-इतिहास में तो इन सामन्तो का कहीं नाम नहीं धाता, राजा सीचा प्रजा से कर वसूल करता था, परन्तु यहाँ भी बीच के काल में, जब केन्द्रीय राज-शक्त कमजोर पड़ गई, तब इस प्रकार के सामन्तों से काम लिया जाने लगा। इन बीच के लोगों की श्रावश्यकता ही तब पडती है, जब सरकार सीघा प्रजा से संपर्क नहीं बना सकती। मुगलो के समय से इस प्रकार के जामीदार चले आ रहे थे, अग्रेजो ने भी जो इस प्रकार की पद्धति से अपने देश में पहले से परिचित थे, जब यहाँ इस प्रथा को चलते देखा, तो भट-से इसे अपना लिया और इसी प्रधा को देश में प्रोत्साहन दिया। इससे उन्हे मालग्रुशारी बसुल करने मे ब्रासानी प्रतीत हुई ग्रीर जामीदारों को भी किसान से मनमाना लगान वसूल करने की छुट होने के कारण इसमें बहुत लाभ प्रतीत हुआ। परन्तु इससे किसान पर क्या गुजरी?

धगर तो जामीदार जामीन को खुद जीतता-बोता या अपने मक्तूरों से जुतवाता-बुवाता और सरकार को मालगुजारी देता, तब तो कोई समस्या नहीं थी। तब तो सरकार ज्मीदार से मालगुजारी लेती, और जमीदार या तो खुद हल जलाता, या मजदूर रखकर खेती करता। वे मजदूर काम करते और मजदूरी लेकर अलग होते और किसी प्रकार की समस्या न खड़ी होती। परन्तु ऐसा नहीं हुआ। जमीदार ने मजदूर रखने के स्थान में किसान को जामीन खेती के लिए दे दी। इस किसान ने खुद लग कर, अपने बीबी-बच्चों को लगाकर, मौके-बे-मौके अपने दूर के सगे-सम्बन्धियों को बुताकर, जाकरत पड़ी तो मजदूरों को मजदूरी देकर, दिन-रात एक करके जमीन को हरा-भरा किया। अब प्रका यह खड़ा हथा कि जिस किसान ने खुन-पसीना एक करके सुखे में

हरियावल खड़ी की उसका उस जमीन पर स्वामित्य है या नहीं ? क्या जमीदार धपनी इच्छा से जब चाहे उसे जमीन पर से हटा सकता है, या किसान का भी उस जमीन पर कोई प्रधिकार है ?

स्वाभाविक तो यही प्रतीत होता है कि उसका भ्रविकार होना चाहिए, परन्तु स्थिति कुछ विचित्र थी। स्थिति यह थी कि प्रांग्रेजों ने जमीदारों की एक श्रेणी बना दी थी और वे स्वय काम करने के स्थान में किसानो को लगान पर जमीन देकर उनसे काम कराते थे, इन किसानों में से भी कई स्वय काम नहीं करते थे, उन्होंने भी धार्ग जमीन लगान पर देने का सिलसिला चला रखा था। परिणाम यह या कि जमींदार श्रीर किसान के बीच भी दूसरे हकदार थे, श्रीर जमीन को उपजाऊ बनाने तथा कृषि को सुधारने के बजाय हर-एक दूसरे को लुट लेना चाहता था। इस चहुँमुखी लुट का मतिम किसान पर बहुत बुरा असर पडता था, उस बेचारे के पास तो कुछ रहता ही न था। उसका जब चाहे कर बढ़ा दिया जाता था, जब चाहे उसे भूमि से बेदखल कर दिया जाता था। इस सारी स्थिति को सुधारने के लिए समय-समय पर कानन बनते रहे। बगाल मे १८५६ मे 'बगाल रेंट-एक्ट' बना जिसे श्री मार॰ सी॰ दत्त ने बगाल के किसानों के लिए राहत का एक्ट कहा। हम पहले ही कह माये हैं कि बगाल मे 'स्थायी-बन्दोबस्त' या श्रीर जमीदारो के साथ एक बार मालगुजारी की राशि निश्चित हो चुकी थी जिसमे कोई परिवर्तन नहीं हो सकता था। ये जमीदार किसानो को मनमानी तौर पर लूटने लगे थे। जब बाहते उनका लगान बढ़ा देते, न देने पर जब चाहे उन्हें जमीन से निकाल देते । अब इस १८४६ के कानन के अनुसार किसानो को तीन श्रेणियों में बाँट दिया गया। जिन किसानों के पास १७६३ से जमीनें थी, और इस बीच उनके लगान नहीं बढ़े थे, उनके लिये निश्चित हमा कि अब आगे भी उनके लगान कभी नही बढेंगे, जिल किसानों के पास पिछले २० साल से ज्मीनें थीं भीर इस बीस साल में उनके लगान नही बढ़े थे, उनके लिए

कहा गया कि यही समक्ता जायगा कि इनके पास १७६३ से ही ये ज़मीनें हैं और उनके लगान भी नहीं बढ़ सकेंगे; जिन किसानो के पास पिछले १२ साल से जमीनें थी उनको मौरूसी ग्राधकार दे दिया गया और यह निश्चय किया गया कि उनका लगान बिना सरकारी आज्ञा के नहीं बढ़ाया जा सकेगा। इस श्रेणी को बगाल के जमींदारों ने बहुत तंग करना शुरू किया। हरचद वे कोशिश करने लगे कि कोई किसान १२ साल तक लगातार एक ज़ंमीन पर रह न सके। 'बगाल-रेंट-एक्ट' के अनुसार यू० पी०, पंजाब, बिहार, उडीसा, बम्बई तथा मद्रास में भी इसी प्रकार के कानून पास किए गए जिनमें किसान को ज़मीनों पर मौरूसी हक देने का प्रयत्न किया गया, उसे जहाँ तक हो सकता था वहाँ तक ज्यादा-से-ज्यादा 'भू-स्वामित्व' दिया गया, परन्तु किसानों की अधिक संख्या इन कानूनों के क्षेत्र से बाहर ही रही, कानून ही ऐसे बनते थे कि उनकी परिभाषा के भन्दर आने वाले किसानो की सख्या बहुत परिमित रहती थी।

जब पहले-पहल १६३५ के 'गवर्नमेट घाँफ इण्डिया एकट' के अनुसार १६३७ में काग्रेस ने चुनाव में भाग लेकर अपना मत्री-मडल बनाया तब किसानो की स्थिति सुधारने के सम्बन्ध में अनेक कानून बनाये गये। इन कानूनों का उद्देश्य था—(क) लगान बढाने पर रोक लगाई जाय, (ख) बेदखली पर रोक लगाई जाय, (ग) किसानों को मौरूसी हक दिये जाय ताकि उनका भूमि पर स्वामित्व हो जाय, यह स्वामित्व पुद्देनी हो, किसान जब चाहे इस अधिकार को दूसरे को दे सके, (घ) बकाया लगान पर राहत दी जाय और बैलों आदि की कुर्की पर रोक लगाई जाय, (ङ) अगर जमींदारों को मालगुजारी में सरकार की तरफ़ से राहत मिले तो किसान को भी लगान में राहत मिले, (च) अगर किसान ज्मीन को उपजाऊ बनाने या उसके विकास में कुछ खर्च करे तो उसे उसका विकास का मुझाबज़ा दिया जाय।

इन उद्देश्यों को सामने रक्षकर काग्रेस सरकारों ने १६३ में बगाल में 'बंगाल-टैनेसी-अमेंडमेट-एक्ट', १६३६ में यू० पी० में 'यू० पी० टैनेसी-अमेंडमेंट एक्ट', १६३६ में सी०पी०-टैनेसी-अमेंडमेंट एक्ट', १६३६ में सी०पी० में 'सी०पी०-टैनेसी-अमेंडमेंट एक्ट' पास किये और इसी प्रकार मद्रास तथा बम्बई में भी इसी प्रकार के कानून पास किये गए जिनसे किसानों को भू-स्वामित्व के अधिकार देने के साथ-साथ अन्य प्रकार की सुविवाएँ भी दी गईं। १६३६ में उत्तर-प्रदेश में जो सुवार हुए वे निम्न बे—

- (क) जमीदार 'सीर' की जमीन नहीं बढा सकता था। 'सीर'जमीन उसकी कहते हैं जो जमीदार अपने लिए रखता है। इस जमीन
  पर वह मजदूर रखकर काम कराता है। क्योंकि जमीदारों को यह
  डर या कि काश्तकार जिस जमीन पर हल चलायेगा वह किसी-न-किसी
  समय काश्तकार की हो सकती है इसलिए जमीदार 'सीर' बढ़ाते रहते
  थे। इस कानून से जमीदार के लिए 'सीर' की मात्रा निश्चित कर दी
  गई जिससे अधिक वह 'सीर' नहीं बढ़ा सकता था।
- (क्ष) कुछ 'सीर'-ज्मीने जमीदारो की न रही और उन पर जो काश्तकार हल चलाते थे वे उनके मौरूसी काश्तकार बना दिये गए।
- (ग) यह निश्चय किया गया कि पाँच साल के अन्देर-अन्दर भूमि का लगान घटाकर १८६५ और १६०६ में जो लगान या वह कर दिया आय।
- (घ) उसके बाद २० साल तक लगान में कोई तब्दीली नहीं होगी, होगी भी तो किन्ही लास अवस्थाओं में ही हो सकेगी।
- (ङ) बकाया लगान पर सूद की दर घटाकर सवा-छः प्रतिशत कर दी गई।
  - (व) बेदखली के नियम कड़े कर दिए गए।
- (छ) किसान को खेत में बाग लगाने, मकान बनाने के प्रधिकार भी दिए गए।

# ८. जमींदारी उम्मूलन कानून (Zamindari Abolition Act)

किसानो की दशा स्थारने के जो प्रयत्न हुए उनके मुख्य उद्देश्य तीन ये-'मू-स्वामित्व' (Fizity of tenure), 'न्याय-संगत लगान' (Fair rents) तथा 'तबादले की स्वतन्त्रता' (Free transfer)। किसान ये तीन बाते चाहता था। इनमें सबसे बडी समस्या 'भू-स्वामित्व' की थी। जब तक जमीदारी-प्रथा बनी हुई थी तब तक इस समस्या का हल होना कठिन था, इसलिए १ जुलाई १६५२ को उत्तर-प्रदेश में से जमींदारी-प्रथा का ही उन्मलन कर दिया गया। 'प्लैनिग-कमीशन' ते प्रथम पंच-वर्षीय-योजना मे इस बात पर जोर दिया था कि किसानो की दशा सुधारने के लिए जमीदारी-प्रया को हटाना होगा। परिणाम-स्वरूप प्रथम-योजना-काल में सब प्रान्तो में इस प्रथा को कानुनन हटा दिया गया । उत्तर-प्रदेश के कुछ जमीदारो ने प्रथम भारतीय-विधान के अन्तर्गत इस घारा के आधार पर कि किसी के निजी श्रधिकार पर कोई कानून वार नहीं कर सकेगा सुप्रीम-कोर्ट में 'जमीदारी-उन्मुलन-कानन' पर आपित की थी, इसलिए कुछ देर तक इस कानून को स्थगित रसना पड़ा, परन्तु इस बीच १९५२ मे ही विधान मे ऐसा परिवर्तन कर दिया गया जिससे यह आपत्ति जाती रही। यह नया कानन प्राय. सभी प्रान्तो में लग चुका है। उत्तर-प्रदेश के अभीदारी-जन्मलन-कानून की मस्य बातें निम्न हैं :---

धभी तक ज़मीदार के नीचे दो तरह के किसान थे—मौरूसी तथा शिकमी। मौरूसी काक्तकार तो वह था जिसका कई साल तक जोतने के कारण भूमि पर स्वामित्व मान लिया गया था, शिकमी काश्तकार वह था जिसे दो-एक साल के लिए जमीन जोतने के लिये दे दी जाती थी, फिर वापस ले ली जाती थी। ज़मीदार भी शिकमी-काश्तकार रख सकता था, मौरूसी-काश्तकार भी शिकमी-काश्तकार रख सकता था। इसके घलावा जमींदार के पास कुछ घीर जमीन होती थी जिसे, अगर वह छोटा जुमींदार था, तो उस पर खुद हल चलाता था भीर इसलिए बह जमीन 'खुदकाश्त' कहलाती थी; ग्रगर वह बडा जमीदार था, तो नौकर रखकर खेती करता था, यह उसकी 'सीर' की जमीन कहलाती थी। इस प्रकार जमीन चार तरह की हुई-मौरूसी, शिकमी, (प्रधिवासी) खुदकाश्त धौरसीर । जमीदारी-उन्मूलन-कानून के अनुसार जमीदार को तो सरकार ने मुझावजा देकर अलग कर दिया। श्रव ये चार तरह के किसान रह गए। इन किसानो में जिनके पास खुदकाश्त तथा सीर की जमीन थी, वह तो उनकी ही रह गई। भगर बड़े जुमींदार भी थे भौर उनकी सीर की जमीन थी, तो वह भी उनकी ही रही, वह उनसे नहीं छीनी गई। कई छोटे जमींदार थे. वे कहल।ते जमीदार थे परन्तु थे कास्तकार ही, स्वय जोतते-बोते थे। यह खुदकाश्त की जमीन भी उनकी ही रही। ब्रब रही मौरूसी ब्रौर शिकमी जमीन । मौरूसी काश्तकार ब्रब तक भूमि का मालिक नही था, जब तक वह लगान देता रहता तब तक उसे कोई बेदखल नहीं कर सकता था। परन्तु जुनींदारी-उन्मुलन-कान्न के अनुसार यह निश्चय किया गया कि जो मौरूसी-किसान लगान का १० ग्रना सरकार को दे देगा वह उस जमीन का पूरा मालिक बन जायगा, वह 'भूमिधर' कहलायेगा । जब तक वह 'भूमिघर' नही बनता तब तक वह जमीदार की जगह सरकार का मौरूसी काश्तकार रहेगा । शिकमी-काश्तकारों की स्थित इससे भी नहीं सुघरी। १९५४ में 'जमीदारी-उन्मूलन-कानून' में इन शिकमी-काश्तकारों की दशा सुधारने के लिये एक कानुन पास किया गया और यह सुधार ३० अक्तूबर १९५४ से लागू हो गया । इस स्वार के अनुसार शिकमी काश्तकारों को सीर के भिष-कार दे दिये गए। मौरूसी-काश्तकारों को १० गुना मुझाविजा देकर 'भूमिघर' के धर्षकार मिले थे, इन शिकमी-काश्तकारों को भी इसी ११

प्रकार के ग्रधिकार देने की व्यवस्था की गई। प्रदेश-भर में इन सब 'म्रधि-वासियो' (शिकमी काश्तकारो) के ४४३२००० खाते थे जिनका कुल रक्बा २२ लाख एकड था। १६५४ से पूर्व ये अधिवासी (शिकमी) अपने खातेदार को लगान देते थे। अब इन अधिवासी-काश्तकारों (शिकमियो) को अधिकार दिए गए कि पाँच वर्ष तक वे अगर अपनी मूमि पर काबिज रहे और उसके बाद मालगुजारी का १५ गुना जमा करके 'मुमिधर' के ग्रधिकार प्राप्त करना चाहें तो प्राप्त कर लें। इस प्रकार वे भी अपनी भूमि के स्वामी हो जाएँगे और सीचे सरकार को माल-गुजारी भदा करेंगे। जिस प्रकार सरकार ने जमीदारों को हटाने के लिए मुम्राविजा दिया है उसी प्रकार खातेदारो को हटाने के लिए भीर शिक-मियों को 'भूमिघर' बनाने के लिए सरकार उन्हें भी मालग्रुजारी के १० से २० गुने नक का मुद्राविजा देगी। अनुमान है कि उत्तर-प्रदेश सरकार को जमीदारों को १३७ करोड़ धौर खातेदारों को १५ करोड़ रुपये का भुगतान करना पडेगा। जमीदारी तथा खातेदारी का खात्मा होने पर उत्तर-प्रदेश सरकार को १०२८ लाख रुपये की पहले की अपेक्षा अधिक भ्राय होगी क्योंकि जमीदार का मुनाफा सरकार को मिलने लगेगा। इससे किसान को भी लाभ होगा क्योंकि मौरूसी तथा शिकमी काश्तकार के 'भूमिधर' बन जाने पर उसे पहले की अपेक्षा लगान आधा देना पड़ेगा। जमीदार एक बेकार की चीज थी, उसके निकल जाने से सरकार तथा किसान दोनो का फ़ायदा हो गया । आशा तो यह की जाती थी कि इतनी सुविधा होने पर किसान १० ग्रुना भर कर 'भूमिधर' बन जायेंगे. परन्तु किसानों में ग़रीबी इतनी है कि अभी तक ऐसे किसानों की सख्या बहुत काफी है जो 'भूमिषर' नहीं बन सके, फिर भी जमीदार के हट जाने से किसानो के संकट का एक बड़ा भारी कारण दूर हो गया। इसका यह मतलब नही है कि किसान की समस्या पूरी-की-पूरी हल हो गई। जमीदार की जगह शब सरकार श्रा गई। सरकार का मतलब है, तहसीलदार या कोई चपरासी । अब ये डण्डा लिए फिरते हैं धीर

किसान एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फैंस गया है। जमींदार तो लल्लो-चप्पो करने से कुछ मान भी जाता था, ये सरकारी प्रफसर भला कब मानने लगे। इस सब स्थिति पर विचार करके किसानो की स्थिति को और प्रधिक सुधारने की जरूरत है ताकि ऐसा न हो कि हमने किसान का दुःख दूर करने के लिए जो-कुछ किया वह सब मिट्टी में मिल जाय।

इस प्रकार हमने देखा कि ग्राम का सगठन किस प्रकार बदलता-बदलता ग्राज कहाँ ग्राकर खड़ा हो गया है।

#### प्रश्न

- भारतीय ग्रामों का प्राचीन-संगठन कैसा या—इस पर प्रकाश डालिए।
- २. 'मालगुजारी' (Revenue) तथा 'लगान' (Rent) में क्या भेद है---यह बतलाते हुए लिखिए कि समींवारी-प्रथा कैसे उत्पन्न हुई ?
- इ. स्थापी तथा ग्रस्थायी बन्बोबस्त में क्या भेद है? खर्मीबारी तथा रम्यतवारी-प्रथा में क्या भेद है? स्थायी तथा ग्रस्थायी बन्दोबस्त का जर्मीवारी तथा रम्यतवारी से कोई सम्बन्ध है या नहीं? ईस्ट-इष्डिया-कम्पनी ने पहले स्थायी-बन्दोबस्त को जारी करके फिर उसे ग्रस्थायी-बन्दोबस्त में क्यों परिशात किया?
- ४. जमींदारी-प्रया, महालवारी-प्रया, रज्यतवारी-प्रया---इन तीनों में क्या भेद है ?
- ५. 'भू-स्वामित्व' (Lend tenure) के सम्बन्ध में अपने यहां क्या-क्या सुधार हुए ?
- ६. क्षमींदारी-उन्मूलन के सम्बन्ध में धाप क्या जानते हैं ?

# ग्राम-पंचायत

( VILLAGE-PANCHAYATS )

# १. पंचायत का पूर्व इतिहास

स्वायत्त-शासन का यही अर्थ नही है कि कुछ लोगो के हाथ में सत्ता माये, मसली स्वायत्त-शासन तो तभी होता है जब जनता के हर व्यक्ति के हाथ में सत्ता माती है। परन्तु हर व्यक्ति के हाथ में सत्ता कैसे मा सकती है ? इसका तरीका ससार की प्राचीन शासन-प्रणालियों मे मिलता है। ग्रीस, इटली, प्राचीन-भारत तथा भ्रन्य देशों में ऐसी ग्राम-सभाएँ होती थीं, जिनमें गाँव का हर वयस्क-व्यक्ति सदस्य होता था। समय-समय पर गाँव के सब व्यक्ति इकट्ठे होते थे भीर गाँव के मसलो को बहुमत से हल करते थे। यूनानी राजा सैल्युकस का राजदूत मैगस्थनीज पाटलीपुत्र में चन्द्रगुप्त मौर्य के राज्य-काल में यहाँ रहा । वह लिखता है कि यहाँ के नगरों में ऐसी सभाएँ हैं, जिनके ३० सदस्य होते हैं, इनकी ६ उप-समितियाँ होती हैं, जो नगर का शासन करती हैं। नगरों की इन सभाग्रो की तरह ग्रामो की सभाएँ भी होती है। इसी पद्धति द्वारा प्राचीन-भारत में ग्रामों का शासन होता था। ग्रसल में, ग्रामों की समस्याओं को प्रामवासी ही समक सकते हैं। अपनी समस्याओं को हल करने मे जितनी दिलचस्पी उनको होती है उतनी दूसरे किसी को नहीं हो सकती। यह सगठन प्राचीन-काल मे था, इसलिए दिल्ली में किसी का भी राज रहा हो, गाँवों में गाँव वालों का ही राज रहा, सौर भारत की धार्षिक तथा सामाजिक व्यवस्था नहीं टूटी । इसी को 'विकेन्द्रीकरण' या पंचायत-राज्य कहा जाता था । संग्रेजो के साने से पंचायत-राज की यह ध्यवस्था टूट गई । हर बात को संग्रेजी-राज्य ने केन्द्रित करना चाहा । सारी शक्ति गाँव से बाने में धौर बाने से जिले में खींच ली गई । जब पंचायतों के पास किसी प्रकार की शक्ति न रही, तो उनका शिथिल हो जाना स्वाभाविक था ।

# २. पंचायतों के ह्वास का कारण

जैसा हमने कहा, अंग्रेजों के भारत में माने से पूर्व इस देश में गाँव-गाँव में पचायतें बनी हुई थीं। मुसलमानों के समय तक पचायतों द्वारा ही मामों का शासन होता था। अंग्रेजो को यहाँ की पचायत- व्यवस्था देखकर प्रत्यन्त भारचयं होता था। परन्तु ग्रंग्रेजो के लिये इस व्यवस्था द्वारा राज करना कठिन था क्योंकि इस व्यवस्था द्वारा तो शासन जनता के हाथ मे देना होता था। यह उन्हें मभीष्ट न था। उन्होंने जिस व्यवस्था को जारी किया उसमें पचायतों का दिनोंदिस हास होने लगा। प्रग्नेजों की व्यवस्था के निम्न कारणों से पंचायतो का हास तेजी से होने लगा—

(क) लगान बसूली की पद्धति—'ग्राम-संगठन' के प्रध्याय मे हम लिख आये हैं कि पहले यहाँ 'महालवारी'-प्रथा थी। इसका यह अर्थ है कि लगान किसान से व्यक्ति-रूप से बसूल न करके 'महाल' से वसूल किया जाता था। गाँवों के कुछ समूहों को 'महाल' कहा जाता था। वसूली का यह काम किसी समय पंचायत करती थी, फिर जमींदारी-प्रथा चलने पर जमींदार करने सथा। ग्रंगेजों के समय यह कामूब बना कि श्रामान प्रयोक व्यक्ति को स्वयं जमा करना चाहिये जिससे प्रचायती-प्रथा की लगान वसूल करने की दृष्टि से ग्रावश्यकता न रही।

- (क्ष) युनिस तथा कचहरी की व्यवस्था— अब तक बाँव की सुरक्षा तथा गाँव के अगड़े निपटाने का काम पंचायत का था, परन्तु अग्रेजों के समय पुलिस की सुदृढ व्यवस्था हो जाने के कारण गाँव की सुरक्षा की जिम्मेदारी पचायब की न रही और गाँवों के अगड़े कचहरियों में जाने लगे। इस प्रकार पचायतों के पास काम न रहने के कारण भी उनका हास होने लगा।
- (ग) जिला-बोर्डों का निर्माण—१८४२ में शहरों के सुशासन के लिये म्यूनिसिपैलिटिया बनी थी, लार्ड रिपन के उद्योग से १८६२ में डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का निर्माण हुमा जिनका काम जिले भर के गाँवों का प्रबन्ध करना था। डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के बनने से सत्ता पचायतों के हाथ में न रही, डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के हाथ में मा गई।

# ३. पंचायत-प्रथा को फिर से चालू करने के प्रयत्न

परन्तु जैसा हम अभी कह आये हैं, स्व-शासन को तभी स्व-शासन कहा जा सकता है जब जनता के हाथ में सत्ता हो। जनता तो अपने देश में गाँवो में फैली पड़ी है। जब तक उस जनता के हाथ में मत्ता नहीं दी जाती तब तक विधान-सभाभो और ससदो के सदस्य चुन लेने से तो काम नहीं चल सकता। ये सदस्य तो प्रान्तो में या केन्द्र में जाकर बैठ जाते हैं। जनता के हाथ में शासन कैसे आये? इस बात को अनुभव कर स्वतन्त्र-भारत में पचायतों के पुनरुज्जीवन का कार्य-कम प्रारम्भ हुआ। पचायतें बनेगी, तो अपने गाँवों का दिन-प्रतिदिन का शासन गाँव वाले स्वय ही तो करेंगे। यह वास्तिवक रूप में जनता का शासन होगा। स्वतन्त्रता के बाद सब प्रान्तो में पचायतों के निर्माण के कानून बनने लगे। १९४७ को भारत स्वतन्त्र हुआ। और ७ दिसम्बर १९४७ को 'उच्चर-प्रदेशीय पंचायत-राज कानून' स्वीकृत हो गया जिसके. अनुसार पंचायत-सभा और पंचायत-राज कानून' स्वीकृत हो गया जिसके.

१९४६ को कर दिया गया। इस कानून मे अन्तिम संशोधन १९४४ मे हुन्ना।

इसका यह मतलब नहीं कि पंचायत के विचार को १६४७ के बाद से ही सोचना शुरू किया गया। इससे बहुत पहले से इस बात को सोचा जा रहा था कि सत्ता केन्द्र मे केन्द्रित न रहकर जनता के हाथ में ग्रानी चाहिए । केन्द्र से प्रान्त में, प्रान्त से जिले में, भौर जिले से गाँव में सत्ता पहेंचेगी, तभी ठीक-ठीक शासन हो सकेगा। १८४२ तथा १८६२ में कुछ ऐसे कानून बनाये गये थे जिनका आशय यह था कि शहरों में म्यूनिसिपल-कमेटियाँ बननी चाहिएँ ताकि वे शहरो का स्थानीय प्रबन्ध कर सके। १८७० में लार्ड मेयो के प्रस्ताव के अनुसार शहरो मे इन म्यूनिसि-पैलिटियो की सख्या बढ़ा दी गई, किन्तू अभी तक गाँवो की तरफ किसी का व्यान नहीं गया। स्थानीय-निकायने को ठीक उग से चलाने धीर शहरो तक ही उन्हें सीमित न रखने का श्रेय लार्ड रिपन को है। १८८२ में स्थानीय-निकायों के लिये लार्ड रिपन के समय में जो प्रस्ताव ्स्वीकृत हुमा वह भारतवर्ष में 'स्थानीय-निकाय विकास-काल' कहा जाता है। इसके बाद १६०६ मे रायल-कमीशन बना। इस कमीशन ने कहा कि हम अब तक ग्रामी का पूननिर्माण करने में इसलिए सफल नहीं हुए क्योंकि हमने नीव से पूर्नीनर्माण के कार्य को नहीं शुरू किया। इस देश की नीव यहाँ के गाँव हैं। ग्रगर हम ग्रामों का पुनर्निर्माण करना चाहते हैं, तो पचायतो का पुनरुजीवन करना होगा। १६१६ में जब मीन्टेगू-चेम्सफोर्ड सूघारों के मनुसार स्व-शासन के ग्रधिकार की मानकर सत्ता प्रान्तीय मन्त्रियो के हाथ मे दे दी गई, तब ग्राम-पचायतो की तरफ़ सरकार का ध्यान विशेष रूप से गया।

इस समय जगह-जगह ग्राम पंचायतें बनी। हर प्रान्त मे ग्राम-पंचायत-कानून बने। १६१६ में बंगाल मे, १६२० में मद्रास, बम्बई, सी० पी० तथा उत्तर-प्रदेश में, १६२६ में बिहार, उड़ीसा, ग्रामाम में तथा १६३४ में पंजाब में ग्राम-पंचायत-कानून स्वीकृत हुआ। बडौदा, मैसूर, ट्रावनकोर-कोचीन बादि रियासतो मे भी यह कानून स्वीकृत हुआ।

## ३. पंचायत-राज का वर्तमान रूप

भारत के संविधान में सरकारी-नीति के 'निर्देशक-सिद्धान्तीं' (Directive Principles) का वर्णन करते हुए स्पष्ट लिखा है कि ग्राम-पंचायतों के संगठन पर विशेष ध्यान दिया जायगा। जैसा हम उत्पर लिख ग्राये हैं, ग्राम-पंचायत के कातून तो पहले ही बन चुके थे, ग्रब स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद इन पचायतों को विशेष रूप से संगठित करने का प्रत्येक प्रान्त ने प्रयत्न किया। ग्राम-पंचायत के सगठन में तीन ग्रन्य संस्थाएँ ग्रा जाती हैं—(क) ग्राम-सभा, (ख) ग्राम-पंचायत तथा (ग) पचायती-ग्रदक्त है हम यहाँ इन तीनो पर कुछ लिखेगे।

#### ४. ग्राम-सभा

१००० से श्राधिक की आवादी के गाँवों मे एक ग्राम-सभा होगी। जिन गाँवों की आवादी कम होगी, उन्हें पास के दूसरे गाँव के साथ मिला दिया जायगा। २१ वर्ष का हर व्यक्ति—पुरुष हो, स्त्री हो, गाँव-सभा का सदस्य माना जायगा। ग्राम-सभा की दो बैठकें अवश्य होगी—एक खरीफ़ की फसल के बाद, दूसरी रबी की फ़सल के बाद। यदि सभा के २० सदस्य लिखित माँग करे, तो आवेदन-पत्र भानेके ३० दिन के भीतर सभा बुलानी होगी। ग्राम-सभा अपना सभापति अपने-भ्राप चुनेगी। खरीफ़ की फसल के बाद की बैठक में सालाना बजट बनाया जायगा भौर रबी की फसल की बाद की बैठक में बजट का रूपया ठीक-से व्यय हुआ या नही—इस पर विचार होगा।

### ४. ग्राम-पंचायत

ग्राम-सभा के १००० सदस्यो पर ग्राम-पंचायत के ३० सदस्य, १००० से २००० सदस्य-संख्या पर ३६ सदस्य, २००० से ३००० की संख्या पर ३६ सदस्य, ३ व ४ हजार की संख्या पर ४४, और ४ हजार से क्रवर की सदस्य-मंख्या पर ५१ सदस्य खुने आयेंगे। अनुसूचित-खातियों की संख्या के अनुपात से पंचायत में उनका स्थान मुरक्षित रखना होगा। इस प्रकार ग्राम-पंचायत को ग्राम-सभा खुनती है, भौर एक तरह से यह ग्राम-सभा की कार्यकारिणी-समिति है। ग्राम-सभा का सभापति ग्राम-पंचायत का भी सभापति समभा जाता है। पंचायत के कुल सदस्यों में से एक-तिहाई सदस्य प्रतिवर्ष हटते जाते हैं, उनकी जगह प्रतिवर्ष नवीन-सदस्यों का खुनाव होता है, भौर इस प्रकार ग्राम-पंचायत कभी भंग नहीं होती।

ग्राम-पंचायतो का कार्य-क्षेत्र भी निर्धारित कर दिया गया है। ग्राम-पंचायतो के लिए दो प्रकार के कार्य हैं—'श्रनिवार्य' तथा 'ऐच्छिक'। श्रनिवार्य-कार्यों में सडको की देख-भाल श्रौर मरम्मत, उनको सम-तल करता, चौडा करना, ग्राम की सफाई, कूएँ, तालाबो की व्यवस्था, उन्हे शुद्ध रखना, मैला जमा न होने देना, जन्म-मृत्यु का लेखा रखना, प्राथमिक-शिक्षा की व्यवस्था करना, पटवारी, सिपाही, चौकीदार श्राद्ध से श्रमर ग्राम-वासियो को शिकायत हो, तो उसे ऊपर के श्रिष्ठकारियों तक पहुँचोना—ये सब काम ग्राम-पंचायतो के लिए श्रावश्यक हैं। ऐच्छिक-कार्यों में ग्रामवासियो की चिकित्सा का प्रबन्ध करना, बाबनालय तथा पुस्तकालय स्थापित करना, बेती तथा जानवरो की नस्ल को सुधारना, खेल-कूद तथा श्रखाडों का भायोजन, रेडियो का प्रबन्ध, ग्राम की रक्षा के लिए स्वयं-सेवक-दल का निर्माण, मेले-तमाशे-हाट-बाजार का लगाना—ये सब ऐच्छिक-कार्य हैं, जिन्हें श्राम-पंचायत कर सकती है।

परन्तु इन कामों के लिए रूपया चाहिए। रूपए के लिए प्राम-सभा को कुछ टैक्स लगाने के प्रधिकार दे दिये गए हैं। प्राम-सभा मजदूरों से २६० सालाना, पल्लेदारों से ३६०, गाडीवानों से १॥ ६०, व्यापारियों से ६६० सालाना वसूल कर सकती है; १६३६ के काश्तकारी-कानून के मातहत लगान में से १ धाना रुपया टैक्स बसुल कर सकती है; बाहर से पैठ तथा मेलो में जो ज्यापारी अपना माल बैचने के लिए आयें उन पर टैक्स लगा सकती है, पशुआे की बिकी, कसाई- खानो से टैक्स वसूल कर सकती है; २०० रुपये वार्षिक की आय बालो पर गृह-कर लगा सकती है। इसके अतिरिक्त सरकार भी आम-सभाओं को आर्थिक-सहायता देती है। अब तो ज्मीदारी ख्त्म हो गई, इसलिए सरकार ज्मीन की मालिक है। अब जो लगान वसूल होगा वह सरकार आम-सभाओं के द्वारा वसूल करने को सोच रही है। इस वसूली के लिए सरकार की तरफ से १ आना रुपया आम-सभाओं को कमीशन दिया जायगा जिससे आम-सभाओं के पास काफ़ी रुपया जमा हो जायगा और इस रुपये को आम-सभा अपने विकास कार्यों पर ज्यय कर मकेगी।

## ६. पंचायती-स्रदालत

जब प्राम-सभाएँ प्रवायत के सदस्य चुनती हैं तब पाँच प्रतिरिक्त सदस्यों को भी प्रचायती-प्रदाजत के लिए चुन लेती हैं। हर गाँव की प्रपनी प्रवायती-प्रदाजत नहीं होती, कुछ गाँव मिलाकर उनकी प्रचायती-प्रदालत नहीं होती, कुछ गाँव मिलाकर उनकी प्रचायती-प्रदालत बना दी जाती है। हर गाँव के पाच-पांच मिलाकर ४-५ गाँवों में २०-२५ सदस्य हो जाते हैं। ये सदस्य मिलकर स्वयं प्रपना एक सरपंच चुन लेते हैं। सरपंचों ग्रीर सहायक सरपंचों का पढा-लिखा होना प्राव-ध्यक है। प्रस्थेक मुकदमें के लिए सरपंच पहले चुने हुए २०-२५ पचों से पांच पचों का एक 'बैच' नियुक्त कर देता है—वादी के गाँव का एक, ग्रीर प्रतिवादी के गाँव का एक पच इस बैच में होना ग्रावस्यक है, शेष तीन पच ग्रन्य गाँवों के होते हैं ग्रीर यह 'बैच' मुकदमा मुनकर उस पर फैसला करती है।

पचायती-मदालत फीजदारी तथा दीवानी—दोनो प्रकार के फैसले करती है। फीजदारी मे निम्न मामले पचायती-म्रदालत सुन सकती है—म्रदालती समन न लेना, मार्वजनिक मार्ग पर लडाई, मार-पीट,

तेज गाडी चलाना, गन्दे गाने गाना, बेगार लेना, ४० रूपऐ से कम की चोरी, बलात्कार, कूएँ या जलाशय को गन्दा करना, भाग लगाना । इन मामलो में पचायती-अदालत जेल की सज़ा नहीं दे सकती, १०० रु० तक जुर्माना कर सकती है। दीवानी मामलो में १०० रूपये तक के मुकदमे का यह भदालत फैसला कर सकती है, जायदाद, बसीयल आदि के मुकदमो को नहीं सुन सकती। यदि कोई भदालत बहुत श्रच्छा काम करती हो, तो उसे राज्य-सरकार ५०० रु० तक के दीवानी मुकदमे सुनने का श्रिकार दे सकती है।

# ७. पंचायतों के कार्य का मृत्यांकन

पंचायतें ठीक तरह से कार्य करें इसके लिये सरकार ने अपनी तरफ से पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। 'पंचायत-राज अधिनियम' के अनुसार पचायतों के कार्य की देख-रेख के लिये अनेक अधिकारी नियुक्त किये हुए है। पचायत-निरीक्षक, पचायत-अफसर, पंचायत-डायरेक्टर आदि अनेक अधिकारी हैं जिनका काम पचायतों की व्यवस्था को देखना है। ग्राम-सभा, ग्राम-पंचायत तथा पंचायती-अदालत के बजट को पचायत-निरीक्षक देखता है। जो पंचायते ठीक काम नहीं करती उन्हें सरकार भग भी कर सकती है, परन्तु इतना सब-कुछ नियन्त्रण रखने पर भी कई कारणों से पचायते उत्तना संतोषजनक कार्य नहीं कर रही जितना करने की उनसे आशा थी। इसके निम्न कारण हैं:

(क) जातिवाब—अभी तक जाति का विचार अपने देश में काफ़ी जड़ पकड़े हुए है। ऊँच-नीच का भेद भी इस जातिवाद की ही उपज है। गाँवों के लोग प्राय अशिक्षित हैं, जाति के विचार के ऊपर वे नहीं उठ सकते। इसका परिणाम यह होता है कि जब कोई बात पंचायत में आती है तब उसे व्यक्ति की जाति की दृष्टि से देखा जाता। है तथाकथित नीच जाति के व्यक्ति के साथ पूरा-पूरा न्याय नहीं

हो पाता। पंचायतो के चुनाव में भी यह कभी नही हो सकता किं सथाकथित नीच जाति का व्यक्ति कभी पंचायत के किसी उच्च-पद पर चुन लिया जाय।

- (स्त) गुटबन्दी प्रत्येक गांव में जो मुख्य-मुख्य क्यक्ति होते हैं। उनके घपने-घपने गुट होते हैं। इस प्रकार के गुट शहरो में भी होते हैं। गुट के लांग घपने साथियो का योग्यता की दृष्टि से नहीं, परन्तु गुद्द बन्दी के कारण साथ देते हैं। गांवों में तो दृष्यनी भी पुष्तैनी चलती है । इस कारण भी प्रवायनें निष्पक्ष-भाव से गांव-सुधार का कार्य नहीं कर पाती।
- (ग) निर्धनता—इसके अतिरिक्त पचायत का कार्य ऐसा है जिसमें धही व्यक्ति भाग ने सकता है जो आधिक-दृष्टि से निर्धिचत हो। हमारे प्रामवासी प्रात. से सार्य तक अपनी रोटी-पानी की व्यवस्था में ही जुटे रहते हैं, उन्हे पवायती बातों के निये समय ही कहाँ है। इसीलिये जो खाते-पीते लोग हैं, वे फुर्झत से बैठकर जो फैसला कर देते हैं उसे गाँव के लोग चुपके से मान लेते हैं। इसमे सन्देह नहीं कि ज्यो-ज्यों देश की निर्धनता दूर होगी, लोग अन्य दिशाओं में भी दिलचस्पी लेने लगेंगे।
- (घ) ब्रिक्शिसा—प्रवायतो के कार्य में इच्छित सफलता न मिलने का कारण प्रामवासियों का शिक्षित न होना भी है। वे अभी अपने अधिकारों के प्रति उतने सबेत नहीं हुए जितना उन्हें होना चाहिये। एगों-ज्यों शिक्षा का प्रवार बढता जायगा, ज्यों-ज्यो वे अपने अधिकारों को समक्रते जायेंगे, त्यो-त्यो वे प्रवायती-सगठन में अब तक की अपनी उदासीनता को छोड़ कर इसमें हिस्सा लेने लगेंगे।

# द. जिला-बोर्ड, ग्रन्तरिम जिला-परिषद् तथा जिला-परिषद्

जैसा पहले कहा जा चुका है, जिले का काम अध्यवस्थित रूप से चलाने के लिये लार्ड रिपन के उद्योग से १८८२ में डिस्ट्रिक्ट-बोर्डों का संगठन प्रारम्भ हुआ। पंचायती का क्षेत्र तो अपने गाँव तक सीमित रहता है, परन्तु सब ज़िलों के सगठन की भी धावक्यकता है ताकि ज़िले भर की शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, कृषि, पशु-पालन भादि कीसमस्याओं को ग़र-सरकारी तौर पर हल किया जाय और यह कार्य जनता के हाथों में सौंपा जाय। इसी उद्देश्य से जिला-बोर्डी की स्थापना हुई जिसमें चुनाव से कुछ लोग भाते थे भौर जिले की समस्याओं को सुलकाते थे। अब जिला-बोर्डी की जगह जिला-परिषदों की स्थापना हो रही है और इस दिशा में उत्तर-प्रदेश तथा राजस्थान सरकार ने कदम बढाया है। इन राज्यों में जिला-परिषदों का सगठन निम्न प्रकार हुआ है:

(क) उत्तर-प्रवेश में अन्तरिम किला-परिषव् उत्तर-प्रदेश की सरकार ने ज़िले के संगठन की रचना में कुछ हेर-फेर करना धावश्यक समक्षा और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के पिछले जो चुनाव होने वाले थे उन्हें रोक कर प्रान्त के ५१ जिलों में १६५८ में 'अन्तरिम-जिला-परिषद्-अध्यादेश' (Interim Zila Parishad Ordinance, 1958) जारी किया। इस अध्यादेश का उद्देश्य यह था कि जिला-बोर्डों की जगह जिला-परिषदें बनायी जायें, और जब तक जिला-परिषदें बनाने का अधिनियम विधान-सभा में स्वीकृत न हो जाय तब तक अन्तरिम-काल के लिये अन्तरिम-जिला-परिषदें काम करें। यह अन्तरिम-जिला-परिषद्ं क्यादा-से-ज्यादा उपयोगी हो सके, इसमें जिले के सब ऐसे व्यक्ति जो जिले में कुछ भी रचनात्मक कार्य करते हैं भाग ले सकें, इस उद्देश्य से इसका संगठन ऐसा किया गया जिसमें प्रायः सभी उपयोगी व्यक्ति था जाते हैं। अन्तरिम-जिला-परिषद् के सदस्य जो गैर-सरकारी तथा सरकारी होते हैं निम्न प्रकार लिये गये। इस परिषद् का अध्यक्ष जिलाधीश बनाया गया।

### रौर सरकारी सदस्य

(क) ज़िले के लोक-सभा, राज्य-सभा, विद्यान-सभा तथा विद्यान-परिषद् के सदस्य ।

### भारतीय-सामाजिक-संगठन

#### 808

- (ख) जिले का एक हरिजन कार्यकर्ता, ग्रगर वह उक्त सदस्यों मे से कोई नहीं है।
- (ग) जिले की एक सामाजिक तथा रचनात्मक कार्यकर्ती देवी,ग्रगर वह उक्त सदस्यों में कोई नहीं है।
- (घ) पाच-गैर-सरकारी सदस्य जिन्हें सरकार मनोनीत करे जिनमे एक घौद्योगिक कार्यों मे तथा गृह ग्रौर कुटीर उद्योग में रुचि रखता हो।
- (ङ) ज़िलाधीश द्वारा मनोनीत दो गैर-सरकारी सदस्य, जिनमें से एक स्काऊट एसोसियेशन का उच्च ग्रधिकारी हो ग्रौर दूसरा जो विकास-कार्यों में ६चि रखता हो।
- (च) मत्री जिला मैनिक, नाविक तथा वायु-सेना बोर्ड (अगर जिले मे हो)।
- (छ) ग्रध्यक्ष भूतपूर्व जिला-बोर्ड ।
- (ज) जिला बोर्ड के मनोनीत सात सदस्य।
- (भ) जिले के हा० मे० स्कूलो के प्रिन्सिपलो द्वारा चुना हुन्ना एक प्रतिनिधि।
- (अ) मैनेजिंग डायरेक्टर जिला कॉ-भ्रौपरेटिव बैक ।
- (ट) अध्यक्ष ज़िला कॉ-अीपरेटिव डिवेलपमेट फेडरेशन।
- (ठ) समस्त चेयरमैन नगर-पालिका, नोटिफ़ाइड एरिया या टाऊन एरिया।
- (ड) गाँव-समाधी के प्रतिनिधि।
- (ढ) एक प्रतिनिधि ज़िले की हर गन्ना मारकेटिंग सोसाइटी से।
- (ण) संयोजक भारत-सेवक-समाज।
- (त) राज्य नियोजन बोर्ड का जिले में रहने वाला गैर-सरकारी सदस्य ।
- (थ) कृषि-पंडित, भगर जिले मे रहता हो।

(द) राज्य-कृषि-बोर्ड का गैर-सरकारी सदस्य, श्रगर जिले में रहता है।

### सरकारी-सदस्य

जनत ४०-४२ ग्रैर-सरकारी सदस्यो के प्रतिरिक्त प्रन्तरिम-जिला-परिषद् के २६-३० सरकारी सदस्य बनाये गये, जो निम्न प्रकार ये-

जिलाघीश (अध्यक्ष), जिला-नियोजन-अधिकारी (मंत्री), जिला पूर्ति-अधिकारी, जिला पशु-पालन-अधिकारी, जिला स्वास्थ्य-अधिकारी, जिला विद्यालय-निरीक्षक, सब-डिवीजनल आफ़्सर कैनाल्स, असिस्टेंट एन्जीनीयर स्वायत्त-शासन, एक्जीक्यूटिव-एन्जीनियर निर्माण-विभाग, जिला रोजगार-अधिकारी, सिविल सर्जन, डिविजनल-फ़ौरेस्ट-अधिकारी, सब-डिवीजनल-आफिसर, जिला उद्योग अधिकारी, जिला सूचना-अधिकारी, जिला कृषि-अधिकारी, जिला सहकारी-अधिकारी, पुपरि-टेडेट आफ पुलिम, सहायक पचायत-राज अधिकारी, जिला हरिजन कल्याण-अधिकारी, सहायक समाज-कल्याण अधिकारी, जिला सगठन प्रान्तीय-रक्षक-दल, जिला सगठका महिला-मगल-योजना।

श्रव ३१ जुलाई १६५६ मे उत्तर-प्रदेश की विधान-सभा में श्रन्तरिम ज़िला-परिषद् के स्थान में जिला-परिषद् के स्थिर रूप से बनाये जाने का प्रस्ताव रखा गया है श्रीर झाशा की जाती है कि शीध्र ही डिस्ट्रिक्ट-बोर्डों के स्थान में जिला-परिषदें कार्य करने लगेंगी।

(क) राजस्थान में जिला-परिषद्—उत्तर-प्रदेश की तरह राज-स्थान में जिला-परिषदों को डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का स्थान दिया गया है। जिला-परिषद् परामर्श देने एवं सरकार व पचायत-समिति तथा पचायतों के बीच श्रुखला स्थापित करने वाली संस्था होगी।

जिला-परिषद् में, जिले की समस्त पचायतो के प्रधान भीर उनकी ' भ्रमुपस्थिति में उप-प्रधान, जिले से निर्वाचित ससद्-सदस्य भीर जिले में निवास करने वाले रोज्य-सभा के सदस्य, जिले से निर्वाचित विधायक-गण, जिले के केन्द्रीय सहकारी बैंक का अध्यक्ष भीर उसके जिला परिषद् का पदेन सदस्य होने की स्थिति में बैक के उपाष्यक्ष सदस्य होगे। परिषद् को अधिकार होगा कि वह जिला-परिषद् में एक महिला, परिगणित जातियो या अनुसूचित जातियो के प्रतिनिधि तथा प्रशासन, सार्वजिनक जीवन व देहातो के विकास में दिलचस्पी रखने वाले अनुभवी अयिक्त, नामजद कर सकेंगे। जिला-विकास-प्रधिकारी जिला-परिषद् का पदेन सदस्य होगा, लेकिन उसे मतदान का अधिकार नहीं होगा।

जिला-परिषद् अपने सदस्यों में से अपना प्रमुख और उपप्रमुख चुनेगी। इनका चुनाव सदस्यों के मनोनयन होने के बाद ग्रुप्त मतदान द्वारा किया जायगा। जिला-परिषद् का कार्य-काल तीन साल रहेगा और लोक-सभा व राज्य-सभा के सदस्यों के लिए यह नियम रहेगा कि वे जब तक ससद् के सदस्य हैं, तभी तक जिला-परिषद् के पदेन सदस्य हो। ससद् सदस्यता समाप्त होते ही उनकी यह सदस्यता भी समाप्त हो जाएगी।

जिला-परिषद् को विभिन्न कार्यों के लिए अपनी उपसमितियां बनाने का अधिकार होगा। जिला-परिषद् सरकार के किसी भी विभाग के जिले के अधिकारी को अपनी बैठक में बुला सकेगी। अधिकार दिया गया है कि जिला-परिषद् अपने तीन-चौथाई बहुमत से प्रस्ताव स्वीकार करके सरकार से जिला-परिषद् के सचिव के तबादले की मांग कर सके। सचिव सरकार द्वारा नियुक्त राज्य-कर्मचारी होगा।

जिला-परिषद् को सचिव से रिकार्ड भांगने का अधिकार होगा। यह पंचायत-सिमिति के बजट की जांच कर सकेगी। राज्य-सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता पचायत-सिमितियों मे बाँट सकेगी। पंचायत-सिमितियों द्वारा तैयार की गयी योजनाओं और उनके कार्य-कलाप में समन्वय कर सकेगी।

ज़िला-परिषद् का प्रमुख, सैचिव भीर अन्य कर्मचारियों के काम-काज पर प्रशासनिक नियन्त्रण रखेगा भीर पंचायतों में उस्साह भीर पंचायतों में उत्साह भौर पहल की भावना कायम करने के लिए प्रयत्नशील रहेगा एवं सरकारी स्वेच्छिक संगठनों के विकास भौर उनके द्वारा किए जाने वाले उत्पादन कार्यक्रमों में उनको सलाह भी देगा।

राज्य-सरकार हर जिला-परिचर् के लिए एक सचिव नियुक्त करेगी जो राज्य-सेवा से सम्बन्धित व्यक्ति होगा। यह नियुक्ति सामान्यतः जिला-परिषद् के प्रमुख की सलाह से होगी और निशेष स्थिति में जिला-परिषद् के कुछ सदस्यों के तीन-चार बहुमत हारा स्वीकृत प्रस्ताव ते होगी।

#### प्रश्न

- प्राचीन-भारत में ग्राम-पंचायत का विचार कित कप में पाया जाता है?
- २. पंचायत-राज का वर्तमान रूप क्या है ?
- ३. पाम-सभा, प्राम-पंचायत तथा पंचायती-सदासत क्या है ?

# भारत की निर्घनता—कारण तथा निवारण

(INDIAN POVERTY—CAUSES AND REMEDIES)

# १. निर्धनता

जब धन नहीं था, तब धनी-निर्धन का भेद भी नहीं था। आदि-काल में तो वस्तुओं को जोड़कर रखने की भी ज़रूरत नहीं थी। धीरे-धीरे बुरे वक्त के लिए जोड़ने की भावना उत्पन्न हुई, और इसके साथ ही सम्पन्न भीर असम्पन्न का भेद उत्पन्न हुआ। युरोप में 'सामन्त-पर्द्धति' (Feudal system) के समय यही भेद मालिक और शुलाम का रूप धारण कर गया, और भौद्योगिक-क्रान्ति के बाद जब भूमि के स्वामित्व के बिना भी व्यक्ति धन का मालिक बनने लगा, जिनके पास जुमान नहीं थी वे भी कल-कारखाने खड़े करके रूपये-पैसे वाले हो गए, तब उन लोगों को जो असम्पन्न थे, जो पहले कभी सामन्त-युग में गुलाम कहे जाते थे, धब मजदूर कहा जाने लगा। पूँजीवाद के युग में दो वर्ग बड़े स्पष्ट रूप में समाज के सामने था गये—एक पूँजीपति थे, दूसरे पूँजी-विहीन थे। इस समय धनी-निर्धन का भेद अत्यन्त स्पष्ट हो गया, और समाज में ये दो श्रेषियाँ बन गई।

धनी तथा निर्धन सापेक्षिक शब्द हैं। जिसे हम धनी समभते हैं वह दूसरे की अपेक्स अपने को निर्धन समभता है, जिसे हम निर्धन कहते हैं वह दूसरे की अपेक्षा घनी होता है। परन्तु फिर भी निर्धनता की परिभाषा की जा सकती है। निर्धनता मनुष्य की उस प्रवस्था का नाम है, जिसमें धामदनी की कभी या फ़िज़लखर्ची से, वह धपनी तथा अपने शाधितों की भौतिक तथा मानसिक बावश्यकताओं की पूरा करने के अपने उस स्तर को कायम नहीं रख सकता, जिसकी समाज के दूसरे लोग उससे भाशा रखते है। भपनी दृष्टि में तो हर-एक भपनी भक्ल भीर दूसरे का धन श्रधिक समऋता है। निधनता की असली परख यह है कि दूसरे भी यह समभ्में कि जो स्तर इसका होना चाहिए, वह नहीं है। हर-एक देश का अपना-अपना स्तर है, अपनी-अपनी वह रेखा है जिससे ऊपर के लोग धनी गिने जाते हैं, जिससे नीचे के लोग निर्धन गिने जाते हैं। श्रमरीका के स्तर के अनुसार जिसे निर्धन कहा जायगा. भारत के स्तर के अनुसार उसे धनी कहा जायगा, भारत के स्तर के अनुसार जिसे धनी कहा जायगा, प्रमरीका के स्तर के प्रनुसार उसे निर्धन कहा जायगा। निर्धनों की समस्या उन लोगों की समस्या है जो व्यक्ति की भपनी दृष्टि के अनुसार नहीं, भपित समाज की दृष्टि में जीवन के स्तर को कायम नहीं रख सकते।

## २. भारत की निर्धनता

भारत संसार का सबसे निर्धन देश है। दाने-दाने को सही सथों में सरसने वाले व्यक्ति इसी देश में पावे जाते हैं। तन-बदन पर कपड़ां नहीं, रहने को भ्रोंपड़ी तक नहीं, सड़क पर रात बिता देते हैं, बीमारी हुई तो मर जाने के सिवाय छुटकारा नहीं—ऐसे व्यक्ति अपने देश में हैं।

हम पहले लिख बाये हैं कि भारत की राष्ट्रीय-बाय १६४ म-४६ में म्ह्रिंग करोड़, १६४६-५० में ६०१० करोड़, १६५०-५१ में ६५३० करोड़, १६५१-५२ में ६६६० करोड़, १६५२-५३ में ६म्६० करोड़ मौर १९१३-४४ में १०६०० करोड़ कूती गई है। यह मामदनी ३६ करोड़ जनसंख्या की है, इसलिए इस समय २६७४ क्या प्रति व्यक्ति धामदनी है—इस देश में । इसका मिप्राय यह हुआ कि हमारे देश में प्रति व्यक्ति २२-२३ रूपमा मासिक मामदनी है। यह मामदनी तब है जब लाखों-करोड़ों रूपमा कमाने वाले पूँजीपतियों की मामदनी को इसमें वामिल कर लिया जाय। मगर उस मामदनी को इसमें से निकालकर सिफ़ं मध्यम-वर्ग की भामदनी का हिसाब लगाया जाय, तो वह तो बहुत ही कम बैठती है। १६५०-५१ में मारत-सरकार ने कृषि तथा मजदूरी करने वाले वर्ग की मामदनी की जाँच करने के लिए जो कमेटी बनाई थी उसके भनुसार इस वर्ग की भौसत भाय सिफ़ं १०४ रु० वार्षिक या =॥ रु० मासिक के लगभग बैठती है। इतनी ग्राय सिफ़ं १०४ रु० वार्षिक या =॥ रु० मासिक के लगभग बैठती है। इतनी ग्राय से किसका ग्रुज्र हो सकता है ?

## ३. भारत की निर्धनता के कारण

(क) अंग्रेजों की आधिक-नीति—जब तक ग्रंग्रेज़ यहाँ रहे तब तक भारत की निर्मनता का मुख्य-कारण श्रंग्रेजों की आधिक-नीति रहा। श्रंग्रेजों की आधिक-नीति मारत के हित में न होकर सदा अपने हित में रही। उन्होंने बाहर के व्यापार पर रोक-धाम करने और देश के भीतर के व्यापार को प्रोत्साहन देने का कोई काम नहीं किया। श्रंग्रेज़ी माल यहाँ बने माल से यहाँ सस्ता बिकता रहा। व्यापार के सम्बन्ध में उन्होंने 'न्यूनतम-हस्तक्षेप' की नीति को अपनाया और बाहर का माल यहाँ श्रा्में ग्रात्म रहा। मुकाबिले में भारत का बना माल टिक न सका। 'न्यूनतम-हस्तक्षेप' के श्रातिरिक्त पाँड और स्पये की 'विनिमय-दर' ऐसी रखी जाती रही जिससे भारत को सदा नुकसान और श्रंग्रेज़ों को सदा नक्षा होता रहा।

बिटिश-काल में भारत के अर्थ-शास्त्रियों तथा अंग्रेज्-शासकों में यहाँ की निर्धनता के विषय में सदा एक विवाद चला करता था। भारत के अर्थशास्त्री कहा करते थे कि अब से अंग्रेज आये तब से इस देश की निर्धेनता बढी, घं पेच कहा करते वे कि भारत पिछले वो हजार साल से निर्धन-देश रहा है, इसकी निर्धनता का मुख्य-कारण यहाँ की बढ़ती हुई जन-संस्था है। इस सिलसिले में दादा माई नौरोजी का कहना था कि तुम इस देश का रुपया तो सब इ कुलैण्ड में सींचते चले बाते हो, यहाँ पूँजी बनने नहीं दे रहे, और जन-संख्या की बेकार दहाई दे रहे हो। धगर देश का रूपया देश में रहने दिया जाय, तो पूँजी बने, धौर पूँजी बनकर कल-कारखाने खुलें, व्यापार बढ़े, 'राष्ट्रीय-ब्राय' बढ़े । फ़िलहाल तो देश की अधिक जन-संस्था कल-कारखाने ही चलाने के लिये अरूरी है। दादा भाई नौरोजी तथा अन्य अर्थ-शास्त्रियों का यह भी कहना था कि देश की निर्धनता का एक कारण 'होम-बार्बेज' है। भारत का शासन लण्डन से होता था । उस सम्पूर्ण-शासन के लिये भारत को पैसा देना होता था। अंग्रेजो को पेंशन हम देते वे। इन मदों में करोडों रुपया यहाँ से सुत लिया जाता था। अभेज बड़ी भारी फ़ौज रखते मे । भारतीय-ग्राय का बड़ा भाग सैनिक-ब्यवस्था पर खर्च कर दिया जाता था। अब ये सब बातें पुरानी हो गई है, परन्त भारतीय-निधनता पर विचार करते हुए इन सबको दोहराना भावश्यक हो जाता है।

(क) पूँजी निर्माण की कम बर — जैसा हमने अभी कहा, भारत में पूँजी का निर्माण उस दर से नहीं होने दिया गया जैसा अन्य देशों में हुआ। रुपये को तो रुपया पैदा करता है। जिस देश के लोग भर-पेट मोजन न पा रहे हों, तन-बदन ढकने को जिनके पण्स कपड़ा न हो, वहाँ वे क्या लायेंगे और क्या क्वायेंगे। पूँजी तो बचत का नाम है। जब बालू खर्च के लिए ही काफी नहीं, तो बचेगा क्या? ऐसी हालत में देश में पूँजी का निर्माण न हो सकना स्वामाविक है, और पूँजी के निर्माण न हो सकने से ज्यापार-उद्योग-बन्चे उस पैमाने में नहीं खड़े हो सके जिस पैमाने में होने चाहिए थे। जन तो ज्यापार-उद्योग से बढ़ता है, वह न हुमा तो देश को निर्मण होना ही था। इसका यह सतलब नहीं कि अपने देश में पूँजी बनती ही नहीं रहीं। बनती रही है, परन्तु

जिस मात्रा में पूँजी बनती रही है उसी मात्रा में ही तो उस पूँजी का स्थापार-धन्धे में विनियोग होगा। जब पूँजी ही कम बढ़ी तब उसका विनियोग भी तो कम ही होगा।

- (ग) अनुत्यादक संखय—जो-कुछ पूँजी बनती भी रही, अपने देश में उसे या तो जमीन में गाड रखने की प्रवृत्ति रही, या हम उसके सीने- चाँदी के जेवर बना देते रहे। हमारा जो-कुछ भी पूँजी का संखय रहा वह उत्पादक-कार्यों में लगने के स्थान में अनुत्यादक-कार्यों में लगने रहा। 'इकोनोमिक जनरल' ने दिसम्बर १६२६ में लिखा था कि इस देश का लगभग ७६६ करोड रुपया सोने-चाँदी के जेवरों में बन्द है।
- (घ) प्राथमिक-उद्योगों पर निर्भरता-कारवर महोदय ने भ्रपनी पुस्तक 'त्रिन्सिपल्स ग्रांफ पोलिटिकल इकौनोमी' में धन-उत्पादन करने के साधनो पर विचार करते हुए उद्योगों को तीन श्रेणियों में विभक्त किया है-प्रथम श्रेणी के 'प्राथमिक-उद्योग' (Primary industries); द्वितीय-श्रेणी के 'माध्यमिक-उद्योग' (Secondary industries); तृतीय श्रेणी के 'वैयक्तिक तथा धन्धे-सम्बन्धी कार्य' (Tertiary, personal and professional services)। 'प्रथम-श्रेणी' के उद्योग फिर दो तरह के होते हैं। एक तो वे जिनमें हम कुछ पैदा करते हैं - जैसे खेती करना, मक्रली-सुर्गी ग्रादि पालना । दूसरे वे जिनमें हम पैदा तो नहीं करते, परन्तु जो बने-बनाये हमें मिल जाते हैं - जैसे शिकार कर लाना, लकड़ी काट लाना । 'द्वितीय-श्रेणी' के उद्योग वे हैं जिनमें हम कोई उद्योग जारी करते हैं। जैसे व्यापार करना, कल-कारखाना लगाना, यातायात के साधन, बैक चलाना, मकान बनाना । 'तृतीय-श्रेणी' के उद्योग वे हैं जिनमे हम वैयक्तिक तौर पर कोई घन्या करते हैं—डाक्टरी का पेक्षा, भ्रष्यापकी, दुकान या सरकारी नौकरी ग्रादि । ये 'सेवा-कार्य' (Services) कहलाते हैं। यह मोटी बात है कि किसी देश की जितनी जन-संख्या 'माघ्यभिक-उद्योगों' तथा 'सेवाझों' में लगी होगी उतनी ही देश की 'राष्ट्रीय-माय' बढ़ेगी। प्रन्य देशों में माघी के लगभग जन-संस्था

'माध्यमिक-उद्योगों', सर्वात् क्यापार धादि में लगी हुई है, मारत की सिकांस जन-संस्था 'प्राथमिक-उद्योगों' धर्मात् कृषि प्रादि में लगी हुई है। प्रपने देश की निर्मता का यही मुख्य कारण है। हमारा देश मुख्य तौर पर कृषि-प्रथमन है, धतः प्रथम-पंच-वर्षीय-योजना में तो उन साधनों की तरफ़ ध्यान दिया गया या जिनसे कृषि की वृद्धि तथा ध्यवस्था हो सकती है। प्रथम-पंच-वर्षीय-योजना का लक्ष्य 'राष्ट्रीय-धाय' को ११ प्रतिशत बढ़ा देना था। योजना के घन्त में बह ११ की जगह १० प्रतिशत बढ़ी। धब द्वितीय-पंच-वर्षीय-योजना में प्रधिक ध्यान कृषि के स्थान में द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी, प्रथात् उद्योग तथा धन्धों की तरफ़ दिया गया है जिससे 'राष्ट्रीय-प्राय' में २५ प्रतिशत वृद्धि की प्राशा की जा रही है।

- (क) जन-संस्था की वृद्धि— भारत की जन-संस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है। १८५० में इस देश की जन-संस्था १० करोड के लगभग थी। यह घग्रेजों का कहना है, हो सकता है ज्यादा हो, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि माजकल के मुकाबिले में बहुत कम थी। १९५१ में हमारी जन-संस्था ३६ करोड १८ लाख हो गई। सौ साल में बढ़ी हुई २६ करोड़ जन-संस्था के लिए जमीन फैलने के बजाय सिकुड़ गई। १६४७ में देश के विभाजन के बाद जन-संस्था बढ़ गई, जमीन कम हो गई। प्रपत्न देश में जन-संस्था की वृद्धि का धनुपात १.८ प्रतिशत प्रतिवर्ष है। इसका यह धर्ष है कि हर वर्ष इस देश में ७० लाख व्यक्ति बढ़ जाते हैं। ऐसी हालत में खमीन हमारी जन-संस्था के बोक को नहीं सँभाल पा रही भौर इसलिये निर्धनता का बढ़ना स्वाभाविक हो गया है।
- (भ) कार्य-समता की कमी—अपने देश में निम्न-वर्ग के व्यक्तियों को खाने को पूरा नहीं मिलता । श्रमी-वर्ग मेहनत करता है, परन्तु ची-दूध नहीं पाता । वनस्पति-धी और चाय के बल पर कहाँ तक दिन-रात एक कर के मेहनत की जा तकती है। जब कोई पौष्टिक पदार्थ साने को नहीं मिलता तब याधा काम ही तो किया जा सकता है। हर क्षेत्र में मही

समस्या है। पौष्टिक-मोजन न पा सकते के कारण अभी पूरा काम नहीं कर पाते। जब अभी-वर्ग पूरा काम नहीं करेगा तब 'राष्ट्रीय-आय' कैसे बढ़ेगी? 'राष्ट्रीय-आय' न बढ़ने का एक कारण अभी-वर्ग की कार्य-समता का गिर जाना है। अन्य देशों के अभी हमारे अभियों से क्यादा काम कर सकते हैं क्योंकि पौष्टिक-भोजन खाने के कारण उनका शरीर बलिष्ठ होता है।

(छ) पूँजीवादी व्यवस्था—गपने देश में पूँजीवादी-व्यवस्था मभी तक चल रही है। यद्यपि हमने 'समाजवादी-समाज' बनाने की घोषणा कर दी है, तो भी मभी सिलसिला तो वही पुराना चल रहा है। मभी तक उत्पादन के साधनों पर राज्य का प्रभुत्व नहीं, पूँजीपितयों का ही प्रभुत्व है, राज्य का प्रभुत्व धीरे-धीरे हो रहा है। ऐसी ग्राधिक-व्यवस्था में यह स्वामाविक है कि मुनाफे का अधिक भाग पूँजीपित ले जायें भीर प्रभिक संख्या गरीबों की रह जाय। वैसा ग्रभी तक ही रहा है।

### ४. निर्धनता के निवारण के उपाय

जब से देश स्वतन्त्र हुमा है तब से भारत-सरकार का घ्यान देश की निर्धनता को दूर करने की भीर विशेष रूप से गया है। निर्धनता को दूर करने के लिये भारत-सरकार ने पहले प्रथम-पंच-वर्षीय-योजना (१६४१-१६५१) चलाई, फिर द्वितीय-पच-वर्षीय-योजना (१६४६-१६६१) चलाई, इसके बाद तृतीय-पच-वर्षीय-योजना चलेगी। आधिक-क्षेत्र में पहले भारत-सरकार ने ६ म्रप्रैल १६४६ को एक प्रस्ताव स्वीकृत किया जिसमें प्रपनी भौद्योगिक-नीति को स्पष्ट किया गया था। उसके बाद ३० मर्गल १६४६ को एक नया प्रस्ताव स्वीकृत किया गया जिसमें पिछले मनुभव के प्रकाश में भपनी भौद्योगिक-नीति को नए सिरे से रखा गया है। भारत-सरकार के ये सब कार्य देश की निर्धनता को दूर करने के लिए हैं। इस प्रकार प्रथम-योजना, द्वितीय-योजना, भौद्योगिक-नीति का प्रथम-प्रस्ताव तथा द्वितीय-प्रस्ताव—ये चार बातें है जिनका भारत

की निर्धनसा के निवारण के विषय में विचार करते हुए जान लेना झावश्यक है। हम इन चारों का यहाँ संक्षेप से वर्णन करेंगे :---

(क) प्रथम-पंथ-वर्षीय-पोजना—धगर देश की धार्थिक-उत्नति को बिना किसी हस्तक्षेप के छोड दिया जाय, व्यक्ति को पूरी-पूरी स्वतंत्रता दे दी जाय, तो जो हालत हो सकती है वह दुनियाँ में प्रव तक होती रही है। कुछ लोग धपने परिश्रम से झागे निकल गए, पूँजीपित बन गए, कुछ इस बहोजहद में पीछे रह गए। बर्वशास्त्र के 'प्रतिस्पर्घा' के नियम से घनी-निर्धन वर्ग उत्पन्त हो गया, मालिक-मजदूर वर्ग बन गया। मजदूरों को जब साथ-साथ रहना पड़ा, तब अपनी अवस्था की तरफ उनका व्यान गया, उन्होंने संगठन बनाये, अपने अधिकारों के लिये उन्होने हड़तालें करनी शुरू की। मजदूरों के साथ सुलह किये बग़ैर पूँजीपतियों का काम नहीं चलता इसलिये कुछ ये भूके, कुछ वे भूके। यह तो आधिक-विकास का एक तरीका है। दसरा तरीका है 'योजना' बनाकर क्राधिक-व्यवस्था को राज्य द्वारा चलाना । जो देश भाधिक-व्यवस्था में बहुत पिछड़े हुए हैं उनके लिए भपने भाग्य को स्थिक्त पर छोड देना श्रव संमव नहीं रहा। इस प्रकार वे अपने की छोड़ देंगे, तो फिर पुँजीवादी-व्यवस्था के बजाय वहाँ भीर कुछ न हो सकेगा। इन पिछडे देशों ने 'बोजना-पद्धति' का माश्रय लिया है। १६२६ में सबसे पहले रूस ने इस प्रकार की 'पंच-वर्षीय' योजना बनाई । रूस ने उसके बाद कई 'पंच-वर्षीय-पोजनाएँ' बनाई', और इनके द्वारा उसने आइचर्यजनक उन्तति की । दूसरे देशों ने भी जहाँ कम्युनिस्म चल रहा है इसी प्रकार की 'पंच-वर्षीय-योजनाएँ' या 'षट्-वर्षीय-योजनाएँ' बनाई' ।

जहां राज्य की तरफ़ से कोई हस्तक्षेप नहीं था, व्यक्ति को स्वतंत्र-विकास के लिए 'न्यूनतम हस्तक्षेप' (Laiseez-faire) के सिद्धान्त के अनुसार छोड दिया गया था, वहाँ 'राष्ट्रीय-आय' में उस प्रकार वार्षिक वृद्धि नहीं हुई जैसी वृद्धि वहाँ हुई जहाँ राज्य द्वारा 'योजना-मद्धित' को अपनाया गया। निम्न धाँकडों से यह बात अस्थिषक स्पष्ट हो जाती है:—

स्यूनतम-१	हस्तकोष से वैयक्तिक-स्वतन्त्र	ता पर चलने वाले देश
देश	समय	'राष्ट्रीय-माय' में वृद्धि
१. अमरीका	१=हह से १६५०	३.२ से ३ प्रतिशत
२. कनाडा	१६०३ से १६२६	२.६ प्रतिशत
<b>३. स्विटज</b> रलं	ण्ड १ ६६० से १६२६	২.৩ স্বরিথন
४. झास्ट्रेलिय	रा १६०१ से १६४ न	२.५ प्रतिचत
रा	ज्य के हस्तक्षेप से योजना ।	पर चलने वाले क्षेत्र

#### 'राष्ट्रीय-साय' में वृद्धि देश समय पहले १५ फिर १६% १६२८ से १६४३ १. रूस १४.५ प्रतिशत १६४७ से १६४३ २. पोलैण्ड १२ प्रतिशत ३. चैकोस्लोवाकिया १६४८ से १६५३ १२ प्रतिशत १९५२ से १९५३ ४. हगरी १६ प्रतिशत ५. बल्गेरिया १६५२ से १६५३ १८ प्रतिशत १९५१ से १९५६

६. भारत १६५१ से १६५६ १८ प्रतिशत
स्वतन्त्रता प्राप्त होने के बाद भारत ने भी अपनी 'पंच-वर्षीय-योजना'
भनाई। १६५० में 'प्लीनग-कमीशन' बनाया गया और १६५१ से
१६५६ की 'प्रथम-पच-वर्षीय-योजना' की नीव रखी गई। इस योजना
के पूरे होने पर 'राष्ट्रीय-आय' ११ प्रतिशत बढ जाने का भनुमान
लगाया गया था, परन्तु योजना के अन्तिम वर्ष में हिसाब लगाने पर
जात हुआ कि 'राष्ट्रीय-आय' ११ की जगह १८ प्रतिशत बढ़ गई थी।
१६५१-५६ की 'प्रथम-पच-वर्षीय-योजना' के अन्त में भनाज के उत्पादन
में १४ प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया था, वह १४ की जगह
२० प्रतिशत बढ़ा। तिलहन में ८ प्रतिशत बृद्धि का अनुमान लगाया
गया था, वह ८ ही प्रनिशत बढ़ा। कपास में 'प्रथम-पंच-वर्षीय-योजना'
के अन्त में ४४ प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया
गया था, वह ८ ही प्रनिशत बढ़ा। कपास में 'प्रथम-पंच-वर्षीय-योजना'
के प्रन्त में ४४ प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया था, वह ४५ प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया
गया था, वह ८ ही प्रनिशत बढ़ा। कपास में 'प्रथम-पंच-वर्षीय-योजना'
के प्रन्त में ४४ प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया था, वह ४५ प्रतिशत वृद्धी का अनुमान लगाया गया था, वह ५ प्रमिन्यन एकड़ प्रूमि में
भनाज पैदा हुपा था, १६५४-५५ में ३५६ मिलियन एकड़ प्रूमि में

स्रानाज पैदा हुसा। महरों ते, बंजर मूमि को तोड़ने से स्रानाज पैदा करने लायक सूमि इतनी स्रधिक बढ़ा ली गई। यह तो 'कृषि-सम्बन्धी-उत्पादन' (Agricultural production) की बात है, 'सौद्योगिक-उत्पादन' (Industrial production) में १६५१ की सपेक्षा १६५५ में २२ प्रतिशत वृद्धि हो गई। १६५०-५१ में देश में ६५७५ मिलियन किलोवाट विजली पैदा होती थी, १६५५-५६ में वह बढ़कर ११००० मिलियन किलोवाट हो गई। सीमेंट का उत्पादन १६५०-५१ में २.७ मिलियन टन हो गया।

इस प्रकार हमारी 'राष्ट्रीय-माय' (National income) तो 'प्रवम-पंच-वर्षीय-योजना' के झन्त में १ प्रतिशत बढी, परन्त इसका यह भिभिप्राय नहीं कि हमारी निर्धनता दूर हो गई। इतना सब-कुछ कर चुकने पर भी हमारा जीवन-स्तर संसार में सबसे नीचा है। हमारे देश में लोगो को भोजन की वह मात्रा नहीं मिलती जो स्वास्थ्य कायम रखने के लिए एक मनुष्य को मिलनी चाहिए। १९५५-५६ में प्रति व्यक्ति १६ गज कपडा पैदा हो रहा या जो बिलकूल भपयप्ति है। भ्रशी तक ६ से ११ वर्ष के ४० प्रतिशत बच्चे स्कलों की शिक्षा से लाभ उठा रहे हैं, और ११ से १४ वर्ष के बच्चों में से पांचवें हिस्से से भी कम बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। देश की प्राधी जनसंख्या की भामदनी १३ रुपया मासिक भी नहीं है। अमरीका की अपेक्षा हमारे यहाँ प्रति-व्यक्ति बिजली का खर्व की तथा लोहे का खर्व की है, जापान की भ्रपेक्षा हमारे यहाँ विजली भीर लोहे का खर्च कमशः है तथा 😽 है। इससे स्पष्ट है कि अभी हमें अपने देश की निर्धनता की दूर करने के लिये कितने अधिक प्रयास की और कितनी ही 'नंच-वर्षीय-योजनाओं' की श्रावस्यकता होगी।

(स) द्वितीय-पंच-वर्गीय-योजना---'प्रथम-गंच-वर्णीय-योजना' के १६५६ में समाप्त होने के बाद, जारत सरकार ने 'द्वितीय-यंव-कर्षीय- योजना' का कार्यक्रम तैयार किया। 'प्रथम-पंच-वर्षीय योजना' तथा 'द्वितीय-पंच-वर्षीय-योजना' में आधार-भूत भेद क्या है ?

पहली योजना का मुख्य-उद्देश्य देश की 'कृषि-सम्बन्धी' (Agricultural) भवस्था को उन्नत करना था, इसलिए योजना पर जितना रूपया संयाया जाना था उसका १६ प्रतिशत कृषि भौर सामुदायिक-विकास. १७ प्रतिहान सिंचाई ग्रादि पर व्यय किया गया । दितीय-योजना का मुख्य-उद्देश्य देश की 'उद्योग-सम्बन्धी' (Industrial) अवस्था को उन्नत करना है, इसलिए योजना पर किये जाने वाले व्यय का १६ प्रतिशत उद्योग तथा स्निज पर भीर २६ प्रतिशत परिवहन तथा संचार पर व्यय किये जाने का विचार है। इसका यह अभिप्राय नहीं कि प्रथम योजना से उद्योग पर व्यय नहीं किया गया, या द्वितीय में कृषि पर व्यय नहीं किया जायगा। अभिप्राय इतना ही है कि प्रथम योजना की भपेक्षा ब्रितीय में व्यय का मुख्य-बिन्द 'कृषि' की जनह 'उद्योग' हो गया। ऐसा क्यों किया गया-इसका एक कारण है। हम इसी भ्रध्याय मे पीछे कह भ्राये हैं कि अर्थोपार्जन के तीन साधन होते हैं-'प्रथम-श्रेणी' के (Primary), 'द्वितीय-श्रेणी' के (Secondary) ्था 'त्तीय-श्रेणी' के (Tertiary) । इनमे से प्रथम- श्रीणी के साधन कृषि धादि है, द्वितीय-श्रेणी के साधन उद्योग आदि है, तृतीय-श्रेणी के साधन देश के धर्भ, विविध-सेवाएँ हैं। शाधिक-उन्नति का नियम है कि देश की अधिक जन-संख्या 'प्रथम-श्रेणी' के साधनों के स्थान से 'दितीय' तया 'तुतीय-श्रेणी' के साधनों मे लगी हो । श्रभी श्रपने देश की हालत यह है कि हमारी श्रम-शक्ति का ७२'४ प्रतिशत हिस्सा कृषि में लगा हुआ है, देश की श्रम-शक्ति का १०-६ प्रतिशत हिस्सा कल-कारखानों तथा छोटे-छोटे घंघों में लगा हुआ है, ७'७ प्रतिशत न्यापार में भीर ह प्रतिशत यातायात तथा सेवा-कार्यों में लगा हुआ है। कहने का अभिप्राय यह है कि 'प्रथम-श्रेणी' के कार्यों में ... कृषि ब्रादि में ... इतनी ब्रधिक श्रम-शनित लगी हुई है कि प्रायः सारी श्रम-शनित इसी मे खप गई है।

निर्धेनता की दूर करने का यह उपाय नहीं है। होना वह काहिए कि हम कृषि-संबंधी बाधुनिक-यन्त्रों की सहायता से थोडे बादिमयों से काम लें, और इस बची हुई जन-संख्या को उद्योग के क्षेत्र में मेजें। भाष्ट्रनिक-यन्त्रों के द्वारा ग्रब से भाभी श्रम-शक्ति कृषि का उसना ही कार्य कर सकती है जितना अब ७२'४ प्रतिशत श्रम-शक्ति करती है। इस बची हुई श्रम-शक्ति को कृषि के क्षेत्र से निकाल कर उद्योग के क्षेत्र में डाल देने की प्रावश्यकता है। जिन देशों ने प्राधिक-उन्नति की है उन्होंने ऐसा ही किया है। उन देशों में कृषि में श्रम-शक्ति कम हो गई है, उद्योगों में बढ़ गई है। १८७० और १६३० के बीच में अमरीका में कृषि पर लगी हुई श्रम-शक्ति ५४ प्रतिशत से कम होकर २३ प्रतिशत रह गई, कांस में ४२ प्रतिशत से कम होकर २५ प्रतिशत रह गई, जापान में ५६ प्रतिशत से कम होकर ४१ प्रतिशत हो गई। जर्मनी में १८८० में ३६ प्रतिशत श्रम-शक्ति कृषि पर लगी हुई थी जो १६३० में २२ प्रतिशत रह गई, इञ्जलैण्ड मे १८७० में १५ प्रतिशत श्रम सक्ति कृषि पर लगी हुई थी जो १६२० में ७ प्रतिशत रह गई। इस समय धमरीका में वहाँ की बाबादी की केवल १२ प्रतिशत सस्या खेती में लगी हुई है। कहने का श्रमित्राय यह है कि कृषि मे श्रधिक शादमी खपाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य कम-से-कम शक्ति लगाकर अधिक-से-अधिक पैदावार करना है। हम अपनी 'ब्रितीय-पंच-वर्षीय-योजना' में श्रम-शक्त को उद्योग-धंधों पर लगाने का प्रयत्न करेंगे क्योंकि 'प्रथम-श्रोणी' के धर्षोपार्जन के साधनों से देश उतना समृद्ध नहीं होता जितना 'हितीय' तथा 'त्तीब'-श्रेणी के अर्थोपाजँग के साधनों से समृद्ध होता है। प्रथम तथा द्वितीय-पंच-वर्षीय-योजना में पहला भेद तो यह है।

इन दोनों योजनाओं में दूसरा मेद यह है कि जहाँ 'प्रथम-योजना' मुक्यत: 'कल्याण-राज्य' (Welfare state) को माधार बनाकर चलाई गई बी वहाँ 'द्वितीय-योजना' मुक्यतया 'समाजवादी क्षंचि के समाज' (Socialist pattern of society) को माधार बनाकर कड़ी की गई

है। 'कल्याण-राज्य' का यही ग्रथं या कि देश का कल्याण हो, श्रीक जन-संख्या गाँवों में बसती है, कृषि करती है, इसलिए गाँवों में सामुदायिक-योजनाएँ वर्ले, कृषि की उन्नित हो, नहरें बनें, सिचाई हो। श्रव जब कि हम योजना के दूसरे चरण मे प्रवेश कर रहे हैं, भौर 'कृषि' के स्थान में 'उद्योग' को सक्य बनाने लगे हैं, तब सबसे बड़ा सवाल यह पैदा हो जाता है कि उद्योगों से जो पूँ जी बढ़ेगी, धन भायगा, वह क्या कुछ-एक लोगों की पेटियों में जमा हो जायगा, या बँटेगा। इसीलिए उत्पादन का जोर उद्योग पर जाते ही यह तय करना भी आवश्यक हो गया कि हम भपने यहां पूँजीवाद को नहीं भाने देंगे। कल-कारखाने बढ़ेंगे, परन्तु इनका बढ़ना देश की 'राष्ट्रीय-भाय' को बढ़ाकर कुछ-एक व्यक्तियों की भामदनी बढ़ाना नहीं होगा, हर-एक की भामदनी बढ़ाना होगा। हम सम्पत्ति बढ़ायेगे, परन्तु साथ ही सम्पत्ति का समान वितरण भी करेंगे। इसीलिये 'द्वितीय-योजना' मे यह घोषित करना भावश्यक हो गया कि हम 'समाजवादी' समाज की रचना करेंगे।

(ग) ६ अप्रैल १६४८ का बोद्योगिक-नीति का प्रस्ताव (Industrial Policy Resolution of 6th April, 1948)—स्वराज्य-प्राप्ति के बाद ६ अप्रैल १६४८ को भारत-सरकार ने अपनी भौद्योगिक-नीति की घोषणा इस प्रस्ताव द्वारा की थी। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि सरकार यह नाहती है कि बौद्योगिक-उत्पादन लगातार होता रहे और उत्पादन का न्याय-संगत वितरण भी साथ-साथ होता रहे। इसके भतिरिक्त इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया था कि देश के भौद्योगिक-विकास में सरकार को भी पहले की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होना होगा। शस्त्रास्त्रों का निर्माण, अग्रु-शक्ति तथा रेलों के यातायात का तो सरकार के हाथ में एक-मात्र अधिकार होगा ही, साथ ही आधारभूत छः बुनियादी उद्योग भी सरकार ही चलावेगी। ये सरकारी उद्योग 'सार्वअनिक-क्षेत्र' (Public sector) के अन्तर्गंत होंगे, और इनके अलावा जो उद्योग होंगे, वे 'निजी-क्षेत्र' (Private sector) में गिने

जामेंथे। १६५५-५६ तक सरकार की यही घोषित नीति रही, परन्तु इस बीच बहत-कुछ बदल गया। इस बीच १६४६ को भारत का विधान स्वीकृत हमा जिसमें प्रत्येक नागरिक के कुछ 'बाबारभूत-बधिकार' स्वीकृत किये गये, कुछ 'प्रेरक-सिद्धान्त' स्वीकृत किये गए। इनमें कहा गया था कि राष्ट्र की भौतिक-सम्पत्ति पर अधिकार वा स्वामित्व इस प्रकार बँटा हुआ होना चाहिए जिससे किसी एक का मला न होकर सबका भला हो; राष्ट्र का आर्थिक ढाँचा इस प्रकार का नहीं होना चाहिए जिससे उत्पादन के साधन तथा सम्पत्ति एक जगह इस प्रकार केन्द्रित हो जाँय कि उससे दूसरो का नुक्सान होने लगे। इन विचारों का परिणाम यह हम्रा कि दिसम्बर १६५४ की भारतीय पालियामेंट ने 'समाजवादी ढाँचे के समाज' (Socialist pattern of society) का निर्माण अपनालक्य घोषित कर दिया। १६४६-६१ के लिये 'प्लैनिंग-कमीशन' ने जो योजना तैयार की उसमे इसी लक्ष्य को भाषार बनाया गया । इन सब परिवर्तनो का परिणाम यह हथा कि भारत सरकार को ६ अप्रैल १६४८ के अपने बौद्यीगिक-नीति के प्रस्ताव को बदलना पड़ा। परिणामस्वरूप ३० अप्रैल १९४६ को भारत-सदकार ने अपनी 'ब्रौद्योगिक-नीति' के प्रस्ताव को दूसरा रूप दिया। वह रूप क्याचा ?

(घ) ३० सप्र ल १९५६ का सौद्योगिक-नीति का प्रस्ताय—(Industrial Policy Resolution of 30th April, 1956)—६ प्रप्र ल १६४८ के प्रस्ताव में 'सार्वजनिक-क्षेत्र' की सीमा बहुत बँघी हुई खी, 'निजी-क्षेत्र' की सीमा बहुत विस्तृत थी। परन्तु जब हमारा उद्देश्य समाजवादी ढाँचा तैयार करना है, उत्पादन को कुछ-एक के हाथों में केन्द्रित न रहने देकर सब में वितरण करना है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के स्तर को ऊँचा करना है, देश में से हर व्यक्ति की निर्धनता को मिटाना है, तब यह सावश्यक हो जाता है कि सरकार भी व्यापार के क्षेत्र में उत्तर साथे, सौर हर-एक ऐसे उद्योग को कंपने हाथ में ले जिसे या तो 'निजी-क्षेत्र' के लोग

साम न होने से शुरू ही नहीं करते, या शुरू करते हैं तो उनका उस उचीन पर इतना एकाधिकार हो जाता है कि मनमाना नक्ता उठाने समते है। भारत-सरकार ने यह देखकर कि द्वितीय-पंच-वर्षीय-योजना में देश का 'उद्योगीकरण' (Industrialization) आवश्यक है, इस प्रस्ताव द्वारा यह घोषणा कर दी है कि ग्रव सरकार भी उद्योगों को धपने हाथ में सेगी। उद्योगों को तीन श्रीणयो में बाँट दिया गवा। प्रथम-श्रेणी उन उद्योगों की है जिन्हे सिर्फ़ सरकार चला सकेगी, धन्य कोई नहीं । इस श्रेणी में १७ बढ़े-बड़े उद्योग है । उदाहरणार्थ, शस्त्रास्त्र, अशु-शक्ति, लोहा, लोहे की भारी मशीनें, विजली के भारी कारखाने, कोयला, खनिज-तेल, कच्चे लोहे, मैंगनीजा, गन्धक, सोना, हीरा भ्रादि की खानें, ताँबा, जस्ता, टिन भ्रादि की खानें भ्रौर इनके सामान, हवाई जहाज, हवाई यातायात, रेलवे, जहाज बनाना, टैलीफ़ोन, बिजली पैदा करना भीर वितरण करना भादि। यह सब सरकार ही कर सकेगी। द्वितीय-श्रेणी में वे उद्योग गिनाये गए हैं जिनमे भीरे-बीरे सरकार प्रवेश करेगी । उदाहरणार्थ, मशीन के पुर्वे बनाना, खाद, रबर, एण्टीबायोटिक श्रीषधियाँ, सड़कों तथा समुद्र का यातायात श्राहि । इनकी संख्या १२ है। इनके झलावा जो बच रहेगा वह 'निजी-क्षेत्र' (Private sector) में भा जायेगा, परन्तु सरकार इस बात के लिए बाधित नहीं है कि वह किस काम को हाथ में ले भीर किस को न ले।

बड़े धंघों के साथ-साथ इस भीचोगिक-नीति के अनुसार सरकार कोटे-छोटे बन्धों को भी प्रोत्साहन देगी। क्योंकि छोटे बन्धों से बेकारी कम होती है इसलिए इन छोटे बन्धों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार इन उद्योगों को भाषिक-सहायता दे सकती है, बड़े उद्योगों के उत्पादन को इस प्रकार नियंग्यित कर सकती है, बिससे इन छोटे बन्धों पर ऐसा असर न पड़े बिससे ये पनप ही न सकें, बड़े बन्धों की बस्तुओं की अपेक्षा छोटे बन्धों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार टैक्स की कमी भी कर सकती है। परन्तु फिर भी सरकार की नीति यही रहेगी कि खुले बाज़ार में 'प्रतिस्पर्धा' के सिद्धान्त के अनुसार छोटे उद्योगों द्वारा पैदा किया हुआ माल बाजार में अपने बूते पर टिक सके, हर वक्त उसे सरकारी सहायता की ही जारूरत न पडती रहे।

इस प्रकार हमने देखा कि निर्धेवता क्या है, भौर खासकर भारत-सरकार इस प्रश्न को 'पंच-वर्षीय-योजनाओ' तथा भ्रपनी 'भ्रौद्योगिक-नीति' द्वारा किस प्रकार हल कर रही है।

#### प्रश्न

- भारत की प्रति-व्यक्ति ग्राय क्या है?
- २. भारत की निर्धनता के क्या कारल है?
- भारत की निर्वनता के निवारण के लिए भारत-सरकार जो उपाय कर रही है उनका वर्णन कीजिये।
- ४. प्रथम तथा द्वितीय पंच-वर्षीय-योजना में आधार-भूत भेद क्या है?
- प्र. ६ ग्रप्न न १६४ म तथा ३० ग्रप्न न १६५६ के नारत-सरकार की ग्रीबोगिक-नीति के प्रस्ताव क्या है भौर इन दोनों में ग्रावार-भूत भेद क्या है ?

# E

## भारत में श्रायोजन

(PLANNING IN INDIA)

## १. भ्रायोजन की भ्रावश्यकता

किसी काम को करने के दो तरीके हैं। एक तो जैसे-तैसे घट-सट उसे करते जाना। जो चीज सामने आई उसे करने लगना, करते-करते दूसरी सामने आगई, तो पहली को छोडकर दूसरी पर जुट जाना। यह रास्ता काम को बेतरतीबी से करने का है। इसमें सब काम अधूरे रह जाते हैं, जो पूरे भी होते हैं, वे साल की जगह पाँच साल ले जाते हैं। दूसरा तरीका हर काम को तरतीब से करने का है। जो काम करने हैं उनमे से सब से ज्यादा जरूरी कौन-सा है, उसे कितने समय में पूरा करना है, क्या-क्या साधन जुटाने हैं—इन सब पर विचार करके किसी तरतीब से, किसी योजना से जब काम किया जाता है, तब काम ढग से पूरे हो जाते हैं।

जिस युग में से हम निकल कर चुके हैं उसमे लोगो का योजना की तरफ तो ध्यान था, परन्तु योजना होना-न-होना बराबर था। इसका कारण यह था कि योजना बनाना तथा उसे चलाना समाज के हाथ में न होकर व्यक्ति के हाथ में था। यह पूँजीवाद का युग था, इसमें पूँजीपित ही निक्चय करता था कि क्या काम होना चाहिये, क्या नही

होना चाहिये, उसी के हाथ में सारी शक्ति केन्द्रित थी। क्योंकि जो काम होना था, पूँजी के बिना तो वह हो नहीं सकता था, इसलिये जिसमें पूँजीपति को अपनी पूँजी बढ़ती दीखती थी उसी में वह हाथ लगाता था, जिसमें पूँजी बढ़ती नहीं दीखती थी, उसमें समाज का कितना ही भला क्यों न हो, पूँजीपति उघर देखता भी न था। पूँजीवाद तथा व्यक्तिवाद साथ-साथ रहने वाले भाई-बहन हैं, इसलिए पूँजी का विनियोग समाज के भलें के लिये न होकर व्यक्ति के भले के लिये होता था। व्यक्ति—अर्थात् पूँजीपति ऐसे कामों में भी पूँजी लगाता था जिसमें समाज का कल्याण तो क्या, समाज का सरासर नुक्तान होता था। उदाहरणार्थ, चीन में अफ़ीम का व्यापार करने के लिए अप्रेज व्यापारियों की करोड़ो रूपया पूँजी लगी रहती थी। वेश्याम्रों का व्यापार करने के लिए अप्रेज व्यापार करने के लिये, शराब के कारखाने खोलने के लिये लाखो, करोड़ो रूपया पूँजीवाद तथा व्यक्तिवाद के युग में ही सभव था।

माज युग ने पलटा खाया है। घाज यह समभा जाने लगा है कि योजना का कार्य व्यक्ति के हाथ में न होकर समाज के हाथ में होना चाहिए, पूँजीपित के हाथ में न होकर राष्ट्र के हाथ में होना चाहिये। व्यक्ति व्यक्ति के कल्याण की योजना तो बना सकता है, भपने भले की बात सोच सकता है, समाज के भले की नहीं सोच सकता। समाज तथा राष्ट्र ही ऐसी योजनाएँ बना सकते हैं जिनमें बेशक पैंसे का नुक्सान हो, परन्तु समाज का कल्याण हो। समाज की शिक्षा, स्वास्थ्य-रक्षा, उत्तम-भोजन, गृह-व्यवस्था आदि पर पूँजीपित तो तभी तक पैसा खर्च करेगा जहाँ तक उसे इनमें भ्रपना निजी लाभ दिखलाई देगा, उससे भागे वह एक कौडी खर्च नहीं करेगा, परन्तु समाज तथा राष्ट्र तो इन मदाँ पर खर्च-ही-खर्च क्यो न होता हो, क्योंकि इन पर खर्च करने से समाज का भला होता है, इसलिये वे इन दिशाओं में जी खोल कर खर्च करते हैं। यही कारण है कि साज जो युग भा रहा है, उसमें योजना का कार्य व्यक्ति प्रथित् पूँजीपति के हाथ से समाज अर्थात् राष्ट्र के हाथ में भाता जा रहा है।

#### २. ग्रन्य देशों में ग्रायोजन

धाजकल जो देश उन्नित करना चाहते हैं, वे कोई-न-कोई योजना बनाकर उसके धनुसार ४-५ साल का कार्य-कम बनाकर चलते हैं। इस दिशा में रूस ने १६२५ में पहले-पहल पंच-वर्षीय-योजना बनाकर कार्य शुरू किया और उसके बाद धनेक पाँच-पाँच बरस की योजनाएँ बनाई। रूस की गिनती पिछडे हुए देशों में की जाती थी, परन्तु धाज इन्ही योजनाओं के परिणाम-स्वरूप वह समरीका से टक्कर से रहा है।

निम्न ग्रांकडों से स्पष्ट हो जायगा कि योजना बनाकर चलने वाले देश उन देशों से कितनी अधिक तरक्की थोड़े ही समय में कर लेते हैं जिनमें कोई योजना बनाकर कार्य नहीं किया जा रहा। निम्न तुलना से स्पष्ट हैं कि योजना बनाकर चलने वाले रूस आदि में बिना योजना के चलने वाले अमरीका आदि से राष्ट्रीय-आय में उतने ही समय में बहुत श्रिषक वृद्धि हुई।

#### योजना बनाकर चलने वाले देश

देश		समय	राष्ट्रीय-ग्राय में वृद्धि	
₹.	रूस	१६२= से १६४३	पहले १५ फिर १६%	
₹.	पोलैंड	१९४४ से १९५३	१४.५ प्रतिशत	
₹.	चौकोस्लोवाकिया	१६४= से १६५३	१२ प्रतिशत	
٧.	हंगरी	१६४२ से १६४३	१२ प्रतिशत	
<b>X</b> .	बल्गारिया	१९४२ से १९४३	१६ प्रतिशत	
₹.	भारत	१६५१ से १६५६	१८ प्रतिशत	

#### विना योजना के चलने वाले देश

₹.	ग्रमरीका	१८६६ से १६५०	३.२ से ३ प्रतिशत
₹.	कनाडा	१८६० से १६२६	२.६ प्रविशत
₹.	स्विट्जरलैंड	१८६० से १६२६	२.७ प्रतिशत
٧,	<b>ग्रॉ</b> स्ट्रेलिया	१६०१ से १६४=	२.५ प्रतिशत

ऊपर जो बाँकड़े दिये गये हैं उनसे स्पष्ट है कि योजना बनाकर बलने वाले देशों की बिना योजना के चलने वाले देशों की अपेक्षा उन्नित की रफ़्तार बहुत तेज होती है। यह सब सोच-विचार कर ही भारत ने स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद योजना के मार्ग को अपनाया है।

#### ३. भारत में ग्रायोजन

१५ भगस्त १६४७ को स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत ने भ्रपनी सरकार बनाई। देश की श्राधिक तथा सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिये भारत-सरकार ने एक प्रस्ताव द्वारा मार्च १६५० में 'योजना-घायोग' (Planning Commission) का सगठन किया । इस प्रायोग ने घप्रैल १६५१ से मार्च १६५६ तक के पांच वर्षों के लिये भारत के चतुर्मु ल विकास के लिये एक योजना बनाई। इस म्रायोग की सिफ़ारिशो पर केन्द्र की सरकार तथा प्रान्त की सरकारें विचार-विनिमय कर सकें. क्या बढाना है, क्या घटाना है-इस सब पर विचार हो सके, इस उद्देश्य से ग्रगस्त १९५२ मे 'राष्ट्रीय-विकास-परिषद' (National Development Council) की स्थापना की गई जिसमें भारत के प्रधान-मन्त्री तथा राज्य-सरकारो के सभी मुख्य-मन्त्री सदस्य-रूप मे भाग लेते हैं। 'योजना-ग्रायोग' का सगठन, उसकी नीति का निर्धारण तो भारत-सरकार ने ग्रपने मार्च १६५० के प्रस्ताव के धनुसार कर दिया, ग्रब भारत-सरकार का प्रतिनिधित्व यह 'राष्ट्रीय-विस्तार-परिषद्' करती है, भीर समय-समय पर 'योजना-आयोग' के कार्य-क्रम पर यही परिषद विचार करती है। 'प्रथम-पंच-वर्षीय-योजना' जब समाप्त हो गई, तब इस 'राष्ट्रीय-विकास-परिषद' ने ही प्रथम-योजना के परिणामो पर विचार-विनिमय किया, भीर योजना-भ्रायोग को 'द्वितीय-पँच-वर्षीय-योजना' के मसविदे के बनाने का भ्रादेश दिया।

'प्रथम-पैन-वर्षीय-योजना' में क्या-क्या हुन्रा, 'द्वितीय-पैन-वर्षीय-योजना' में क्या-क्या होगा--इसका सक्षिप्त-सा परिचय यहाँ देना ग्रमगत न होगा।

(क) प्रथम-पँच-वर्षीय-योजना— मारत का योजनाओं द्वारा जो पुनर्निर्माण हो रहा है उस सिलसले में १६५५ में हम पहली पँच-वर्षीय योजना को समाप्त कर चुके हैं, उसके बाद १६५६ से द्वितीय-पँच-वर्षीय योजना प्रारम्भ हुई है। इन दोनो योजनाओं में सामाजिक-कल्याण की मादना को प्रधान रखा गया है।

पहली पँच-वर्षीय योजना का म्राधार 'कल्याण-राज्य' (Welfare state) स्थापित करना था। 'India-1959' के म्रनुसार प्रपने देश की ३६६६ करोड जनता में से २६ ५० करोड गाँवो में बसती है। ये २६ ५० करोड देश की सारी जन-संख्या का ५२७ प्रतिशत है। ये ५२.७ प्रतिशत ध्यक्ति ५ लाख गाँवो मे रहते हैं जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। इसलिए 'कल्याण-राज्य' का यही मर्थ हो सकता था कि ऐसी योजना बनाई जाय जिससे गाँव में रहने वाली जनता को भीर कृषि का सुधार हो। इन्ही भावनाभ्रो को सामने रखकर १६५१-५६ के लिए जो प्रथम योजना बनाई गई. उस पर निम्न व्यय किया गया.—

१. कृषि श्रीर सामुदायिक विकास २७२ करोड़—१६ प्रतिशत २ सिंचाई श्रीर बाढों का नियत्रण ३६५ करोड़—१७ प्रतिशत ३६५ करोड़—१७ प्रतिशत ३६६ करोड़—११ प्रतिशत ४ उद्योग श्रीर खनिज १७६ करोड़— ७ प्रतिशत ५ परिवहन श्रीर संचार ५५६ करोड़—२४ प्रतिशत ५ समाज-सेवा, मकान श्रीर पुनर्वास ५४७ करोड़—३२ प्रतिशत ७ विविष ४१ करोड़— २ प्रतिशत

२,३४६ करोड---१०० प्रतिशत

योग

इस प्रकार कृषि तथा सामुदायिक-विकास पर ३७२ करोड रुपया खर्चे किया गया जो सम्पूर्ण त्र्यय का १६ प्रतिशत था। 'सामुदायिक-विकास' (Community development) के धन्तर्गत 'सामदायिक-योजना' (Community project) की स्कीन को प्रारम्भ किया गया जो 'सामाजिक-कल्याण' के लिए श्रावश्यक थी। शक्तबर १९५२ में मह प्रोग्राम शुरू हुआ । प्रथम-पैच-वर्षीय योजना समाप्त होने तक १२०० 'विकास-क्षेत्रो' (Development blocks) में काम किया गया जिनमें से ६०० 'सामुदायिक-योजना-क्षेत्र' (Community project) के अन्तर्गत बे भीर ६०० 'राष्ट्रीय-प्रसार-सेवा-क्षेत्र' (National Extension Service) के श्रन्तर्गत थे। 'सामुदायिक-योजना-क्षेत्र' (Community Project Block) या 'राष्ट्रीय-प्रसार-सेवा-क्षेत्र' (National Extension Service Block) में भेद इतना ही है कि इनमें से पहली शुरू-शुरू में चली थी. दूसरी बाद में चली, पहली ज्यादा गहराई में जाती है, दूसरी उतनी गहराई मे नहीं जाती, पहली पर ज्यादा रुपवा खर्च होता है, दूसरी पर कुछ कम खर्चे होता है--वैसे कार्य-क्षेत्र दोनों का एक-सा है। ये दोनों ६०-७० हजार की बाबादी के क्षेत्र मे जिसमे, लगभग १०० गाँव हों, १५० से १७० वर्ग-मील भूमि हो, चालु किये जाते हैं। इन क्षेत्रों में कृषि, परिवहन, सडकें, शिक्षा, स्वास्त्र्य, बेरोजगारी, गृह-समस्या तथा समाज-कल्याण के सब कार्य जनता के सहयोग तथा सरकार की सहायता से किये जाते है।

उक्त कार्य मुख्य तौर पर गाँव बालो की 'भाधिक-स्थिति' सुधारने के लिए किये गए थे। उनकी 'सामाजिक तथा सास्कृतिक स्थिति' सुधारने के लिए प्रथम-पेंच-वर्षीय योजना में ५४७ करोड़ रुपया समाज-सेवा, मकान तथा पुनर्वास के लिए भ्रमण रखा गया था जिसमे ४ करोड रुपया समाज-कल्याण के लिए था। १२ भ्रगस्त १६५३ को सरकार ने एक 'केन्द्रीय-समाज-कल्याण बोर्ड (Central Social Welfare Board) बना दिया जिसकी भ्रष्यक्षा श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख हुई। जैसे 'सामु-

दायिक-विकास' योजना का काम गाँव में शिक्षा, स्वास्थ्य, बैरोजगारी, समाज-कल्याण बार्द कार्य करना था, वैसे 'केन्द्रीय समाज-कल्याण बोर्ड' का काम भी समाज-कल्याण का कार्य करना ही है, परन्तु इसका कार्य-क्षेत्र प्रधिकतर स्त्रियों, बच्चो, प्रपंगो, धनाथो, विधवाधो धादि की समस्याओं को हल करना है। इस उद्देष्य से 'केन्द्रीय समाज-कल्याण बोर्ड' की देख-रेख में प्रान्तो में 'राज्य समाज-कल्याण सलाहकार-बोर्ड' (State Social Welfare Advisory Boards) बनाये गए हैं और इन बोर्डों के धन्तर्गत 'समाज-कल्याण-विस्तार-सेवा' (Welfare Extension Service) बालू की गई है। 'समाज-कल्याण-विस्तार-सेवा' तथा 'राष्ट्रीय-प्रसार-सेवा-क्षेत्र' में कही-कही दोनो का कार्य-क्षेत्र एक जा पडता है और दोहरा काम होने लगता है। इसे बचाने के लिए श्रव १६५७ में 'सामुदायिक-योजना-क्षेत्रों' के समाज-सेवा के कार्य-प्रधात् स्त्रियो, बच्चो, धपगो, धनाथो, विधवाधो धादि की समस्या का कार्य 'केन्द्रीय समाज-कल्याण बोर्ड' (Central Social Welfare Board) द्वारा ही होगा।

(ल) द्वितीय-पंच-वर्षीय-योजना—प्रथम-पंच-वर्षीय-योजना का भाषार 'कल्याण-राज्य' (Welfare state) की स्थापना करना था, तो द्वितीय-पंच-वर्षीय-योजना का भाषार 'समाजवादी-समाज' (Socialistic society) की स्थापना करना है। प्रथम-पंच-वर्षीय-योजना पर २,३५६ करोड रुपया व्यय किया गया, तो द्वितीय पर ४,८०० करोड रुपया व्यय किया गया, तो द्वितीय पर ४,८०० करोड रुपया व्यय किया जा रहा है। प्रथम १६५१ से १६५६ तक चालू रही, द्वितीय १६५६ से १६६१ तक चालू रहेगी। द्वितीय-पंच-वर्षीय-योजना में प्रथम की अपेक्षा क्यय मे जो न्यूनाधिकता होगी वह निम्न तालिका से स्पष्ट हो जायगी—

योजना की मर्वे	पहली-योग	ना	दूसरी-य	ोजना
१. कृषि तथा सामुदायिक				
विकास	३७२ करोंड़ १	६ प्रतिशत	ና ሂ६ሂ ጭ ፡	१२ प्रतिशत
२. सिंचाई ग्रीर बाढों का				
नियन्त्रण	₹8€ "	<b>१</b> ७ ,,	<b>ሄሂ</b> ፍ "	٤,,
३. बिजली	२६६ ॥	۱۱ ۶۶	880 n	٤ ,,
४. उद्योग ग्रौर खनिज	,, 309	· ,,	<b>८६१</b> "	₹€ "
५. परिवाहन ग्रौर संचार	ሂሂዲ "	२४ ,, १	(,₹58 ,,	?8 ,,
६. समाज-सेवा, मकान				
स्रौर पुनर्वास	xx0 "	२३ "	ERE "	२० ,,
७. विविध			११६ "	
योग	२,३४६	१००	8,500	१००

प्रथम पँच-वर्षीय-योजना मे देश के एक-चौषाई हिस्से में 'सामुदायिक योजनाएँ' तथा 'राष्ट्रीय-प्रसार-सेवा-क्षेत्र' चल रहे थे । द्वितीय योजना मे यह लक्ष्य रखा गया है कि समूचे देश में इन योजनाओं का जाल विछा दिया जाय, और १६६१ के अन्त तक देश का कोई ग्रामीण-भाग ऐसा न रहे जिसे इन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ न पहुँचे । पिछली योजना में जहाँ 'सामुदायिक-विकास' पर ३७२ करोड़ रुपया व्यय हुन्ना था, वहाँ इस योजना के अनुसार इस विकास पर ५६५ करोड़ रुपया व्यय होगा।

## ४. सामुदायिक-विकास-योजनाएँ (Community Development Projects)

जब सरकार देख लेती है कि किसी काम को जनता ने करना शुरू कर दिया है, तब समय बीतने तथा उस कार्य की उपयोगिता सिद्ध हो जाने पर सरकार भी उसे भपने हाथ में लेने लगती है। ग्रामों के पुनर्निर्माण का कार्य पहले-पहल जनता की तरफ से ही शुरू हुआ था।

इस कार्य की भावश्यकता भीर सफलता को देख कर सरकार ने भी इस काम में हाथ डाला। भगर सरकार का पहले का-सा भं भेजी दर्रा ही रहता, तो शायद इस कार्य का श्रीगरोश न होता, परन्तु इस बीच १६३७ मे काग्रेसी सरकार सत्तारूढ हो गई थी। इन लोगों ने भिन्न-भिन्न प्रान्तों मे ग्रामों के पुननिर्माण के कार्य को शुरू कर दिया। भिन्न-भिन्न प्रान्तों मे निम्न कार्य हुआ—

- (क) बिहार बिहार मे १६३ न मे 'ग्राम-विकास-विभाग'
  (Rural Development Department) लोला गया । इस विभाग के स्थीन भ्रादर्श-केन्द्र स्थापित किये गए। एक-एक केन्द्र में २० से ३० गांव थे। इस विभाग का उद्देश्य छोटे-छोटे गृहोद्योगो को जारी करना था। उदाहरणार्थ, गांव में लिइड्यां लगाना, तेल की घाणी चलवाना, भीषिधयाँ वितरण करना, ग्राम के स्वास्थ्य की देख-भाल, ग्राम की पँचायत का सगठन भी यही विभाग करता था। इस विभाग की तरफ़ से ग्राम में प्रौढ-शिक्षा के केन्द्र भी लोले जाते थे।
- (स) बन्बई—बन्बई मे भी 'ग्राम-पुनर्निर्माण-विभाग' (Rural (Reconstruction Department) इन्ही दिनो खोला गया। इस विभाग को ग्राम-पुनर्निर्माण के कार्य मे सहायता देने के लिए प्रान्तीय-स्तर पर 'ग्राम-विकास-प्रान्तीय-पटल' (Provincial Board of Rural Development की रचना की गई। इस पटल में कृषि-विशेषज्ञ, पशु-विशेषज्ञ, गृहोद्योग विशेषज्ञ रखे गए ताकि ग्रामो के हर पहलू के विकास मे वे ग्रपना परामर्श दे सकें।
- (ग) बंगाल—बंगाल में ग्राम-पुर्नीनर्माण के डाइरेक्टर के ग्रधीन 'ग्राम-विकास-विभाग' खोला गया जिसका काम कृषि के उन्नत उपायों का प्रचार, ग्रामवासियों की जीवन की परिस्थितियों का सुन्नार, उनके भोजन का क्तर उच्च करना, उनके लिए ग्रामोद-प्रमोद के सामन जुटाना तथा गाँवों में ग्रामोद्योगों को प्रोत्साहन देना था। इस काम के लिए प्रान्त भर में भिन्न-भिन्न सोसाइटियाँ बनाई गई जिन्होंने जंगल

काटे, सडकों को सुधारा, नालिया बनाईं, मलेरिया भाकान्त स्थानों में कुनीन बांटी, खेती के लिए जमीन काटी, कूए खुदवाये और उत्तम बीज का ग्रामवासियो में वितरण किया।

(घ) उत्तर-प्रदेश — उत्तर-प्रदेश में 'प्रान्तीय ग्राम-विकास पटल' (Provincial Rural Development Board) की कांग्रेसी-सरकार ने स्थापना की। इस प्रान्तीय-पटल के ग्रंघीन जिलों में 'जिला ग्राम-विकास संघ' स्थापित किए। जिले में भी १५-१५ गाँवों की इकाइयाँ बनाई गई जिनमें विकास के कार्यों को प्रारम्भ किया गया। १६४०-४१ में १५-१५ गाँवों की उत्तर-प्रदेश में ७६५ इकाइयाँ काम कर रहीं थी। इन सब में सुधार-कार्य भिन्न-भिन्न प्रकार के संगठनों से चलाया गया जिनमे पँचायतो का भी विशेष भाग रहा। गाँवों में उत्तम बीज बाँटना, गाय-बैल की नस्ल सुधारना, ग्रामोद्योग जारी करना, स्वास्थ्य तथा शिक्षा की समस्याओं को हल करना इन सगठनों का काम रहा। अनेक गाँवों में पानी की समस्या का हल किया गया, गाँव-घर बनाये गये।

इसी प्रकार श्रसम, मद्रास, सी० पी०, कोचिन, काश्मीर, मैसूर, बड़ौदा, हैदराबाद—सब जगह ग्राम-पुनर्निर्माण की योजनाएँ १६३७ के बाद काग्रेस-मन्त्री-मण्डल बनने पर चलाई गईं भौर सब जगह कृषि-सुधार, पशु-सुधार, बीज-सुधार, पँचायत-निर्माण भ्रादि कार्यं किये गए। भ्राचकल जो 'सामूहिक-योजनाएं' भीर 'राष्ट्रीय-विस्तार-सेग्रा-खण्ड' चल रहे हैं उनका बीजारोपण इसी समय हो गवा था।

इन 'सामूहिक-योजनाओं' तथा 'राष्ट्रीय-विस्तार-सेवा-खण्डों' पर विशेष तौर पर ष्यान स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद गया। ध्रपने देश की सरकार का ष्यान विशेष तौर पर ग्रामो के संगठन की तरफ़ गया: इसी दृष्टि से पँचायतों का निर्माण हुग्ना, इसी दृष्टि से 'सामूहिक-योजनाओं' के बीज को वृक्ष का रूप दिया गया। ग्रामों का उद्घार करने के लिए बहुत गहरा काम करना होगा। एक-एक गाँव को पकड़ कर उसकी सब समस्याम्रो को सुलभाना होगा। गाँव की समस्यायें है—कृषि, पशु, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रौढ-शिक्षा, सहकारिता, मकान, सडक, पानी—यह सब-कुछ। जब तक हर समस्या का समाधान नही होता, तब तक गाँव का पुनर्निर्माण भी नही होता। इसी लक्ष्य को सामने रखकर स्वतन्त्र मारत की सरकार ने 'सामुदायिक योजनामों' (Community Projects) की रूप-रेखा तैयार की ग्रौर १९५२ में महात्मा गाभी के जन्म दिन—र मक्तूबर—को उसे जारी किया।

## ५. सामुदायिक-योजनाम्रों की रूप-रेखा

२ म्रक्तूबर १९५२ को 'सामुदायिक-योजनास्रो का जो कार्य-क्रम जारी हुमा उसको रूप-रेखा निम्न थी:—

- (क) 'ख्रय-गामी-योजना' (Pilot Project) के परीक्षण—योजना चानू की जाय इससे पहले उस प्रकार के परीक्षण कर लेना आवश्यक था। इस प्रकार के परीक्षण भिन्न-भिन्न प्रान्तों में जारी किये गए। इनमे उत्तर-प्रदेश की १६४८ मे प्रारम्भ की गई 'इटावा-अग्रगामी-योजना' (Etawah Pilot Project) प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त मद्रास की 'फिरका-अग्रगामी-योजना', ट्रावन्कोर-कोचीन की 'मार्तडम-अग्रगामी योजनाए' भी प्रसिद्ध है।
- (क्क) 'सामुदायिक-योजनाएँ' (Community Projects)—उक्त प्रग्र-गामी योजनाभी से प्रोत्साहित होकर बड़े पैमाने पर ग्राम-पुनर्निर्माण की योजनाभों का प्रारम्भ किया गया। शुरू-शुरू मे प्लानिंग कमीशन ने ५५ 'सामुदायिक-योजनाभों' की स्वीकृति दी। इन ५५ 'सामुदायिक-योजनाभों' के लिये ४० करोड रूपये की स्वीकृति दी गई। इनको सफल बनाने में भ्रमरीका ने ४ करोड की सहायता दी। भ्रमरीकी सहायता उपकरणों के रूप में दी गई थी। प्रथम-पँज-वर्षीय-योजना मे प्लैनिंग कमीशन ने पहले पाँच वर्षों के लिये १०२ करोड रुपया बजट में रखा था। इसका उद्देश्य यह था कि ५५ योजनाभों पर ४० करोड खर्च

हो जाने पर इसी प्रकार की अन्य योजनाएँ भी इस १०२ करोड़ रुपए से ही जारी की जायें। एक 'सामुदायिक-योजना' (Community Project) २ लाख व्यक्तियों के क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करती थी। इसमें ३०० गाँव सम्मिलित किए गए थे। प्रत्येक 'सामुदायिक-योजना' (Community Project) पर ६५ लाख खर्च किया गया। इन ३०० गाँवों की कृषि, पशु, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की सब समस्याओं को हल किये जाने का प्रोग्राम था। जैसा ऊपर कहा गया, ५५ 'सामूहिक-योजनाओं' का यह कार्यक्रम २ अक्तूबर १९५२ को जारी किया गया।

(ग) 'सामुदायिक विकास-सच्ड' तथा 'राष्ट्रीय विस्तार-सेवा-सण्ड' (Community development Blocks and National Extension Service Blocks)--- कपर जिन 'सामुदायिक-योजनाम्नो' का हमने वर्णन किया वे २ अक्तूबर १६५२ में शुरू की गई । इनके ठीक एक साल बाद अक्तूबर १९५३ मे उनसे कुछ छोटी योजनाम्रो का प्रारम्भ किया गया । इनका नाम था 'सामुदायिक विकास-खण्ड' (Community development Blocks & National Extension Service Blocks) 1 इन दोनो लण्डो मे भेद सिर्फ इतना या कि 'राष्ट्रीय-विस्तार-सेवा-खड' में कार्य-कम उतना गहरा नही था जितना 'सामुदायिक विकास-खण्ड' में था, वैसे दोनों का क्षेत्र १०० गाँव, ६० से ७० हजार की माबादी तथा १४० से १७० वर्गमील क्षेत्र था। 'सामुदायिक-योजनाम्रों' (Community Projects) पर तो अमरीका से ४ करोड की सहायता ली गई थी, इन 'सामुदायिक-विकास-खण्डों' के लिये किसी से किसी प्रकार की सहायता नहीं ली गई। ध्यान रखने की बात यह है कि 'राष्टीय विस्तार-सेवा-खड' का काम जब गहराई से चल पड़ता है, तब वही 'सामुदायिक विकास-खंड' के रूप में परिणत हो जाता है। प्रथम-पँच-वर्षीय-योजना तक एक 'सामुदायिक-योजना' (Community project) में तीन 'सामदायिक-खण्ड' (Community development

blocks) भे, भौर इन 'विकास-खण्डो' की योजना १९५३ में शुरू की गई थी। अब द्वितीय पँच-वर्षीय-योजना मे योजना को नए सिरे से ढाला गया है। बडे पैमाने की ३०० गाँवों की 'सामुदायिक-योजनाम्रो' (Community projects) को छोड दिया गया है, श्रीर उनके स्थान में १०० गांवो के 'विकास-खण्ड' (Development blocks) बनाए गए है। इन 'विकास-खण्डो' में पहले 'राष्ट्रीय-सेवा-खण्ड' (N E. S. Blocks) के रूप में तीन साल तक काम होता है भीर उस पर आ। लाख व्यय होता है, जब वह जड पकड जाता है तब उसे 'सामुदायिक विकास-खण्ड' (Community development block) मे बदल दिया जाता है जो फिर तीन साल तक चलता है भौर उस पर भी ७॥ लाख व्यय होता है और इस प्रकार छः साल काम हो चुकने के बाद उस काम को ग्रागे चलाने के लिये कुछ स्टाफ छोड दिया जाता है। इस दृष्टि से 'राष्ट्रीय विस्तार-सेवा-खण्ड' तथा 'सामुदायिक-विकास-खण्ड' एक ही योजना के दो पहलु बना दिए गए हैं। प्रथम पँच-वर्षीय-योजना में देश का एक चौथाई हिस्सा इन योजनाओं के अन्तर्गत या गया, श्रब द्वितीय पँच-वर्षीय-योजना में सारा देश इन विकास-योजनाम्रो के म्रन्तर्गत म्रा जायगा । द्वितीय-पैंच-वर्षीय-योजना में सारे देश मे ३८०० 'राष्ट्रीय विस्तार-सेवा-खण्ड' (N.E.S. blocks) जारी किए जा रहे हैं जिनमे से जड पकड जाने पर ११२० को 'सामुदायिक विकास-खण्डो' (Community development blocks) मे परिवर्तित कर दिया जायगा भीर जो-जो 'राष्ट्रीय विस्तार-सेवा-खण्ड' गहरा होता जायगा, वह 'सामुदायिक विकास-खण्ड' के रूप मे बदलता जायगा।

'राष्ट्रीय-विस्तार-सेवा-खण्ड' (N. E. S. block) तथा 'सामुदायिक-विकास-खण्ड' (Community development block या C D. Block) मे जो थोडा-बहुन ग्रन्तर है वह उनमें काम करने वाले स्टाफ़ से स्पष्ट हो जायगा। 'राष्ट्रीय विस्तार-सेवा-खण्ड' में निम्न स्टाफ रहेगा—१ 'विकास-भिषकारी'; ३ 'विस्तार-ग्रिषकारी' (इन तीनो मे से एक कृषि का,

एक पशुत्रों का तथा एक सहकारिता एवं पैंचायतों का विशेषज्ञ होगा); सामाजिक-शिक्षा के सगठन-कर्ता (इन दो में से एक स्त्री तथा एक पुरुष होगा), १ ग्रोवरसीयर (इसे स्वास्थ्य-सेवा का ज्ञान होना चाहिए) ; १० 'बहुघधी ग्राम-सेवक', १ गणक तथा भण्डारी; १ क्लर्क श्रीर ३ नीकर । 'सामुदायिक विकास-खण्ड' में उक्त स्टाफ़ तो रहेगा ही, परन्त् इसके घलावा निम्न स्टाफ़ ब्रितिरक्त रहेगा- बहुधन्त्री ग्राम-सेवक' १० की जगह १२ हो जायेंगे। इनके ग्रलाबा ४ पशुग्रों के काम के सहायक; १ डाक्टर; १ कम्पाउण्डर, १ लेडी हेल्य विशिटर; ४ दाईयाँ; १ स्वास्थ्य-शिक्षक; २ मंगी-यं ग्रौर रहेंगे। सामाजिक-शिक्षा के संगठनकर्ताम्रो के ऊपर १ मुख्य समाज-सेवा संगठनकर्ता भी 'सामुदायिक विकास-खण्ड' मे रखा जायगा । परन्तु वह तीन 'सामुदायिक विकास-खण्डो' के लिए एक होगा । इससे स्पष्ट है कि 'राष्ट्रीय विस्तार-सेवा-खण्ड' की श्रपेक्षा 'सामुदायिक विकास-खण्ड' में बहुत ज्यादा भेद तो न होगा, परन्तु स्वास्थ्य की दिशा मे 'सामुदायिक विकास-खण्ड' में बहुत ज्यादा ध्यान दिया जायगा। भोर-समिति की ग्रल्पकालीन स्वास्थ्य योजना को 'सामुदायिक विकास-खण्डो' मे स्थान दिया गया है । कृषि. पशु, सहकारिता, पचायत, शिक्षा, मनोरजन मादि सब क्षेत्रो मे इन विकास-खण्डो मे घ्यान दिया जायगा । द्वितीय पैंच-वर्षीय-योजना मे १६५६ से १६६१ तक ६६६ नवीन 'राष्ट्रीय विस्तार-सेवा-खण्डों' की स्वीकृति दी जा चुकी है।

(घ) 'बहुषंधी ग्राम-सेवक' (Multi-purpose village-level workers)—जनत दोनों खण्डों में १०० गाँव होते हैं, इन सौ गाँव की समस्याओं को कैसे हल किया जाय है ऊपर के सारे काम का संचालन तो किसी एक ही स्थान से हो सकेगा, और विकास-अधिकारी उसी एक स्थान पर रह सकेगा, फिर इन १०० गाँवों के साथ सपर्क कैसे स्थापित किया जायगा ? इस समस्या को हल करने के लिए ३ से ५ हजार के

क्षेत्र के १० गाँवो के लिये एक-एक 'बहुघन्धी ग्राम-सेवक' (Multi-purpose village-level worker) रखा गया है। एक 'विकास-खण्ड' में क्यों कि १०० गाँव होते हैं इसलिए एक खण्ड में १० ग्राम-सेवक 'रखने की व्यवस्था की गई है। इनका काम १० गाँवों के लोगों से सम्पर्क स्थापित करना, उनकी समस्याओं को समभना, इन समस्याओं को 'विकास-खण्ड' के ग्राधकारियों के पास लाना ग्रीर हल समभकर गाँव के लोगों तक पहुँचाना होगा। ये ग्राम-सेवक इस सारी योजना की जान है। इन ग्राम-सेवकों को बाकायटा प्रशिक्षण दिया जाता है ग्रीर इनका ग्राम-वासियों की कृषि, पशु, लेन-देन कर्ज, शिक्षा, चिकित्सा ग्रादि हर समस्या से जानकारी रखना ग्रावश्यक है।

प्रथम पँच-वर्षीय-योजना के अन्त तक भारत की ग्रामीण जनता का एक-वौद्याई हिस्सा या तो 'सामुदायिक विकास-खण्डो' (Community Development Blocks) या 'राष्ट्रीय विस्तार-सेवा-खण्डो' (National Extension Service Blocks) के अन्तर्गत आ चुका था। प्रथम पँच-वर्षीय-योजना काल मे कुल १२०० 'खण्ड' (Blocks) कन चुके थे जिनमे से ७०० 'सामुदायिक-विकास-खण्ड' तथा ५०० 'राष्ट्रीय-विस्तार-सेवा-खण्ड थे। इन पर ५२.४ करोड रुपया व्यय हुमा। द्वितीय पँच-वर्षीय-योजना काल में १६६०-६१ तक भारत का सम्पूर्ण ग्रामीण प्रदेश इन विकास खण्डो मे ग्रा जायगा जिनमें से ४० प्रतिशत विकास-क्षेत्र 'सामुदायिक-विकास-खण्ड' (Community Development Blocks) का रूप धारण कर लेगे। द्वितीय-योजना मे इस सम्पूर्ण विकास-कार्य के लिए २०० करोड़ रुपया रखा गया है।

१६५२ से १६५८ तक 'सामुदायिक-विकास-खण्ड' (Community Development Blocks) तथा 'राष्ट्रीय-विस्तार-सेवा-खण्ड' (National Extension Service Blocks) का जो कार्य जलता रहा है उसकी रूप-रेखा निभ्न तालिका से स्पष्ट हो जाती है:—

विकास खण्ड	स्वीकृत खड	जारी किए गए खण्ड	इनमें कितने गाँव भ्रागये	जनसंख्या [लाख में]
सामुदायिक				
विकास खण्ड				
(C D Blocks)			1	
१६५२-५३	२०६	२०६	२७३८८	१६६
8688-88	५६	५६	द४द४	४२
१६५५-५६	१५२	१५२	२१४३८	१२४
१६४६-५७	२५०	२४०	३६०१७	१८६
१६५७-५=	१८६॥	१८६॥	२४४३०	११२
				l

विकास खड	स्वीकृत खड	जारी किए गए खण्ड	इनमे कितने गाँव ग्रा गए	1
राष्ट्रीय विस्तार	-			
सेवा खण्ड				
(N.E.S. Blocks)				,
25xx-xx	1139	1139	२८३	१८
१६५५-५६	१८७	१८७	२७२६१	१३८
१६५६—५७	88X 1	<b>8</b> 68	६६६११	333
१६५७-५८	७३४	४६७	£0008	302
योग	२१४२	२१५२	२७६०२६	6868

जून १६५७ के ग्रांत तक ११८६५७ गाँव जिनमें ६०३ करोड़ जन-सख्या भा जाती है 'सामुदायिक-विकास-खण्डो' (Community Development Blocks) तथा १५७०६६ गाँव जिनमे ८.६ करोड़ जन-संख्या भा जाती है 'राष्ट्रीय-विस्तार-सेवा-खण्डों' (National Extension Service Blocks) के ग्रन्तगंत ग्रा गई थी। द्वितीय पंच-वर्षीय-योजना काल के बचे हुए वर्षों में 'सामुदायिक-विकास-खण्डों' तथा 'राष्ट्रीय-विस्तार-खण्डों' का जो कार्य-क्रम निर्धारित किया जा चुका है वह निम्न है.—

वर्ष*	प्रस्तावित राष्ट्रीय विस्तार सेवा-खण्ड	प्रस्तावित सामुदायिक विकास-खड
	(Proposed N.E.S. Blocks)	(Proposed C.D. Blocks)
<b>१६</b> ५=-५६		२६०
8 E X E - 40	003	300
१६६०-६१	१०००	३६०

उक्त तालिका में प्रस्तावित सामुदायिक-विकास-खण्डो की जो सख्या दी गई है उसका श्रमिप्राय यह है कि प्रस्तावित राष्ट्रीय-विस्तार-सेवा-खण्डो में से उतनी सख्या मे गहराई से काम किया जायगा श्रौर उतने 'गष्ट्रीय-विस्तार-सेवा-खण्ड' बहुत श्रधिक कार्य किये जाने के कारण 'सामुदायिक-विकास-खण्ड' का रूप धारण कर लेगे क्योंकि यह हम पहले ही स्पष्ट कर श्राये हैं कि इन दोनो मे कार्य की गहराई का ही भेद है, श्रन्य कुछ नहीं।

### ६. सामुदायिक-योजनाभ्रों तथा राष्ट्रीय-विस्तार-सेवाभ्रों का मृत्यांकन

(Evaluation of the working of C. D. and N. E. S. Blocks)

प्लैनिंग-कमीशन ने 'सामुदायिक-योजनाथ्यो' तथा 'राष्ट्रीय-विस्तार-सेवाश्यो' की यथार्थ स्थिति का मूल्याकन करने के लिए, यह जानने के लिए कि इन योजनाथ्यो में कहाँ तक सफलता मिली है, कहाँ हेर-फेर तथा परिवर्तन की भावश्यकता है, एक सस्या बनाई हुई है जिसका नाम है— 'प्रोग्राम इवल्युएशन आगंनाइजेशन' (Programme Evaluation Organisation) । इस संस्था की तरफ से एक 'प्रोजेक्ट इवल्युएशन आफिसर' (Project Evaluation Officer) भी नियुक्त

<sup>\*</sup> India 1958.

किया जाता है। इस संस्था द्वारा सामुदायिक योजनाश्रो का निरीक्षण करके, उनके कार्यकर्ताश्रों से मिल-जुलकर, उनकी कठिनाइयो को समक्तकर, श्रीर हर बात की जाँच-पडताल करके समय-समय पर रिपोर्ट तैयार की जाती है। १६५५ तथा १६५६ मे भी इस प्रकार की रिपोर्ट तैयार हुई, श्रीर मई १६५८ में इस सस्था की पाँचवी रिपोर्ट प्लैनिंग-कमीशन के सम्मुख प्रस्तुत की गई। १६५८ की रिपोर्ट में सामुदायिक-योजनाश्रो तथा राष्ट्रीय-विस्तार-सेवाश्रों के विषय में जो मुख्य-मुख्य बाते कही गई, वे निम्न हैं:—

- (१) विस्तार-खण्ड के कार्यकर्ताओं की संख्या और विस्तार-खण्ड पर किया जाने वाला ज्यय विस्तार-खण्ड के क्षेत्र के अनुकूल होना चाहिए—'प्रोग्राम इवैत्युएशन आगंनाइजेशन' का कहना है कि योजना खण्डो के श्रव्ययन से पता चला है कि जन-सख्या की दृष्टि से योजना का क्षेत्र प्रायः २५ प्रतिशत बडा है, श्रीर जो बडे क्षेत्र हैं उनमें उस क्षेत्र के अनुरूप उतना अधिक न तो स्टाफ ही रखा गया है और न उतने बड़े क्षेत्र के लिए उतने घन की व्यवस्था की जाती है। इसका परिणाम यह हुआ है कि प्रोग्राम को उतनी गहराई मे न चलाकर हल्का करना पडता है। सामुदायिक-योजनाओं और राष्ट्रीय-विस्तार-सेवाओं को उपयोगी बनाने के लिए इन क्षेत्रों में जितने कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है और जितने धन की आवश्यकता है उसकी व्यवस्था किये बिना इन योजनाओं का पूर्ण रूप से सफल होना कठिन है।
- (२) विकास-खण्डों की संस्था तभी बढ़ानी चाहिए जब कार्य-कर्ताम्रों की संस्था पर्याप्त हो—'प्रोग्नाम इवैल्युएशन भ्रागंनाइजेशन' के सदस्यों का कहना है कि उन्होंने जहाँ तक वस्तु-स्थिति का भ्रष्ययन किया है उसके अनुसार तो यह परिणाम निकलता है कि विकास-क्षेत्रों

<sup>\$</sup>The Fifth Evaluation Report on Working of Community Development and N. E. S. Blocks published by the Programme Evaluation Organisation.

मे कार्य करने वालो का अभी बहुत अभाव है। उदाहरणार्थ, ४० प्रतिशत विकास-क्षेत्रों में 'क्षेत्र-विकास-अधिकारी' (Block Development Officer—B. D. O.) पूरे समय तक उपस्थित नहीं थे और 'विकास-योजना-क्षेत्रों' (C. D. Blocks) तथा 'विस्तार-सेवा-क्षेत्रों' (N. E. S. Blocks) में कृषि-विवेधक योजना-काल के एक-चौथाई समय तक उपस्थित नहीं थे। इस सबका यही परिणाम हो सकता हं कि योजना तो चालू रही, परन्तु योजना को क्रियान्वित करने वाले व्यक्तियों का अभाव रहा। जब योजना को चलाने वाले व्यक्ति न रहे, तब योजना भी क्या चली होगी ?

- (३) सामुदायिक-योजना और राष्ट्रीय-विस्तार-सेवाझों का प्रोग्राम और उसे पूर्ण करने के लिए रखे गए कार्यकर्ता उस-उस क्षेत्र की स्थानीय आवश्यकताओं को देखकर तदनुरूप होने चाहिएँ—ऐसा प्रतीत होना है कि भिन्न-भिन्न क्षेत्रों की योजनाये उस-उस क्षेत्र की स्थानीय आवश्यकताओं को देखकर नहीं बनाई गई। परिणाम यह होता है कि योजना का जो प्रोग्राम बनाया जाता है वह स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता और इससे वहाँ के लोगों के जीवन को योजना छू नहीं पाती। लासकर स्टाफ रखते और प्रोग्राम बनाते हुए स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखा जाता।
- (४) 'खण्ड-विकास-काधिकारी' (Block Development Officer) की योग्यता और उसकी स्थित उसकी कर्तमान योग्यता और स्थित से कंची होनी चाहिए ज्यो-ज्यो समय बीतता जायगा त्यो-त्यो अपने देश में सत्ता का विकेन्द्रीकरण होता जायगा और सत्ता कुछ लोगों के हाथ में केन्द्रित रहने के स्थान में जन-साधारण के हाथ में आ जायेंगी। प्रजातात्रिक-युग का यह अवश्यमभावी परिणाम है। इसका परिणाम यह होगा कि जितने विकास-क्षेत्रों में काम करने वाले अधिकारी हैं उनका महत्व बढ जायगा क्योंकि वे भारत के ग्रामों में बसने वाली जनता के निकटतम सम्पर्क में रहने बाले ब्यक्ति होंगे। ऐसी स्थिति में

इन कार्यकर्तामों का महत्व पहले से बहुत मिषक बढ़ जायगा। क्योंकि इनका महत्व बढ़ेगा इसलिए यह भावश्यक है कि ये लोग योग्यता में भव से बढ़े-बढ़े हों भौर इनकी स्थिति इनकी वर्तमान स्थिति से ऊँची मानी जाय।

- (१) कृषि के प्रसावा प्रम्य सभी क्षेत्रों में भी विकास तथा विस्तार (Development and Extension) के कार्य को बढ़ाया जाय धौर विशेषकों को प्रपता कार्य करने दिया जाय, उन्हें प्रवन्ध के कार्य से सुकत किया जाय—फिलहाल विकास-क्षेत्रों में कृषि के प्रलावा 'विस्तार-कार्य' (Extension work) बहुत कम दिखाई देता है। जो भी विशेषक्र इन विकास-क्षेत्रों में कार्य करते हैं, वे प्रायः प्रवन्ध के कार्य में क्यस्त रहते हैं। प्रगर हम इन क्षेत्रों का सब दिलाओं में विकास चाहते हैं तो इन विशेषक्रों को प्रपने-प्रपने क्षेत्रों में विशेष ध्यान देना होगा। उदाहरणार्थ, चिकित्सा-विशेषक्र को चिकित्सा की तरफ़, शिक्षा-विशेषक्रों को शिक्षा की तरफ़ ध्यान देना होगा। इस समय कृषि-विशेषक्र तो कृषि के विस्तार में लगा ही रहता है, प्रन्य विशेषक्र प्रवन्ध के कार्य में व्यस्त रहते हैं। इस स्थित को वदलना होगा।
- (६) 'क्षेत्र-विशेषक' (Block Specialists) तथा ग्राम-सेवक के पारस्परिक संपर्क को बढ़ाना तथा ग्राम-सेवक के कार्य तथा क्षेत्र को स्वव्यः करना ग्रावश्यक है—इस समय ग्राम-सेवक तथा ब्लाक-विशेषकों का सम्पर्क कृषि के क्षेत्र को छोडकर ग्रन्य क्षेत्रों मे न के बराबर होता है। विशेषक भी ग्रपने-ग्रपने क्षेत्र में ग्राधकतर प्रबन्ध के काम में लगे रहते हैं, ग्रीर सम्भवतः इसी कारण उन्हे या तो ग्राम-सेवक की ग्रावश्यकता नहीं पड़ती, ग्रीर ग्रगर कभी ग्रावश्यकता पड़ती भी है, तो वह इतना कम प्रशिक्षित होता है कि उनके किसी काम नहीं ग्रा सकता, वे उसके बगैर ग्रपना काम चला सकते हैं। यह स्थिति ठीक नही है। हमारी योजना मे ग्राम-सेवक 'बहु-शन्धी विस्तार-कार्यकर्ता' (Multi-purpose extension worker) है, परन्तु वह इस मूमिका को सफलता

से निबाहने के लिए तैयार नहीं किया जाता । या तो उसका प्रशिक्षण प्रधिक विस्तृत-क्षेत्रों के लिए होना चाहिए ताकि वह प्रत्येक विशेषज्ञ को उसके काम में सहयोग दें सके, या उसका प्रशिक्षण कुछ ही क्षेत्रों में होना चाहिए ग्रीर उसे काम करने के लिए भी सीमित क्षेत्र देने चाहियें। इस समय उसके कार्य का क्षेत्र बहुत ग्रिषक विस्तृत है परन्तु उसकी योग्यता का क्षेत्र इतना विस्तृत नहीं है। इस समय ग्राम सेवक को जितनी योग्यता होती है उसकी अपेक्षा उसके कार्य का क्षेत्र २५ प्रतिशत अधिक विस्तृत है। इसके ग्रितिरिक्त ग्राम-सेवक जहाँ रहता है उस स्थान को छोडकर ग्रन्य ग्राम जिनमे उसे काम करना है उसकी सेवाग्रों का ४५ प्रतिशत कम फ़ायदा उठा पाते हैं।

- (७) विकास-क्षेत्रों के लिए घन प्राप्त करने की व्यवस्था को सरल बनाना होगा—विकास-क्षेत्रों के लिए जितना घन स्वीकृत किया जाता है उतना वे खर्च नहीं कर पाते। इसका कारण है घन प्राप्त करने की व्यवस्था का पेचीदा होना। या तो ठीक समय पर घन की स्वीकृति नहीं प्राप्त होती, जब स्वीकृति हो भी जाती है तब भी दफ्तरी लम्बी-चौडी कार्यवाही के कारण धन समय पर प्राप्त नहीं होता जिससे कार्य प्रधूरे पड़े रह जाते हैं।
- (द) जनता का सहयोग प्राप्त करने के उपायों पर विचार करने की आवश्यकता है—जब से सरकार द्वारा विकास का कार्य प्रारम्म हुआ है तब से जनता मे यह भावना उत्पन्न हो गई है कि यह सब-कुछ सरकार का काम है, इसमें जनता को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सरकारी लोगो की भावना भी ऐसी ही रहती है कि वे अपने अफसरीपन में अधिक रहते हैं। इस सबसे परिवर्तन की आवश्यकता है। इस दृष्टिकोण का परिवर्तन तभी हो सकता है जब इन क्षेत्रों में सरकारी कार्यकर्ता वे लोग हो जिनकी भावना जनता की भावना हो, जो जनता के साथ हिल-मिल सकते हो, उनके साथ एक-जान हो सकते हों,

जीपों में सैर करते फिरने वाले और चपरासियों से अपने घर के काम कराने वाले जनता में किसी प्रकार का उत्साह नहीं पैदा कर सकते।

(१) हरिजनों तथा ग्रन्थ मूमिहीनों को साथ पहुँचाने के लिये विकास-कार्यों की रूप-रेखा में परिवर्तन करना होगा—इस समय जो विकास-कार्य चल रहे हैं उनसे हरिजनों तथा अन्य पिछड़े यगों को भी लाभ पहुँचा है। उदाहरणार्थ, कुएँ खुदे हैं, सड़कें बनी हैं, स्कूल खुले हैं। इन सबका इन पिछड़े वगों को भी फ़ायदा पहुँचा है। इन पिछड़े वगों के लिये कही-कही विशेष तौर पर भी कार्य हुआ है। परन्तु फिर भी विकास-क्षेत्रों में ग्रिधिक कार्य कृषि सम्बन्धी ही हुआ है, और क्योंकि हरिजनों तथा अन्य पिछड़े वगों के पास भूमि ही नही है इमलिये इन्हें अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा कम लाभ मिला है। इस दृष्टि को सामने रखते हुए हमें विकास-क्षेत्रों के कार्य की रूप-रेखा में कुछ ऐसा परिवर्तन करना होगा ताकि इन्हें भी लाभ पहुँच सके।

इस प्रकार हमने देखा कि भारत के ग्रामों का पुर्नीनर्माण पहले गैर-सरकारी तौर से चलता रहा ग्रौर श्रव सरकार की सहायता से विकास-योजनाम्रो द्वारा बड़ी तीव्र गति से चल रहा है।

#### प्रश्न

- १. योजना की क्या श्रावदयकता है ?
- जिन देशों में आयोजन के अनुसार कार्य किया गया उनकी प्रगति की उन देशों के विकास से तुलना करो जिन्होंने आयोजन के अनुसार कार्य नहीं किया।
- ३. सामुदायिक-विकास-योजना की रूप-रेखा लिखिए।
- ४. 'सानुवायिक-विकास-सन्द' (Community Development Block) तथा 'राष्ट्रीय-विस्तार-सेवा-संद' (National Extension Service Block) में क्या भेद है ?

- ५. उत्तर-प्रवेश में 'ग्रग्रगामी-योजना' (Pilot project) कहाँ शुरू हुई ?
- ६ १६४८ तक 'सामुदायिक-विकास-सण्डों' (C. D Blocks) तथा 'राष्ट्रीय-विस्तार-सेवा-सण्डों' (N. E. S. Blocks) की क्या स्थित रही ?

## १०

## भारत में सामाजिक-कल्याण

(SOCIAL WELFARE IN INDIA)

### भारत में समाज-कल्याण संबंधी भ्रायोजन की रूप-रेखा

किसी भी साँकल की मजबूती उसकी कमजोर-से-कमजोर कड़ी के क्यर निर्भर है। अगर साँकल की सब कड़ियाँ मजबूत हैं, परन्तु एक कड़ी कमजोर है, तो वह साँकल उस कमजोर कड़ी के स्थान से ही टूट जायगी। समाज की साँकल की मजबूती भी उसकी कमजोर कड़ी पर निर्भर करती है। इसलिये समाज को सबल बनाने के लिए समाज के निर्वल सक्झों को मजबूत बनाना आवश्यक है।

वैसे तो संपूर्ण समाज को सबल बनाना कल्याणकारी राज्य का कर्तव्य है और इसी कर्तव्य को निभाने के लिये राज्य की प्राधिक-प्राय को बढ़ाना, जीवन-स्तर को ऊँचा करना—यह सब राज्य कर रहा है, परन्तु इतने ही से तो काम नहीं चलता। इन सबके प्रतिरिक्त समाज के जो निर्वल प्रञ्ज हैं उनकी देख-रेख करना भी राज्य का कर्तव्य है, क्योंकि जैसा हमने ग्रभी कहा शक्तिशाली-से-शक्तिशाली राज्य ग्रपने किसी एक निर्वल प्रञ्ज से शक्तिहीन हो सकते हैं। बाँघ कितना ही मजबूत क्यों न हो, ग्रमर उसमें किसी एक जगह भी छेद है, तो नदी का

पानी उसी छेद मे से रिस्ता-रिस्ता सारे बांध को तोड सकता है। राज्य के इन कमजोर ग्रङ्गो की देख-रेख करना ही 'समाज-कल्याण' (Social Welfare) का ग्राधारभूत विचार है।

इसी बात को दृष्टि मे रखते हुए भारत के सविधान मे जहाँ धाधारभूत तथा प्रेरक सिद्धान्तो . (Fundamental Human Rights and Directive Principles) में 'कल्याणकारी-राज्य' (Welfare state) की कल्पना की गई है, वहाँ समाज के दोनो पहलुम्रो को ज्यान में रखा गया है-एक पहलू है समाज का माथिक-ढाँचा, दूसरा पहलू है समाज का सामाजिक ढाँचा । ग्राधिक ढाँचा बनेगा समाजवादी समाज का. धनी-निर्धन के भेदभाव को दूर करने का; सामाजिक ढाँचा भी बनेगा समाजवादी समाज का, मनुष्य-मनुष्य के भेद-भाव की दूर करने का, स्त्री-पृरुष की सामाजिक-विषमता को, पुरुष-पुरुष की सामाजिक विषमता को, जात-बिरादरी की पैदा की हुई सामाजिक-विषमता को दूर करने का। इसी सामाजिक कार्य-कम के अन्दर वे प्रोग्राम भी आ जाते हैं जिनके अनुसार हमें समाज के उपेक्षित, होन, अधिकार-शून्य वर्ग के प्रधिकारों की रक्षा करनी है, उनकी तरफ विशेष ध्यान देना है। समाज के इस उपेक्षित-वर्ग की देख-रेख का ही दूसरा नाम समाज-कल्याण संबंधी आयोजन है। स्त्रियों की समाज में सदियों से उपेक्षा होती रही है। कही विधवाएँ है, कही स्त्रियों में शिक्षा का अभाव है, कहीं स्त्रियो का ग्राधिक-शोषण कर उन्हे नरक-समान जीवन में धकेला जा रहा है- ये सब समाज-कल्याण की समस्याएँ हैं। इसी प्रकार बच्चो की समस्याएँ हैं। निर्धन बच्चो को भरपेट खाने को नही मिलता, उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, बच्चो का स्वास्थ्य उन्नत होगा तो देश को होनहार युवक मिल सकेंगे । इनकी समस्याएँ भी समाज-कल्याण की समस्याएँ है। इनके अतिरिक्त समाज में लगडे- जुले है, अपंग है, भपाहिज हैं, बूढे हैं, कोडी हैं, भिखमंगे हैं। ये भी तो समाज के शक् है। जिन कारणो से समाज में इस प्रकार के व्यक्ति बढते हैं उन्हें दूर करना और इस समय जो इन कष्टों से कराह रहे हैं उनके कष्ट को दूर करना—यह किसका काम है ? मब तक तो धनी-मानी लोग दान देते थे, उनके दान से विधवाश्रम, म्रनाथालय, कोढी-घर चलते थे, परन्तु जब से कल्याणकारी-राज्य के विचार ने जन्म लिया है तब से किसी की दया पर निर्भर रहने के स्थान में राज्य की तरफ से इन दिशाम्रों में घ्यान देना—यह विचार जड़ पकडता जा रहा है। धनी-मानी लोगों की दया हो तभी दीन-दुखियों के कष्ट दूर हो, उनकी दया न हो, तो समाज इन कष्टों के बोम से दबा ही रहे—यह स्थिति माज के युग में नहीं रह सकती। यही सब सोचकर भाज जहाँ समाज के विकास के लिए भाषिक-योजनाएँ बन रही हैं, वहाँ समाज-कल्याण सबधी योजनाएँ भी बन रही हैं।

#### २. केन्द्र तथा राज्य के समाज-कल्याण-बोर्ड

जब से अपना देश स्वतन्त्र हुआ है, तब से 'संविधान' के अनुसार यह तो हम घोषित ही कर चुके हैं कि इस देश का विकास 'कल्याणकारी-राज्य' (Welfare state) के रूप में होगा। सरकार की तरफ से जो मंत्रालय बने हैं, वे जनता का कल्याण करने के लिए ही बने हैं। श्रम-समस्याधों को हल करने के लिये श्रम-मंत्रालय, शिक्षा की समस्याधों को हल करने के लिये शिक्षा-मंत्रालय, शिक्षा की समस्याधों को हल करने के लिये शिक्षा-मंत्रालय, स्वास्थ्य की समस्याधों को हल करने के लिए स्वास्थ्य-मंत्रालय बने हैं। इन सबका काम सरकारी तौर पर 'सामाजिक-कल्याण' करना है। परन्तु सारा-का-सारा सामाजिक-कल्याण सरकारी तौर पर ही तो नहीं होता। गैर-सरकारी तौर पर भी तो 'सामाजिक-कल्याण' का कार्य होता है। जनता ने अब तक सैकडों समाज-कल्याण के काम धपने बूते पर चला रखे थे। इन सबको सहायता देना भी कल्याणकारी-राज्य का काम है। इसी उद्देश्य से १२ अगस्त १९५३ को कैबिनेट ने 'केन्द्रीय-समाज-

कल्याण बोर्ड' (Central Social Welfare Board) की स्थापना की जो शिक्षा-मत्रालय की साधारण देख-रेख मे स्वायत्त-संस्था के रूप में काम कर रहा है। इसकी अध्यक्षा श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख नियत की गईं। इस बोर्ड का काम तीन तरह का है-एक काम तो मब तक जो समाज-कल्याणकारी कार्य जनता की तरफ से चल रहे थे, उनकी जाँच-पडताल कर योग्य सस्याम्रो को परामर्श तथा आर्थिक-सहायता देना है, दूनरा भिन्न-भिन्न मन्त्रालयो द्वारा जो समाज-कल्याण-सम्बन्धी कार्य चल रहे हैं उनमें पारस्परिक-सहयोग स्थापित करना, तीसरा जहाँ समाज-कल्याणकारी कार्य नहीं चल रहे वहाँ योजनाएँ बनाने के लिये प्राधिक सहायता देकर जनता को प्रोत्साहित करना। प्रथम-पँच-वर्षीय-योजना में 'केन्द्रीय-समाज-कल्याण-बोर्ड' की योजनाची के लिये योजना-आयोग ने ४ करोड रुपया खर्च के लिए रखा था, अब द्वितीय-पैच-वर्षीय-योजना में यह रूपया ३० करोड व्यय होगा। इस रुपये से जनता द्वारा चल रही समाज-कल्याण-योजनाम्रो को सहायना दी जायगी श्रीर नवीन समाज-कल्याण के कामो को श्राधिक-सहायता द्वारा प्रोत्साहित किया जायगा।

केन्द्रीय-समाज-कल्याण-बोर्ड क्योंकि केन्द्रीय-संस्था है, इसलिये उसका हर प्रात के कार्य की गति-विधि के विषय में जानकारी रख सकना कठिन था। इस कठिनाई को दूर करने के लिये मार्च १९५४ में केन्द्रीय-समाज-कल्याण-बोर्ड ने एक प्रस्ताव द्वारा शिन्न-भिन्न राज्यों में 'राज्य समाज-कल्याण सलाहकार बोर्डों' (State Social Welfare Advisory Boards) की स्थापना की। इन राज्य-बोर्डों का काम केन्द्रीय-बोर्ड को इस बात का परामर्श्व देना है कि उनके राज्य में कौन-कौन-सी सस्थाएँ हैं जिन्हे आधिक-सहायता देना रुपये का सक्रयय होगा, अपक्यय नहीं होगा।

# ३. द्वितीय-योजना में समाज-कल्याण का बजट

हम पहले दर्शा आये हैं कि समाज-सेवा, मकान तथा पुनर्वास पर जो ६४६ करोड रुपये व्यय होगा, इस व्यय का विवरण निम्न प्रकार है---

शिक्षा	३२०	करोड़ रु०				
स्वास्थ्य	२६७	**				
<b>ग्रा</b> वास	१२०	**				
श्रम	२६	"				
पिछडे वर्गों का कस्याण	03	"				
समाज-कल्याण	२६	**				
पुनर्वास	03	**				
<b>क्षित बेकारो की समस्या</b>						
की योजनाएँ	¥.	<u></u>				
योग	£8€	- करोड				

इन रकमो में कुछ हेर-फेर होता रहता है। उक्त तालिका में 'समाज-कल्याण' के लिए २० करोड़ की राशि दिखाई गई है, परन्तु इस समय स्थित यह है कि 'समाज-कल्याण' के लिये द्वितीय पँच-वर्षीय-योजना में 'योजना-म्रायोग' (Planning Commission) ने ३० करोड़ की स्वीकृति दी है जो भ्रगले पाँच सालों में स्त्रियों, बच्चों तथा भ्रपगों के लिये अ्यय की जा सकेगी। पिछली योजना में ४ करोड़ रुपया इस मद में खर्च हुन्ना था। इसमें से कुछ भनुदान उन सस्थान्नों को दिया जायगा, जो पहले से ही स्वय समाज-सेवा का कार्य कर रही है।

#### ४. राज्य के कल्याण-बोर्डी के कार्य

राज्य-बोर्डों मे लगभग ६ सदस्य होते है जिनमे से श्राघे केन्द्रीय-बोर्ड नामजद करता है, बाकी श्रीघे राज्य-सरकार नियत करती है। राज्य-बोर्ड के श्रध्यक्ष की नियुक्ति राज्य-सरकार केन्द्रीय-बोर्ड की सलाह से करती है। इन राज्य-बोर्डों की भ्रष्यक्षा स्त्रिया ही होती है। इन राज्य-सलाहकार-बोर्डों का काम चार तरह का है, जो निम्न है—

- (क) धार्षिक-सहायता—एक काम तो है जनता द्वारा चलायी जा रही समाज-कल्याण-सबधी सस्याध्रों की जाँच-पडताल करके उनको धार्षिक-महायता देने के लिये केन्द्रीय-बोर्ड से सिफारिश करना। राज्य-बोर्डों का यह कर्तव्य है कि वे ध्रपने सदस्यो द्वारा हर सस्था की पडताल करायें धौर यह सस्था कैसी है—इस सबध में ध्रपनी मिफ़ारिश के साथ धार्षिक-सहायता के लिये भेजे गये प्रार्थना-पत्र को केन्द्रीय-बोर्ड तक पहुंचायें ताकि ध्रयोग्य संस्थाध्रो को सहायता न मिल जाय। सहायता मिल जाने के बाद यह देखना कि रुपये का सदुपयोग हुआ है, हिसाब की जाँच करना—यह सब जिम्मेदारी राज्य-बोर्ड की है।
- (ल) कल्याएग-विस्तार-योजना---राज्य-बोर्ड का दूसरा काम 'कल्याण-विस्तार-योजनाम्रो' (Welfare Extension Projects) का चलाना है । 'कल्याण-विस्तार-योजनाद्यो' का प्रारम्भ १५ ग्रगस्त १६५४ से किया गया। 'कल्याण-विस्तार-योजना' (Welfare Extension Project) का अभिप्राय यह है कि एक-एक योजना मे २०-२५ गाँव भीर २० हजार की स्राबादी श्रा जायगी। इस बीस हजार की साबादी या २०-२४ गाँवो मे यह योजना चलेगी। प्रथम-पेंच-वर्षीय-योजना मे इस प्रकार की भारत भर के ३५२ जिलों में ३५२ 'कल्याण-विस्तार-योजनाम्रो' (Welfare Extension Projects) के चलाने का केन्द्रीय-बोर्ड ने प्रोग्राम बनाया था। द्वितीय-पँच-वर्षीय-योजना मे हर जिले में एक की जगह चार 'कल्याण-विस्तार-योजनाएँ' जारी की जायँगी। ये योजनाएँ राज्य-बोर्डों की सीधी देख-रेख मे चलाई जायेंगी। इन २०--२५ गाँवो में ३ से ५ गाँवो की ट्रकडियाँ बनाकर उनमे एक-एक 'बहु-धधी केन्द्र' (Multi-purpose centre) खोला जायगा । इस प्रकार २०-२४ गाँवो मे ५ से ७ तक 'बह-धधी-केन्द्र' खोले जायेंगे जिनका काम स्त्रियो तथा बच्चो की समस्याग्रो को हल करना होगा। केन्द्रीय-

बोर्ड की इस योजना को क्रियांन्वित करने का काम राज्य-बोर्डों का है। ये राज्य-बोर्ड ही योजना के लिए उचित क्षेत्र चुनेगे। राज्य-बोर्ड इन २०-२४ गाँवों के लिये एक 'योजना-पूरक-समिति' (Project Implementing Committee) का निर्माण करेगा जिसमें स्थानीय समाज-सेवक सदस्य बनाये जायेगे। इस प्रकार केन्द्रीय-बोर्ड राज्य-बोर्ड वारा भीर राज्य-बोर्ड योजना-पूरक-समितियों द्वारा 'कल्याण-विस्तार-योजनाम्मो' के कार्य की देख-रेख करेगा। 'योजना-पूरक-समिति' को सारे काम की देख-रेख के लिये 'केन्द्रीय-बोर्ड' से एक जीप भी दी जायगी। यह सारा कार्य ग्रब शुरू हो गया है।

- (ग) परिवार-कल्याएा-योजना—राज्य-बोर्ड का तीसरा काम 'परिवार-कल्याएा-योजनाम्ना' (Family Welfare Schemes) को जारी करना है। 'कल्याण-विस्तार-योजनाएँ' (Welfare Extension Projects) तो गाँवो मे चलती हैं, कुछ योजनाएँ शहरो के लिये भी सोची गई हैं। शहरों के लिये चलाई गई इन योजनाम्नो का उद्देश्य मध्य-स्तर की स्त्रियो को काम-धंधा देना है। इस तरह की एक योजना दिल्ली मे नजफगढ स्थान पर चलाई गई। इस योजना में एक दियासलाई का कारखाना खोला गया जिसमें २०० के लगभग स्त्रियों को काम मिल रहा है। केन्द्रीय-बोर्ड के निरीक्षण मे राज्य-बोर्ड भिन्न-भिन्न राज्यों में इस प्रकार के काम जारी करने की स्कीमे बना रहे हैं जिनसे मध्य-स्तर की स्त्रियों को ज्यादा-से-ज्यादा काम मिल सके। म्रब हैदराबाद, पूना ग्रादि में भी ऐसे ग्रायोजन खोल दिए गये हैं।
- (घ) नवीन-योजनाएँ चालू करना—राज्य-बोर्ड का चौथा काम यह है कि समाज-कल्याण का कार्य करने वाली भिन्न-भिन्न सस्थामो को ऐसे काम करने के लिये प्रोत्साहित करें जो ग्रब तक कोई सस्था नहीं कर रही। कई जगह तो एक ही काम के लिये कई सस्थाएँ हैं, भौर कई जगह किसी जरूरी काम के लिए भी कोई संस्था नहीं है। इस कमी को दूर करना भी राज्य-बोर्ड का काम है।

केन्द्रीय-बोर्ड की संरक्षा में राज्य-बोर्ड के जिस प्रकार के कार्य-कम का हमने ऊपर उल्लेख किया उसमें मुख्य कार्य-कम है--- कल्याण-विस्तार-योजना' (Welfare Extension Project)। इस योजना का काम गाँवों में चलता है। इस योजना के अनुसार गाँवों में अपढ स्त्रियो की प्रक्षराम्यास सिखाया जाता है, उन्हें सीना-पिरोना-काढ़ना सिखाया जाता है। बच्चो के लिये बाल-बाडी खोले जाते हैं, उनके खेलने-कृदने का प्रबन्ध किया जाता है। गाँवो में दर्वाई बाँटी जाती है, कीर्तन-भजन का प्रोग्राम धलता है, दाइयो का इन्तजाम होता है, श्रम-दान से सडको भ्रौर गलियों की सफाई ग्रादि की जाती है। जैसे केन्द्रीय-बोर्ड की 'कल्याण-विस्तार-योजना' (Welfare Extension Project) है, वैसे 'सामुदायिक-विकास-योजना' (Community Development Project) मे 'राष्ट्रीय-प्रसार-सेवा' (National Extension Service) है । केन्द्रीय-बोर्ड की तरफ़ से यह प्रयत्न किया जाता है कि जो काम 'राष्ट्रीय-प्रसार-सेवा' द्वारा हो रहा है, उससे प्रतिरिक्त कार्य को 'कल्याण-विस्तार-योजना' द्वारा किया जाय, उसी काम को न दोहराया जाय । अप्रैल १६५७ से यह निश्चय किया गया है कि ग्रव तक 'राष्ट्रीय-प्रसार-सेवा' (N E, S) का जो काम स्त्रियों, बच्चो, ग्रपगो, ग्रपराधियो म्रादि के लिए किया जाता था, वह सब केन्द्रीय-बोर्ड की देख-रेख मे 'कल्याण-विस्तार-योजना' (Welfare Extention Project) द्वारा होगा ।

# प्र. समाज-कल्याण के कार्यों की रूप-रेखा

हमने समाज-कल्याण का कार्य करने वाली सरकारी सस्था 'केन्द्रीय-समाज-कल्याण-बोर्ड' तथा राज्य के बोर्डी की रूप-रेखा का वर्णन किया। इसका यह मतलब नहीं है कि समाज-कल्याण का कार्य ग्रीर किसी सगठन की तरफ से नहीं हो रहां। शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल, तार, बिजली, बॉध—ये सब कार्य समाज-कल्याण के ही तो हैं, ग्रीर इन सबको पूरा करने के लिए ग्रलग-ग्रलग मन्त्रालय बने हुए हैं। केन्द्रीयसमाज-कल्याण-बोर्ड ग्रपने सीमित क्षेत्र मे समाज-कल्याण का कार्य
कर रहा है। इसका क्षेत्र स्त्रियो, बच्चो, ग्रपंगो, तथा ग्रपराधियों के
सुधार ग्रादि तक सीमित है। इस दिशा मे ग्रन्य ग्रनेक सस्थाएँ कार्य
कर रही हैं। उदाहरणार्थ, कस्तूरबा-स्मारक-ट्रस्ट गाँवो मे स्त्रियो
की समस्याग्रो को हल करने, कुष्ठ रोगियो के लिए ग्रस्पताल ग्रादि
खोलने की दिशा मे पर्याप्त काम कर रहा है। भारत-सेवक-समाज का
सगठन भी समाज-कल्याण को दृष्टि में रखकर ही किया गया है। यह
मस्था सर्त्रथा जनता के सहयोग से समाज-कल्याण का कार्य कर रही है।
समाज-कल्याण की सब सस्थाएँ—केन्द्रीय तथा राज्य कल्याण बोर्ड,
कस्तूरबा ट्रस्ट, भारत-सेवक-समाज ग्रादि—समाज-कल्याण का कार्य
जिन क्षेत्रो मे कर सकती हैं ग्रीर कर रही हैं, वे हैं—स्त्रियो का क्षेत्र,
बच्चो का क्षेत्र, बाधितो का क्षेत्र, कुष्ठ पीडितो का क्षेत्र तथा
पिछडी जातियो का क्षेत्र। इन सब के विषय मे हम यहाँ सक्षेप
मे कुछ लिखेगे—

### [ स्त्रियों के क्षेत्र में समाज-कल्यारा ]

(क) स्त्रियों की स्थिति— स्त्रियों के सम्बन्ध में सब से वहीं समस्या उनकी स्थिति की है। श्रव तक भारतीय-नारी को घर के क्षेत्र में ही सीमित रखा गया है, श्रव वह धीरे-धीरे सामाजिक-क्षेत्र में भी अपना स्थान बना रही है। यह ठीक है कि कुछ स्त्रियों के विधान-सभाग्रों तथा संसद् का सदस्य बनने या मिनिस्टर बन जाने से स्त्रियों की स्थिति में कोई मौलिक भेद नहीं पड जाता, परन्तु यह भी ठीक है कि उच्च पदों पर कुछ स्त्रियों के पहुँच जाने से स्त्री-मात्र में आत्म-विश्वास की भावना श्रवश्य बढ जाती है। इन सब बातों के अलावा स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए 'सामाजिक-विधान' (Social legislation) को बदलने की जरूरत है। हम इस पुस्तक में उन सामाजिक-विधानों की पहले एक श्रव्याय में चर्चा कर श्राये हैं जिनके पारित होने से स्त्री की

स्थिति मे बहुत फर्क पड गया है। कोई समय था जब यहाँ सती-प्रथा थी। इनके प्रलावा बाल-विवाह, विघवापन, अनमेल विवाह —ये सब भार-तीय नारी के जीवन को कडवा बनाने के लिए बहुत काफी हैं। इन सब की तरफ़ श्रब समाज का ध्यान जा रहा है, और ऐसे विधान बन रहे हैं जिनसे इस स्थिति में सुधार हो रहा है।

- (क) भातृ-सदन स्त्रियों की सबसे बड़ी समस्या मातृत्व की है। ग्रपने देश मे प्रथम-प्रसव का समय जीवन-मरण का समय समभा जाता है। प्रशिक्षित दाइयों की हजारों की सख्या में जरूरत है। राज्य के कल्याण-बोर्डों की तरफ से गाँवों में ऐसे केन्द्र खोले जाने की व्यवस्था है जहाँ प्रसव की सब सुविधा दी जाय ग्रीर प्रसव के बाद जज्जा-बच्चा का ख्याल रखा जाय। इस दृष्टि से मातृ-सदन खोलना समाज-कल्याण का बड़ा भारी काम है। इसके साथ-साथ स्त्रियों के मनोरजन के साधन उपस्थित करना भी कई सस्थाएँ कर सकती हैं।
- (ग) आर्थिक-उद्योग—गाँवो तथा शहरो दोनो स्थानो मे मध्य-वर्ग की स्त्रियो के लिए कुछ ऐसे उद्योग खोलना या उन्हे ऐसा प्रशिक्षण देना जिससे अपने फालतू समय मे वे कुछ कमा सकें और परिवार की आर्थिक-सहायता कर सके—यह भी स्त्रियों के सामाजिक-कल्याण के लिए आव-ध्यक कदम है। जिस समय पुरुष अपने काम-धधे पर चला जाता है, बच्चे पढने चले जाते हैं, उस समय स्त्री के लिए करने को कुछ नहीं रहता। ऐसे समय का उपयोग करने के लिए कुछ ऐसे उद्योग खोले जा सकते हैं जिनमे कमाई भी हो जाय, समय का भी सदुपयोग हो जाय। जो स्त्रियाँ मेहनत-मजदूरी पर निर्भर करती हैं उनके लिए भी कुछ ऐसे उद्योग खोले जा सकते हैं, जो उन्हीं के अनुकूल हो।
- (घ) नैतिक-सुधार समाज-कल्याण का एक बड़ा क्षेत्र नैतिक-सुधार का है। स्त्रियो की अनैतिक-कार्य मे अपने समाज मे घकेला जाता है। इसी का दुष्परिणाम वेश्या-वृत्ति है। १६५० में राष्ट्र-सघ के निश्चय के अनुसार ससार से वेश्या-वृत्ति को दूर करने के लक्ष्य पर

भारत ने भी हस्ताक्षर किए थे, अत. वेश्या-वृित्त को दूर करना हमारा लक्ष्य तो कभी का बन चुका है। इसी दृष्टि से स्त्रियो के इस अमैतिक-व्यापार की छान-बीन करने के लिए २४ दिसम्बर १९५४ को 'केन्द्रीय-समाज-कल्याण-बोर्ड' ने 'सामाजिक एवं नैतिक स्वास्थ्य सलाहकार समिति' की स्थापना की थी। इस समिति के सदस्यों ने देश में जगह-जगह जाकर वेश्या-वृत्ति के कारणों की जाँच की। अपनी जाँच के आधार पर समिति ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसका निचोड यह था:—

- (i) व्यभिचार को बन्द करने के लिए पर्याप्त मात्रा मे व्यापक कानून नहीं हैं। इस घृणित व्यापार को चलाने वाले श्रव्सर कानून के शिकंजे से बच निकलते हैं। जो कानून चगुल में फॅस जाते हैं वे भी कानून के जरिये ही थोडा-बहुत ले-देकर बरी हो जाते हैं। इसलिए वेदयावृत्ति पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए एक व्यापक कानून बनाना चाहिए।
- (n) सारे देश में व्यभिचार के व्यापार को चलाने वालों का एक जाल-सा बिछा हुआ है। जब तक दृढतापूर्वक इसे सरकारी तौर पर नहीं रोका जाता तब तक यह नहीं रुक सकता।
- (ii) यद्यपि वेश्या-वृत्ति नगरो की समस्या है, तो भी इस व्यापार के लिए मधिकतर लडिकयाँ गाँवो से भगाई जाती हैं। ६६.५ प्रतिशत वेश्याएँ देहाती होती हैं। ५५ ४ प्रतिशत वेश्याएँ माधिक-कारणो से यह ध्रधा करती हैं, २७७ प्रतिशत घरेलू भगडों, वेमेल विवाहो, विघवापन मादि के कारण इधर ग्रा भटकती हैं, १६.६ प्रतिशत प्रचलित सामाजिक प्रयाग्रो के कारण यह पेशा अपनाती हैं।

इस रिपोर्ट के ग्राधार पर दिसम्बर १६५६ मे पालियामेट में एक बिल पेश हुग्रा जिसका नाम था— 'स्त्रियो तथा लडकियों के ग्रनैतिक व्यापार का ग्रवरोध' (Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Bill, 1956)। दिसम्बर १६५६ में ही यह स्वीकृत होकर ग्राधनियम बन गया। उसका उद्देश्य स्त्रियो तथा कन्याग्रो

के अनैतिक व्यापार को रोककर वेक्या-वृत्ति को बन्द करना है। समाज-सुधारको का कहना है कि यह अधिनियम इतना व्यापक नहीं है जिससे यह धघा पूरी तरह से रुक सके, इसलिए इसे और अधिक कडा करने की जरूरत है।

ये थोडी-बहुत समस्याएँ हैं जिनका स्त्री-जाति से सम्बन्ध है। समाज-कल्याण की कोई भी तस्था इन दिशाक्रो मे से किसी एक दिशा मे भी काम करके श्रेय की भागी बन सकती है।

#### बिच्चों के क्षेत्र में समाज-कल्यारा ]

बच्चो के बड़े होने से ही समाज बनता है, इसलिए बच्चो की समस्याग्रो पर परिवार, समाज तथा राज्य—इन तीनो को ध्यान देना चाहिए। वैसे तो इन तीनो को बच्चो के प्रश्नो को ग्रपने-ग्रपने स्तर पर हल करना ही है, परिवार को उत्तम, हृष्ट-पुष्ट तथा उतने ही बच्चे पैदा करने हैं जितनों की वह परवरिश कर सकता है, समाज को उनके लिए उत्तम परिस्थिति उत्पन्न करनी है ताकि उनके सस्कार शुद्ध बने, राज्य को उनकी शिक्षा का प्रबन्ध करना है, परन्तु कई ऐसी भी दिशाएँ हैं जिनकी तरफ समाज-कल्याणकारी सस्थाएँ ग्रपना ध्यान दे, तो बच्चो की ग्रनेक समस्याएँ हल हो सकती हैं। उन्ही का हम यहाँ उल्लेख करेगे—

- (क) पौष्टिक-भोजन (Nourishment) कई बच्चो का पौष्टिक-भोजन न मिल सकने के कारण विकास नहीं हो पाता। माता-पिता गरीब हैं — इसलिये वे घर में उन्हें दूध-घी दे नहीं सकते, दूसरा उनके लिये कोई रास्ता नहीं। ऐसे बच्चों को पाठकाला में दूध देना, विटामिन की गोलिया देना — ये सब काम समाज-कल्याण सस्थाएँ कर सकती हैं। दूध ग्रादि इकट्ठा करने का काम सार्वजनिक चन्दे से तथा ट्रस्टों के मनुदान से हो सकता है।
- (स) हीन-बुद्धिता (Feeblemindedness)---इस समय सब तरह के बालक एक-साथ पढते हैं, कुशाग्र-बुद्धि तथा हीन-बुद्धि। हीन-बुद्धि

बालकों को मलग छोडकर उनके लिए पढाई की मलग व्यवस्था करना अरूरी है ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। कुशाय-बुद्धि बालकों के साथ हीन-बुद्धि बालकों के पढने से वे भौर धिक हीन-बुद्धि हो जाते हैं। इस दिशा में समाज-कल्याण-संस्थाएँ बहुत भ्रच्छा कार्य कर सकती हैं।

- (ग) बाल-परामर्ज-केन्द्र (Child guidance clinics)— बच्चों को अपने विकास की ठीक दिशा बतलाने के लिए तथा माता-पिता को बालक की मानसिक प्रवृत्ति बतलाने के लिए परामर्श-केन्द्र खुलने चाहिएँ, नहीं तो बच्चे श्लांखें बन्द करके जीवन के मार्ग पर चलते हैं। इस तरह का केन्द्र हर राज्य में एक तो होना ही चाहिए, श्लीर श्लापर हर शहर में एक हो सके, तो श्लीर श्लाच्छा है। समाज-कल्याण-संस्थाश्लो के इस दिशा में भी श्लग्रसर होने की जारूरत है।
- (घ) ज्ञिशु-गृहों की व्यवस्था (Creches)—१६४८ के फैक्टरी-एक्ट के अनुसार जिस कारखाने में २५० या इससे ज्यादा स्त्रियाँ काम करती हैं वहाँ शिशु-गृह का होना लाजमी है, इसलिए बडी फैक्टरियों मे तो शिशु-गृहों की व्यवस्था है, परन्तु इस व्यवस्था को समाज-कल्याण का कार्य करने वाली सस्थाएँ अधिक व्यापक बना सकती हैं। माता काम भी करे, बच्चे की देख-भाल भी करे—ये दो काम एक-साथ नहीं हो सकते, इसलिए जहाँ-जहाँ स्त्रियाँ काम करती है, वहाँ-वहाँ सब जगह शिशु-गहों की व्यापक व्यवस्था होनी चाहिए।
- (क) खेलों का प्रबन्ध (Play activities)—बालक के विकास के लिए खेलना प्रत्यन्त धावश्यक है। शहरों में इतना तंग स्थान होता है कि बालक गलियों तथा सड़कों पर ही गेंद-बल्ला चलाते देखे गए हैं। वैसे तो म्यूनिसियैलिटियों का कर्तव्य है कि बालकों के खेलने के मैदानों की व्यवस्था करें, धगर वे नहीं करते, तो इस दिशा में जनता में इस बात की माँग पैदा करना और जहाँ तक हो सके वहाँ तक

भ्रान्दोलन करके इस बात का प्रबन्ध कराना समाज-कल्याण सैंस्थाएँ कर सकती हैं।

- (क) बालकों के केन्द्र (Children's centres)—बालको के लिए जहाँ कीडा-केन्द्र खोलने की जरूरत है, वहाँ ऐसे बाल-केन्द्र भी खोलने की जरूरत है जिनके द्वारा बालको को इन-डोर खेल खेलने का भ्रवसर मिले, उनके योग्य पुस्तकालय हो, वे ड्वामा भ्रादि कर सके, चित्र, करा समीत भ्रादि सीख सके। समाज-कल्याण-सस्थाओं के लिए काम करने का यह भी भ्रच्छा क्षेत्र है। इस दिशा में बालकान-जी-बारी, बालको की बिरादरी, किशोर-दल भ्रादि सगठन ग्रच्छा काम कर रहे हैं। वे बालको के कैम्प भी लगाते हैं जिनमे भिन्न-भिन्न शहरों के बालक इकट्ठे होते हैं, भ्रापस में मिलते हैं, इससे एक-दूसरे के निकट भ्राने भी एक-दूसरे को ममभने का उन्हें भ्रच्छा श्रवसर मिलता है।
- (इ) युवापराध (Juvenile delinquency)—गरीबी, पारिवा-रिक-विगठन, बुरी मगत म्रादि कारणो से बालापराध तथा युवापराध—ये दोनो बच्चो की गम्भीर समस्याएँ हैं। इन समस्याम्रो को हल करने के लिए युवा-मुधार-गृह (Reformatories) खोलने की म्रावश्यकता है। यह काम सरकार भी कर मकती है, जनता के महयोग से समाज-कल्याण का कार्य करने वाली मस्थाएँ भी कर सकती है।

#### [बाधितों के क्षेत्र में समाज-कल्यारग]

'बाधित' (Handicapped) व्यक्ति बच्चे भी हो सकते हैं, युत्रा भी हो सकते हैं। समभा यह जाता है कि बाधित-व्यक्ति समाज के किसी काम का नहीं, या उसे इस योग्य नहीं बनाया जा सकता कि वह समाज के किसी काम झाये। यह गलत धारणा है। अष्टावक ऋषि के शरीर में भाठ बल पडे हुए थे, परन्तु वे भारत के महान् ऋषि थे। महाराजा रणजीर्तासह के एक आँख नहीं थी, परन्तु उन जैसे बुद्धिमान राजा कम हुए हैं। प्रेजीडेट रूजवेल्ट तथा लार्ड वेवल लगडे थे, परन्तु कूट राजनीतिज थे। एडीसन बहरे थे परन्तु उन्होंने मसार को ग्रामोफोन दिया,

बीधोवेन भी बहरे हो गए थे किन्तु वे संसार के प्रसिद्धतम गायक हो गए, डिमोस्थनीज हकलाते थे परन्तु वे अद्वितीय वक्ता थे। असल में, बाधित व्यक्तियों के जीवन के विकास की धारा शारीरिक-दिशा में तो एक जाती है, परन्तु उतने ही वेग से मानसिक-दिशा में फूट निकलती है।

समाज में दो प्रकार के अपंग या बाधिन व्यक्ति पाये जाते हैं—
(१) मनोबाधित (Mental cripples), तथा (२) शरीरबाधित
(Physically cripples)। इनमें से शरीर-बाधित तीन प्रकार के हैं—
(क) चक्षु-विहीन (Blind), (ख) बिधर तथा मूक (Deaf and dumb) तथा (ग) अंग-विहीन बालक (Orthopaedic orapples)। अग्रेजी मे औरयौस (Orthos) का अर्थ है—'ठीक'—तथा पेस
(Pais) का अर्थ है—'बालक'। 'ठीक बालक की अग-हीनता'—इस
शब्द का अर्थ हुआ। इस प्रकार का अग-हीन ब्यक्ति जैसा हमने अभी
कहा, बालक भी हो सकता है, युवा भी हो सकता है।

अयक्ति की बाधित दशा के चार कारण हो सकते हैं—(१) जन्म, (२) रोग, (३) दुर्वटना तथा (४) रोगादि के कारण ग्रग-छेद ग्रर्थात् ग्राङ्ग काट देना । कभी-कभी बच्चा जन्म से ग्रन्था होता है, ग्रन्था नहीं तो बहरा तथा गूँगा होता है, या जन्म से ही उसका कोई ग्रन्य ग्रग नहीं होता । कभी-कभी ये बाबाएँ किसी रोग से उस्पन्न हो जाती हैं । चेचक से ग्रन्था हो जाना साधारण-मी बात है । कभी-कभी किसी दुर्घटना से कोई मानसिक या शारीरिक क्षति हो जाती है । इसके श्रतिरिक्त कभी-कभी हाथ-पैर काट देना पड़ता है ।

बाधित बच्चों या युवाध्रों के प्रति समाज की तीन तरह की धारणाएँ दिखाई देती हैं—(१) पहनी धारणा तो खूरणा की है। अन्धा हो, काणा हो, सूना हो, लगडा हो—समाज के अधिकाश व्यक्ति यह समभते हैं कि में समाज के लिए सर्वया शून्य के समान हैं। इस प्रकार की धारणा से इन बाधितों के हृदय को जो चोट पहुँचती है उसे बाधित व्यक्ति ही

समक सकता है। इससे उनके हृदय में हीनता की भावना स्थिर रूप से जम जाती है। (२) दूमरी घारणा बया की है। समाज के कुछ व्यक्ति इस प्रकार के बाधितों के प्रति सहानुभूति दिखाते हैं, उनके लिए दान देते हैं। लूले-लगड़े भीख मांगते हैं, और दयालु-हृदय के लोग उनकी भोली में दो-चार पैसे डाल देते हैं। इससे बाधितों में म्रात्म-सम्मान की भावना नहीं रहती, पर-निर्भरता उनके जीवन का सूत्र बन जाती है। (३) तीसरी घारणा बाधिनों में म्रात्म-सम्मान की भावना उत्पन्न करमें की है। इस घारणा के म्रनुसार बाधित व्यक्ति चाहे बच्चा हो, चाहे युवा हो, नमाज का ठीक वैसे ही म्रग है, जैसे दूसरा कोई। इस घारणा को मानने वालों का कहना है कि म्रगर बाधितों को चिकित्सा तथा शिक्षा सम्बन्धी पूरी-पूरी सुविधाएँ दी जाँय, तो वे समाज में म्रन्य व्यक्तियों जैसा ही जीवन बिता सकने हैं। समाज-कल्याण के क्षेत्र में विचार करने बालों के विचार की यह तीसरी दिशा है।

बाधितों के सम्बन्ध में हम लोग समाज-कल्याण के क्षेत्र में क्या-क्या कर रहे तथा कर सकते हैं इस सम्बन्ध में थोडा-सा विचार कर लेता ग्रसंगत न होता—

(क) मानसिक-बाधित—यद्यपि मानसिक-बाधित कभा भी स्वस्थ व्यक्ति का जीवन व्यतीत नहीं कर सकता, तो भी ग्रगर उस पर विशेष रूप से व्यान दिया जाय, तो सुख-पूर्वक जीवन जरूर व्यतीत कर सकता है। ग्रमरीका मे ५० साल से मानसिक-बाधित बच्चों के स्कूल खोले जा रहे हैं, ब्रिटेन मे १६५४ में १६४५६ बाधित लड़के ल कियों को शिक्षा देने के लिये २१७ स्कूज खुले हुए थे जिनमे प्रति बालक २०० से ३०० पौड तक व्यय किया जा रहा था। इङ्गलैण्ड मे स्टौरक्रिज मे सनफ़ील्ड नाम का प्रसिद्ध स्कूल है जो १६३० मे स्थापित हुग्रा था। इसमे ग्राँस्ट्रिया के डा० रूडोफ स्टीनर (Dr. Rudof Steiner) की शिक्षा-प्रणाली के ग्रनुसार बाधित बच्चों की देख-रेख की जाती है। डाँ स्टीनर की पद्धित के ग्रनुसार बच्चों को

ऐसी परिस्थिति में रखा जाता है जिसमें वे भूल जाते हैं कि उनमें किसी प्रकार की कमी है, उनमे हीनता की भावना उत्पन्न नहीं होने दी जाती, उन्हें हाथ का काम विशेष रूप से सिखाया जाता है। इस प्रकार के स्कूल समाज-कल्याणकारी संस्थाएँ खोलकर समाज-कल्याण के क्षेत्र में सबसे उत्तम काम कर सकती हैं।

(ल) शारीरिक-वाधित (अन्थे)—१६३१ के बाद से भारत में अन्धों की सख्या नहीं ली गई। १६३१ में यहाँ ६ लाल अन्धे थे। सबसे पहले अन्धों का स्कूल अमृतसर में १८८७ में स्थापित हुआ। १९५६ तक भारत में ५० के लगभग अन्ध-विद्यालय स्थापित हो चुके हैं। इन स्कूलों में सिर्फ २००० विद्याधियों की देख-रेख हो रही है। बाकी अन्धे अपने कर्मों को रोते सिर पटकते रहते हैं। नर्सरी-स्कूल में जाने लायक बच्चों के लिये तो भारत भर में १९५६ तक सिर्फ एक स्कूल था—दक्षिण-भारत के पालम कोट्टा जगह पर और वहाँ भी कुल ५ से कम आयु के ४ बच्चे शिक्षा पा रहे थे।

कई बच्चे जन्मान्ध होते हैं, कई विटामिन की कमी के कारण प्रन्धे हो जाते हैं, कई बीमारियों से, कई पैदायश के समय की माता की मसावधानी से, कई मांख माने पर गलत दवा डाल देने से। जिस तरह से भी कोई भन्धा हुमा हो, समाज की उसके प्रति प्रतिक्रिया उसके जीवन को बना या बिगाड देती है। हमे ऐसे स्कूल स्थापित करने होंगे जिनमें ऐसे बच्चों को जो शारीरिक मांख से नहीं देख सकते परन्तु प्रज्ञा की भांख से देख सकते हैं, भपना विकास करने योग्य बनाया जा सके। महींप दयानन्द के गुरू विरजानन्द सरस्वती प्रज्ञा-चक्षु थे, परन्तु वे व्याकरण और वेदों के भगाध पिटत थे, मिल्टन प्रज्ञा-चक्षु थे, परन्तु पैरेडाइज लौस्ट के लेखक के रूप में महान् किव हुए। क्योंकि कोई भन्धा है, इसलिये वह कुछ नहीं कर सकता—यह कितनी भ्रान्त धारणा है। सत्य तो यह है कि मांखों के न होने से मनुष्य बहि:वृत्ति नहीं रहता, वह भन्तवृत्ति हो जाता है, ब्यान को भ्रधिक केन्द्रित कर सकता

है, भ्रीर समाज के लिये न-जाने कौन-सा अन्ध-व्यक्ति किस नई उपज को लाकर दे सकता है।

१६४८ तथा १६५० में बम्बई में अन्धों की समस्याओं पर विचार करने के लिए अखिल-भारतीय-कान्फों में हुई थीं। १८-२३ अप्रैल १६५५ में मसूरी में इसी प्रकार की एक कान्फोंस हुई जिसका उद्घाटन अमरीका की प्रसिद्ध प्रज्ञा-चश्च श्रीमती डा० हैलन कैल्लर (Helen Keller) ने किया। इस कान्फोंसो में अन्धों की समस्याओं पर विशेष खल दिया गया, उनके बनाये सामान की प्रदक्षिनी की गई। अन्धों के पढ़ने की पद्धित को जैले-पद्धित (Braille System) कहते हैं। उनके पढ़ने की खास तरह की पुस्तकें होती हैं जिन्हें हाथ से छूकर पढ़ा जाता है। इस उद्देश्य से देहरादून में एक केन्द्रीय-जैले-प्रेम (Central Braille Press) भी है जहाँ ऐसी पुस्तके छपती हैं। देहरादून में अन्धों को प्रशिक्षण देने के लिए एक 'युवा-प्रशिक्षण-केन्द्र' (Adult Training Centre for the Blind) भी है।

(ग) शारीरिक-बाधित (बहरे तथा गूंगे)—१६३१ की गणना के अनुसार भारत में ७ लाख बहरे थे, जिनमें से बहरे बच्चे २,३०,००० तथा ३५०० स्कूल जाने की आयु के थे। उसके बाद कोई गणना नहीं ली गई। १६५७ तक बहरों के ४४ स्कूल खुल चुके थे जिनमे २००० के लगभग बालक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इनमें से पहला स्कूल १८६४ में बम्बई में लीला गया। १६५५-५६ में ५० विधरों को सरकार द्वारा मान्यता-प्राप्त बिधर-शिक्षणालयों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्र-धृति दी गई थी। दितीय-पँच-वर्षीय-योजना में बिधरों के लिए एक 'प्राविधिक-प्रशिक्षण-केन्द्र' (Technical Training Centre) खोलने की योजना है जिसमें शुरू में १०० नवयुवक भर्ती किये जायेगे। इस केन्द्र पर १७ लाख रूपया खर्च किया जायगा। अनुभव बतलाता है कि बिधर व्यक्ति ऐसी मशीनों को जिनके चलाने में कुशलता की जारूरत हो, ग्रन्य व्यक्ति ऐसी मशीनों को जिनके चलाने में कुशलता की मुद्रणालयों में जहाँ

बिधर व्यक्ति कम्पोजीटरों का काम करते हैं यह देखा गया है कि वे भन्यों की अपेक्षा श्रव्छा और अधिक काम करते हैं। इसका कारण यहीं है कि सुन न सकते के कारण वे अपना समय बातचीत में नहीं खोते और काम किये जाते हैं।

१६-२४ सितम्बर १६५५ में मसूरी में मारत के शिक्षा-मंत्रालय की तरफ से बिथि की समस्याम्रो पर विचार करने के लिए एक कान्फेंस हुई थी जिसमें सरकार की तरफ से बताया गया कि सरकार ने कई व्यवसायों में बिथि को भर्ती करने का निश्चय किया है। द्वितीय-पँच-वर्धीय योजना में ३००० बिधर व्यक्तियों को काम पर लगाया जायगा। समाज-कल्याणकारी सस्थाएँ ऐसे व्यक्तियों की गणना लेकर उन्हें सरकारी कामों में लगवा सकती हैं। इंगलैंण्ड में तो हर कार्य-नियोजन-कार्यालय में एक विशेष-अधिकारी होता है जिसे 'बाधित व्यक्तियों का पुन संस्थापक अधिकारी' कहते हैं। इसका काम अन्थे, यूँगे, बहरों को काम दिलाना होता है। ऐसी व्यवस्था अपने देश में भी होने की आव-स्थकता है।

(घ) शारीरिक-बाधित (श्रंग-विहोन) ग्रग-हीन श्रवस्था जन्म के कारण हो सकती है, रोग, दुर्घटना तथा रोगादि के कारण श्रग का छेदन कर देने से भी हो सकती है। ग्रधिकतर ग्रग न होने, काट दिये जाने या कट जाने से हमारे समाज मे भीख माँगने के सिवाय कोई चारा नहीं रहता। भीख माँगने की समस्या ग्रग-हीनों के कारण विकट रूप धारण कर जाती है। परन्तु श्राजकल प्राय सभी ग्रगों के कृत्रिम ग्रम बनते हैं जिनसे व्यक्ति की अपगता उतनी कष्ट-दायक नहीं रहती। लगड़े बैसाबी से चलते है, लूनों के लिए भी हाथ-के-से उपकरण निकल श्राय है। इन उपकर गों को ग्रधिक सस्ता करने की जरूरत है। इस दिशा में समाज-कल्याणकारी सस्थाएँ व्यान दें, तो मानव-समाज का बहुत बड़ा क्षेत्र, जो ग्रभी निकम्मा समक्ता जाता है, समाज के काम तो ग्रा ही सकता है, इसके माथ उन लोगों में ग्रपने प्रति जो ग्रानि की भावना

उत्पन्न हो जाती है उसे भी उन्हे उपयोगी कामों में लगाकर दूर किया जा सकता है।

# [ कुच्छ-पीड़ितों के क्षेत्र में समाज-कत्यारग ]

इस समय देश मे १५ से २० लाख के लगभग कृष्ठ-रोगी हैं। इस रोग से लोग इतने घबराते हैं कि कोई कोढी को पास खडा होने नहीं देना चाहता। समभा यह जाता है कि इन्पलुएजा की तरह यह फैलने बाला रोग है। असल मे, ऐसी बात नहीं है। यह रोग न तो आनुवंशिक है, न इसका गर्मी या प्रमेह से कोई सम्बन्ध है। यह एक तरह की छूत की बीमारी है परन्तु इसकी छूत घीरे-घीरे देर तक कुष्ठ-रोगी के साथ रहने से लगती है। बड़ो की भरेशा बच्चों को भासानी से इसके कीटाण् पकडते हैं। वह भी छूत लगने से ४ से १४ वर्ष के पीछे इनका असर दिखाई देता है, इसलिए कृष्ठ-रोगी के साथ जिस समय सम्पर्क हुन्ना हो, उसके वर्षों बाद इसके कीटाण अपना प्रभाव दिखा सकते हैं। सम्भवतः इसीलिए कोडी से लोग इतना परहेज करते हैं। कोढ हो जाना मानो मरने से पहले मर जाना है। कोढी ग्रस्पताल में जाकर ठीक भी हो जाय, प्रागे बीसारो नहीं फैलेगी इसका प्रमाण-पत्र भी ले घाये, तो भी जिसको एक बार कोढ हो गया, उसे भला-चगा होने पर भी रिश्तेदार तक परिवार मे शामिल नहीं करते। यह बीमारी इतनी भयंकर नहीं जितना इस बीमारी से पैदा होने वाला सामाजिक-बहिष्कार भयकर है। ऐसी हालत मे समाज-कल्याण की दिशा में कार्य करने वालों का कर्तव्य है कि कुष्ठ के विषय मे वास्तविक स्थिति को समाज के सामने स्पष्ट करके रखे।

वास्तिविक-स्थिति यह है कि रोग की शुरूग्रात में इसका इलाज हो सकता है। तुबरक तेल (चेलमुग्ने का तेल) सूई द्वारा रोगी की मास-पेशी में डाला जाता है भौर सल्फ़ोन नामक टिकियाँ खिलाई जाती हैं। इससे रोग अच्छा हो जाता है। परन्तु रोगी शुरू में इसका इलाज न करके इसको छिपाता है। इसे छिपाने की अवस्था ही ऐसी है जब इ सका इलाज हो सकता है, और इसी अवस्था में यह फैलता भी है। जो रोगी हम रोज-मर्रा बाजारों में देखते हैं, जिनकी अँगुलियाँ गल जाती हैं, नाक बैठ जाती हैं, मुँह पर एक अजीब तरह की मुर्दानगी छा जाती है, उस अवस्था में रोगी की हालत जल चुके मकान की तरह की होती है। वह तो जल चुका, राख हो चुका, अब वह भयकर जरूर लगता है, परन्तु उससे आग नहीं फैलती। आग तो तब फैलती है जब उसकी लपटें उठ रही होती हैं। दु:ख यही हैं कि उस हालत में लोग इसे छिपाये रहते हैं, और अपने घर में ही अपने बीबी-बच्चों को, साथ के पड़ोसियों को आग लगाते रहते हैं।

कुष्ठ का इलाज करने के लिए द्वितीय-पँच-वर्षीय योजना में भ्रनेक कुष्ठ-धाम बनाये जाने की व्यवस्था है। समाज-कल्याण-संस्थाएँ यह काम भ्रपने हाथ में ले सकती हैं।

#### [ विछड़ी जातियों के क्षेत्र में समाज-कल्याएा ]

भारत की जाति-व्यवस्था के परिणामस्वरूप हमारे देश मे एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो गया है जिसे पिछड़ी जातियों के नाम से पुकारा जाता है। कई लोग इन्हें हरिजन कहते हैं। जाति-व्यवस्था का धर्थ है—ऊँच-नीच का भेद! इसी भेद के पर भाषार पिछडी जातियाँ, जगली जातियाँ, जरायम पेशा जातियाँ, म्रङ्क्त जातियाँ—इस तरह की भिन्न-भिन्न जातियाँ उत्पन्न हो गई हैं जिनका भाषार भाषिक तथा सामाजिक है।

'सविधान' के तीसरे हिस्से की धारा १७ के अनुसार अञ्चलपन को अवैधानिक करार दे दिया गया है, परन्तु फिर भी यह भावना हमारे सगठन में इतनी रची-मिची है कि अब तक हमारे मनो मे से यह भावना नही मिट जाती तब तक सिर्फ कानून बन जाने से कुछ नही हो सकता। फिर भी इस भावना को मिटाने के लिए इन जातियों को, जिन्हें परिगणित जाति का भी नाग दिया जाता है, विशेष अधिकार दिये गए हैं। लोक-सभा तथा विधान-सभाओं में इनकी

सीटें सुरक्षित रखी गई हैं, हर ऊँचे पद के लिए इन्हें भ्रन्यों की भ्रपेक्षा कम योग्यता होने पर भी स्थान दिया जाता है। इस संबका उद्देश्य है कि भ्रव तक जिन नियोंग्यताश्रो के ये शिकार रहे हैं उनके दुष्परिणामों से उन्हें बचाया जाय।

इस समय परिगणित जातियों की संख्या ७७६ है, भीर इन ७७६ जातियों में व्यक्तियों की संख्या ४६८.३७ लाख है। प्रथम-पँच-वर्षीय योजना में इनके कल्याण के लिये ३६ करोड रुपया रखा गया था, द्वितीय योजना में ६१ करोड रुपया रखा गया है। इस रुपये का सदुपयोग समाज-कल्याण-संस्थायों के सहयोग से ही हो सकता है।

जगली-जातियों के विषय में दो बाते ध्यान देने की हैं। इनका मध्ययन हम लोग दो तरह से करते हैं। कई लोग तो सिर्फ प्राचीन-मानव के प्रध्ययन के रूग में इन जातियों का अध्ययन करते हैं। मानों ये किसी चिडियाघर के जानवर हो। ऐसे अध्ययन में सहानुभूति की मात्रा नहीं रहती। इसरा अध्ययन सहानुभूतिपूर्ण अध्ययन है। ये जगली जातियाँ चिडियाघर के जानवर नहीं, हम जैसे ही मानव-समूह हैं। इन को सहायता देने के लिये इनमें घुल-मिल जाने की, इनके साथ सहानुभूति प्रकट करने की आवश्यकता है। इन्हें यह अनुभव नहीं होना चाहिये कि उनके ऊपर कोई विचार, कोई सभ्यता थोपी जा रही है। ईसाई पादरी क्या करते थे? वे इन जातियों के बीच उन जैसे बन कर बस जाते थे। समभा यह जाता है कि इनके लिये सडके बना देना, इनके लिये स्कूल और अस्पताल खोल देना काफी है। यह बात नहीं है। हम स्कूल खोलें, सडकें बनाये, अस्पताल जारी करें, परन्तु साथ ही इनके जीवन में घुल-मिल जाँय, तभी हम समाज-कल्याण की दृष्टि से सफल कदम उठा रहे होगे।

ऊपर हमने समाज-कल्याण के कार्य की जो रूप-रेखा दी है, उसके अतिरिक्त युवक-आन्दोलन, अपराध-निरोध, भीख-निवारण आदि अनेक कार्य हैं जो समाज-वल्याण की दृष्टि से किये जा सकते हैं। इस मार्ग पर जो सस्या चल पड़ती है उसे प्रोग्राम की कमो नहीं रहती।

#### प्रश्न

- केन्द्रीय-समाज-कल्य.गा-बोर्ड तथा राज्य-परामर्श-बोर्ड के क्या-क्या कार्य हैं?
- २. समाज-कल्याम् के कार्यों की रूप-रेखा लिखिये।

# भ्रशुद्धि-शुद्धि-पत्र

पुष्ठ	पंक्ति	प्रशुद्ध	গুৱ
१७	२०	परिशिष्ट	प्रश्न-पत्र
ĘĘ	१४	जाति-प्रथा	जाति-व्यवस्था
<b>=</b> 8	×	(२)	(ख)
= ?	२२	(३)	(可)
= 1	१२	पर्वाह	परवाह
33	१,२२	प्रजापत्य	प्राजापत्य
१००	8	<b>ग्र</b> सुर	श्रासुर-
११७	२१	ग्रास्मान	भासमान
200	8	पचायतो में उत	साह <b>×</b>
		ग्रीर	
२०६	38	योग	इस कॉलम में जो योग
			दिया गया है वह पहले
			तथा दूसरे नक्शे-
			दोनों का योग है
२०६	२०	६०३	€.₹₹
305	२२	<b>इ.</b> ६	द. <b>६</b> १

- १९५६ के इन्टर के समाज-शास्त्र का द्वितीय प्रश्न-पत्र सब प्रश्नों के समान घडू है। किन्ही पाँच प्रश्नो के उत्तर दीजिए।
- १. जाति-व्यवस्था की परिभाषा कीजिए ग्राँर यह बतलाइये कि हिन्दुग्रो की जाति-प्रणाली की कौन सी विशेषताये भारतीय मुसलमानो मे मिलती हैं?
- २. जातिवाद (Casteism) से श्राप क्या समभते हैं ? इसके विकास के कारणो व सामाजिक प्रभावो पर प्रकाश डालिए। क्या इसे दूर करने के लिए जाति-प्रणाली को समाप्त करना अनिवार्य है ?
- ३. किन ग्राधारो पर ग्राप एक परिवार को सयुक्त परिवार कह सकते हैं ? भारतीय सयुक्त परिवार के ढाचे मे क्या परिवर्तन हो रहे हैं ? इन परिवर्तनो के कारणो पर सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए ।
- भारतीय कबीलो, मुसलमानो श्रौर हिन्दुश्रो के विवाह के उद्देश्यो
   श्रौर नियन्त्रणो या निषेधो की तुलना कीजिए।
- हिन्दुश्रो, ईसाइयो श्रीर मुमलमानो मे विवाह-विच्छेद से सम्बन्धित
   नियमो की तुलनात्मक विवेचना कीजिए।
- ६. बाल-विवाहो को रोकने के लिये सरकार ने कौन-कौन से कानून बनाए श्रीर इन कानूनो मे क्या दोष थे ? क्या भारत मे बाल-विवाहो की सख्या इन कानूनो की वजह से ही घट रही है ?
- भारतीय ग्रामीण समुदायो की विशेषताये बतलाइए भ्रौर इनमें परिवर्तन लाने वाले कारणो भ्रौर उनके प्रभावो की व्याख्या कीजिए।
- मारतीय मज्दूरों में मातृत्व संरक्षण (Maternity protection) के लिए सरकार ने कानूनों के द्वारा किस प्रकार की सुविधाएँ प्रदान की हैं ? क्या ग्रापके दृष्टिकोण से इन कानूनों में सुधार होने की ग्रावश्यकता है ?
- सामुदायिक विकास योजनात्रों के कार्यक्रम पर प्रकाश डालिए। ग्रामों की उन्नति करने में इस कार्य-क्रम से कहाँ तक सफलता मिली है ?
- १०. 'एक व्यक्ति की निर्घनता ईश्वर की देन है।' भारतीय निर्घनता के भाषार पर इस कथन की समालोचना कीजिए भौर इसको दूर करने के उपाय बतलाइए।